16.13 hours

GENERAL BUDGET (2016-17)– GENERAL DISCUSSION DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL), 2016-17 DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2015-16 –Contd.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष के तमाम माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था। इस कदर भाषण किया जा रहा था कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में खुशहाली आ गई है और कोई भी तरक्की और विकास की ऐसी योजना नहीं बची है जिसे इस सरकार ने बजट के द्वारा लागू न कर दिया हो। आंकड़ों की बाजीगरी बड़ी अजीबोगरीब है। किसानों के हित के लिए और किसानों के कल्याण के लिए योजना चालू की गई, कृषि बीमा योजना से लेकर बहुत सारी बातें की गईं। माननीय कृषि मंत्री जी आपके ही विभाग का आकलन है कि देश में कृषि बीमा के लिए तकरीबन कम से कम देश 18,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है लेकिन आपने मात्र 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फीसदी किसानों का बीमा करेंगे और किन्हें छोड़ेंगे? आपने कहा है कि अगले पांच सालों में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। हम भी किसान के बेटे हैं। हमारे पिता जी भी किसान हैं। मंत्री जी, आप बाद में जवाब दे दीजिएगा।

माननीय सभापति : स्टेट के बारे में क्लेरिफाई करना चाहते हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदय, पहले की सरकार का सवाल है, बजट एलोकेशन जो भी होता हो, जितना किसान बीमा करता था उसका भुगतान कराता था यह ऑन डिमांड होगा। यह एक सामान्य प्रावधान है। देश में जितने किसान बीमा कराए इस अभियान में लगे हुए हैं कि अभी तक 20% किसान बीमा कराते हैं, हमारा अभियान है कि 100% किसान बीमा कराए। राज्य के खजाने में इसके लिए कमी नहीं है और राज्य की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी।

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति महोदय, आप भारत सरकार के मंत्री हैं हम आपकी बात को काटना नहीं चाहते। यही बात एक साल पहले अप्रैल-मई में जब ओले पड़े थे उस समय भी तमाम बातें हुई थीं। उत्तर प्रदेश ने उस समय साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन आपने मात्र 2800 करोड़ रुपये दिया था। मंत्री जी इस बात को स्वीकार कीजिए। आपने कहा कि अगले पांच सालों में किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देंगे। मुझे माननीय मंत्री जी बता दीजिए, मैं भी किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं, बिना समर्थन मूल्य बढ़ाए यह कैसे होगा? जब फसलों की लागत से ज्यादा समर्थन मूल्य नहीं देंगे तो आपके पास कौन

सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। इस बात का जवाब माननीय कृषि मंत्री जी या माननीय वित्त मंत्री जी जो भी जवाब देना चाहें, दें। कृषि विभाग के बजट को भी बढ़ाने की बात की गई है। मैं आपके आंकड़ों की बाजीगरी से पूरी तरह असहमत हूं। आपने कृषि विभाग का बजट 35, 000 करोड़ रुपये दिखाया है जिसमें 15,100 करोड़ क्रेडिट का बजट है जो कि पहले के जितने भी बजट पेश हुए उन बजटों में वित्तीय संस्थाओं को पैसा जाता था कृषि मंत्रालय के बजट में इसको शामिल नहीं किया गया था। उसे बढ़ाकर आप आंकडों की जादूगरी करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक किसानों के समर्थन मूल्य का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह आपका तीसरा बजट है। आप अपने कार्यकाल में दो बजट और पेश करेंगे। आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों का समर्थन मूल्य डेढ़ गुना करेंगे। अब यह कैसे करेंगे, इसका हम जवाब आपसे जरूर चाहते हैं।

आपने कृषि सिंचाई योजना की बहुत तारीफ की। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के जितने भी वक्ता बोलें, उन्होंने इस बारे में कहा। आपने इसमें 5717 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मैं इस सदन में फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग का बजट 12,800 करोड़ रुपये का है, जबकि यह योजना पूरे देश के लिए है। ...(व्यवधान) हमने चार साल जो किया, वह प्रदेश की जनता के सामने है। ...(व्यवधान) हम एक-एक करके बात करेंगे। ...(व्यवधान) केवल 5717 करोड़ रुपये देकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे पूरा परिवर्तन आ गया। यहां बुन्देलखंड के बारे में तमाम साथियों ने चर्चा की। आप बता दीजिए कि क्या बुन्देलखंड की सूखे की समस्या में 5717 करोड़ रुपये से कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है? क्या माननीय मंत्री जी आपको इस बात का अंदाजा नहीं है? क्या आपके पास जीपीआर से लेकर तमाम योजनाएं नहीं जातीं? आपको इस बात का अहसास होना चाहिए।

सभापति महोदय, हम वीकर सैक्शन की बात करना चाहते हैं। आपने खाद सुरक्षा में सब्सिडी घटा दी। आपने उर्वरक में सब्सिडी घटा दी। गरीबों के लिए इस तरह की जो तमाम योजनाएं थीं, उन सबमें आपने सब्सिडी घटाने का काम किया है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। इस बजट को मैं आंकड़ों की जादूगरी या आंकड़ों की बाजीगरी जरूर कह सकता हूं। जहां तक बहुत सारी योजनाओं का सवाल है, तो मैं आपसे आज गरीब लोगों की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि आप इंदिरा आवास योजना में केवल 70 हजार रुपये दे रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 70 हजार रुपये में कोई भी आवास तैयार नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोहिया आवास के नाम से 3 लाख 5 पांच हजार रुपये का प्रावधान किया है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की बराबरी आप इस चीज में कीजिए। ...(व्यवधान) गरीबों की जो सेवाए हैं ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के

बहुत सारे साथी यहां हैं। 3 लाख 5 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान) मै दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : अभी तो हमने शुरू ही किया है। आप इनता अन्याय मत कीजिए। आप इतना बड़ा बजट पास करा रहे हैं, हमें बोलने के लिए थोड़ा समय और दे दें। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister's reply is scheduled at 6 o'clock. Still we have a list of 25 Members, who want to participate. Therefore, I request you to conclude your speech.

श्री धर्मेन्द्र यादव: इसके साथ-साथ भारत सरकार पहले केन्द्रीय योजनाओं में 90 फीसदी अंश देती थी और 10 फीसदी राज्य सरकारें देती थीं। उसे आपने घटा दिया। अब 60 फीसदी केन्द्र सरकार देगी और 40 फीसदी राज्य सरकार देंगी। मैं वित्त मंत्री जी को अहसास कराना चाहता हूं कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें एक भी योजना प्रदेश सरकार अपने स्तर से पूरी नहीं कर पायेगी। जितनी चालू योजनाएं हैं, वे सभी योजनाएं पूरी तरह से ठप्प हो जायेंगी। अब इस सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम का बहुत प्रचार किया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, इस समस्या से आप भी जूझ रहे हैं और हम भी जूझ रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम के लिए आपने बजट में एक रुपये का भी प्रावधान नहीं किया, जबकि आप सांसद आदर्श ग्राम बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरे गांव की भी चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से देश के सामने तमाम ऐसी समस्याएं हैं, जो इस बजट में आनी चाहिए। अब जीएसटी बिल पास नहीं हुआ, लेकिन आपने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया। तमाम ज्वैलर्स और व्यापारियों का आंदोलन आपके सामने है। आज देश के सामने इस तरह से बहुत सारी समस्याए हैं। मैं सत्ता पक्ष के सांसदों से अपील करूंगा कि वे देश को ऐसे ख्वाब नहीं दिखाइये। एक बार पहले भी आपने शाइनिंग इंडिया कहा था, इसलिए आप उस तरह के सपने दिखाने का प्रयास मत कीजिए। उस समय का परिणाम भी आपके सामने है। यदि आप अभी भी संभल कर नहीं चलेंगे, तो आने वाले परिणाम भी आपके सामने होंगे। इसलिए एक बार फिर मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले सर्विस टैक्स हटाएं और किसान का समर्थन मूल्य डेढ़ गुना करें।

सभापति महोदय, मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जी इन चीजों पर ध्यान देंगे। अगर वे ध्यान नहीं देंगे तो देश की जनता इसका जवाब देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय सदस्य सिंचाई का अच्छा विषय लाए हैं। यह बहुत अच्छा विषय है। आपने सही कहा कि इसका बजट मात्र 5700 करोड़ रुपए है। लेकिन आप इसे पूरा देखें, इसमें लिखा है कि 20,000 करोड़ का नाबार्ड द्वारा सिंचाई के लिए कॉर्प्स फंड बनाया गया है।

इसी में आगे लिखा है कि देश के अंदर 89 बड़ी परियोजनाएं 15-20 साल से लंबित हैं। इसमें से 23 परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने के लिए बजट में 12,751 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जहां तक राज्य की सहायता की बात है, एनडीआरएफ के बारे में अपने चर्चा की है, आपको स्मरण होगा कि 2009-2010 में भी पूरे देश में और यूपी में बहुत सूखा हुआ था। उस समय आपने 12,000 करोड़ रुपया मांगा था और 515 करोड़ रुपए मिले थे। हम आए हैं तो नार्म्स बदले हैं। 7,500 करोड़ रुपए मांगे थे और हमने 2,800 करोड़ रुपया दिया। आप देखिए कि कितना अंतर है। 2015-2016 में आपने 2,057 करोड़ रुपए मांगे थे हमने 1,300 करोड़ रुपए दिए हैं। कितना बड़ा अंतर है, 12,000 करोड़ रुपए में सिर्फ 500 करोड़ रुपए यानी इस तरह से नॉर्म्स बदले हैं, ज्यादा सहायता की है।

तीसरी बात है, आपकी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है, अच्छी बात है। लेकिन हम 60 प्रतिशत शेयर देते हैं। स्वाभाविक है कि सभी राज्यों का मिला दें और यदि सभी राज्य पैसा मिलाते हैं तो भी पैसा कहां से जाता है, या तो राज्य के रिसोर्सिस से होंगे या नहीं होंगे। मैं आपके ध्यान में एक बात लाकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी होती है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी अच्छी तरह बताएंगे। केंद्रीय करों में 2013-2014 में आपके राज्य को 63,000 करोड़ रुपया मिला था। इस वर्ष 99,165 करोड़ रुपया मिला है, यह पैसा इसी काम के लिए है। राज्यों को अंशदान देने में भारी बढ़ोतरी हुई है।

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय सभापति जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON: No.

Only Shri Chandulal Sahu's speech will go on record.

… (*Interruptions*)… *

---

* Not recorded.

*__श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर):__ मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभारी हूँ, जिन्होंने देश के विकास से संबंधित 2016-17 का बजट पेश किया। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ जरूरी सुझावों को मानने के लिए अनुरोध करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने धारा 80 टी.टी.ए. के अंतर्गत छोटी आय पाने वाले लोगों के लिए ब्याज की सीमा 10,000 रूपए बरकरार रखी है। मेरा मंत्री से निवेदन है कि यह सीमा बढ़ाकर 20,000 रूपए कर दी जाये। बजट में चिकित्सा हेतु 80 डी. के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रूपए और अन्य नागरिकों के लिए 25,000 रूपए की सीमा तय की गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह सीमा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रूपए की जाये तथा आम नागरिकों के लिए यह सीमा 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रूपए तक की जाये, क्योंकि आजकल चिकित्सा पर बहुत अधिक खर्च आता है। आयकर की धारा 10 के तहत आम नागरिकों को 1800 रूपए प्रति माह यात्रा भत्ता देने की व्यवस्था की गई है, जो पहले 990 रूपये थी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यात्रा भत्ता 1,800 रूपए बहुत कम है। कृपया इसको बढ़ाकर 2,500 रूपए किया जाये।

धारा 44 एडी के तहत यदि एक करदाता की आय एक करोड़ रूपए है तो उसे अपने कारोबार का 8 प्रतिशत आयकर का भुगतान करना होगा। इसी धारा में व्यापारी के लिए यह सीमा 2 करोड़ रूपए तक कर दी गई है। माननीय, सलाहकार और वकील पेशा के लोग इस धारा से वंचित रखे गये हैं, जिससे उनको अपना लेखा-परीक्षा कराना पड़ता है और अपने खातों का पालन करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कानूनी, चिकित्सा, तकनीकी परामर्श, अभियांत्रिकी और सलाहकारों को भी इस धारा में लेकर 2 करोड़ रूपए तक केवल 8 प्रतिशत आयकर की राशि के दायरे में लाया जाए। इससे मध्यम वर्ग के नागरिकों को लाभ होगा।

---

* Speech was laid on the Table.

*SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Respected Speaker Madam,

I could not get opportunity to speak on General Budget, kindly allow me to associate with Nand Kumar Singh Chauhan. I would further like to say that this Budget is dedicated for "Rural India"ग्रामीण भारत" ।इस बजट में युवा, महिला, विशेा तौर पर किसान एवं मजदूर का ध्यान रखा गया है ।

Increase of 94% for farmer and agriculture sector from 22928 crore to 44,485 crore is the highest ever Budget of 38,500 crore for MGNREGA, 19,000 crore for PMGSY, 20,000 for National Rural Health Mission, 97,000 crore for roads, 1,02,000 crore for rail network. New opportunities for employment and entrepreneurs. Start up India and Stand up India are good examples of this.

One Rank One Pension for ex-serviceman is a welcome step which was pending for the last three decades. We could see positive response from all corners and everyone appreciated the General Budget.

* Speech was laid on the Table.

HON. CHAIRPERSON : Shri Chandulal Sahu.

श्री चंदूलाल साहू (महासमन्द) : माननीय सभापति जी, यह बजट सर्वश्रेष्ठ बजट है। यह बजट इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह किसानों, गांवों और गरीबों के लिए बनाया गया है। इस बजट में कृषि कल्याण के लिए अच्छी व्यवस्था करके सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है। इस योजना के लिए सरकार की तरफ 38,984 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों के बारे में कहा जाता है कि किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में पलता है और ऋण में मर जाता है। इस समस्या को दूर करने, किसानों को सहूलियत देने और किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि सिंचाई योजना स्वागत योग्य है। मेरे गरियाबंद जिले में बहुत सिंचाई योजनाएं जो लंबित हैं, वे सब इस योजना में पूर्ण हो जाएंगी और किसान खुशहाल होगा। इस बजट में प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। यह सब किसानों के लिए राहत देने वाला बजट है।

किसानों के संबंध में यह कहा जाता है कि वास्तव में किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता। इस भ्रम को तोड़कर इस बजट में किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे दुकानदार और व्यवसायी हैं, वे साहूकार और महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं। उनसे निजात पाने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा बैंक योजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, जो अपने हिसाब से उनसे कर्जा लेकर एक अच्छा व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। इस हिसाब से लगभग 5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसलिए बजट का प्रावधान किया गया है।

फसल बीमा योजना जो अभी तक किसानों के लिए लागू की जाती थी। किसान जो लोन लेते थे, उनका बीमा होता था, लेकिन बीमा राशि प्राप्त नहीं होती थी। इस बजट में जो खरीफ और रबी की फसल है, उसके लिए डेढ़ प्रतिशत और दो प्रतिशत की व्यवस्था करके जो 20 प्रतिशत लोगों का बीमा होता था, उसे सौ प्रतिशत किया गया है। निश्चित रूप से इससे किसानों की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा। किसान जब अच्छा उत्पादन करेंगे, तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

इसके साथ साथ जो गरीब बैंक के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रधान मंत्री जन धन योजना लागू करके, निशुल्क ज़ीरो में जो खाता खुलवाने की व्यवस्था की गई है, इससे लोगों में एक जागरूकता आई है। लोगों का बैंक के प्रति विश्वास बढ़ा है। बैंक से संबंध जुड़े हैं और इस प्रकार से प्रधान मंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत खाता खुलवाकर जो अतिरिक्त पैसा बचता है, उसमें जमा करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ किसानों के लिए सॉयल हैल्थ कार्ड की व्यवस्था की गई है। किसान परम्परागत खेती करते हैं। जो खाद पड़ौस में किसान डालते हैं, उसको देखकर उतनी खाद वे डाल देते हैं जबकि

उनको यह नहीं मालूम कि मेरी भूमि की उर्वरक क्षमता क्या है? मेरी भूमि में कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालनी चाहिए। यह अभी तक उनको नहीं मालूम था लेकिन यह इस कार्ड के माध्यम से हर किसान को पता चलेगा कि उसे कितनी खाद डालनी है। इसलिए इस कार्ड की योजना से किसानों को बहुत फायदा होगा।

इसके साथ साथ लोगों से मैं चर्चा करता था कि बजट में क्या जोड़ा जाए तो लोग कहते थे कि जिस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में शासन से पैसा दिया जाता है, गांवों के विकास के लिए रेल भवन के लिए पैसा दिया जाता है लेकिन जो महात्मा गांधी जी की भावना थी कि ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त किया जाए, उनको भी एक वित्तीय पॉवर दी जाए। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपये देकर एक व्यवस्था दी गई है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और गांव के मुखिया के बीच में बैठकर गांवों की जो मूलभूत समस्या और आवश्यकता है, उसका समाधान कर सकें।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र से संबंधित भी कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा।

माननीय सभापति : एक मिनट में अपने क्षेत्र के बारे में बताकर अपनी बात को समाप्त करिए।

श्री चंदूलाल साहू : सर, मेरे क्षेत्र में सिंचाई की बहुत सारी लम्बित व्यवस्था है जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण लम्बित है। महासमुद्र के जो 12 बांध लम्बित हैं, उनको पूर्ण कराया जाए। इसके साथ साथ केन्द्र सरकार संचालित जो केन्द्रीय विद्यालय हैं, उस विद्यालय में अनुशंसा के लिए बहुत से परिवार हमारे पास आते हैं। मैं चाहता हूं कि शासन की तरफ से जो पैसा राज्य सरकार को दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा जो संचालित स्कूल हैं, उन स्कूलों की व्यवस्था भी अच्छे से की जाएं और उसमें यातायात के जो नियम हैं, उन नियमों को भी पढ़ाया जाए क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को यातायात के नियम नहीं मालूम होने के कारण ही दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए इसको भी सम्मिलित किया जाए ताकि लोग शुरु से ही जान जाएं कि यातायात में हमें किस प्रकार से सावधानी बरतनी है। धन्यवाद।

*__श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)__: माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2016-17 का बजट 29 फरवरी को सदन में प्रस्तुत किया गया और हर साल की भांति इस साल भी बजट पर लोगों ने अपनी-अपनी राय दी है और हमें इस बात का भी पता है कि हर इंसान को बजट को लेकर एक खास उम्मीद होती है। सरकार द्वारा जनता को क्या-क्या और किस तरह की राहत मिलेगी और टैक्स का नया स्लैब क्या होगा, जनता इन सब बातों के लिए बजट को ध्यानपूर्वक सुना करती है।

मैं जानता हूँ कि सरकार की कोशिश होती है कि बजट से जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, लेकिन इसके बावजूद सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और यह बजट कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लाई गई योजना है और इसके माध्यम से गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है और सरकार ने इस बजट में इस योजना के लिए 19 हज़ार करोड़ रूपए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या यह आवंटन वित्त वर्ष 2016-17 के लिए पर्याप्त है क्योंकि अभी भी ठेकेदारों का पिछला बकाया शेष है और देश के बहुत से गॉवों को इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ने का काम भी करना है। अतः इस योजना के लिए और अधिक निधि दिए जाने की जरूरत है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है लेकिन भारतीय किसान कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण आत्महत्या कर लेता है और सरकार ने इसे रोकने और किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए बजट में 1500 करोड़ रूपए का आवंटन किया है। यह सरकार का किसान हितैषी होना दर्शाता है और इसी के मद्देनज़र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रूपए का आवंटन भी इस बजट में किया है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इन किसान कल्याणकारी कदमों से देश का किसान तरक्की करेगा और समृद्ध होगा।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑरेगेनिक चेन फार्मिंग के लिए 400 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है और पांच लाख एकड़ भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करने का निर्णय लिया है जो कि सरकार का सराहनीय कदम है और इसके साथ ही साथ किसानों व कृषि की योजना को लागू करने के लिए नाबार्ड के साथ 20 हज़ार करोड़ रूपए का बजट दिया गया है और सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का है, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

---

* Speech was laid on the Table.

भारत गॉवों का देश है और आज भी हमारी जड़ें गॉव से जुड़ी हैं लेकिन इन गॉवों तक बिजली पहुॅचाना हमारी सरकार का लक्ष्य है हमारी सरकार ने अब तक कुल 5553 गॉवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 2.7 लाख करोड़ की धनराशि गांवों और नगर निगम को इन क्षेत्रों को विद्युतीकरण करने हेतु दिये जाने का प्रावधान इस बजट में दिया गया है, मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूॅं।

सरकार ने स्किल इंडिया के लिए 17 करोड़ रूपए और राजमार्गों के लिए 55000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है जोकि विकास और रोज़गार दोनों प्रदान करेगा।

अगर टैक्स की बात की जाये तो मिडिल क्लास के लिए यह बजट उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है जितना मध्यम वर्ग का व्यक्ति उम्मीद कर रहा था। क्योंकि सरकार ने सर्विस टैक्स बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है और इससे जनता की जेब पर बुरा असर पड़ने वाला है। अतः सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

हर साल सरकार बीड़ी, सिगरेट, सिगार, गुटखा पर टैक्स बढ़ा देती है जबकि यह चीजे मनुष्य के जीवन के लिए कोई जरूरी नहीं है और सरकार जो भी टैक्स इन चीज़ों से लेती है, उसी टैक्स के पैसे से जनता को इन सब चीजों से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करती है और मेरा यह मानना है कि इन सब चीज़ों पर टैक्स लगाने या बढ़ाने के बजाय, सरकार को इन चीज़ों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

देश की जनता को लग रहा था कि इस समय सरकार द्वारा जनता को इनकम टैक्स की सीमा में छूट की सीमा बढ़ा दी जायेगी ताकि आम आदमी अपने ऊपर कुछ और खर्च कर सके, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और जनता को टैक्स सीमा में छूट न देकर जस का तस रखा गया है। मेरा सरकार को सुझाव है कि इनकम टैक्स में यह छूट की सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रूपए तक करनी चाहिए ताकि नौकरी पेशा लोगों को राहत मिल सके।

अतः मैं अंत में यही कहना चाहूॅंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अनेक उपायों और योजनाओं के लिए निधि आवंटित कर एक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है लेकिन अगर इनकम टैक्स सीमा में छूट को बढ़ा दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम होता।

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I would like to present an objective examination of the Union Budget 2016-17 - my submission shall be structured in the following manner: first, I'd like to underline the general intent any Government Budget should be based on; second, I will outline the backdrop against which the Budget was presented; lastly, and most importantly, I'll like to analyze whether the Government has been able to constructively address the challenges facing the economy (the 'backdrop' performance, if I may) while substantially conveying policy intent with clarity (the 'general intent' problem, so to say),

What a Government Budget should convey assumes specific significance with regard to India: while technically, any Budget is supposed to be a document simply presenting receipts and expenditure forecasts, India's Budget presentation has largely been a policy note of the incumbent Government of India, meant to trace out its intended policy measures to push India towards a higher growth trajectory ("What even is growth?" is something I shall arrive at later) -given that the Government has virtually inherited this convention and has made no visible attempts at challenging it, this Budget should therefore be rightly analyzed as a policy document, and not just as an accounting presentation (like many other countries' budgets). I now come to the general guidelines the Budget should be framed on: while this framework in relation to guidelines (in its entirety) is often backdrop-dependent, there are certain uniform goals our Budget should work towards -1. Reducing poverty in a time-bound manner, 2. Improving the ease of doing business to create jobs, and 3. Making consistent strides towards equality in opportunity, both economically and socially. These objectives are interlinked, and the Budget 2016-17, an opportunity for the Government to showcase its vision in relation to achieving the India our forefathers had dreamt of, is clearly a missed opportunity.

* Speech was laid on the Table.

I now turn to the backdrop against which the Budget was presented: owing to two deficient monsoons and falling commodity prices, Indian agricultural growth has stagnated (in negative territory in 2014-15 and 1.1% in 2015-16); weak global demand (owing significantly to China's slowdown, which presents an opportunity to India to gain investors' attention) has resulted in India's export's falling consistently for the past 11 months, a devastatingly disappointing performance by India's standard; and widespread accusations in relation to social injustice being perpetrated by the present dispensation (followed by well-meaning statements by the Chief Economic Adviser and the Governor of the RBI, hinting at strong positive correlations between 'tolerance' and economic development); the question, therefore, to ask is: "How has the Budget delivered on these front? The answer, disappointingly, is that the Government has failed on all, and my third phase of the submission shall elaborate on why I believe so.

The credibility of the promises made by the Budget, firstly, is undermined by certain performance indicators in relation to 2015-16 Budget: Revised Estimates (RE) (Capital Expenditure) for 2015-16 is lower than the Budget Estimates (BE) 2015-16 by 3.9% - all schools of thought in Economics converge on one agreement for sure: capital expenditure, by increasing capacity, fuels long-term economic growth and is essential to keep a nation on a fast-paced growth trajectory. Bu underperforming on this respect, the Government has clearly sent worrying signals, both in India and abroad. While the Government's move to increase its 2016-17 BE for Capital Expenditure over the 2015-16 RE by 3.9% is welcome, the devil lies in delivery, and I earnestly hope the Government meets the all-important Capital Expenditure target for 2016-17.

While it is commendable that the Government stuck to the fiscal roadmap in 2015-16 at (3.9%) and has a BE for 2016-17 at an even lower 3.5%, this analysis lies on overoptimistic revenue targets from one-time sources (like disinvestment, where the Government failed miserably in 2015-16) and not through sustainable revenue-generating avenues.

We now turn to allocation for the backbone of the Indian economy, agriculture: funds allocated for the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare (DoA) have been raised from the revised estimate (RE) of Rs. 15,809 crore in 2015-16 to a budgeted estimate (BE) of Rs. 35,983 crore for Financial Year 17, a significant increase of 127%. However, it is extremely important to note that much of the increase (Rs. 15,000 crore) is due to interest subsidy on short-term credit, which was Rs. 13,000 crore earlier and was shown under the Department of Financial Services. Adjusting for that, the nominal increase in allocation to farmers is just 33%.

In relation to women and child development, where spending fell by Rs. 1,188 crore in 2015-16 relative to 2014-15, the budgeted increase in spending in 2016-17 is just Rs. 56.23 crore. As a result, spending on the all-too-important Integrated Child Development Services, which fell from Rs. 16,415 crore in 2014-15 to Rs. 13,636 crore in 2015-16, is now budgeted to receive only Rs. 15,873 crore.

Strikingly, 100% Women-Specific Programmes saw a significant downward revision (Rs. 11,388.41 crore against Rs. 16,657.11 crore) (RE vs BE 2015-16) - 46% lower.

The Government's stance on education is very worrying: While there been a slight increase in the allocation in absolute terms, the budgetary allocation for education has declined, both as a percentage of GDP and as a percentage of the total Budget. It was 0.5% of GDP and 3.8% of the revenue expenditure for 2015-16, and it is down to 0.48% of GDP and 3.7% of the Budget Estimates this year.

That the allocation for the infrastructure-intensive Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has gone up from Rs. 15,187 crore in 2015-16 to Rs. 19,000 crore in 2016-17 is a positive move and shall definitely contribute to the upliftment of village economies by providing connectivity to rural areas and generating jobs.

The budget promises to raise farmers' incomes by 15% a year. Even if output increase by 3% a year (highly ambitious target, that too), agricultural prices

will have to rise by 12% a year. That figure signals worse inflation than India has seen in five decades. And if all prices proportionately increase, what will the farmers get out of the price increase in farm produce?

The Government missed its Income Tax Collection target for 2015-16 (9.4% lower) and relied on indirect taxation to ramp up tax collection. As we all know, indirect taxes are regressive: the poor is hurt more, and despite stark differences in their abilities to pay taxes, the poor and the rich are taxed at the same rates.

After the backlash, the Government ultimately announced the withdrawal of the Budget proposal on taxing the Employees Provident Fund. The drastic proposal had sought to make up to 60% of savers' corpus withdrawn from the EPF tax-free if invested in annuity (automatically implying that the remaining 40% is taxable). The period return on the annuity was also to be taxable. I firmly believe that employees should have the choice of where to invest, and that the objective of encouraging people to join the pension scheme could well be achieved through other means, and it's extremely important that the Government henceforth hold wide consultations and arrive at decisions (with wide ramification) through consensus-building.

While the Budget moves in the correct direction in relation to our rural economy, the thrust is definitely not enough: setting unachievable targets (like increasing farmers' incomes by 100% in 5 years) for short-term gains does not bode well for budget-making as a process, and more importantly, for the spirit of democracy; ramping up indirect taxation and hurting the middle class is as regressive a step as imaginable and betrays the mandate the people of India provided the Government with. With no clarity in relation to the long-term policy objectives of the Government and clear roadmaps for achieving proposed solutions to India's economic social woes, the Union Budget 2016-17 clearly leaves a lot to be desired.

*SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): The Finance Minister presented the General Budget in the House for the Financial Year 2016-17, which seems promising a lot for the rural sectors, including the agriculture and rural infrastructure. However, the truth is somewhat different while looking at the budget papers. It was expected that the current budget would have provisioned more for the rural sector, at least to give a boost to the farming sector which was badly hit by the drought last year, where almost half of the country was under severe drought. While looking at the growth performance of the agricultural sector, which constitutes mainstay of livelihood for majority of our population, has declined sharply from 4.2% in 2013-14 to -0.2 % in 2014-15. Following two consecutive drought years in 2013-14 and 2014-15, output of a number of crops such as rice, wheat, oilseeds, cotton, pulses and groundnut has fallen in 2014-15 compared to the previous year.

It has been found that overall increase of the Union Government budget from Rs. 17.85 lakh crore in 2015-16 RE to Rs. 19.78 lakh crore for the next financial year. However, the overall magnitude of the Union Budget shows a marginal decline from 13.2% of GDP in 2015-16 RE to 13.1% of GDP in 2016-17 BE. In absolute numbers, the total size of the Union Budget is projected to an increase of Rs. 2 lakh crore. But, out of this increased outlay, almost two-third would be in areas of Non-plan spending (particularly on account of higher interest payments, pensions and defence spending) while one third of it would be in Plan spending (including the social sectors and infrastructure sectors). Similarly, the gross central tax to GDP ratio is projected to be 10.8%, which is at the same level as that of current year's revised estimate. This indicates, there is no such increase in tax-GDP ratio in one hand and the target of Fiscal Deficit to GDP pegged at 3.5%, which shows the fiscal conservatism of the Government not to spend more.

* Speech was laid on the Table.

Further, in the wake of significant changes in the country's federal fiscal architecture, where the claims of the Union Government that it has shared huge amount of resources, following the Fourteenth Finance Commission recommendation , with the State Governments doesn't reflect the case. As one would have remembered, following the restructuring of plan financing (there is reduced central assistance to states in the major plan schemes), which equalizes the higher devolution of resources received by the States from the Finance Commission recommendations. Due to changes in the country's fiscal architecture, 2015-16 has been the year of uncertainty about the fund sharing pattern in Centrally Sponsored Schemes (CSS). The NITI Aayog Committee of Chief Ministers has finally resolved some of these debates by recommending a 60:40 fund sharing pattern between the Union Government and the States for most of the prominent social sector schemes like, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal, National Health Mission, Integrated Child Development Services and Swachh Bharat Abhiyan, among others. The greater degree of autonomy of flexibility now available to the States (in terms of setting their expenditure priorities), combined with the reduction in the funding share of the Union Government in a host of CSS, implies that the priorities in the State Budgets would have stronger role now in determining the overall allocation of budgetary resources in a range of development sector in the country.

However, the Union Government needs to take note of the existing social and regional disparities along the internal security problems in the country. The Union Budget 2016-17 could have played a crucial role in addressing these disparities by allocating more resources in areas and for the sections of population that are lagging behind, particularly poorer states of the country, including Odisha for better coordination of socio-economic development of the nation.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Mr. Chairman, Sir, I do not want to take much of your valuable time because the Chair had already informed all of us to complete our speech within five minutes. I am waiting since morning. I do not want to say anything beyond the time allotted to me and I should complete by mentioning only 2-3 things to the hon. Finance Minister.

More than one thousand people have committed suicide in Karnataka. I do not want to quote the numbers in the other States. What is the remedy that you are going to give to them? This is all that I want to know. In future, what are all the programmes that you have announced? There are 38 programmes, and I do not want to debate on all these issues. More than one thousand people have committed suicide. Our hon. Prime Minister came to Belagavi to address the farmers. I do not think that he has mentioned anything about the farmers who have committed suicide. You were also there.

Drinking water is a major problem. I am not going to say that this Government alone has taken steps to provide drinking water. In the last 65 years, whoever was in office, have they have not done anything? We should not unnecessarily criticize each other. They have also done something. I can quote several instances. When was the Bhakra-Nangal Dam constructed? Are we still able to complete the Indira Gandhi Canal? The Accelerated Irrigation Programme was initiated by me in 1996. A copy of the speech is here, but I do not want to say that we have done it. The circumstances forced us to take such decisions. So many major and minor irrigation projects were pending. That is why we had taken the decision, not for the sake of one State or the other. Let me be plain about it. I do not want to cross the limits.

Sugarcane growers are now in a bad situation. More than 110 sugarcane growers have committed suicide in Mandya, which is one of the major sugar producing areas. Unfortunately, the sugarcane growers numbering more than 110 have committed suicide. In the whole State, in every district, they are committing

suicide even today. After the announcement of all these programmes, I do not know how best the Union Government will come to their rescue.

On the recovery of loans by the banks, on NPAs, so much debate has taken place; the name of one gentleman from my Home State was also taken. However, you have clarified something yesterday and I welcome it. At least, the Government of India is taking some steps in that direction. A farmer who takes a loan of Rs. 50,000, Rs. 60,000, Rs. 70,000, Rs. 80,000 or even up to one lakh rupees from the banks are the ones who are committing suicides. How many of them have been covered by the Scheduled Banks or the Cooperative Banks? Their number is not more than 30 per cent; and the remaining 70 per cent is dependent on the moneylenders. I welcome the announcement of Mudra Bank. But will we be able to cover all the farmers to the extent of 100 per cent? Let us discuss this. We are all coming from the farming community, including you and myself. I am not going to claim that I am the champion of the farmers' causes. I am not going to say that. All of us are equally interested in them.

Today morning Shri Rahul Gandhi raised the farmers' issue through an Adjournment Motion and the hon. Speaker has given the ruling that it can be taken up in some other form. The point is that the entire House is concerned about the farming community because basically we are farmers. This country cannot give a go-by to the farming sector, whatever may be your approach to make India a powerful country in the whole world. Even today, more than 58 per cent of the population is dependent on the farming sector, whatever may be the development over all these years.

Sir, the Commerce Minister is sitting here. You have not put any taxes on beedi, but you have put heavy taxes on cigarettes. Our people are growing tobacco, whether it is in Belgaum, Mysore or Hassan. Why do you put such restrictions? Is cancer being caused by smoking only? Those people who are not smoking, are they not suffering from cancer? It is all right if you want to ban it, but think of an alternative crop and provide them an alternative avenue for their

livelihood. If the Government wants to take some steps, you should think about the alternatives for them. When this matter came up some five years back, you have abolished *Ganja*. Similarly, tobacco can be abolished and that is all right. If you take that example as a model scheme, you must think of some alternatives. Madam, who is in-charge of the Commerce Ministry, is sitting here. If you take Silk, for example, you have put 30 per cent tax on the import of Silk, just to curb the Silk coming from China. Our sericulture farmers today are committing suicide in Ramnagar, Kolar and so on. We are all coming from farming community. We are actually suffering. People are criticising us as to why MPs from Karnataka have no voice. I am not taking any sides here. All of us are equally interested.

He has said that the hon. Prime Minister has now announced a programme of insurance. Potatoes grown in more than 15,000 hectares have been completely destroyed. I tried my best to change the seeds. Our people are dependent only on Punjab. We wanted to change the potato seeds. We want to get it from Holland. The seed from Holland is the best one. When Shri Sharad Pawar was the Agriculture Minister, he had said that there was a powerful lobby. We tried our best. I was there as the Prime Minister hardly for ten months. What were the schemes that we had provided? You are now thinking that you can directly give funds to the farmers.

I just would like to take two minutes to mention as to how much benefit we had given to the farmers at that time. I took oath as the Prime Minister on 1st June. The Budget was presented to this House on 19th July, 1996. The Vote of Confidence was on 11th June. I took a decision on 15th June to reduce the rate of Dianium phosphate and phosphatic fertilizers. It was an additional burden of Rs.2,800 crore. The Finance Ministry had put a lot of objections by saying that unless the provision is made in the Budget and approved by the Parliament, it could not be done. I overruled all these things. For sprinkler irrigation and drip irrigation, we had provided subsidy to the extent of 90 per cent to the women cultivators. I can send the Budget copy. We had given the subsidy to the extent of

50 per cent on tractors and power tillers. The growth of agriculture had risen during that year. One can go through the Report of the *Economic Survey* of the next year. It was 9.6 per cent. One can go to the Library and read the Report of the *Economic Survey*.

He has talked about completing the 26 projects. In my humble opinion, I feel that it is practically impossible. Even in the case of Narmada Dam, they have not utilised the water completely. The World Bank was insisting and because of Shrimati Medha Patkar, the project was stopped. I took some decision to increase the height of the Dam. Even today it has not been completed. I can quote several instances as to what we had done during the short span of time. The Tehri Dam project was stopped. We had overruled all the objections raised by the local leaders. Shri Sunder Lal Bahuguna had sat on *dharna* and hunger strike for one month. We tried to persuade him. We have completed that project.

You are not neglecting the farmers. I am not going to say that you are. But you have to take certain steps. Thirty-eight programmes were announced. But the basic issue is, what exactly is the reason that farmers are committing suicide? Are we in a position to provide funds for agricultural sector at the time when farmers want to sow the seeds? Timely money availability is not there. As regards fertilisers, you wanted to see that usage of chemical fertilisers is reduced. I agree with you.

HON. CHAIRPERSON : Devegowdaji, please conclude.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He knows what to say. You need not intervene. It is between the Chair and him. You please sit down.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, you are also fighting, you came with us to meet Madam. I am not going to say you have neglected. There is no need of taking credit by anybody. Let all the 28 Members, this side or that side, take the credit.

Do something to save the farmers from this crisis. No farmer is a willful defaulter in my humble opinion. I will give you a small example. When I was the

Prime Minister I asked Late Kurien, gave Rs.100 crore, to start a milk society by women in Karnataka. Today there are 4,000 milk societies. No milk society organized by women is a defaulter. You have to find out ways and means to provide jobs in the local area itself.

Yes, you want to create jobs. What type of jobs? Jobs in service sector, all are being outsourced. Go to the airport. In State Governments today, Class IV employees are being outsourced for Rs.8000. You have accepted the 7th Pay Commission Report. The Principal Secretary or the Cabinet Secretary who was getting Rs.1 lakh earlier is going to get Rs.2.9 lakh now. What is the fate of the Class IV employees? They are being paid Rs.8,000. What is the cost of living? We are all human beings. Prime Minister's dream is that poverty must be removed irrespective of caste or creed. Can we achieve that? We can speak volumes on these issues.

As regards voluntary disclosure scheme, we also introduced this scheme because we had no money at that time. Now at least the Prime Minister has gone almost all over the world and tried to persuade them to invest in India. Japan is coming forward to invest in the so-called railways. I do not want to speak about that. The point is to generate money within India itself. Only one issue made me take that decision. Mr. Wolfensohn, World Bank President, came to India. He raised an objection that we were diverting the money lent by World Bank deviating from their conditions. At that time there was a controversy between him and myself. I said, you cannot. We are going to fix the priority. Whatever conditions the previous Government agreed to, I would not agree. Then he said we cannot get any funds. Then I told Chidambaram to introduce the Voluntary Disclosure Scheme. We got Rs.36,000 crore black money and the revenue was Rs.10,800 crore.

Now, you are going to apply the same thing. I would caution you only one thing. The Prevention of Corruption Act is also going to bring within its purview the benami transaction. You have brought it under the Voluntary Disclosure

Scheme also. Please clarify that position to the House when you are going to reply.

Hon. Chairperson, now I conclude because there are so many speakers. I thank the entire House for having allowed me to speak a little more than what the Hon. Chairperson had permitted me. Thank you.

*श्री राजीव सातव (हिंगोली) : 2014 के चुनाव की गर्मियों में कुछ नारे चला करते थेः

- ''बहुत हुयी देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार''
- ''मिलकर करें सपने साकार, अब की बार मोदी सरकार''
- ''बहुत हुआ रोज़गार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार''
- ''बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की मार मोदी सरकार''

अब जब 2016 की गर्मियां आ गयी हैं, तब मोदी जी भी सोचते होंगे कि आज अगर वही जुमले बनते तो कैसे होतेः

- देश में महंगाई 17 महीने के स्तर को पार, क्या करें मोदी सरकार?
- कृषि विकास दर 4 प्रतिशत से चली गयी शून्य के उस पार, कैसे होगा किसान का उद्धार?
- नौकरियों का कोई माप करती नहीं सरकार, फिर कैसे पता कितनों को हैं रोज़गार का इंतजार?
- इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेगेटिव में चला गया है यार, क्या करें मोदी सरकार?
- निर्यात 315 डॉलर बिलियन से घटकर रह गया सिर्फ 227.7 डॉलर बिलियन यार, पर आखिर कर क्या सकती है मोदी सरकार?
- मैन्युफैक्चरिंग नहीं जा रही 17 प्रतिशत जी.डी.पी. के पार, मेक इन इंडिया से कैसे होगा व्यापार?
- डॉलर जायेगा 70 रूपया के पार, न फरक पड़ता यह है मोदी सरकार?

गौर करने की बात है कि मोदी जी चुनाव के दौरान डबल डिजिट विकास की बात करते थे, अरूण जेटली जी पिछले वर्ष तक 8.5 प्रतिशत की बात करते थे, और अब अरविंद सुब्रामनियम जी इकोनोमिक सर्वे में 7 प्रतिशत विकास दर की बात करते हैं। 20 मास में अनुमानित विकास दर डबल डिजिट से 7 प्रतिशत तक आ गयी है, यह भी तब जब कच्चा तेल कई दशकों के निचले स्तर पर है।

सभी बड़े मंत्रालयों में से एक ही जिसका आवंटन पिछले साल के मुकाबले घटा है, वह है- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण।

5.5-6 प्रतिशत महंगाई दर सुनकर लगता है कि ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं है, परंतु अगर आप किसी भी अर्थशास्त्री से बात करें तो वही यही चिंता व्यक्त करेगा कि जिस समय दुनिया 0-0.5 प्रतिशत महंगाई दर पर चल रही है, अगर तब आपकी 5.7 प्रतिशत महंगाई दर है और आगे 6 प्रतिशत पार करने के संकेत हैं तो अच्छे दिन कदापि नहीं है।

* Speech was laid on the Table.

आज जो आवश्यक वस्तुओं के दाम हैं, उसे देखकर पता चलता है कि यह सरकार इस वादे में पूरी तरह से विफल रही है। जो किसान गॉंव में खेती करके फसल उगाता है, उस किसान के लिए इस देश में महंगाई का स्तर सबसे ज्यादा है।

दालों के दाम एक साल में इतना तीव्रता से आगे बढे हैं, जितना पिछले 10 साल में नहीं बढ़े हैं। इस देश के गरीब इंसान के प्रॉटीन पोषण का निरपवाद स्रोत दालें होती हैं। आप बाज़ार में जाकर कोई भी दाल 200-220/कि.ग्रा. में लाकर दिखा दें, तो काफी बड़ी बात होगी। इतनी महंगाई के बावजूद सरकार सो रही है। इसे देखकर ये प्रचण उठता है कि क्या सरकार कुछ बड़े जमावट करने वालों की मदद रही है? आजकल सोशल मीडिया पर ये व्यंग है कि चिकन और फिश दाल से सस्ती है, इस पर रोये या हँसे, समझ नहीं आता।

मोदी जी ने मन की बात में 28 फरवरी को कहा था कि बजट उनका इम्तेहान है, पर लगता है कि मोदी जी और उनकी सरकार को एक्जाम के आखिरी पांच मिनट में बहुत सारे जवाब लिखने की आदत है। पिछले साल की आधी घोषणाओं पर अमल बजट के 2 दिन पहले की कैबिनेट मीटिंग में होता है और कुछ घोषणाएं पिछले साल की ऐसी भी थी, जिनमें इस साल ''वर्क इन प्रोग्रेस'' में ही रह गयी हैं- मोदी जी ने पिछले साल के एक्जाम में कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया ही नहीं।

मोदी जी अपने हर भाषण में भारत के डेमोक्रेटिक डिवीडेंड की बात करते हैं। भारत में 65 प्रतिशत आबादी 35 से कम आयु की है, इसकी बात करते है। पर क्या वे उनके लिए रोज़गार उपलब्ध करवा पा रहे हैं? मोदी और भाजपा ने कहा था कि अगर वह सत्ता में आयेंगे तो 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरियां उत्पन्न करेंगे... क्या हुआ उस वादे का? सरकार को सबसे पहले नौकरियों की संख्या वैसे ही पारदर्शी और सार्वजनिक करनी चाहिए जैसे जनगणना या जी.डी.पी. का आंकड़ा सार्वजनिक होता है। 2016 को भारत में नौकरियों के आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं है, यह शर्म की बात है।

इस साल सरकार किसानों की स्थिति के बारे में जागी है। यह अच्छी बात है। पर मोदी सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जब कृषि विकास दर यू.पी.ए. के समय 4 प्रतिशत थी, आज 0 प्रतिशत पर आ चुकी है। पिछले वर्ष सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही 3228 आत्महत्या हो चुकी हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

पिछले 20 महीने में किसानों की समृद्धि के नाम पर मोदी सरकार ने सिर्फ कृषि मंत्रालय का नाम बदल दिया है। हमारे देश में 46 किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ये ही है किसानों की समृद्धि के काम? क्या दिल्ली में एक मंत्रालय का नाम बदल देना ही किसानों की समृद्धि का कार्य है? इस सरकार के मुताबिक किसान आत्महत्या का कारण प्रेम संबंध और नपुंसकता है। किसानों की समृद्धि के नाम पर

मोदी सरकार किसान विद्रोही भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई। ऐसा बिल जो इनके खुद के सांसद समर्थन करने को तैयार नहीं थे। चन्द उद्योगपतियों के लिए किसानों की जमीन छीनना, यही है किसानों की समद्धि?

मोदी सरकार के इस वर्ष तथा पिछले वर्षों में पिछड़े वर्गों के लिए आवंटन न तो उनकी जनसंख्या के अनुरूप होता है और न ही आवंटित राशि पूर्ण वर्ष में उपयोग की जाती है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए 1979-80 में स्पेशल कंपोनेंट प्लान (एस.सी.पी.) और ट्राइबल सब प्लान (टी.एस.पी.) का प्रावधान हुआ। उस प्रावधान हेतु आवंटन के आंकड़े देखकर मैं स्तब्ध रह गया।

2008 में जब पूरा संसार वित्तीय संकट से गुजर रहा था, तब भारत इकलौता जनतंत्र था जो 8 प्रतिशत प्लस की ग्रोथ रेट से विकास के पथ पर बढ़ रहा था। आज भाजपा अपनी पीठ थपथपाती है पर आज की तरह तब वैश्विक संकेतक विकास के अनुकूल नहीं थे। समय की विडंबना देखिए, आज जब पेट्रोल हमें सिर्फ 23 रूपए लीटर का पड़ना चाहिए, उसके लिए सरकार हमसे 60 रूपया वसूलती है।

सरकार जो कहती थी, बहुत हुई महंगाई की मार। वह सरकार 100 डॉलर अंतर्राष्ट्रीय दाम कम होने पर 10 रूपए दाम कम करती है। इससे किसको फायदा पहुॅंचाने की कोशिश है? यह गौर करने की बात है कि अगर आज क्रूड ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय दाम उतना ही होता, जितना यू.पी.ए. के समय था, तो इस देश में महंगाई का स्तर कहॉं होता, यह तो भगवान ही जानता है।

मोदी जी ने इसी सदन में कहा था (27 फरवरी 2015) ''मेरी राजनैतिक सूझबूझ कहती है, मनरेगा कभी बंद मत करो... मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता-जागता स्मारक है... यह आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा...'' आज वही ''विफलता के स्मारक'' को मोदी सरकार ने रूपए 38,500 करोड़ का आवंटन किया है।

सत्ता में आने से एक महीने पहले मोदी जी ने कहा- "on Aadhaar, neither the Team that I met nor PM could answer my Qs on security threat it can pose. There is no vision, only political gimmick" आज उनकी सरकार उस आधार के आधार पर चल रही है। आज वही सरकार आधार को संवैधानिक समर्थन देना चाहती है। यह अलग बात है कि राज्य सभा का उपमार्ग करके ऐसा बिल लाना सरकार की बुलडोज कार्यशैली का नमूना है।

मैं विनम्रता से अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूॅं। सरकार से निवेदन है कि उन पर गौर करें;

1. आज हमारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। छोटे नगर तो छोड़िए, मुंबई जैसे महानगर भी कुछ बारिश के बाद बंद हो जाता है। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वांटम लीप की सख्त जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर का चक्र रूका पड़ा है।

2. किसानों को सिर्फ गेहूँ और चावल में ही नहीं बल्कि 10-15 फसलों में एम.एस.पी. प्लस 50 प्रतिशत प्रोफिट की जरूरत है, कार्यान्वयन पर बल देने की जरूरत है।

3. पी.डी.एस. में हमारे देश में सबसे बड़े स्कैम होते हैं.. हर साल 40 प्रतिशत अनाज गायब होता है। पी.डी.एस. में हर साल चोरी बढ़ती जा रही है और गरीबों को बाज़ारों में से जरूरत का सामान खरीदना पड़ता है जबकि बीच के दलाल सब कुछ चट कर जाते हैं।

4. भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को विदेशी विनियम से बचाने की जरूरत है। तभी यह कंपनियॉं भारत की ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रख पाएंगी।

5. भारत को शीघ्र ही पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, इस पर राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार को पॉलिसी बनाने की जरूरत है।

6. भारत के मजदूर, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कानूनों की जरूरत हैं। इस पर राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार को पोलिसी बनाने की जरूरत है।

7. भूमि अधिग्रहण नहीं, बल्कि इस देश को एक फंक्शनिंग लैंड मार्केट की आवश्यकता है।

8. केंद्र सरकार को हर कार्य के लिए 'सेस' लगाने की प्रथा को रोकना पड़ेगा। सरकारी खातों में 1 लाख 40 हज़ार करोड़ रूपए बेकार पड़ा है। वह पैसा देश के विकास में क्यों कारगर नहीं है और क्यों सरकार नए सेस लगाती जा रही है? कृषि कलायन एक सेसा नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म होना चाहिए।

आज हालत यह है कि हमारा बजट का एक चौथाई हिस्सा सिर्फ ब्याज के भुगतान में ही चला जाता है। हमारे बजट का 1/5 हिस्सा हमारी रक्षा के विभिन्न माध्यमों में लग जाता है। न हम स्वास्थ्य पर और न ही शिक्षा पर वह ध्यान दे पा रहे हैं, जो हमारे देश के नागरिक हमसे उम्मीद करते हैं।

हमारे किसान, मजदूर को बाज़ार में एम.एस.पी. तक नहीं मिल पा रहा। वहीं बाज़ारों में दाम अपने चरम पर हैं। यह सब तब है जब रिकॉर्ड अनाज एफ.सी.आई. के गोदामों में सड़ रहा है।

हमारे नौज़वानों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा और हमारे ही देश के नौज़वान विदेशों में कंपनियॉं बना रहे हैं और खरीद रहे हैं। इस देश को 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने की जरूरत है, नहीं तो डेमोग्राफिक डिवीडेंड नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक डिजास्टर की तरफ हमारे अनुमान से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं।

मैं मिर्ज़ा गालिब की कुछ पंक्तियों के साथ अपना भाषण समाप्त करूँगा, प्रधानमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री कृप्या गौर करें-

तेरे वादे पर जिए हम,
तो यह झूठ जाना,
कि खुशी से मर ना जाते,
अगर ऐतबार होता।

*[*] **श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी):** इस बजट द्वारा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार समृद्ध, श्रेष्ठ, गौरवमयी भारत के निर्माण की प्रक्रिया में देश को सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया गया है, वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ी है, बल्कि हर देशवासी के मन में नयी ऊर्जा, नये उत्साह, नई स्फूर्ति का संचार हुआ है। इसके लिए मैं माननीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली जी व वित्त राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ।

मेरा पूरा विश्वास है कि सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, रोज़गार सृजन और कृषि क्षेत्र में उन्नत नया अध्याय लिखने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभएगा। सबका साथ-सबका विकास का जो आवाहन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस बजट से भारत के चहुंमुखी विकास को चार चांद लग जाएंगे। बजट में ग्रामीण भारत की चिंताओं और समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। ऐसा इतिहास में पहली बार है जब किसी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र और किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और एक तय समय-सीमा अवधि में किसानों की आय को न सिर्फ बढ़ाने बल्कि उसे दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान बजट ग्रामीण भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और यह सही भी है क्योंकि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के लिए यह जरूरी है कि हम शहरी भारत और ग्रामीण भारत के बीच की दूरियों को निरंतर कम करें, इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढॉंचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। गांवों में रोज़गार का एक बड़ा जरिया बनकर उभरे मनरेगा कार्यक्रम के लिए भी सरकार ने अच्छा खासा धन उपलब्ध कराया है और इस योजना के ग्रामीण ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा सिंचाई योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। लगातार गिर रहे भूमिगत जल के स्तर को देखते हुए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इससे न सिर्फ असिंचित खेतों को पानी मिल सकेगा, बल्कि जल का बेहतर प्रबंधन भी किया जा सकेगा, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे।

वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट में तमाम छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो दीर्घकालिक दृष्टि से बेहद अहम है। ऐसी एक योजना सभी घरो में एल.पी.जी. उपलब्ध कराने की है। इससे पर्यावरण को तो फायदा होगा, ही साथ ही, गरीब महिलाओं को ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करने से होने वाले तमाम रोगों से भी निज़ात मिलेगी। इसी तरह देश के 18,500 गांवों में 1 मई 2018 तक बिजली पहुॅंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो स्वागतयोग्य है।

---

[*] Speech was laid on the Table.

इसी तरह, रोज़गार सृजन की गति तेज करने के लिए स्टार्ट अप इंडिया पर बल दिया गया है जो एक सही कदम है, इस समय सरकार की प्राथमिकता युवाओं के लिए रोज़गार अवसरों का सृजन करना है। रोज़गार के सृजन की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है और इस कारण बजट पर युवाओं का बहुत ध्यान भी है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने निजी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नव उद्यमियों को तमाम वित्तीय सुविधाओं के साथ कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है। उम्मीद है कि सरकार की इस पहल से देश में रोज़गार सृजन में तेजी आएगी और युवाओं की अपेक्षाएँ पूरी होंगी। एस.सी./एस.टी. तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैण्ड अप इंडिया योजना बनाई गई है। इसके लिए जहां एस.सी. वर्ग के कल्याण के लिए तमाम मंत्रालयों के तहत 38,833 करोड़ रूपए रखे गए हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सरकार ने प्रस्तावित बजट में गत वर्ष 6,580 करोड़ रूपए की तुलना में इस साल 7,350 करोड़ रूपए दिये हैं। इसमें एस.सी. स्कॉलरशिप के लिए 2,791 करोड़ रूपए और एस.टी. बच्चों के लिए 1200 करोड़ व वन बंधुओं के लिए 600 करोड़ रूपए रखे गये हैं। इस बजटीय आवंटन से यह तबका किसी के यहां नौकरी करने के बजाय खुद लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने में सफल हो सकेगा। यह एक बहुत उपयोगी कोशिश इस बजट में नज़र आ रही है।

सरकार ने युवाओं को रोज़गार दिलाने के मकसद से देशभर में 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने के लिए 1700 करोड़ रूपए का प्रावधान कर इस योजना से 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ मिलेगा। जिंदगी की बदलती चाल-ढाल को देखते हुए आज हममें लगभग सभी क्षेत्रों में कुछ बदलाव की गुजाइश दिख रही है, जो समस्त दिशाओं की ओर अनुकूलता का परिणाम ही है। यही कारण है कि हम आज शहर सहित तमाम क्षेत्रों में डिजीटलाइजेशन का भी पड़ाव आता है। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाए गए है। आज हम ई-बैंकिंग, ई-टिकटिंग, ई-कॉमर्स जैसी तमाम डिजीटल सेवा का लाभ ले रहे हैं। जहां अब गांव-गांव में इंटरनेट की पहुंच को आसान बनाने के लिए ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाई जा रही है, जो कही न कही मौजूदा सरकार की डिजीटल सोच और उस ओर बढ़ाए गए आवश्यक कदम के परिणाम है। इस क्रांतिकारी बजट में ई-हॉस्पिटल भी एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के परिणाम तथा प्रभाव की गति तेज करने के लिए भारत में स्वास्थ्य संचार प्रयासों को मजबूत करने के लिए डायलिसिस के लिए एक देशव्यापी योजना शुरू की गई है। आज देश में किडनी संबंधी विकारों के बढ़ने से ऐसे लोगों की तादाद बढ़ने लगी है, जिनके लिए डायलिसिस कराना एक मजबूरी बन जाता है। इस बजट में सरकार ने देश के हर परिवार को एक लाख रूपए का हैल्थ कवर देने का फैसला किया है। परिवार में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो यह राशि 1 लाख 30 हज़ार रूपए होगी। वित्त मंत्री जी के इस कदम से बहुत से जरूरतमंदों को अपना इलाज

कराने में मदद मिलेगी। इस मद में सरकार ने 30 हज़ार करोड़ रूपए देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे देश में गरीबों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने के लिए 2016-17 में तीन हज़ार जन औषधि केंद्र खोलने व संक्रामक व असंक्रामक रोग, एड्स, टी.बी., अंधता निवारण, परिवार नियोजन और अन्य मदों के लिए भी पैसे का इंतजाम इस बजट में किया गया है। हैल्थ बजट गत वर्षों से कई बेहतर है। मुझे खुशी है कि सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से मरीज़ों का ख्याल रखा गया है। इस बजट में डायरेक्ट रूप से डायलिसिस फ्री कर दिया है, राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा का फायदा देशभर के 2.5 लाख लोगों को मिलेगा।

वित्तमंत्री जी ने अपने इस बजट में हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करके देश की इकोनोमी को रफ्तार देने की कोशिश की है। रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए मंत्री जी ने खुले दिल से खज़ाने के दरवाजे खोले हैं। दरअसल रोड हाईवे बढ़ाने से कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ-साथ रोज़गार के मौके पैदा होंगे और साथ-साथ इकोनोमी पर पोजिटिव असर पड़ेगा। सरकार ने बंद पड़े हवाई अड्डों को दोबारा चालू करने के लिए भी रकम का प्रावधान किया है। रोड ट्रांसपोर्ट सैक्टर में अटके पड़ 70 में से 65 फीसदी प्रोजेक्ट ट्रैक पर लौट आए है। इस बजट में सड़क परिवहन मंत्रालय को 45 हज़ार 500 करोड़ रूपए मुकाबले 57 हज़ार 900 करोड़ रूपए मिले हैं। इसका मुख्य कारण हमारे सड़क परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गड़करी जी की कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली का जीता-जागता उदाहरण है, इसके लिए मैं गडकरी जी को धन्यवाद देता हूँ।

2016-17 के बजट में प्रधानमंत्री जी का आर्थिक दृष्टिकोण अब और ज्यादा स्पष्ट होने लगा है। दरअसल यह भारत की तस्वीर बदलने के लिए युवा भारत को सशक्त करने वाला बजट है। यह बजट इस मान्यता को आगे बढ़ाता है कि युवा व उद्यमी, अर्थव्यवस्था और देश की तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे निवेश और नौकरियों के लिए केवल कुछ बड़े कारपोरेट समूहों पर निर्भरता के परंपरागत आर्थिक मॉडल का विकल्प भी तैयार होगा, लिहाजा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले तीन साल में एक करोड़ से अधिक युवाओं की कार्यकुशलता में सुधार के मद में निवेश पर मुख्य ज़ोर है। इसके जरिये यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों की पूंजी तक पहुंच के रास्ते में आने वाली बाधाएँ दूर की जा सकें। कौशल विकास मिशन के तहत 76 लाख युवा पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं और इस बजट प्रस्तावों के अनुसार 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना से इस तादाद में और वृद्धि होगी। जो कंपनियॉ बेरोज़गारों को 25000 रूपए तक के वेतन पर काम देंगी, उन्हें टैक्स में छूट देने के निर्णय से भी देश में रोज़गार के सृजन बढ़ने में मदद मिलेगी।

यह बजट गांव, गरीब, किसान और नौज़वान के लिए है, इससे उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। खास बात यह है कि इस बार बजट में 0.5 फीसद कृषि कल्याण सेस और सरकार के खजाने में जमा होने वाले काले धन पर 7.5 फीसदी सेस के प्रावधान से कृषि योजनाओं को अधिक गति मिलेगी।

आज़ादी के बाद पहली बार आम बजट में 36 हज़ार करोड़ रूपए का प्रावधान कर कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई के लिए 5.717 करोड़ रूपए दिये गये हैं, जिससे पूरे देश में 5 लाख तालाब व कुओं का निर्माण किया जायेगा। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए 362 करोड़ रूपए दिये गये हैं। मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराए जाने का प्रावधान है तथा जैविक खेती के लिए बजट में 297 करोड़ रूपए का आवंटन कर गत वर्ष की अपेक्षा 19 फीसदी अधिक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सफल बनाने के लिए उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मद में 1,700 करोड़ रूपए दिए गए हैं। दलहन उत्पादन के लिए 500 करोड़ रूपए का आवंटन कर इस बजट में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, को सफल बनाया गया है।

इस वर्ष के बजट में किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट ग्रामीण भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और सही भी है, क्योंकि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है, गांव की सड़के अब हिचकोले नहीं लेंगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन जिस तरह से अब हो रहा है, वैसा पहले नहीं था। 27 हज़ार करोड़ रूपए इस योजना के तहत खर्च किए जाने हैं व साथ ही 65 हज़ार नई बस्तियों को सड़कों से जोड़ना, गांवों के लिए एक सुनहरा उपहार है।

बजट में किसानों, गरीबों और वंचित लोगों का ध्यान रखा गया है। मैं प्रधानमंत्री जी और अपने दोनों वित्त मंत्री जी को उनकी दूरदर्शिता के लिए बधाई देता हूँ। इस बजट में सामाजिक क्षेत्र, कौशल विकास व रोज़गार सृजन पर ज़ोर दिया गया है। यह बजट आम जनता की अपेक्षाएँ पूरी करेगा।

जय जवान, जय किसान, जय नौजवान...

आओ सब मिलकर बनाये, मेरा भारत महान...

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं वर्ष 2016-17 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक सशक्त और पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित ही इन्हीं आधारों और विश्वास से की भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह किसी तरह से सुदृढ़ हो और गांव में रहने वाले गरीब और किसान हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन में सुधार आ सके, इसी को ध्यान में रखकर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा कुछ मानक तय किए जिन्हें उन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्था का स्तम्भ बताया है, जिसमें ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, रोजगार, कर सुधार, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन हैं। मेरे से पूर्ववक्ता अभी बता रहे थे कि बहुत सी समानताएं इस बजट में नजर आती हैं। इस तरह की समानताएं होना शुभ संकेत है। विदेशी लोग जो यहां पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हें अगर यह लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थायी है और उसमें कोई फेरबदल या उतार-चढ़ाव नहीं होता है, जो अच्छी नीति पुरानी सरकार लेकर आती है, उसको यह सरकार भी चालू रखती है और देवेगौड़ा जी भी अभी यही कह रहे थे कि चिदम्बरम जी ब्लैकमनी के लिए जो स्कीम लाए थे, इस बजट में उसकी निरंतरता बनाए रखी गयी है। यह बहुत शुभ संकेत है। लेकिन इसी बात को हमारे मुख्य विरोधी दल के उपाध्यक्ष जी ने कहा कि जब मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को सुना तो मुझे चिदम्बरम जी की योजनाएं सुनायी दे रही थीं, मैं चौंक गया और हिल गया। यह चौंकने का विषय नहीं है, यह सौभाग्य का विषय है। शशी थरूर जी ने भी अपने भाषण में लगभग यही बातें कही हैं। उन्होंने बहुत सारी शायरी को तोड़ा-मरोड़ा। अगर मैं यह कहूं कि बहुत सारे शेरों का उस दिन शशि थरूर जी के द्वारा कत्ल हुआ, तो गलत नहीं होगा। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की नौंक-झोंक, आनाकानी, मान-मुनोव्वल तो चलता रहेगा। एक शेर अपने प्रतिपक्ष के साथियों के प्रस्तुत करना चाहता हूं-

माना कि मोहब्बत को छिपाना है मोहब्बत,
चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ।
रंजीश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ।
आ फिर से मुझे छोड़ के लिए जाने के लिए आ।

जब देश के हित की बात होती है और प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत को पाने के बाद उस जगह बैठते हैं और उनके मन में आर्थिक सुधार लाने के लिए जो भावनाएं होंगी, वह वही होंगी जो आज से 31 साल पहले राजीव गांधी जी के मन में थीं और 31 साल पहले राजीव गांधी जी भी वहीं बैठे थे। अगर इस बजट

में वह निरंतरता है तो यह सौभाग्य की बात है। आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में छाई हुई है। केवल भारत की ही 7.6 प्रतिशत विकास दर है, ब्रिक्स नेशन्स की अर्थव्यवस्था में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

कुँवर भारतेन्द्र सिंह : मान्यवर, मैं दो विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा।

माननीय सभापति : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह: पहला शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा पर बहुत कम मेरे सहयोगी साथी बोल पाए हैं। शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के बाद हमें उसकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना है, यह बात वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कही है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक आएं। वाजपेयी जी ने यह कार्यक्रम 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में शुरू किया था। उस समय 57 प्रतिशत बच्चे स्कूल से ड्राप आउट कर जाते थे। ...(व्यवधान) मान्यवर, मैं बीजेपी का सांसद हूं, हम लोग 282 हैं। हमें सचेतक ही नहीं बोलने देते हैं।

माननीय सभापति : अभी बहुत सारे स्पीकर्स हैं।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह : हमें बड़ी मुश्किल से बोलने का मौका मिला है, आप हमें थोड़ा समय और दे दें।

HON. CHAIRPERSON: A long list of Members is there. Please conclude.

… (*Interruptions*)

कुँवर भारतेन्द्र सिंह : मैं शिक्षा पर बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2016 में 97 प्रतिशत स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं, वे विद्यालयों में भर्ती हैं और 57 परसैन्ट ड्राप आउट का रेट गिरकर 4.1 परसैन्ट हो गया है। कक्षा एक और कक्षा दो के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कार्यकलाप आधारित अध्ययन को जोड़ा जा रहा है, रीडिंग पीरियड को इनक्लूड किया गया है, समय सारणी में पढ़ने की अवधि निर्दिष्ट की गई है और यह जो मॉडल है, यह सिक्किम से लिया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में भी बड़ी सफलता से इसका संचालन हुआ।

महोदय, स्कूलों के बच्चों के लिए एक सारांश नाम की नीति लाई गई है, जिसमे माता-पिता स्कूल के अध्यापक और स्वयं विद्यार्थी मिलकर...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

KUNWAR BHARATENDRA SINGH: I have just started speaking. I wish to speak only on education which no other Member has spoken about. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I understand that but there is a long list of Members. What can I do? Please conclude in half a minute.

कुँवर भारतेन्द्र सिंह : बच्चों के कार्यों में सकारात्मक देखरेख हो सके, पढ़े भारत, बढ़े भारत के आधार पर सभी बच्चों की बेसिक एजूकेशन मे सुधार लाया जा रहा है। शिक्षकों और बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। शिक्षकों और उनके संबंधित कार्य को प्रशिक्षण जैसे प्रधानाचार्य को अलग प्रशिक्षण और जो बच्चों को, शिशुओं को टीचर कक्षा एक और दो में पढ़ा रहे हैं, उन्हें अलग प्रशिक्षण। डिजिटल शिक्षण संस्था विकसित करना तथा टीचर वीडियों द्वारा अगर कोई नया प्रयोग ला रहे हैं तो उसे अपलोड करें, ताकि अन्य टीचर भी उससे देखकर लाभ उठा पायें।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

… (*Interruptions*)

KUNWAR BHARATENDRA SINGH: Allow me to at least finish on basic education. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is a system here; there is discipline here.

कुँवर भारतेन्द्र सिंह : जो सेवानिवृत्त लोग हैं और जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वे भी इसमें मदद करें। इसके लिए मुख्य रूप से यह किया गया है।

I would only like to compliment the Tamil Nadu Government, Sir. … (*Interruptions*)

I am concluding. Allow me to conclude. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have to conclude within 30 seconds now.

Kunwar Bharatendra Singh, please conclude now.

KUNWAR BHARATENDRA SINGH: I only wish to conclude by saying that anybody who has India first in their hearts and I hope all of us are very fortunate. It is not only the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister but also all of us who have got elected to this august House are very fortunate. If all of us hold in our hearts that we should really make this august House an instrument of change and if we really support it and support change and rise above our partisan politics,

I am sure, we will be able to change the picture of our great nation and make it lead and become the *dharm guru* of the next century.

[*]**श्रीमती रीती पाठक (सीधी):** भारत को बदलने की दिशा में किए गए प्रयास अर्थात् सामान्य बजट 2016-17 में किए गए महत्वपूर्ण सुधार का मैं समर्थन व स्वागत करते हुए कहना चाहती हूँ-

बजट हर एक के सम्मान का।

गांव, गरीब, किसान का।

भारत की उड़ान का।

अर्थात् बजट 2016-17 को कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जहां कृषि को 84 प्रतिशत अधिक अर्थात् दोगुने आवंटन में किसानों के कल्याण की राशि को 15,309 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 35,984 करोड़ रूपए कर दिया गया, तो सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ की लंबी अवधि का फंड तैयार किया गया है, जिससे यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगले 5 साल में किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी।

बात यदि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की आती है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से प्रति परिवार को एक लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इसमें भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देते हुए अतिरिक्त 30,000 रूपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में 1000 करोड़ रूपए से हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी स्थापित की गई है। इसके अलावा विश्व पटल पर उच्च शिक्षा में भारत को पुनः स्थापित करने की दिशा में अनोखी पहल हमारी सरकार करने जा रही है, जिसके लिए 10 सरकारी व 10 गैर सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को पढ़ाई और शोध में विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने आधार के जरिए सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म बनाया, जहां जरूरतमंदों को सब्सिडी और अन्य वित्तीय मदद के लिए नया कानून बनाया गया है। ऐसे कई नये प्रयोग, जो सफल होते दिखाई दे रहे हैं, इस बजट में उन्हें बड़ी हिस्सेदारी मिली है।

अब यदि हम इस बजट को क्षेत्रवार वर्गीकृत करके देखें तो इसका लाभ समझ में आता है। जैसेकि मंत्रालयों के द्वारा कमज़ोर वर्गों के लिए अधिक आवंटन किया गया है।

किसानों को निम्न प्रावधानों से लाभ होगाः

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बहुत ही कम प्रीमियम पर पूरा बीमा.
- उत्पाद को बेचने में सहायता के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ई-प्लेटफॉर्म.

---

[*] Speech was laid on the Table.

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई की बेहतर सुविधाएं, लंबी अवधि का सिंचाई फंड, भूजल के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और ज्यादा कुएं और तालाब.
- कर्ज के ब्याज की वापसी का दबाव कम करने के लिए 15,000 करोड़ रूपए का आवंटन.
- गांवों की सड़कों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बढ़ावा.
- क्या बोया जाए, इसकी जानकारी देने के लिए सॉयल हैल्थ कार्ड.
- गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर-अरबन मिशन की शुरूआत.
- बिचौलियों को हटाते हुए सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभ.

जहां तक गरीबों की बात है, निम्न सुविधाओं से उन्हें फायदा होगाः

- 1 लाख रूपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना.
- हर परिवार को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवा बनाए जाएंगे कुशल.
- ई.पी.एफ.ओ. सहायता के जरिए सरकार नौकरी पाने में मदद कर रही है.
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर-अर्बन मिशन से गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार.
- सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान.
- बिचौलियों को हटाते हुए सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभ.
- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के जरिए सस्ती दवाइयां दी जाएंगी.
- 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी.

सरकार ने युवाओं के लिए निम्न व्यवस्था की हैः

- नए नियमों और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की सहायता से विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों तक पहुंच.
- सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे स्कॉलरशिप का लाभ.
- स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, डिग्री, अन्य एकेडमिक अवार्ड और मार्कशीट रखने के लिए डिजीटल तिज़ोरी सरकार ने बनाई है.

- उद्यमियों के सपनों को स्टार्ट अप और स्टैण्ड अप इंडिया जैसी स्कीमों से लाभ पहुंचाया गया.
- रोज़गार सृजन के कदमों से नौकरियों की तादाद बढ़ी है.
- मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नेशनल करियर सर्विस के जरिए कौशल विकास.
- बेहतर सड़क और रेल संपर्क.

उद्यमियों के लिए निम्न उपायों से अनुकूल माहौल बनेगाः

- स्टार्ट अप्स के लिए शुरूआती तीन साल तक लाभ में 100 फीसदी छूट.
- मुद्रा योजना के जरिए 1 लाख 80 हज़ार करोड़ रूपए का कर्ज देने का लक्ष्य.
- स्टार्ट अप्स के लिए बेहतर माहौल देने के लिए कंपनीज एक्ट में बदलाव.
- नई स्टार्ट अप नीति में ईको सिस्टम और नियम-शर्ते भी आसान.
- प्रिजम्टिव टैक्सेशन स्कीम की धारा 44 एडी के तहत टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रूपए की गई.
- प्रस्तावित दीवालिया संबंधी कानून के अंर्गत उद्योग बंद करना आसान होगा.
- जुर्माने और ब्याज की छूट संबंधी आवेदन एक साल के भीतर निपटाए जाएंगे.

मध्यवर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने निम्न उपाए किए हैं-

- दालों की कीमत में स्थिरता के लिए प्राइज स्टैबलाइजेशन फंड.
- होम लोन के 50,000 तक रूपए के अतिरिक्त ब्याज पर छूट, साथ ही हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में टैक्स छूट का लाभ.
- डिजीटल लिट्रेसी मिशन में पंजीकरण कराकर डिजीटली साक्षर होने का मौका.
- आयकर की धारा 87 ए के तहत छूट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई.
- मकान किराए संबंधी आयकर की धारा 80 जीजी में छूट की सीमा 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई.
- सड़क परिवहन के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं.
- नेशनल पेंशन स्कीम से 40 फीसदी धन की निकासी पर कर छूट, साथ ही नियोक्ता भी पेंशन फंड में ज्यादा योगदान दे सकता है.
- आयकर रिटर्न में गड़बड़ी के समाधान के लिए ई-सहयोग योजना लागू.
- जनता की स्वास्थ्य जरूरतों के मद्देनज़र नेशनल डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम.

- अवैध धन जमा करने वालों से निपटने के लिए केंद्रीय कानून, ताकि वे अपनी बचत का सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकें.
- बिचौलियों को हटाते हुए सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभ.

बाज़ार को लाभ प्रदान करने हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं-

- अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश 2 साल में लॉंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए एलिजिबल होगा.
- मजबूत एवं पर्याप्त रूप से कैपिटलाइज बैंकिंग सेक्टर के कारण उपयुक्त माहौल.
- लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लॉंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव नहीं.
- स्थायी और सटीक अनुमानित टैक्स रेजीम से भारत पर भरोसा बढ़ा.
- मजबूत कॉरपोरेट बॉण्ड मार्केट और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म.
- सीमा और उत्पाद शुल्क में बदलाव से मेक इन इंडिया को बढ़ावा.
- विवाद निपटान योजना के तहत टैक्स संबंधी मामलों का आसान समाधान.
- जनरल इंश्योरेंस कंपनियॉं स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड हो सकेंगी.
- सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के जरिए फायदा.
- ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में 100 फीसदी एफ.डी.आई. को पूर्णतया मंजूरी.

*ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI) :The budget 2016-17 appears to be more farmer friendly and infrastructure development oriented. According to the Finance Minister, the income would be doubled in 5 years. He also promised to implement programs to achieve this end. Large allocations have been made to the infrastructure development. But a close analysis of the budget declarations reveals that there is nothing to cheer for the growers of cash crops.

To keep the promise of doubling the income of farmers in 5 years, it is required to raise farmer's income by 15% a year. Even if the farmers can increase their output by 3% a year, agriculture price will have to raise by 12% a year which will worsen the inflation. Therefore without introducing specific schemes targeted for increasing the income of the farmers by means of increased productivity, decrease in cost of production and ensuring high market price, the present announcement also will remain as a promise as in the case of earlier declarations and announcements for the agrarian sector.

When we analyze the budget announcements, it would reveal that the agrarian economy especially the cash crops and plantation crops sector will not be benefited. As we are all aware that because of the problems faced by the growers of cash crops like Rubber, Cardamom, Coffee, Tea, etc. due to the fall of price of Rubber, the growers are finding it very difficult to survive. The price of Natural Rubber has been fallen from Rs. 250/kg to Rs. 85/kg during 2011-2016. The Rubber growers are not getting the cost of producing the commodity, so is the case of cardamom and the cash crops. Now cardamom is fetching only Rs. 400/kg against the production cost of Rs. 750/kg. Tea and Coffee Sector is also having the very same issues. As a result of price fall, all these sectors are in distress. The poor labourers and the small scale growers are really in deep crisis. They are not in a position to send their children to schools, repay the loans availed from various financial institutions, avail treatments for ailments and meet all other financial commitments incidental to their survival as human beings. Though the economic

* Speech was laid on the Table.

and social scenario has become so hostile, the Government is not taking up the responsibility to mitigate the hardship of the people. The respective State Governments, representatives of the people including Members of Parliament and all other stake holders have represented the Government to introduce targeted programmes to address the issue faced by the growers of rubber, cardamom and other cash crops. But unfortunately, the budget 2016-17 did not make any efforts to address the issues of this sector, instead the allocation to the Commodity Boards, Rubber Board, Spices Board and Coffee Board have been reduced drastically. The allocation of the Rubber Board has been reduced from Rs. 161.75 crore to Rs. 132.75 crore, for Spice Board that is reduced from Rs. 95.35 crore to 70.35 crore and for Coffee Board its reduced from 136.54 crore to 121.54 crore.

The functioning of the Commodity Boards especially Rubber Board and Spices Board is a matter of frustration. The Rubber Board is functioning without a full time Chairman. Though the Spices Board is having a full time Chairman, the activities of the Spices Board especially that relating to the development of cardamom and its marketing which is the mandate of the Spices Board under the provisions of the Spices Board Act 1986, are not being undertaken as if the same was done during the past. I had occasion to raise this matter earlier before especially the withdrawal of the Spice Board from the development of small Indian cardamom which is being grown in the high ranges of Idukki district of Kerala State. The lesser allocation of funds to the Commodity Boards will affect the very activities of the Rubber Board and Spices Board in the development front including the dispersal of subsidies for re-plantation and other allied activities.

It is the common case of all the Political Parties that an amnesty scheme should be brought in to mitigate the hardship of the Rubber and Cardamom farmers. All the political parties and other stake holders have represented the matter before the Government but the budget proposals have disappointed all of them. In fact, we have requested for a Rs.1500 crore amnesty scheme for the Rubber growers and Rs.500 crore amnesty scheme for the Small Indian

Cardamom Growers to tide over the crisis which they are facing at present due to the wrong policies of the Government which has been followed since the introduction of globalization and neoliberal economic policies. It is not the farmers but the Government which has failed to protect the interests of the agrarian economy while entering International treaties of trade including ASIAN agreement, GATT, WTO agreement, etc. Therefore, it is the responsibility of the Government to protect the interest of the farmers, labourers and others those who are depending on the agrarian economy by introducing targeted schemes and programs for ensuring the sustenance of the sector.

I urge upon the Government to raise the allocation of the Commodity Boards especially that of Spices Board and Rubber Board. I also request the Government to allocate more funds for development of cardamom especially the small Indian Cardamom which is being grown in the high ranges of Idukki district in Kerala. I also hope that the Government will introduce amnesty schemes for the growers of Rubber and Cardamom to avoid farmers suicide in large scale.

*श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर): 2016-17 का यह बजट गांव के गरीब गुरबार और किसानों के हित का बजट है। इस बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वही मनरेगा योजना के तहत 38,500 करोड़ रूपए दिए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिए थे और अब तक की सबसे बड़ी राशि है। ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड़ रूपए दिए हैं। पिछले बजट से करीब आठ हज़ार करोड़ ज्यादा दिए हैं। हमारी सरकार गांव में बसने वाले किसानों और गरीबों की सरकार है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रूपए तथा राज्यों का हिस्सा मिलाकर 27,000 करोड़ रूपए दिए गए हैं। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रूपए दिए गए है, जो पिछले वर्ष से 11 प्रतिशत ज्यादा है। इस वर्ष पांच लाख तालाब और पांच लाख कुएँ बनाने का लक्ष्य है। बिजली के क्षेत्र में 8,500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मई 2018 तक सभी गॉवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए 1,700 करोड़ खर्च करके 1,500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जायेंगे। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की महिला सदस्य के नाम पर सस्ते दर पर एल.पी.जी. कनेक्शन देने का लक्ष्य है। डेढ़ करोड़ परिवारों को जन-धन योजना के तहत लाखों-करोड़ों परिवारों को लाभ मिला है। वहीं बीमा के क्षेत्र में गरीबों के हित में, किसानों के हित में बीमा दिया गया है। जैसे- फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, एक लाख रूपए का हैल्थ् कवर देने वाली सुरक्षा बीमा योजना, सीनियर सिटीजन के लिए 30 हज़ार का अतिरिक्त टॉप अप पैकेज। पढ़ाई के क्षेत्र में स्कूल-कॉलेज के सर्टिफिकेट, डिग्रियों, और मार्कशीट के डिजीटल डिपोजिटरी बनाई जाएगी। 62 नये नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे, इसके अलावा हमारी सरकार ने 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

इस बजट में किडनी रोगियों और गरीब रोगियों को हमारी सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश के प्रत्येक जिले में डायलिसिस सेंटर और देशभर में 300 जन औषधि सेंटर खोलने का लक्ष्य है। दालों की महंगाई कम करने के लिए, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रूपए का फण्ड दिया गया है और दाल के दामों में स्थिरता बनाए रखने के लिए 900 करोड़ अलग से दिए गए हैं। अंत में आज के हालात और कल की जरूरत को देखकर यह बजट बनाया गया है।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

---

* Speech was laid on the Table.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने सामान्य बजट वर्ष 2016-17 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बिहार से आता हूं, हमारी पार्टी बहुत छोटी है, हम दो सांसद हैं। आप कम से कम हमें बोलने के लिए छः-सात मिनट दीजिए। बिहार में हमारी सरकार है तो हम अपनी कुछ बातें यहां रखना चाहते हैं।

महोदय, हर साल की भांति इस साल भी बजट पेश हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योकि किसानों के प्रति जो उनकी सोच और रवैया है, वह बहुत सकारात्मक है। लेकिन जो बजट पेश हुआ है, ऐसा नहीं है कि यूपीए की सरकार में विकासहीन बजट होता था और आपकी सरकार तीसरा बजट पेश कर रही है। गाँव अभी तक देख रहा है कि यह जो तीसरा बजट पेश हो रहा है, इससे विकास होने वाला है या यह विकासहीन है। हम लोग बिहार से आते हैं। बिहार में लगातार माननीय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव के वक्त बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर पटना के गाँधी मैदान में वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी तो बिहार को मैं विशेष राज्य का दर्जा दूँगा।

महोदय, प्रधान मंत्री जी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, वित्त राज्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि बिहार पिछड़ा राज्य है, लगातार बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। बिहार पिछड़ा राज्य है, जिस तरीके से ओडिशा पिछड़ा राज्य है, जो पिछड़ा अनुदान हमें मिलता था, उसमें भी कटौती कर दी गई है। अगर बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो बिहार का जो चुनाव हुआ, उसका आपने रिजल्ट देखा, दो बार जो आपका बजट हुआ, आपको आशा थी, लेकिन बिहार की जनता ने आपको नकार दिया। हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था करें। अभी भूतपूर्व प्रधान मंत्री देवगौडा जी किसानों की हालत पर बोल रहे थे, आज देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बजट में कहा गया है कि किसानों की जो बदहाली है, उसे हम दूर करेंगे। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लाई गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसानों की जो हालत है, उसमें लगातार व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहाँ किसान था, वह आज भी वहीं है। लगातार किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। कृषि मंत्री जी भी अभी यहाँ बैठे थे, वे चले गए हैं। हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ की चपेट में रहता है। उत्तरी बिहार में नेपाल से जो पानी आता है, उसके बारे में आज तक भारत सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा और माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि नेपाल से बात करके अगर नदी परियोजनाओं को नहीं बनाया गया तो निश्चित रूप से बिहार में जो बाढ़ आती है, उसका निदान नहीं होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी माननीय प्रधान मंत्री जी के ऊपर होगी। कई वादे

उन्होंने किए थे, उन्होंने यह भी कहा था कि गरीबों का जो कच्चा मकान है, उसको मैं पक्का मकान बनाऊँगा। जो बजट आया है, उस बजट को देखकर साफ लगता है कि पिछले बजट की तुलना में इस बजट में इन्दिरा आवास में 54 परसेंट की कटौती की गई है। कहीं न कहीं गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा है। अभी कुछ साथी बता रहे थे कि दलितों के लिए बजट में कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपसे विनती और निवेदन करूँगा कि इन्दिरा आवास के लिए जो पैसा मिलता है, पहले इसमें यूपीए की सरकार में लगातार बढ़ोत्तरी रही, लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है, लगातार इसमें कटौती की जा रही है। हम आपने विनती और निवेदन करेंगे कि 54 परसेंट की जो कटौती हुई है, उसे पूरा किया जाए।

महोदय, बिहार में प्रधान मंत्री जी ने लगातार, मोतिहारी की सभा में उन्होंने कहा था कि बन्द पड़ी हुई चीनी मिलें हैं, जो किसान वहाँ लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिहार में सात चीनी मिलें बन्द हैं, उन्हें फिर से चालू कराया जाए। यह व्यवस्था निश्चित रूप से की जाए। महँगाई की चपेट में लगातार गरीब लोग मर रहे हैं, बाजार में अरहर की दाल 250 रूपए प्रति किलोग्राम मिल रही है, टमाटर 90 रूपए प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि महँगाई के लिए आप कोई नीति बनाइए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*[*]**श्री हरि मांझी (गया):** यह आम बजट मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जो किसानों और गरीबों से जुड़ा हुआ है। किसानों की आय को दोगुना करने पर ज़ोर दिया गया एवं कृषि के क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी और इस बजट में 35,984 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर 5,500 करोड़ रूपए एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर 5,300 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ज़ोर दिया गया है, इस बजट में 97,000 करोड़ रूपए देने का प्रावधान किया गया है। जिसमें 5,500 करोड़ रूपए राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों पर खर्च किए जाएंगे। जिससे 50 हज़ार किलोमीटर स्टेट हाईवे एवं 10 हज़ार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों का निर्माण होगा तथा स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्गों में तबदील किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग को इस बजट में 87,765 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गॉवों को स्वच्छ करने पर ज़ोर दिया गया है। महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना में इस बजट में 38,500 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। जिससे गॉवों में इस योजना से 5 लाख नए तालाब का निर्माण कराया जाएगा। इससे मज़दूरों को रोज़गार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जन औषधि योजना के लिए 33,150 करोड़ रूपए दिए गए हैं। जिससे गरीबों को कम कीमत पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए 3,000 जन औषधि स्टोर खोले जाएंगे।

पंचायती राज मंत्रालय के तहत ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2.87 करोड़ रूपए दिए गए हैं।

इसी तरह यह बजट गरीबों के हित में है और गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए एल.पी.जी. गैस कनेक्शन देने के लिए इस बजट में 2,000 करोड़ रूपए दिए गए हैं और उच्च शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 1,000 करोड़ रूपए दिए गए हैं तथा देशभर में 62 नये नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। युवाओं के कौशल विकास हेतु स्किल इंडिया मिशन में 1,700 करोड़ रूपए दिए गए हैं और 1 मई, 2018 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह आम बजट रोजगारोन्मुखी एवं विकासोन्मुखी बजट देशहित में है।

---

[*] Speech was laid on the Table.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी तीन दिन पहले इस चर्चा में इंटरप्ट करते हुए हमारे वित्त राज्य मंत्री जी ने संसाधनों की सीमा का उल्लेख किया था। मैं थोड़ा उसी का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारी कुल जो प्राप्तियाँ हैं, वे 14 लाख 44 हजार 156 करोड़ रूपए की हैं। डेफिसिट का, उधारी आदि 5 लाख 33 हजार, 904 करोड़ रूपए की जोड़कर के कुल 19 लाख, 78 हजार, 60 करोड़ रूपए का यह हमारा हिसाब है। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर 17 लाख, 31 हजार 37 करोड़ रूपए का है।

17.00 hours

इसमें हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वह 2 लाख 47 हजार 23 करोड़ का है। मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कि इसमें लगभग 4 लाख 92 हजार करोड़ हमें ब्याज के अंदर देना पड़ता है। ये जो चीजें हैं, जो सीमायें हैं, जब भी कहीं हमारे विपक्षी बात करें या कोई बात करे, वास्तव में इन आंकड़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ब्याज की देनदारी कैसे घटे, हमारी सरकार ने .2 पर्सेंट इसे कम किया है और हमारी आय कैसे बढ़े? जब तक आय नहीं बढ़ेगी, देनदारियां नहीं घटेंगी, तो एक सामान्य नागरिक के बजट की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि तब तक हम ठीक से सारी चीजों को नहीं चला सकते हैं। बजट के जो सारे प्रावधान हैं, इस बात को लेकर किए गए हैं कि हमारी आय बढ़े, हमारी देनदारियां घटें, विकास के कामों के अंदर सम्यक रूप से धन का निवेश हो और उस दृष्टि से बेहद संतुलित बजट, प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर ध्यान रखते हुए प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

एक और चीज जो रूपए को बचाने के लिए होती है, वह भ्रष्टाचार की होती है। भ्रष्टाचार यदि होता है तो रूपया छीजता है। इस सरकार के प्रावधानों ने, इस सरकार की कोशिशों ने उसको कम किया है, इसलिए हम लोगों के पास पहले के मुकाबले रूपए की उपलब्धता ज्यादा है। समय की सीमा जरा डिस्टर्ब कर देती है।

दूसरा, इस बजट के संबंध में कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर समग्रता की एक दृष्टि मौजूद है। हम लोग बिजली की बात करते हैं। बिजली सबको चाहिए। बिजली की जरूरत बढ़ रही है। यदि फासिल फ्यूल का हम उपयोग करते हैं, तो दुनिया भर के अंदर पॉल्यूशन का निर्माण होता है, हमारे देश के अंदर भी निर्माण होता है। यह हमारी सरकार की विशेषता है कि सौर ऊर्जा के विकल्प का बेहतर उपयोग करते हुए हमने बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किया है और दुनिया से और देश से प्रदूषण को कम करने का भी उपाय किया है। कुलमिलाकर समग्रता की एक दृष्टि इस बजट के अंदर विद्यमान है।

17.02 hours (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

पानी की समस्या है, पानी के प्रदूषण की समस्या है। शुद्ध पानी की उपलब्धता कम होती चली जा रही है। हमारी सरकार ने इन सारी बातों को सोचते हुए, वित्त मंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए, मनरेगा के अंदर जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, उनको ठीक करने का निर्णय लिया है और उनके लिए धन का आबंटन किया है, यानी जो समग्रता की दृष्टि है, कहीं पर कोई योजना बनाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसकी चिंता पूरी तरीके से सरकार ने की है।

मैं एक छोटा सा निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि स्वर्ण से जुड़े हुए व्यवसाइयों की हड़ताल चल रही है। एक प्रतिशत एक्साइज से देखा जाए तो उनको आपत्ति नहीं है। आपत्ति व्यवस्था के द्वारा उनका शोषण किए जाने की है। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि आय बढ़ाते हुए भी शोषण उनका न हो, इसको सुनिश्चित करने की कृपा करें।

मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूं कि आजकल अभिव्यक्ति की आजादी के साथ हमारे कांग्रेस के लोग बहुत जुड़े हुए हैं, बड़ी प्रतिबद्धता उनकी दिखाई देती है, इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। खासकर जहां उनके युवा नेता जाएंगे, वहा जाना उनकी मजबूरी ही है। अभी युवा नेता जेएनयू तक गए हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं। बहरहाल अभिव्यक्ति की आजादी के इन समर्पित पैराकारों ने, इनकी पार्टी ने वर्ष 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। मैं भी 21 महीने जेल में रहा था। तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसको पढ़कर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और समस्यायें बहुत ज्यादा हैं।" हे पथिक, गतिमान रहे तू। तुझे लड़ना निपटना है, आज पथ के घोरतम से। है तुझे इतिहास रचना, अनवरत, अनथक श्रम से। प्राण का दीपक जलाकर स्वयं ही द्युतिमान रहे तू। ले विजय विश्वास मन में, रे पथिक गतिमान रहे तू। हे पथिक गतिमान रहे तू। " मैं बहुत-बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं कि अगले साल का बजट इसी दिशा में बढ़ता हुआ रोजगार के अवसरों को बढ़ाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुष्ट करे, उनकी तरह शक्ति बढ़ाए, देश के अंदर संसाधनों की वृद्धि हो और घाटे कम हों। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Hon. Chairperson, Sir, I sincerely thank you for giving me an opportunity to speak on the discussion on the General Budget. At the outset I would like to compliment the Government, especially the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister on presenting a balanced Budget meeting the expectations of different sections of society. It is all the more a very Herculean Task given the global economic situation. The reaction of the stock market after the Budget is a testimony to the way the people of this country have received the Budget.

Sir, I would like to further compliment the Government for the spirit with which they have received the criticisms and suggestions and effected the required modifications to the Budget. I specifically refer to the following initiatives announced by the Government, namely, withdrawal of tax on PF withdrawals which will benefit a large number of salaried class consisting mostly of lower and middle level employees; implementation of the *Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana* to approximately cover 50 per cent of agricultural land holding at a nominal premium of 2 per cent for Kharif and 1.5 per cent for Rabi crops; introduction of a new health insurance scheme to protect against hospitalization; increasing the assured amount from Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 and by a further sum of Rs. 30,000 in case of senior citizens; providing cooking gas connections for BPL families. I specifically welcome the allocation made for the rural sector. An amount of Rs. 87,765 crore has been allocated to this segment which I represent in this House. I welcome the Government's proposal to enhance the total investment in the road sector including PMGSY allocation to Rs. 97,000 crore. I also welcome the proposed Plan expenditure by 15.3 per cent. However, in spite of the best efforts of the Government to provide a well balanced Budget, there are certain grey areas which require further consideration of the Government and necessary modifications may be announced.

The enhancement of a clean energy cess on coal by Rs. 200 per tonne will push up the cost of power generation. In fact, we demand that the clean energy

cess be completely withdrawn. The allocation of Rs. 1804 crore for skill development is meager and has to be enhanced. A major chunk of global reduction of petroleum prices has been appropriated by the Union Government by way of additional taxes without passing on the benefit to the consumer. I request the Government to pass on the benefit of reduced global prices of petroleum to actual consumers so that whenever there is any increase in the global prices, consumers will not murmur in paying the increased prices. On ethical grounds, I request the Government to evolve a policy of co-relating domestic prices with global prices.

Sir, I would also like to invite the attention of the Government to the increased Central Excise Duty on petrol and diesel by way of surcharges and cess denying the devolution to the States. A large number of additional taxes, cess and surcharges are being freshly levied in this Budget apparently for giving a push to agriculture. The last two years of this Government witnessed the lowest growth in Minimum Support Prices for Paddy and Cotton. We cannot expect to double the income of farmers in the next five years without correspondingly increasing the MSPs matching the actual cost of production on one hand and increasing the access to bank credit to farmers to 100 per cent from the present 40 per cent.

Sir, it is a matter of concern that despite such a massive campaign on Make in India, our imports of manufactured goods is increasing every month. I would like to request the Government to take serious initiatives to arrest this trend. At the cost of repetition I demand, on behalf of my Party, that the Union Government honour all the commitments made in the AP Re-organization Act, 2014 including the grant of a special category status and speedier implementation of the Polavaram project.

I would request the hon. Prime Minister to rise to the occasion keeping aside the technalities in view of the heartburn of the people of Andhra Pradesh. We are only requesting to implement the provisions of the Bill and the commitment made on the issue in the House proceedings.

This Government should honour the statement made in the House by the earlier Government in response to the demand by the then Opposition who are now in power. This is an extremely sensitive issue and silence any longer on the part of the Government is not warranted and it may lead to undesirable consequences.

Hence, I earnestly request the hon. Prime Minister to kindly address this issue at the earliest.

Lastly, I wish you to highlight an issue concerning the people connected with jewellery, namely, the increase in excise duty of one per cent on jewellery.

Thousands of artisans and employees in manufacturing industry will be affected by this measure. Jewellery is not an investment but a sentimental item in the lives of the people of this country and specially women.

Jewellery is a high volume and low margin business. I may remind that the earlier Government has tried to impose this hike twice and withdrew the same on facing resistance.

I would request the Government to withdraw the hike which will please all the artisans and skill workers.

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इतनी बधाई देता हूं जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।...(व्यवधान) चूंकि मैं गांव से आता हूं, किसानों के बीच से आता हूं, इस बार के बजट में चाहे गांव के लिए हो, चाहे गरीब व्यक्ति के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे कृषि के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, रोजगार के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो या नौजवानों के लिए हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका इस बार के बजट में ध्यान नहीं रखा गया।

मुझे अभी गांव जाने का मौका मिला। इस बजट के आने के बाद से कांग्रेस बहुत घबरा गई है। उसे लग रहा था कि शायद 2019 में कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इस बार के बजट ने कांग्रेस के रास्ते 2019 के लिए ही नहीं बल्कि 2024 तक के लिए बंद कर दिए हैं क्योंकि जिस प्रकार यूपीए सरकार भ्रष्टाचार करती रही है, उसे माननीय मोदी जी की सरकार ने रोकने का काम किया है। देश में 20 करोड़ से अधिक प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खातों का खुलना, इससे पहले खातों के माध्यम से लूट मचाकर स्विस बैंक में पैसा जमा करने का काम किया जाता था। अब इस सरकार ने व्यवस्था की है कि जो भ्रष्टाचार करने का काम करेगा, उसकी जगह बैंक में धन जमा करके सुख भोगने की नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में भेजने का काम करने का रास्ता बनाया है।

इस सरकार ने इस बार स्वास्थ्य की दृष्टि से कदम उठाया। इससे पहले 30 हजार रुपये का एक स्मार्ट कार्ड बनता था जिसके आधार पर इलाज की सुविधा दी जाती थी। अभी मैं गांव गया था। वहां जाकर देखा कि एक लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए 30 हजार रुपये का टॉप-अप, फसल बीमा योजना, अब किसान को दुखी होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, वित्त मंत्री जी के बजट के माध्यम से यह संदेश गया है। गांव का कायाकल्प करने के लिए इस बार सरकार ने एक गांव के लिए 80 लाख रुपये देने का काम किया है। इस बजट से अब गांवों का कायाकल्प होगा। व्यवस्थाओं का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। अब सही तरीके से विकास होगा। विकास के कारण गांव खुशहाल होंगे।...(व्यवधान) हम नए सदस्य हैं। आप बड़े लोगों को बोलने का समय दे देते हैं, हमें भी एक-दो मिनट अतिरिक्त समय दे देंगे तो अच्छा रहेगा।...(व्यवधान) जिस दिन बजट आया, मैंने दूसरे दिन अखबारों को पढ़ा। अखबारों ने लिखा कि सरकार चली गांवों की ओर। अखबारों में जब इस प्रकार के समाचार आए तो हमारे कांग्रेस के साथी घबरा गए, उनको लगा कि मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से गरीबों, गांवों, किसानों और युवाओं के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है और उनको बढ़ावा दे रही है,

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार चाहे माताओं और बहनों की बात करूं, देश की सुरक्षा की बात करू, मेक इन इंडिया की बात करूं, डिजिटल इंडिया की बात करूं, स्टार्ट-अप की बात करूं, रेल की बात करूं, सड़क की बात करूं, गरीबों के लिए घर की बात करूं, कौशल विकास की बात करूं ऐसी तमाम सारी योजनाओं या सस्ती दवाओं की बात करूं, ऐसी तमाम सारी योजनाओं द्वारा जिस प्रकार से इस सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी को अपने क्षेत्र और क्षेत्र के किसानों की ओर से बधाई देता हूं। इस बजट से निश्चित तौर से देश में खुशहाली आएगी, गरीबों की गरीबी दूर होगी और देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नम्बर एक पर पहुंचेगा। मैंने कुछ लाइन कांग्रेस के साथियों के लिए लिखा है, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने खेल को लूटा, रेल को लूटा, गरीबों को लूटा, किसानों को लूटा और पूरे हिन्दुस्तान को लूटा, कोयले को लूटा, फोन को लूटा मैं किन-किन बातों का जिक्र करूं, इन्होंने पूरे देश, नौजवानों को लूटने का काम किया और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the discussion on the General Budget 2016-17. On behalf of my Party, the Communist Part of India, I would like to say that the emphasis on agriculture and the rural sector in the Budget for 2016-17 suggests that it has been clearly influenced by the prevailing political climate in the country. It has been done in the background of the ruling party's rout in Delhi and Bihar Assembly elections after the last Lok Sabha elections and keeping in mind the prospects in the forthcoming Assembly elections in five States, Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry. But the realisation of the Budget's noble objective lies in its implementation.

The agriculture and farmers' welfare has got Rs. 35,984 crore in this Budget, which is just 1.81 per cent of the total expenditure of Rs. 19.78 lakh crore and the focus is on doubling farmers' income by 2022. For farmers who are already in distress, five years is a long time away. The peasants are committing suicide basically because of their failure to pay back the loans that they have taken from moneylenders.

According to the official estimates, over 12,000 farmers had committed suicide during the year 2014-15. A provision of Rs. 15,000 crore has been made in the Budget towards interest subvention to reduce the burden of future loans repayment. But there is no provision in the Budget for writing off their present loans.

The Government has already written off Rs. 1.14 lakh crore of bad loans taken by the corporate houses during the years 2013-15. The Finance Minister has promised that NPA issue will be tackled during the year, which means much more NPAs will be written off.

The Finance Minister claims that he has allocated the highest ever amount of Rs. 38,500 crore in 2016-17 for MGNREGA as against Rs. 34,699 crore allotted in 2015-16. But it is lower than what was spent last year, which was over Rs. 41,000 crore. Moreover, the number of man-days of the employment provided

has come down to less than 40 per household as against the promised 100 days and there is an accumulated arrears of wages amounting to more than Rs. 6,500 crore. So, the actual allocation will be Rs. 32,000 crore for 2016-17 and at the end of the current year, there will be a larger amount of arrears of unpaid wages.

There is no mention of increase in the public health spending in the Budget. It stands at 1.2 per cent of the GDP. Creation of Dialysis Centres in the District Hospitals will help in tackling the rising chronic cases of renal failures but it has to be ensured that the facilities are well maintained and are functional always.

The decision to open 3,000 *Jan Aushadhi* Stores across the country to provide affordable medicines is a people-centric move but it should be ensured that generic medicines are tested and of the best quality.

Expenditure on Integrated Child Development Scheme has been drastically cut for the second year in a row from Rs.15,483.77 crore for 2015-16 to Rs.14,000 crore in 2016-17 although the Supreme Court wanted the scheme to be enlarged and universalised.

Sir, these are some observations I could mention about the Budget 2016-17 within the meagre time available to me. Thank you very much, Sir.

* SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): We are listening from the media about increasing of MP's remuneration allowances from Rs.1.40 lac to Rs.2.80 lac per month. But instead of increasing MP's remuneration allowances, it is necessary to increase MPLAD funds from Rs.5 crore to Rs.25 crore per year.

My Nasik constituency consists of 455 villages, 1 Nasik Municipal Corporation, 4 Nagarpalikas and 1 Devlali Cantonment Board. Now, we are getting Rs.5 crore as fund for Local Area Development for such a large constituency for one year, which means for five years it will be Rs.25 crore. If I decide to use MPLAD fund for only rural area villages for all over five years i.e. Rs.25 crore for 455 villages, I can give only Rs. 5.49 lac for one village in five years and nothing for the urban area i.e. Nasik Municipal Corporation, 4 Nagarpalikas and 1 Cantonment Board.

Near about 50% of MPs consist of more than 75% of rural area i.e. about 1000 villages in their constituencies. Generally, people either from rural or urban areas select their representative expecting that basic necessity work would be done by the MP from MPLAD fund within five years in their area which is not possible from the government scheme. More basic necessities are needed in rural areas. Also, the urban people have expectations of same work by MP in their area.

I request hon. Finance Minister that instead of increasing MP's remuneration allowances, increase the MPLAD Fund from Rs.5 crore to Rs.25 crore per year. So the MPs can satisfy the people to some extent.

---

* Speech was laid on the Table.

* SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM) : The Union Budget 2016-17 was a big disappointment for the Telangana state governments, which was looking forward to a host of benefits for the youngest state of the country. The only consolation was a mention about the tribal university for which Rs.1 crore was allotted. Rs.20 crore for IIT-Hyderabad, Rs.15 crore for INCOIS, Rs.62 crore for the Centre for DNA fingerprinting and Rs.60 crore for the Advance Research Centre.

The budget was silent on the vociferous demand made by all parties of the region to accord special status to Telangana. There are eight backward districts in Telangana, but the Centre has not made any announcement in this regard.

The people of Telangana who eagerly awaited the announcement of according national project status to Pranahita-Chevella in the budget have been left totally disappointed.

I have been requesting the Government time and again to set up a steel plant at Bayyaram in Khamman district and the 4000 MW coal based project in Telangana. But, the Central Government has ignored them again.

Since the Government had forcibly merged 7 Mandals of Bhadrachalam Division of Khammam District of Telangana into Andhra Pradesh, the Government should consider a special package for their welfare, rehabilitation and resettlement. So far, no rehabilitation measure has been taken.

There was a proposal during UPA Government to establish a Campus of Indian School of Mining, Dhanbad in Khammam District, but no effort has been made to fulfill the long cherished desire of this mineral rich region.

Hence, I request the hon. Finance Minister to initiate steps to address the genuine problems of people of Telangana in the present Budget and render justice to the Telangana State.

---

* Speech was laid on the Table.

[*] RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM) **:** It is often said that you can convince anyone in the world if you manage to keep the people of India happy with a union budget of the government. The nature of the task is that huge and daunting that people seldom promise to deliver what is expected of them. In such a scenario, in spite of the global economy being in turmoil, the Finance Minister has presented an outstanding budget and that has lived up to the hype and expectation of the billion people of this great nation. The budget was flawless and so much so that even the opposition found it hard to criticize the budget. The Minister has ensured that this is a farmer and middle class friendly budget and that has given a string that this government is not anti-poor and anti-farmer. Let's look at what makes this budget truly a people budget.

Growth of economy accelerated to 7.6% in 2015-16. India has been hailed as a 'bright spot' amidst a slowing global economy by IMF. Foreign exchange reserves touched highest ever level of about 350 billion US dollars. Despite increased devolution to States by 55% as a result of the 14th Finance Commission award, plan expenditure increased at RE stage in 2015-16 in contrast to earlier years. These have resulted in ensuring that the faith in the Indian economic system stayed intact under the leadership of the hon. Prime Minister and the Finance Minister.

Going through the Government's road map, it reassures us that the government is committed to deliver on what it had promised to set up. Government plans to focus on ensuring macro-economic stability and prudent fiscal management, boosting domestic demand, continuing with the pace of economic reforms and policy initiatives to change the lives of our people for the better. This is highly important for the stability of the markets and economy. Focus on enhancing expenditure in priority areas of farm and rural sector, social sector, infrastructure sector, employment generation and recapitalization of the banks will ensure that the growth is not stopped. Strengthening of the weaker

---

[*] Speech was laid on the Table.

sections of the society and the renewed pitch to pass the GST bill has been a great move and will ensure that India remains the focal point of world growth.

The Finance Minister has mentioned that government has total of nine focal points for the growth of India. I want to mention why these are important and let us look at what they focus on.

Farmers form the majority of our work force and it is important that the government keeps them happy and ensure their development. A ruined farmer is a nation's curse. The government allocation for Agriculture and Farmers' welfare is Rs.35,984 crore which is unforeseen. Irrigation is a problem which needs to be addressed and the dedicated Long Term Irrigation Fund will be created in NABARD with an initial corpus of about Rs.20,000 crore which will go a long way in helping. Farm insurance has been announced which is outstanding achievement of the government and allocation under Prime Minister Fasal Bima Yojana worth Rs.5500 crore is very encouraging though more must be allocated.

If India wants to grow then the growth must be rural driven and not urban driven. Therefore, renewed vigor was needed to ensure the rural growth is kick started. Total allocation stands at Rs.87,765 crore. The move to grant 2.87 lakh crore to Gram Panchayats and Municipalities will empower the third tier of governance in India and that is highly important to ensure the last mile development. Rural employment has been a challenge but Rs.38,500 crore allocated for MGNREGS, which is the highest ever and if spent fully, will ensure that the impact of bad monsoons and unseasonal rains will not affect the farmers to that extent. 100% village electrification by 1st May, 2018, is a landmark step that the people will be ever grateful for. I am personally grateful for the setting up of District Level Committees under Chairmanship of senior most Lok Sabha MP from the district for monitoring and implementation of designated Central Sector and Centrally Sponsored Schemes as we will be able to answer our voters in a better way of what schemes are being implemented.

Rs.2,000 crore allocated for initial cost of providing LPG connections to BPL families will considerably increase the health status of the people who still use traditional means of cooking. I am specifically grateful for the 'National Dialysis Services Programme' to be started under National Health Mission through PPP mode as my constituency has a huge history of kidney ailments and this will help them immensely.

India is the youngest country in the world and we have to make use of the demographic dividend to our advantage. Move to set up 1500 Multi Skill Training Institutes will ensure the skilling of our population which is important. I request the Minister to allot one such centre in my constituency. The move by GoI to contribute 8.33% for all of new employees enrolling in EPFO for the first three years of their employment will help in the increasing of employment in a great way.

Rural connectivity is the need of the hour and the total investment in the road sector, including PMGSY allocation, of Rs.97,000 crore during 2016-17 will help realise this dream of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The performance of the government is outstanding in this regard and India's highest ever kilometres of new highways were awarded in 2015. There is plan to approve nearly 10,000 kms of National Highways in 2016-17. Action plan for revival of unserved and underserved airports to be drawn up in partnership with State Governments will ensure air connectivity is provided.

Companies all around the world want to start business in India and therefore constitution of a task force will help realise this dream of making India the best country to do business in. I personally would like to commend the move to ensure Automation facilities 3 lakh fair price shops by March 2017 and amendments in Companies Act to improve enabling environment for start-ups.

The government has stuck to its fiscal path which is highly important and gives a positive sign to the investors and the global agencies. Moves like abolition

of plan and non-plan expenditure and move to have sunset dates for all schemes will ensure timely delivery of services to the people.

Raise in the ceiling of tax rebate under section 87A from Rs.2000 to Rs.5000 to lessen tax burden on individuals with income up to Rs.5 lakhs was well received and the increase in limit of deduction of rent paid under section 80GG from Rs.24000 per annum to Rs.60000 to provide relief to those who live in rented houses is something that will immensely help the middle class salaried people who are the only ones to properly pay their income tax on time.

The renewed vigour of this government to Make in India will give huge impetus to manufactures which will in turn help growth. The Finance Minister's move to ensure housing is affordable will help put a roof over the heads of millions of Indians. The move to ensure accountability via technology is something that I would like to commend personally.

In spite of the budget being pro-poor and friendly, it was disappointing to see nothing significant allotted to Andhra Pradesh. I would like to make a renewed pitch for the grant of special status for Andhra Pradesh and for financial packages. We are in the process of constructing a new capital, we need funds to construct the capital. Andhra Pradesh, post the unscientific separation, is trying to build a new capital, a new city Amaravati. Despite repeated assurances, the central government has failed in dishing out any sort of assistance to the state of Andhra Pradesh towards the same. Our hon. Chief Minister Shri Nara Chandra Babu Naidu Garu is pulling out all stops to ensure the already bruised state gets a world class capital. The plans are ready, but the only thing that is lacking is the assistance from the centre. As per the state government estimates ,there is need of Rs.1,00,213 crores but the Central government has released only a fraction of that amount, about 1000 crores. This is of utmost importance as you know even to kick start basic governance functioning we need capital city infrastructure in place. The work towards the construction of the capital city has just begun and to ensure that the work does not stop we need a steady flow of funds. Telangana did not

face such a problem as they inherited our capital city but we have to bear the additional burden of constructing a quality capital city from scratch. Therefore, I request the government in to please give the assistance that the state deserves.

Overall, this is a pro-people budget and I am in complete support of it.

[*] SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL) **:** As far as overall the current year's union budget is concerned, I would like to mention that since the BJP has absolute majority and formed a stable government at the Centre, people of the country have great expectation from its budget. But the General Budget presented by hon. Finance Minister Shri Arun Jaitely has not mentioned any significant steps to solve the problem in agriculture, infrastructure, employment and other problems.

Hon. Finance Minister Shri Arun Jaitely in his budget speech mentioned that "public money should reach the poor and the deserving without any leakage." The government's move to introduce a law to give statutory backing for Aadhaar is a welcome step. Better late than never, the government anyhow realised the intention of the UPA government in bringing the Aadhaar card with an aim at expanding access to financial services to deserved people of the country.

Another important thing I would like to mention is that the proposal of tax on EPF withdrawal was taken back by the union government after receiving a number of representations from various sections, including Members of Parliament.

I would like to point out that the government should take steps for a comprehensive review of such new proposal before making any announcement.

The NDA government claims that agriculture and farmers' welfare was a pillar of the government's agenda to transform India and it would strive to double income of farmers by 2022.

In the 2016-17 Union Budget, the target for agricultural credit in the coming fiscal is an all-time high of Rs.9 lakh crore. While allocating Rs.35,984 crore for agriculture and farmers' welfare, Rs.5,500 crore has been allocated for effective implementation of the Prime Minister Fasal Bima Yojana and Rs.15,000 crore for loan interest subvention. The budget also announced an online

[*] Speech was laid on the Table.

procurement system to be undertaken through the Food Corporation of India, and other schemes for irrigation, conserving soil fertility and connectivity from farm to markets.

In this regard, I would like to point out that making announcements itself is not enough to achieve the target. As we have seen even in the third quarter of the current financial year the yield has no result. Instead, the government should ensure the budgetary allocation is fully utilized for the purpose meant for within the stipulated time.

With regard to irrigation, the union government in its budget mentioned that 89 languishing projects under Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) will be fast-tracked to help 80.6 lakh hectares. Anyhow, it is a welcome step as the AIBP scheme was implemented by the UPA government itself. Now the NDA government is taking up the projects which were undertaken under the scheme. According the budget estimates "these projects require Rs.17,000 crore next year and Rs.86,500 crore in the next five years. We will ensure that 23 of these projects are completed before March 31, 2017," I hope the government would take all necessary steps to ensure timely completion of these projects.

At present, our country has only 46 percent of the 141 million hectares of net cultivated area in the country covered by irrigation. The Finance Minister announced that Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana will be implemented in a mission mode with an aim to irrigate 28.5 lakh hectares.

With regard to Namma Metro project, the budget has earmarked only Rs.667 crore for carrying out works related to Phase-II. The Bangalore Metro Rail Corporation Limited had requested a sum of Rs.1,080 crore for the same. Since people of Bengaluru are facing difficulties in having better urban transportation due to increased population in the city, I would like to urge upon the union Finance Minister to look into it and consider to allocate the requested fund to enable the BMRC to complete the Metro project on time.

As far as education is concerned, there is no significant announcement about any massive outlay for education, health and social welfare. Creation of a Higher Education Funding Agency (HEFA) has been announced with a fund of Rs.1,000 crore. It looks that it will be mostly used to redress the problems of students seeking educational loan. Current outstanding educational loans may be around Rs.50,000 crore. It is not clear that how a fund of Rs.1,000 crore will resolve the massive requirements of educational loans.

As per the UN Human Development Index, 2015, India is lagging behind. But Union Budget presented by the Finance Minister does not show adequate commitment and financial allocation towards it to remove this malady. The United Nations Human Development Report, 2015 has ranked India on 130th position among 188 nations listed in the UN Human Development Index. Among BRICS countries , India is left behind by Russia, Brazil, China and South Africa.

The Budget has announced that 62 more Navodaya Vidyalayas will be opened in the next two years. There are thousands of government schools functioning without proper school building, there is no quality education due to poor infrastructure, lack of teaching faculty in those schools. But there are no indications how millions of government schools will be improved to provide quality school education. Right to Education (RTE) was launched in 2009 with lot of noble expectations, but the RTE scheme is losing its steam due to half-hearted implementation and lackluster execution.

During XII Fifth Year Plan, it was expected that Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) will lift our school education and higher education from the current stagnancy and will help our schools, universities and colleges to attain respectable standards. The budget proposal does not talk about RTE, RMSA and RUSA.

NDA Government has been giving emphasis on skill development since its formation; a provision of Rs.1,700 crore has been made for setting up 1,500 multi skill training institutes. It has been announced that 10 million youth will be

provided skill training under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) during 2016-19. A Digital Literacy Scheme has also been announced in the budget to cover 60 million additional households.

I would like to point out that the banks are discouraging to avail education loan for higher studies. Talented but poor students are facing difficulties to pursue higher education. I would like to say that the proposed higher education financing agency would be an economic spring for the Indian education sector. Setting up a dedicated agency would give the thrust that is needed today. Hence, I would suggest that the government should fix the target to banks in this regard. So, that it would benefit both the students as well as the financing system.

Another important point I would like to make is - we hardly have any university in top 500 universities of the world. We have a serious dearth of original research and focus on such area is forthcoming. Development of world-class teaching institutions is a dire need for the rapidly developing India. In that direction, it is good step from the Government for enabling a regulatory architecture to provide to 10 public and 10 private institutions to emerge as world-class teaching institutions. I hope it would help the Higher Education sector which has been sluggish for past few years and will get a much-needed stimulus to grow further.

The e-commerce sector in India has seen extraordinary growth, due to internet and mobile penetration, leading to an increased online consumer base. Our indirect tax system is equipped with conventional transactions involving goods and services, without focus on transactions executed online. In the absence of a defined framework on indirect taxation of such online transactions at present, e-commerce companies usually operate as marketplaces for facilitation of sale of goods or provision of services. So, there is a need to bring online transaction into the area of e-commerce taxation.

I would like to point out that the Union Government has not responded to setting up of a AIIMS like hospital in Karnataka state. I submitted representation

to request to sanction AIIMS like hospital at my Ramnagara district, Harohalli Indusitrial area in Kanakapura Taluq, which is part of my Bangalore Rural Lok Sabha constitutency. The suggested area is surrounded by Taluqs such as Ramanagara, Channapatna, Kanakapura and Magadi which have a sizeable working population and they will also benefit from this super specialty hospital.

India's public spending on healthcare is just 1.3% of the GDP. With 75% of the population outside the health insurance ambit, the government needs to put the spotlight on health insurance. As per the latest records of the World Health Organization, patients in India pay for 58% of the total healthcare expenditure. So, I would like to request the government to create better healthcare infrastructure in all the government hospitals in the country.

The union government has earmarked Rs.38000 crore for MGNREGA scheme. I would like to point out that as per the reports there are significant number of job seekers who have not got the mandatory 100 days of work. I would like to suggest the government that apart from allocating funds to MGNREGA, there is also need to ensure that mandatory 100 days of work is made available to uplift the poor from the clutches of poverty.

People voted for BJP government believing Shri Narendra Modi ji's promise of "better days" in India's 2014 general election but the very people are feeling disgusted about the way in which the NDA government is just making tall promise and nothing is visible on the ground. People have lost their hope on the NDA government even though this year's budget promised more aid to the countryside. Growing discontent in rural India, where two-thirds of the country's 1.3 billion people live, is seen every parts of the country as there is no significant change taking place since the new government came to power.

The severe drought has lead to widespread distress in many states including Karnataka. The state government of Karnataka has declared drought in 27 out of 30 districts as it received 35 percent deficient rainfall. According to reports, over thousands of farmers suicides have been reported in various parts of the country.

Hence, I impress upon the Union Government to make it mandatory to provide short term crop loan to farmers in nationalized banks. It would help to prevent farmers to borrow money from private money lenders and also put an end to incidents of farmers committing suicide.

The drought has also triggered a serious water crisis in the region. The water levels in reservoirs have decreased to alarmingly low levels. The weak monsoon coupled with this crisis has affected fodder availability for cattle. The state government is making all efforts to supply water through tankers to villages and started fodder banks to save the cattle. With the drought conditions failing to abate, the state government requested the intervention of Centre for the financial assistance of Rs.3803 crores. So far the Centre has approved Rs.1540 crores. Hence, I request the Union Government to release the required money to Karnataka to take up drought relief activities at the earliest.

*__डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर):__ 2016-17 का आम बजट माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने पेश किया यह बजट कॉमन मैन को ध्यान में रखकर किया है। इस बजट में कुछ बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं जैसे कि देश के सभी सिविल हॉस्पिटल में ''डायलिसिस'' सेंटर का शुरू करना। यह बहुत ही बड़ी बात है। आज पूरे हिन्दुस्तान में ''डायलिसिस'' की बड़ी समस्या सामने आ रही है। कम दाम में यह सुविधा अब हर जिले के सिविल हॉस्पिटल में शुरू करके लोगों के हित में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के हित में निर्णय लिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आरोग्य के लिए और एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में लिया है। ''जेनेरिक'' मेडिकल स्टोर्स हर जिले में सात से आठ सेंटर शुरू होंगे। 3000 मेडिकल जेनेरिक स्टोर्स को कम दाम में दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र लातूर में अभी शुरू भी हो रहा है। केवल ''शासकीय'' सरकारी हॉस्पिटल के रूग्णों को ही नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल के रूग्णों को भी यह सस्ती दवायें देने का काम माननीय सरकार ने किया है। मैं माननीय अर्थमंत्री अरूण जेटली जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

---

* Speech was laid on the Table.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2016-17 के आम बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। इस संसद में आजादी के बाद से लेकर अभी तक हर साल बजट पेश हुआ और हर सरकार ने अपने-अपने तरीके से काम करने की कोशिश की। लेकिन अरुण जेटली जी ने तीसरी बार जिस विश्वास के वातावरण में यह बजट पेश किया, उसकी सराहना करनी पड़ेगी। इस सरकार की पूर्ण बहुमत के साथ आने के बाद स्वच्छता अभियान से शुरुआत हुई। शौचालय, जन-धन योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, अटल पैंशन, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से इस सरकार की शुरुआत हुई। अब स्वच्छ भारत अभियान से क्या होने वाला था? इस देश में इतनी गंदगी हो गयी थी, जिसे साफ-सफाई करने की आवश्यकता थी। हमारे यहां कहावत है कि लक्ष्मी वहीं आती है, जहां स्वच्छता होती है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चालू किया और उसमें इस देश के प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, सभी मंत्रिगण और सभी मुख्य मंत्रियों ने इसमें सहयोग दिया। इसी के साथ स्वच्छता का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री जी ने वर्ल्ड में दौरे करके भारत की प्रतिमा खड़ी की, जिससे कई इन्वेस्टर्स हमारे देश में आये। इससे पहले भी बैंकों में अकाउंट खोलने के लिए किसी को मनाही थी, लेकिन किस विश्वास से बोला जाता? एक साल में 22 करोड़ लोगों ने बैंकों में अकाउंट खोले हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलेंगे, लेकिन हमारे देश के स्वाभिमानी लोगों ने 35 हजार करोड़ रुपये बैंकों में जमा किये। अब यह 35 हजार करोड़ रुपया कहां था? वह एक सामान्य किसान, मजदूर और बर्तन मांजने वाली महिला की जेब में थे। उनके शक्कर के डिब्बे, चायपती के डिब्बे में वे पैसे थे, जिसे उन्होंने बैंक में जमा किये। इस कारण लोगों में एक विश्वास आया और देश में विश्वास का एक माहौल बना।

मैं अरुण जेटली को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुद्रा योजना के लिए एक अलग बैंकिंग व्यवस्था की। अब हम सबको काम नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने सबको अपने पैरों पर खड़े करने का स्वाभिमान दिया। जन-धन योजना में भी आम आदमी को पांच हजार रुपये देकर प्रतिष्ठा बनायी। उसे क्रेडिट कार्ड दिया। आज तक देश में गरीबी हटाओ के नारे लगे, लेकिन लोगों की गरीबी नहीं हटी। लेकिन जिस आदमी में काम करने का जज्बा है, खुद के पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत है, कुछ स्किल दिखाने, कुछ व्यवसाय करने की क्षमता है, ऐसे लोगों को बिना गारंटी और बिना प्रापर्टी के पांच हजार रुपये

से लेकर दस लाख रुपये तक देने की योजना लागू की। आज हमारे देश का हर ऐसा जवान दस लाख रुपये का मालिक बना है, तो वह सिर्फ मुद्रा योजना के माध्यम से बना है।

मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा मुद्रा योजना का उद्घाटन हुआ। ...(व्यवधान) मेरी कांस्टीटुएंसी में 16,743 लाभार्थी हैं, हमने 155 करोड़ रुपया बांटा है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। ये सब प्रेक्टिकल हो रहा है। इस दृष्टिकोण से सरकार बहुत योजनाएं लाई है, लेकिन मुद्रा योजना से आम आदमी में विश्वास आया है कि वह खुद अपने पैरों पर खड़े होकर, बिजनैस कर सकता है और देश को आगे ले जा सकता है। इनमें अब यह भावना पैदा हो रही है।

अब मैं सांस्कृतिक मंत्रालय में कलाकारों का मानदेय के विषय पर आता हूं। 16,50,00 करोड़ का बजट है। देश में ये लोग अलग-अलग तरह की कला का प्रदर्शन करते हैं और जीविका अर्जन करने की कोशिश करते हैं। 3,500 कलाकारों को मानदेय दिया गया है लेकिन अभी भी बजट 16,500 करोड़ रुपए है। मेरा निवेदन है कि बजट को बढ़ाने का प्रावधान किया जाए ताकि कलाकारों को हौसला मिल सके।

मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, अरुण जेटली जी को बजट के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद।

*श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया): माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा सदन के समक्ष 2016-17 वर्ष हेतु लाया गया जनरल बजट एक व्यापक एवं दूरदृष्टि वाला बजट है। यह बजट राष्ट्रहित व देशवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। देशवासियों द्वारा इस बजट का स्वागत किया गया है। सबसे बड़ी बात इस जनरल बजट की यह है कि यह बजट भारत की प्रगति और विकास में सहायक सिद्ध होगा। मैं इसका भरपूर स्वागत करता हूँ और इस बजट के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। भारत देश में कृषि उपजाऊ जमीन के लिए केवल 50 फीसदी हिस्से को सिंचाई साधन उपलब्ध हैं बाकी 50 फीसदी बरसात पर निर्भर है, जिसके लिए इस बजट में कृषि सिंचाई सबंधी योजना लाकर सरकार ने किसानों को भरपूर लाभ प्रदान किया है, इससे किसान की मानसून पर निर्भरता कम होगी। कृषि संबंधी बीमा योजना, किसानों और आम नागरिकों को करो में छूट व ग्रामीण क्षेत्रों में मा. वित्त मंत्री जी ने कौशल विकास तथा रोज़गार सृजन के लिए विशेष घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं। जनरल बजट में सरकार ने शिक्षा व रोज़गार और युवा सशक्तीकरण के लिए प्रावधान किया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के विदर्भ सहित देश के अन्य ग्रामीण एवं अति पिछड़े क्षेत्रों, जहां पर शिक्षा एवं सुख-सुविधाओं का अभाव है, वहां के वास्ते सरकार द्वारा विशिष्ट योजनाएं लाकर स्थानीय वासियों को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है। दुर्गम क्षेत्रों एवं अति पिछड़े क्षेत्रों की समस्या जैसे पीने का पानी, कृषि सिंचाई के साधन, शिक्षा संस्थाओं का अभाव को दूर करने के वास्ते सरकार द्वारा प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है।

कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत खराब हुई फसल का शीघ्र आकलन; पीड़ितों को शीघ्र व उचित मुआवजा; तथा ड्रोन द्वारा आकलन किए जाने की आवश्यकता है। कौशल विकास के अंतर्गत युवा वर्ग को शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण; रोज़गार सृजन व स्वरोजगार; कुशल उद्यमी; स्टार्ट अप-स्टैण्ड इंडिया; तथा अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा एवं महिला-उद्यमिता की आवश्यकता है।

मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा में स्किल्ड, अनस्किल्ड रेशियो 50 : 50; मनरेगा के तहत प्रत्येक किसान को साल में 200 दिन की मजदूरी; श्रमिकों को शीघ्र व पूर्ण वेतन; तथा आने वाली शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

माननीय प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई योजना पर शीघ्र कार्यवाही करने; मानसून पर निर्भरता में कमी लाने; दुर्गम क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली जैसी सुविधाएं; तथा छोटे किसानों को शीघ्र लाभ दिए जाने की आवश्यकता है।

---

* Speech was laid on the Table.

* KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR) : I support the General Budget 2016-17 presented by the hon. Finance Minister. The Budget has unveiled a big focus on revival of rural demand through a carefully drafted focus on the agricultural sector that should strive to increase agricultural productivity. Some of the key focus areas, among others include unified agriculture market, promotion of soil health cards on a mission mode basis, expanding the net cultivable area under irrigation and routing fertilizer subsidy on a pilot basis through the DBT Scheme. The Budget has also underlined a specific focus on the social sector, that is, Education and Healthcare. The new Health Insurance Scheme and tax rebate for Senior Citizens for the pension scheme will provide succour in a country that has no comprehensive social security in place.

The Government's thrust to reorient its interventions to double the income of the farmers by 2022 seems very appealing. The Budget speech promises doubling the "income security" to farmers in the next five years. Proposals regarding Krishi Kalyan Cess of 0.5% on all taxable services for financing initiatives relating to improvement of agriculture and welfare of farmers, and the Krishi Kalyan surcharge to impose 7.5 per cent on undisclosed income towards agriculture and rural economy are welcome. While cesses are meant for complementing or supplementing the additional requirement for a specific purpose, the Government has been using cess money as a replacement of the existing allocation rather supplementing.

Budget 2016 focused on improving the quality of life for a majority of the population that lives in villages and small towns, with agriculture as its main occupation. Against the backdrop of slackening global demand, the Government aims to create a robust local market for the goods that India produces and services that it provides.

The Government committed Rs.2.21 lakh crore towards improving infrastructure, including the construction of roads, highways and railway lines. It

* Speech was laid on the Table.

also outlined a plan to partner with States to revive 160 defunct small airports. Around Rs.3,000 crore per annum will be spent over 15-20 years to develop nuclear power within the country, which is energy-starved with demand for power projected to rise exponentially. "The huge investment planned in infrastructure will create new jobs and strengthen their purchasing power. "It will also create demand for commodities like steel and power, and boost economic growth."

The decision to allow up to 100 percent FDI through FIPB [Foreign Investment Promotion Board] in marketing of food products produced and manufactured in India is progressive and will help in farm diversification, reducing wastage and encourage the industry to produce locally." "This far-reaching reform will benefit farmers, give impetus to the food processing industry and create vast employment opportunities. " "Some good initiatives around agriculture reforms, social sector spending and rural electrification will help in growing rural income and create demand for various kinds of products and services."

"Budget 2016-17 seems promising for India's youth -whether it is about the quality of education, focus on skill development, improving teaching and research outcomes, emphasis on job creation or creating ease of business to promote entrepreneurship.

A person earning Rs.1.2 crore a year will pay roughly Rs.1 lakh more as surcharge due to the hike. Our Government continues with the philosophy of making the high income earners pay more.

India is poised to become a roaring tiger on the strength of its vast domestic market and economic fundamentals. It is imperative that we use this opportunity to take the bold steps and the needed calculated risks to tide over the sluggishness in the rest of the world. It is my opinion that India is the point of inflection and this Budget has decidedly determined the coordinates of that inflection point in a positive manner.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the General Budget for 2016-17.

Sir, the hon. Finance Minister's vision and determination has not been properly reflected in this Budget. There are only some small signs of relief, emphasis on PMGSY and a new scheme namely, National Dialysis Services Programme which is good. These things deserve support from all sections.

While discussing about financial management, a close scrutiny on expenditure is very much required. Quoting C&AG, *The Times of India*, has given a report. Considering the time constraint, I do not want to quote it fully. It says that if you look at the spending pattern in the first nine months of the current financial year, it presents a different picture. Ten Ministries have not spent even half of what was allocated to them till December, 2015. At the other extreme, there are seven Ministries which have spent over 90 per cent of their funds although one-fourth of the year was still remaining. What is the reason for this paradoxical situation? This is a very important aspect which we have to look into.

In the Budget, the Finance Minister announces new programmes and fund allocation is increased to some sectors. But, unfortunately, the implementation process is very poor. This report says that in the Ministry of Overseas Indian Affairs, the expenditure in this period is only six per cent, in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, the expenditure is 18 per cent, in the Ministry of Labour and Employment it is 29 per cent and in the Ministry of Minority Affairs, it is 38 per cent. Why is it so? This has to be examined. I feel some Departments are interested only in submitting proposals for increased allocation of funds and they are not at all bothered about the expenditure. With regard to minority affairs, I feel there is a conspiracy going on as to how to create stumbling blocks in implementing the minority development programme in our country. The implementation process is very poor in this sector. Many petitions are pending before Maulana Azad Foundation for scholarship schemes etc. This has to be specially examined.

Sir, para 104 of the Budget Speech of the Minister is very good and I congratulate him for that. It says ‘for good governance, we have to capitalize on the country’s unity in diversity. To strengthen understanding of each other, it is proposed to create a closer engagement between different States and the Districts in a structured manner. *Ek Bharat Shreshtha Bharat* Programme will be launched to link States and Districts.’ This is what has been stated here. But what exactly is happening here?

I would like to tell you about these new things. You are saying, unity, diversity and all kind of things. Regarding Aligarh Muslim University and Jamia, the Government of India has given an affidavit in the Supreme Court that they are going to withdraw the minority status of these two Universities. But it is quite unfortunate. These two Universities have given tremendous contribution in the preservation of secularism and the progress of this country. Why have you taken this stand? The Government of India has given such an affidavit. I would like to tell you that the Government is violating the Constitution. The Constitution guarantees certain minority rights. You are encroaching on that. In this way, how are you going to materialize your dream of ‘Ek Bharat Shreshtha Bharat’?

Similarly, you have to take special care of minority rights. This Government’s strategies are deadly against the minorities. That is to be seriously attended to; otherwise our dreams, not only the Minister’s dream, Mahatma *ji*’s dream, unity in diversity, all these things will be spoiled. I appeal to the Government to take a serious view in this regard and ensure justice to the deprived sections of the society, especially the minorities. Thank you, Sir.

*श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** मुझे आम बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

यह बजट उस समय आया जब देश का हर नागरिक एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। किसान सूखे के दौर से गुजर रहा है। बाज़ार में मंदी से व्यापारी परेशान है। निर्यात गिर रहा है और नौज़वानों को रोज़गार नहीं मिल रहा। इस चौतरफा मार से दुखी एक आम नागरिक सरकार और उसके बजट से क्या आशा रखता है। उसकी उम्मीद होती है कि क्या उसकी आय बढ़ जाएगी, क्या बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी, उसको नौकरी के अवसर मिलेंगे और उसका जीवन आसान होगा। उसके बाद निचले और मध्य वर्ग के लोग उम्मीद करते हैं कि जरूरी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, इलाज का खर्च कम होगा। टैक्स में राहत मिलेगी। बाज़ार में मांग बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। वर्ष 2016-17 के आम बजट ने सभी वर्गों को ज़ोर का झटका दिया है। इस बजट में जहां गरीबों व किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं, तो सर्विस टैक्स बढ़कर 14.5 फीसद से 15 फीसद हो गया है। इससे हर सेवा महंगी होगी। हवाई यात्रा, रेल टिकट, केबल, सिनेमा, बीमा पॉलिसी, मोबाइल बिल, होटल का खाना, जिम समेत अन्य जरूरी सुविधाएं महंगी हो जाएंगी। बेहतर बजट की उम्मीद लगाए लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। सर्वाधिक परेशानी मध्यम वर्ग को होगी। इससे गरीब तबके के लोगों की जेब भी ढीली होगी।

दुःख की बात है कि इस बजट ने सभी को सिर्फ निराश किया है। आप घरेलू निवेश को लें या विदेशी निवेश के लिए उचित वातावरण की बात करें, घरेलू उत्पादन देखें या निर्यात में वृद्धि, सब तरफ निराशा और असफलता। यह हमेशा बड़े-बड़े शहर के लोगों की बात करने वाली सरकार को अचानक ध्यान आया कि भारत की 60 प्रतिशत से अधिक जनता गॉव में रहती है। आज किसान, कृषि और गरीब का ध्यान आ गया। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह एक अच्छी बात है। इतिहास गवाह है कि हमारी पिछली सरकारों की हर नीति और हर योजना किसानों के हित के लिए और गरीबी हटाने के लिए inclusive growth में विश्वास रखती थी।

बजट में कृषि क्षेत्र व किसानों के लिए काफी कुछ कहा गया है, यह कहना आसान है, लेकिन यह नहीं बताया कि इसको अमल में कैसे लाएंगे। बजट में किसान की आय आने वाले पांच वर्षों में दोगुनी करने का जो सपना दिखाया। यह वैसा ही जैसे Black Money वापस लाकर हर जेब में 15-15 लाख रूपए डालने का वायदा किया था। यह फसलों का समर्थन मूल्य बिना बढ़ाए, फसल लागत को बगैर घटाए कैसे संभव हो पाएगा। Fertilizer subsidy में Rs. 2000 crores की कटौती कर के किसान का भला

* Speech was laid on the Table.

कैसे होगा, मंत्री जी ही बता सकते हैं। जेटली जी नहीं बताना चाहते की जादू की कौन सी छड़ी घुमाएंगे और सब अपने आप हो जाएगा? कोई Road map तो होना चाहिए ना?

किसान कल्याण के नाम पर 0.5 प्रतिशत Cess लगा दिया उससे 5000 करोड़ रूपए मिलेंगे। किसानों की जेब से निकाल कर उन्हीं पर खर्च किया जाएगा।

कितनी आश्चर्य की बात है कि बजट Speech में किसानों के द्वारा आत्महत्या का कोई जिक्र नहीं। वित्तमंत्री कहते हैं कि उन्होंने कृषि को अभी तक का सबसे बड़ा 35,984 करोड़ रूपए का फंड दिया है। सच्चाई कुछ और है। Numbers के गोलमाल में माहिर इस सरकार ने 15,000 करोड़ रूपए के 'interest subvention' को वित्त मंत्रालय से हटा कर कृषि में दिखा दिया। यानि कृषि को असली allocation केवल 20,984 करोड़ रूपए का ही है जो यू.पी.ए. द्वारा दी गई 2013-14 की बजट धनराशि से कम है। देश के 86 प्रतिशत किसान Small and Marginal farmers हैं। बजट मे उनके लिए कुछ भी नहीं रखा। खुशी की बात है कि जब कुछ अच्छा याद आया तो यू.पी.ए. की A.I.B.P. योजना को फिर से जीवित करके 89 मुख्य सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए 17,000 करोड़ रूपए रखे हैं, जो बहुत कम है। अगर यह राज्यों को बांटा गया तो उनका शेयर कुछ भी नहीं बनेगा। हमारा कहना है कि इस योजना को 3 वर्षों में पूरा कर दिया जाये।

ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा शोर है। हालत यह है कि ग्रामीण मांग गिर कर सबसे निचले स्तर पर है। Labour Bureau के ऑकड़े बताते हैं कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार, unskilled casual workers की Novermber 2013 से November 2015 के बीच आय (मजदूरी) real terms में 2.14 द्रङ्खद्ध cent per annum गिर गई। 2013 से पिछले 5 सालों में यह 6 per cent per annum की दर से बढ़ी और ऐसा rural demand और सरकार का ग्रामीण क्षेत्र में खर्च बढ़ने के कारण हुआ।

MNREGA इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस योजना के महत्व को समझा। यह demand and increased wages का एकमात्र स्रोत है। इसके लिए 38,500 करोड़ रूपए का बजट रखने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि यू.पी.ए. ने 2010-11 में इस योजना को ङ्क. 40,100 crores allocate किये थे। वित्त मंत्री कहते हैं कि खर्च कम हुआ था। मेरा कहना है कि पिछले 5-7 सालों में MNREGA में minimum wages 40% से अधिक बढ़े, यदि आपका budget allocation UPA के level पर है तो financial और physical progess कहाँ से होगी और man-days कैसे बढ़ेंगे? आपके Chief Economi Advisor का ही कहना है कि यू.पी.ए. के समय में 2005 और 2012 के बीच गरीबी कम होने की गति भारत के इतिहास

में सबसे तेज रही है। ये पिछले दशक से दो गुना तेज था। 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी से हटाया गया इन 8 सालों में। गरीबों की हालत सुधारने के ग्एग़्ळ्रस्ए लिए के ज़रिए आपको भी ऐसा ही करना होगा।

Nirmal Bharat Abhiyan की repackaging करके Swacch Bharat Mission बनाकर और 150 प्रतिशत allocation बढ़ाकर चालू करने का स्वागत है। लेकिन यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर देखें, तो RE 2015-16 के मुकाबले यह 5 प्रतिशत कम है। आपको मानना होगा कि यह एक राजनीतिक बजट है। सरकार देश में जनता के सामने चुनावी बजट लाकर एक और जनता को खुश करना चाहती है तो दूसरी ओर विदेश में अपनी साख बनाने के लिए 'मूडी जी' को attract करना चाहती है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। यू.पी.ए. की योजनाओं का नाम बदल दिया और बड़े-बड़े खोखले वायदे जोड़ दिए। आज जो अच्छे नतीजे दिखाई दे रहे हैं वह यू.पी.ए. सरकार की सही नीतियों के कारण हैं और यह एन.डी.ए. सरकार भी मानती है, लेकिन जनता को बताने से शर्माती है।

शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह बजट निराशाजनक है। आपके सलाहकार भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ Privatization के लिए हो रहा है। जनता के भले के लिए यू.पी.ए. की योजनायें ही अच्छी हैं। बजट में बदलाव जो 5 राज्यों के चुनाव को सामने रखकर बनाया गया है। आम जनता के हित में नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए इस बजट में वित्त संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हज़ार करोड़ का प्रबंध है। पिछले वर्ष के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र की राशि में जिस तरह की भारी कटौतियॉं की गई थी, वर्ष 2016-17 के बजट में तकरीबन उसी रूझान को बरकरार रखा गया है। पिछले वर्ष की कटौतियॉं इतनी ज्यादा थीं कि इस वर्ष के Allocations के आंकलन के लिए पिछले बजट को तुलना का आधार बनाना भ्रामक होगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट में 330 राज्य विश्वविद्यालयों और 35,829 कॉलेजों के बारे में भी कुछ नहीं कहा। ये शिक्षण संस्थाएँ 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और वर्तमान में जर्जर हाल में हैं। आपको Crude Oil (पेट्रोलियम) से जो बचत हुई है, उस पैसे को शिक्षा और स्वास्थ्य (हैल्थ) के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गुलबर्गा जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में जहां कम से कम 40 विभाग होने चाहिए, अभी केवल 10 हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कम बजट होने से ऐसा हो रहा है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें नागरिकों के सशक्तिकरण और विकास की विषमताओं को दूर करने के लिए उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है। इस लिहाज से सरकार का दायित्व बनता है कि वह

सकल घरेलू उत्पाद (स्न्.द्द) का कम से कम 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में निवेशित करे; लेकिन वर्तमान में इस निवेश का 1 प्रतिशत से भी कम होना चिंता का विषय है। लगभग यही स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र की है। Health care industry में सरकार ने medical equipment and devices के आयात शुल्क में वृद्धि के मसले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इससे healthcare की cost बढ़ जाएगी और इसका असर गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। देश की जनता के लिए बीमा योजना लागू की गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार healthcare से मुंह मोड़ ले। National health Mission के लिए पिछले 19,135.37 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 2016-17 में 19,437 करोड़ रूपए किया गया है, जो केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि है। लगभग यही स्थिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व Mid Day Meal योजना की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में पिछले साल लगभग 52 प्रतिशत की कटौती की गई थी। इस वर्ष पिछले बजट के संशोधित संस्करण से 30 फीसदी अधिक अनुदानों की पेशकश की गई जो यह भ्रम पैदा करती है कि इस काम के लिए बजट बढ़ाया गया है जबकि ऐसा नहीं है। इससे जाहिर होता है कि सरकार दिखावे के लिए कहती कुछ है और करती कुछ और है।

इस बजट में मई 2018 तक सभी गॉवों में बिजली पहुॅचाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, लेकिन ग्राम ज्योति योजना जैसी व्यवस्थाओं के आवंटन में पिछले साल की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत की कटौती की गई है। अन्य महत्वपूर्ण कटौतियों में अनुसूचित जाति उपयोजना व जनजातीय उपयोजना शामिल हैं; जिनमें क्रमशः कुल योजना परिव्यय का सिर्फ 7 फीसदी व 4.4 फीसदी हिस्सा आवंटित है, जो जनसांख्यिक अनुपात के आधार पर निर्धारित उनके हिस्से से लगभग 75,764 करोड़ रूपए कम है, इससे भी यही विदित होता है कि इस सरकार की मनोदशा दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कैसी है।

देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 4.7 लाख करोड़ रूपए का एन.पी.ए. है और इसके लिए सिर्फ तीन वर्षों के लिए मात्र 75 हज़ार करोड़ रूपए आवंटित किये गये हैं, जबकि बैंकों के लिए कम से कम 1.8 लाख करोड़ रूपए का आवंटन जरूरी था। आश्चर्य की बात है कि रक्षा (Defence) बजट के मुद्दे पर सरकार ने चुप्पी साध ली। जनता को कुछ बताया नहीं। (क्ष्ड्ड) 2015-16, के अंत में capital budget का 40 % (Rs. 37,000 crore out of Rs. 93,675 crore fund) बचा रहा जो किसी भी January-March 2016 quarter, में खर्च नहीं हो सकता। अतः Rs. 15,000 to Rs. 20,000 crore (15 to 20 per cent) वापस करना पड़ेगा। रक्षा के क्षेत्र में क्या यह ठीक है। प्रमुख मुद्दों पर सरकार चुप रहना चाहती है और रक्षा के क्षेत्र पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया। रूपये की कीमत गिरने से purchasing power भी गिर गई। Inflation के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हथियार,

ammunition, और रक्षा उपकरण 12 से 15 प्रतिशत तक हर साल महंगे हो जाते हैं। बजट को कम दिखाने के लिए रक्षा के क्षेत्र को भी नहीं बख्शा। रक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की गति बहुत धीमी है। पुराने हथियारों और उपकरणों को बदलने के लिए कम से कम जी.डी.पी. का 3.0 प्रतिशत खर्च होना चाहिए जो अभी केवल 2.3 प्रतिशत है। An amount of Rs. 6000 Crore has been projected for sustainable ground water resource management. This however, needs to be supported trhough regulatory legislation to ensure sustainable extraction. आंध्रप्रदेश को स्पेशल Package देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। पिछले क्षेत्रों के लिए जो Provision किया जाता था, वह भी निकाल दिया।

The Union Budget 2016-17, addressess the key issues of indoor air pollution in rural households by emphasizing on improved access of subsidized LPG to BPL rural families- an allocation of Rs. 2000 crore has been made. Given the pratical difficulties of putting in place the supply chain quickly, it would have been prudent to also focus on other options also including improved cookstoves using locally available biomass. There are major reductions in some of the key programmes related to children belonging to minorities like 'Pre-Matric Scholarship for Minorities' (reduced by 10.48%), 'Post Matric Scholarship for Minorities' (reduced by 5.19%), 'Scheme for Providing Education to Madrassas/Minorities' (reduced by 68.04%), 'Incentive to Children of Vulnerbale Groups among Schedule Castes' (reduced by 90%). 'Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme' also saw a significant 25 percent reduction against the previous year's allocation.

यह सारी बातें जो बजट में आई हैं, जाहिर है यह सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी सूट-बूट की सरकार ही है और किसान, महिलाओं, पिछड़े वर्ग और विद्यार्थियों के सिर्फ आंकड़ों को दिखाकर जनता में यह भ्रम पैदा कर रही है कि बजट में उनके लिए बढ़ावा दिया गया है। असल में सरकार गरीबों की थाली में कुछ नहीं दे रही और अमीरों की जेब से कुछ निकाल नहीं रही।

असलियत यह है कि तीसरा बजट भी निराशाजनक है।

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) :** मैं मान्यवर वित्तमंत्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किये गये आम बजट 2016-17 का समर्थन करती हूँ।

भारत के हर क्षेत्र के निवासी की आशा अपेक्षाएं इस सरकार के आने से बढ़ी हैं। लोगों को मान्यवर प्रधानमंत्रीजी नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व में एक विश्वास और यह सरकार अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम होने का विश्वास दृढ़ हो रहा है। इसीलिए पिछले साल में सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में जो-जो योजनाएं घोषित की है उन योजनाओं को जनता का भरपूर साथ एवं प्यार मिला है। फिर चाहे वह जनधन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो या 75 लाख लोगों का गैस की सब्सिडी त्यागना या अन्य योजनाएं, लोगों ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया है वह दिखाता है कि अगर विकास करने की चाह सरकार प्रमाणिकता से रखती है तो जनता भी उसी प्रकार जुड़ती है और उन सरकारी योजनाओं को सफल भी बनाती है। मेरा शहर सूरत हीरे, टेक्सटाईल, जरी, सूरतवसियों का मनमोजीलापन, उनकी रहनसहन और खाने की अलग पहचान, लोगों को मदद करने हेतु सदैव आतुरता वगैरह के कारण पहचाना जाता है। आपत्ति को अवसर में पलटना सूरत की पहचान है। यहां पर हीरे की बात करें तो 7 डीटीसी होल्डर हैं। करीब 4500 छोटे बड़े यूनिट हीरे को तराशने का कार्य करते हैं। जो करीब दो लाख करोड़ का टर्नओवर और एक्सपोर्ट करते हैं। 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से हीरा रोजगार देता है। मुझे प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना है साथ ही साथ हमारे हीरा उद्यमियों ने बहुत ही उत्साह से करीब करीब अपने सभी कारीगरों को इन योजनाओं का सुरक्षा कवच प्रदान किया है।

सरकार सिर्फ इतने भर से न रुकी पर इस बजट में जो स्वास्थ्य संबंधी बीमा योजना लागू करने जा रही है उसका भी मैं स्वागत करती हूँ। जिस योजना के तहत देश की एक तिहाई आबादी को अस्पता के व्यय के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने का आयोजन है। जिनका मैं स्वागत करती हूँ। जिससे आम आदमी को, गरीब परिवारों को अपने स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ आरोग्य सुविधा लेने में कोई झिझक नहीं रहेगी। मेरा विश्वास है कि जनता इस योजना को भी उत्साह एवं उमंग से स्वीकार करते हुए भारत के विकास को आगे ले जाने में अपना सहयोग देगी। बीपीएल परिवारों को

---

* Speech was laid on the Table

महिला के नाम पर सिलिन्डर देने की योजना से स्वास्थ्य में तो सुधार आयेगा ही परन्तु आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा, महिलाओं का अपने परिवार में सम्मान बढ़ेगा और इस स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आयेगा। सरकार का स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय डाईलिसिस सेवा कार्यक्रम की भी मैं स्वागत करती हूँ इससे किडनी के रोगियों को एवं उनके परिवारों को सहूलियत मिलेगी।

मेरा शहर कपड़े के कारण भी जाना जाता है जहां पर 6 लाख पावर लुम्स है, 400 प्रोसेसिंग हाउस है, 1 लाख से ज्यादा एम्ब्रॉईडरी मशीनस हैं, रोजाना 4 करोड़ मीटर कपड़ा मेरे शहर के करीब 6 लाख सीधे जुड़े हुए एवं 4 लाख परोक्ष रूप में जुड़े हुए कारीगर तैयार करते हैं। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम से मेरे शहर के युवा एवं विद्यार्थियों को स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया - स्टेंडअप इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं में उत्साह, उमंग को बढ़ावा देती है इन कार्यक्रमों के कारण से शहर में भी रोजगारी के अवसर बढ़ेगे क्योंकि सूरत ऐसा शहर है जहां शायद ही देश का कोई भी जिले का व्यक्ति काम ना करता हो। रोजगारी प्राप्त करता ना हो, विशेषकर टेक्सटाईल एवं हीरे के क्षेत्र में इन कार्यक्रमों का सकारात्मक असर दिखाई देगा। हर योजना को हमारी योजना बताने वाले पुरानी योजना के कार्यान्वयन में उनकी लापरवाही को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते। यह इस बात का उदाहरण है। माननीय अटलजी की सरकार के वक्त सूरत का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीमान् काशीरामभाई राणा द्वारा टेक्सटाईल अपग्रेडेशन फंड की योजना चलाई गई थी आज इस योजना में लोगों को जो आर्थिक लाभ होता है उससे वे अपने धंधे को आगे ले जाने में काम आता है। लेकिन आप की सरकार ने इस योजना के पैसे ही रिलीज नहीं किये थे। इस सरकार द्वारा करीब 12 हजार करोड़ के पैकेज को रिलीज करना आनंद की बात है। मैं विशेषकर उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ क्योंकि इससे शायद सबसे ज्यादा फायदा मेरे शहर को मिलेगा।

साथ ही साथ मेरा शहर जो एक समय गंदे शहरों में गिना जाता था आज दुनिया के श्रेष्ठ शहरों में अपना पैर जमाकर खड़ा है। तो उस शहर को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित करने के लिए मैं मान्यवर प्रधानमंत्री जी एवं सरकार का आभार प्रकट करती हूँ। सूरत जो सोने की मूर्त के नाम से पहचानी जा रही थी, वो अब स्मार्ट सूरत, सुंदर सूरत के नाम से जानी जायेगी। मैं स्मार्ट सिटी में सम्मिलित करने के कारण सूरत शहर में सुविधाएं बढ़ेगी, पर्यटन को बड़ा फायदा होगा। स्मार्ट सिटी

हेतु जो मानदण्ड आपने तय किये हैं मुझे विश्वास है कि मेरे शहर के नागरिक राज्य एवं केन्द्र सरकार की कसौटी पर खरे उतरेंगे।

मैं मान्यवर वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का स्वागत एवं समर्थन करती हूँ।

*[*]**श्री राम टहल चौधरी (राँची) :** आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में माननीय वित्त मंत्री जी ने 2016-17 का बजट प्रस्तुत किया है इसका मैं समर्थन करता हूँ। इस प्रस्तुत बजट में सरकार की प्राथमिकता देश की बहुसंख्या किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा कमजोर वर्गों पर केन्द्रित है इसमें उनके कल्याण पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। देश की ग्रामीण व्यवस्था की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने का ध्येय स्थापित करने के लिए ग्रामीणों के लिए कई योजनाएं इस बजट में रखी है। भारत गांवों में बसा है और ग्रामीण विकास से देश के विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज देश में किसान बहुत हतोत्साहित है, सूखे एवं बाढ़ की मार से किसानों की आय में 50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी ने किसान और खेतीबाड़ी पर मेहरबानी की है। किसानों के अलावा छोटे करदाताओं को भी इस बजट से राहत मिली है। 5 लाख से कम आय वालों को इस बजट से तीन हजार का फायदा हो रहा है, इससे 2 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।

देश के गांवों के विकास के लिए सरकार ने 87,700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। ग्राम पंचायत और अन्य निकायों के विकास हेतु 2 लाख 87 हजार करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र विकासोन्मुखी होगा। देश के गांवों से पलायन को रोकने के लिए मनरेगा अच्छा काम कर रहा है इसमें कुछ कमियाँ है, उसमें सुधार किया जाना अति आवश्यक है। इस बजट में मनरेगा पर 38000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। गांवों में तालाब और ग्रामीण सड़कों पर अच्छा काम हो रहा है। जो गांव बिजली न होने से अभी भी अंधेरे में है उन सभी गांवों में विद्युतीकरण किये जाने का ऐलान किया गया है देश के गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 27 हजार करोड़ दिए जाएंगे इससे किसानों को अपना माल मंडियों तक पहुँचाने में आसानी होगी इससे किसानों को अपनी फसल को मुनाफाखोर और बिचौलिया को नहीं बेचने पड़ेगा और किसानों को उनकी फसल की लागत से ज्यादा मूल्य मिल पाएगा।

---

[*] Speech was laid on the Table

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है इसके लिए कृषि क्षेत्र को 35,984 करोड़ का आबटन दिया गया है। देश में सूखे की मार झेल रहे किसानों को 28.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचित किया जाएगा। मैं झारखंड क्षेत्र से आता हूँ जहां पर कई सालों से किसान सूखे से प्रभावित हैं किसान अपने खेतों की फसल में बीज बोने और खाद दिये जाने के बाद पानी के न होने से उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है जो इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खेतीबाड़ी में रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता कम हो रही है। खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जा रहे हैं इससे भूमि की जाँच समय-समय पर करवाने के लिए एवं मृदा कार्ड के लिए 14 करोड़ का दिये हैं।

किसानों को उनकी फसल की लागत से ज्यादा मूल्य मिले इसके लिए एग्रीकल्चर मार्किटिंग के लिए ई प्लेटफार्म स्थापित किये जाने का विचार है इससे डिजिटल के माध्यम से किसानों की फसल मुनाफे में बेचने के अवसर मिलेंगे। प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बरसात से राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का श्री गणेश किया है इससे किसानों को कम प्रीमियम देना होगा पर किसानों को हुए नुकसान के लिए अधिकतम मुआवजे के रूप में पैसे मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 5500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विकास के लिए लोन की अत्यंत आवश्यकता है पूर्व में किसानों को लोन के लिए साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था और यही साहूकार किसानों का खून चूसने का काम करते हैं इससे सरकार ने राहत पहुँचाने के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये रखा है और दलहन और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ दिये हैं इससे बढ़ती दालों की कीमत को रोका जा सकता है।

देश के विकास को बढ़ाने और लोगों को खुशहाल रखने में शिक्षा और स्वास्थ्य का काफी महत्व है। देश में अभी ऐसे कई स्थान हैं जहां पर साक्षरता का स्तर कम है सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए खर्च की राशि 22500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है उच्च शिक्षा ऋण के लिए इस बजट में एक हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी प्रतिभाएं हैं और प्रतिभाओं की खोज के लिए ग्रामीण छात्रों की पहचान कार्य को बढ़ावा दिये जाने के लिए

जहां पर नवोदय विद्यालय नहीं है वहां पर 62 नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने का कार्य किया जाएगा। हैफा यानी शिक्षा वित्त पोषण एजेन्सी का गठन किया जा रहा है जिसके माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये से उच्च शिक्षा का ढांचा सुधारने हेतु निवेश किया जाएगा। यह संगठन बिना लाभ बिना हानि के आधार पर क्रियान्वित होगा। बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 28010 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी के कौशल विकास के कार्य को बढ़ावा दिये जाने हेतु अनेक उपाय इस बजट में किये गये हैं एवं सरकार के प्रयासों से अभी तक 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1500 संस्थान स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए 1700 करोड़ रुपये रखे गये हैं। नेशनल बोर्ड द्वारा एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने का आश्वासन दिया गया है। देश के विकास में सहायता मिलेगी। शिक्षा के साथ भोजन यानी मध्याह्न भोजन योजना पर 9700 करोड़ रुपये का खर्च किये जाने का प्रावधान है। देश में मध्याह्न भोजन में कई गड़बड़ियों के समाचार सुनने को मिलते हैं इस संबंध में सख्ताई से जाँच की जानी चाहिए।

देश के लोगों का स्वास्थ्य का बनाये रखने के लिए इस बजट में काफी प्रावधान रखे हैं। देश में प्रति वर्ष 2.2 लाख मरीजों की संख्या हर साल के हिसाब से बढ़ रही है। केन्द्र सरकार द्वारा इस बजट द्वारा देश के जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं शुरू करने का विचार है, गरीब और मध्यम वर्ग डायलिलिस का खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं है। इस बजट के माध्यम से नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करने का विचार है जिसमें प्रति परिवार को एक लाख रुपये से कवर किये जाने का विचार है।

बजट में वित्त मंत्री जी ने बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी का तोहफा दिया है। अगले दो साल में बीपीएल परिवार के पाँच करोड़ घरों में एलपीजी पहुँचाने का लक्ष्य रखा है इससे लकड़ियों को जलाने के बाद जो प्रदूषण हो रहा है उसको दूर करने में मदद मिलेगी। एक अनुमान है कि एक घंटे लकड़ी का चूल्हा जलाने पर 400 सिगरेट जलाने के बराबर धुंआ निकलता है।

मेरे गृह राज्य झारखंड जो सूखे की चपेट में बार-बार आ रहा है जिसके कारण यहां के किसानों की हालत काफी दयनीय हो गई है इस संबंध में मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि झारखंड में जो सिंचाई योजनाएं चल रही हैं उनके लिए अलग से अधिक धन उपलब्ध कराने की

कृपा करें जिससे किसानों को खेती के लिए समय पर पानी मिल सके। झारखंड में ग्रामीण सड़कों की हालत अन्य राज्यों से बहुत खराब हैं और बरसात के समय ग्रामीणों को कई कठिनाई का सामना करना पड़ता है झारखंड को सड़कों के विकास एवं निर्माण धन की काफी आवश्यकता है। मेरा संसदीय क्षेत्र झारखंड के बीचोंबीच में है एक छोर से दूसरे झारखंड के जाने वाले वाहन राँची से ही गुजरते हैं जिसके कारण राँची की सड़कों पर घंटों जाम बना रहता है और कई दुघर्टनाएं भी होती हैं। राँची शहर में यातायात को कम करने के लिए राँची रिंग रोड बनाया जा रहा है जो काफी समय से लम्बित है इसके लिए केन्द्र स्तर पर मदद की जाये।

सरकार का पूरा प्रयास है कि वृद्ध एवं वृद्धा, विकलांग लोगों को एवं विधवा महिलाओं इत्यादि सभी को विधवा पेंशन सुविधा मिले परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है इस संबंध में यह प्रावधान बना रखा है कि जिन वृद्ध एवं वृद्धा, विकलांग लोगों एवं विधवा महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड है उन्हें यह पेंशन की सुविधा मिल पाएगी अगर इन वर्गो के पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो इन वर्गों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन नहीं मिल सकती है। दुख के साथ सरकार को सूचित करना पड़ रहा है इन वर्गो के बीपीएल कार्ड भी नहीं बनाये जा रहे हैं जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। यह बताते हुए खेद महसूस हो रहा है कि जो बीपीएल कार्ड के पात्र नहीं है उन लोगों के पास बीपीएल कार्ड है और जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि बजट के माध्यम से राशन कार्ड को जारी करने में नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाये और जाली राशन कार्ड को रद्द किया जाये।

मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की दुर्दशा की तरफ दिलाना चाहता हूँ यह राष्ट्रीय राजमार्ग कई राज्यों को जोड़ने का काम करता है जिसमें पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा प्रमुख है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड राँची से बहेरा गोडा पर बड़े वाहन एवं यातायात भी बहुत चलता है इस बेहरा गौडा से राँची के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर चार लेन वाला मार्ग बन रहा है परन्तु खेद है कि जिस ठेकेदार को यह कार्य दिया हुआ है वह इसे धीमी गति से बना रहा है जो कार्य एक साल में बनना है ठेकेदार 12 साल लेगा। आवश्यकता इस बात की है कि इस ठेकेदार के कार्यो की जाँच की जाये और जनहित में इसे तुरन्त हटाया जाया। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द बनाने हेतु बजट के माध्यम से अधिक धन दिये जाने का प्रावधान किया जाये।

मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र राँची में स्थित हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मजदूरों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है और रिटायर्ड मजदूरों एवं कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्हें कई साल तक पेंशन एवं बकाया राशि नहीं मिला है जिनके कारण उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको वेतन एवं बकाया राशि और पेंशन समय पर मिले इसके लिए बजट में प्रावधन किया जाये।

मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री धर्मवीर (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आम बजट रखा है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं नया सदस्य होते हुए भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह तीसरा आम बजट है और इस बजट की न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष का हर व्यक्ति भी तारीफ करता है और खासकर गांव में रहने वाला आदमी भी इसकी तारीफ करता है।

आप किसी भी प्रदेश के किसी भी गांव में जाएं, तो आम आदमी की जुबान पर है कि यह बजट ऐसा बजट है जिसकी वजह से गांव का किसान और मजदूर आवश्यकता के अनुसार उस गाव का विकास भी कर सकता है और उस गांव की स्थिति भी सुधर सकती है।

जिस प्रकार से आर्थिक मंदी के बावजूद इस बजट का बड़ा हिस्सा माननीय वित्त मंत्री जी ने खेतीबाड़ी के लिए दिया है। एक समय के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान, जय किसान कहा था। चूंकि किसान ही इस देश में अन्न का उत्पादन करता है और उसी किसान के घर से जवान पैदा होता है जो देश की रक्षा करता है जहां वन रैंक, वन पेंशन के माध्यम से हमारे वित्त मंत्री जी ने इसका समाधान किया है। मेरी इसके साथ ही यह सरकार से प्रार्थना है जो जवान शहीद हो जाता है, उसकी शहीदी का सम्मान बढ़ाने के लिए इसमें कुछ न कुछ प्रावधान किया जाए, ऐसी मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है।

जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र और गांवों के विकास के लिए आपने इतना बड़ा बजट रखा है। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के बाद हर गांव में जिस प्रकार से 80 लाख रुपया जाएगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार को भी कहें कि वह भी अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस का पैसा इकट्ठा करके योजनाबद्ध तरीके से पूरे पांच साल का अगर वह प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पूर्ण रूप से शहर की तरह उसका विकास न हो।

गंगा सफाई अभियान के लिए आपने इतने बड़े बजट का प्रावधान किया है, लेकिन मेरा छोटा सा सुझाव है कि जिस प्रकार से रोड और रेल कनैक्टिविटी के लिए इतना भारी बजट आपने पहली बार रखा है जिसकी वजह से सारे देश का विकास सड़क और रेल के माध्यम से होगा। मेरा छोटा सा सुझाव है कि इसी प्रकार से यदि किसानों को बचाना है तो किसानों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, नदियों को जोड़ने का जो सपना माननीय वाजपेयी जी का था और हमारे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का भी है, उसको इम्पलीमेंट करने के लिए, नदी जोड़ने का एक मंत्रालय किसी प्रकार से होना चाहिए।

हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन यह महकमा रोड, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाए तो जिस प्रकार से सड़कों का काम तेजी से हुआ है, उसी प्रकार से जल मार्ग, रोड्स और इसी

प्रकार से नदी जोड़कर किसानों को अगर आप पानी देंगे तो खासकर पश्चिमी भारत, यू.पी., हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक जो शारदा गंगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे इलाके में पीने का पानी भी खत्म होने जा रहा है।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज के दिन ही हमारे पड़ौस के पुराने पंजाब ने एक फैसला किया है कि 40 साल पहले हमने जमीन एक्वायर की थी। वहां पर 90 प्रतिशत नदी का और नहर का काम हो चुका है लेकिन उन्होंने डीनोटिफाइ करने का जो काम किया है, यह देश तोड़ने का काम है। किसी प्रकार से पंजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए वर्ना यह एक ऐसी शुरुआत होगी जिसकी वजह से संवैधानिक ढ़ांचा खराब हो जाएगा। जो स्वर्णकार का आंदोलन चल रहा है, इसमें गरीब आदमी ही नहीं हैं बल्कि आम आदमी भी जब सामान लेने जाता है, उनके पास पैन कार्ड नहीं होता, इसका समाधान जरूर किया जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Thank you, Chairman, Sir, for allowing me to speak on discussion on the General Budget 2016-17.

The Central Government has presented its 3rd General Budget 2016-17. India is the first democratic country with the highest population in the world. Though there are vast human resources in India, still two out of four are under poverty. In this regard, the Budget that benefits the poor and middle class people are said to be a good Budget.

Though the Government says that our country's economy is growing very fast, yet it is very backward in giving employment and implementing people welfare projects and schemes. The Government is talking about the welfare of farmers as agriculture is the backbone of this country. But there is nothing in this Budget for development of agriculture and farmers. In this Budget, there is nothing good for the farmers, who are already suffering under huge debt. Some of them have committed suicide due to distress. Loans for industrialists have been waived off but there is no loan waiver scheme for farmers, who are living in a pitiable condition. The middle class and the poor people, who voted for this Government, have totally been ignored.

Higher allocation for irrigation is welcomed. We have to see its implementation because only then the real goal will be achieved.

The Government has been raising its irrigation spending every year but they have failed to bring any extra area under the irrigation scheme. How does higher allocation help Agriculture? It is disappointing to see that there is no encouragement for agri-biotech research by public or private institutions for growing the agriculture sector. We further believe that for transforming the Indian agriculture, countering the ill-effects of climate change, improving livelihoods and addressing food requirements of the nation, technological intervention is of utmost importance. There is no mention of any new scheme for industrial growth. Announcements like increase in funds for MNREGA are welcomed. No visionary

schemes have been announced for Defence sector. No schemes have been announced for the growth of economy. Health Insurance announcements are quite welcomed. While the spending on health care has gone up, we will have to wait and see how many of the initiatives announced actually reach the people.

The Integrated Defence Staff have said that their demand of Rs. 31 lakh crore worth of acquisitions are still pending over the last 15 years. The Government has not announced any clear strategy on its disinvestment policy.

An increase in Income Tax Slab was eagerly awaited by the common man. The same has not happened. It could have increased liquidity. Jewellers are to go on strike against the announcement in the Budget of Rs. 1 lakh cap on cash purchase of jewellery.

No other State in the country is as 'debt-stressed' as West Bengal because of the gross misrule of the previous Left Front Government for long 34 years. I once again urge upon the Central Government on behalf of my Chief Minister Mamata Banerjee to stop deducting funds to the State Government and give immediate relief from the debt burden, so that growth and development efforts continue to be unhindered.

Thank you, Sir.

***श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर)** : 2016-17 का जो आम बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जेटली साहब के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें हर प्रकार के संभव प्रयास किया गये हैं जो जनहित में है एवं सराहनीय है, जिसमें मंद वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को दैदीप्यमान प्रकाश स्तम्भ के रूप में आई.एम.एफ द्वारा भी सराहना की गई है। सरकार ने पिछले दो वर्षो से मानसून के प्रतिकूल 13 प्रतिशत कमी के बावजूद भी बेहतर वृद्धि प्राप्त की है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा में काफी सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं, पिछले कुछ वर्षो में किसान द्वारा घटित घटना को देखते हुए/गरीब जनता के लिए खर्च से बचने के उपाय स्वास्थ्य बीमा योजना को सृजित कर नयी उपलब्धि दी गई है। बी.पी.एल. परिवार को रसोई गैस कनेक्शन दिया जाना, गरीब लोगों के चूल्हे जलाने तक विशेष ध्यान रखकर अनेकों उपलब्धियों को सरकार ने आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है।

शिक्षा मंत्री से मेरी गुजारिश है कि जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़) में नवोदय विद्यालय खोले जाने की अति आवश्यकता है। सिम्स अस्पताल बिलासपुर में 150 सीटें हैं, जिन्हें 200 सीट किया जाये और साथ ही पी.जी. क्लास खोलने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। बिलासपुर में एयरपोर्ट की स्थापना की जाए। छ.ग. राज्य बनने के बाद भी आज तक यहॉ प्रशासनिक अभिकरण नहीं है। चूंकि बिलासपुर में छ.ग. का हाईकोर्ट है न्यायिक हब के रूप में पृथक छ.ग. के लिए प्रशासनिक न्यायिक अभिकरण बिलासपुर में स्थापित किया जाए।

---

* Speech was laid on the Table

*__श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) :__ मैं बजट 2016 पर अपने विचार रखता हूँ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा और दशा के संबंध में एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है जिसका मैं समर्थन करता हूं। यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित आम लोगों के लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं अपने सभी विपक्षी साथियों से भी अपेक्षा करता हूं कि विकास के इस सिद्धान्त **"सबका साथ सबका विकास"** को सार्थक करने के लिए सरकार का सकारात्मक सहयोग करें।

हमारी सरकार बजट के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करने हेतु कृतसंकल्प है जो वास्तव में राष्ट्रनिर्माण की कड़ी भी है। हमारा बजट गांव-गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि, युवा बेरोजगारों को रोजगार, सबको सामाजिक सुरक्षा तथा झोपड़ी एवं खुले आकाश के नीचे रहने वाले सभी वर्ग के गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के मद्देनज़र बजट में अनेकों योजनाएं लाई गई हैं जिनसे राष्ट्र निर्माण को तीव्रगति मिलेगी।

इसके अलावा **"मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया"** के द्वारा व्यापक रोजगार सृजन की राह प्रशस्त हो रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं अनुसंधानों को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा कुपोषण को जड़ से खत्म करने हेतु इस बजट के द्वारा कृत-संकल्प है।

मैं वित्त मंत्री जी को एक बहुत ही बढ़िया बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा साथ ही अपने अपने सभी संसद सदस्यों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद-विवाद करना चाहिए जोकि लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बेबुनियादी मुद्दों को लेकर संसद की कार्यवाही में अवरोध पैदा करके संसद की कार्यवाही बाधित करना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यह जन भावनओं के साथ खिलवाड़ एवं क्रूर मजाक है।

---

* Speech was laid on the Table

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संसद जन आंकाक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने वाली सर्वोच्च संस्था है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सोनीपत की ओर दिलाना चाहता हूं कि खरखौदा-गोहाना-कटरा मार्ग को तत्काल कार्य शुरू करवाया जाए। इसके साथ ही साथ केएमपी मार्ग का कुण्डली से तत्काल शुरू करवाने की व्यवस्था करवायें जिससे यातायात की सुविधा जनता को उपलब्ध हो सके। गढ़ (सोनीपत) से वजीराबाद तक यमुना नदी के रास्ते जल मार्ग चालू करवाया जाए। इससे सस्ते और जन उपयोगी मार्ग की शुरूआत होगी। जो मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 पर मेरे संसदीय क्षेत्र में कुण्डली के आसपास लाखों की तादाद में फैक्टरी में कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रास करना पड़ता है। जिसके कारण कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है। अतः कुण्डली के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो फुट ब्रिज बनवाने की व्यवस्था करें। मेट्रो रेल को सोनीपत तक बढ़ाने हेतु इस बजट में धन का प्रावधान करने का कष्ट करें ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत जो एनसीआर में आता है यात्रियों को आने-जाने के लिए सुविधा मिल सकें। अंत में, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 11 से 12 मार्च, 2016 को मेरे प्रांत हरियाणा और मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत में इतनी अधिक ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण मेरे अनुमान से किसानों की लगभग 40 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अभी भी 19 मार्च तक वर्षा एवं ओलावृष्टि दोबारा होने से इंकार नहीं किया है। मेरे प्रांत का किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। पीछे धान एवं दलहन और सब्जी की फसलों का नुकसान हुआ था लेकिन किसान को उम्मीद थी कि गेहूं, सरसों आदि की फसल से गुजर-बसर हो जाएगा। लेकिन पिछले तीन-चार दिन से किसान की वह आशा भी समाप्त हो गई है। लेकिन वह आज प्राकृतिक आपदा के कारण मायूस होकर सरकार की तरफ सहायता हेतु निहार रहा है।

आखिर में मेरी आपसे पूरे जोर के साथ बहुत ही विनम्रता से आपसे प्रार्थना है कि तत्काल किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 20 हजार रु0 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलाने का इस बजट में प्रावधान करने का कष्ट करें जिससे वह अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपनी बेटियों की शादी कर सके। इसके साथ ही अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

[*]**श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर):** मैं वर्ष 2016-2017 के आम बजट पर अपने विचार रखता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी के कर कमलों द्वारा सदन के पटल पर पेश किया गया यह बजट देश में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। बजट के माध्यम से वित्त मंत्री जी नए भारत की स्पष्ट सोच के साथ सामने आए हैं। इस सोच के केन्द्र में नौ स्तम्भ है और मुख्य आधार है गाँव-गरीब और किसान। ये नौ स्तम्भ है **(1) किसान (2) गाँव (3) सामाजिक क्षेत्र (4) बुनियादी ढांचा (5) सुशासन (6) शिक्षा व सुधार (7) कर सुधार (8) वित्तीय सुधार और (9) खजाना प्रबंधन के रूप में।** माननीय मंत्री ने गाँव एवं किसानों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त इस बजट में युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। **हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने कहा कि यह बजट गाँव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा।** जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने शायराना अंदाज में कहा कि -

''**कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें...**

... इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें।''

वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट बहुत ही संतुलित एवं सधा हुआ है। बजट में ग्रामीण भारत की चिंताओं और समस्याओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र एवं किसानों पर इतना ध्यान दिया। किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। यह एक अच्छी पहल है क्योंकि सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में देश की तमाम आर्थिक तरक्की के बावजूद किसान लगातार बदहाल हो रहे थे।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के शुरुआती दो बजट को इस बजट के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। शुरुआती दो बजट जहाँ शहरी भारत के विकास पर अधिक केन्द्रित थे तो वर्तमान बजट ग्रामीण भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। यह सचमुच में एक सराहनीय कदम है क्योंकि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी गाँवों में निवास करती है। आर्थिक विकास को और

[*] Speech was laid on the Table

अधिक गति देने के लिए यह जरूरी है कि हम शहरी भारत एवं ग्रामीण भारत के बीच की दूरियों को कम करे।

अब शहर ही नहीं, गाँव भी स्मार्ट और समृद्ध बनेंगे। गाँव वालों को भी शहरों की तरह अच्छी सड़कें, स्वच्छ पानी और वह सारी जरूरी सुविधाएं मिलेगी। गाँवों का कायाकल्प होगा। गाँवों से पलायन रूकेगा। इस बजट में केन्द्र सरकार ने इसका पूरा प्लान पेश किया है। वित्त मंत्री माननीय जेटली जी ने बजट में पंचायत संस्थाओं को मजबूत और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्वराज अभियान नाम से एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह सचमुच में एक सराहनीय कदम है।

यह बजट इस मान्यता को आगे बढ़ाता है कि युवा देश की तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है। निजी उद्यमता को बढ़ावा देने की नीति का अनुसरण किया है और इसके लिए नव उद्यमियों को तमाम वित्तीय सुविधाओं के साथ कर में छुट देने का निर्णय लिया गया है। उम्मीद है इस पहल से रोजगार सृजन में तेजी आएगी और युवाओं की अपेक्षाएं पूरी होंगी।

बजट में सरकार ने गरीबी रेखा पर खड़ी लगभग 30 प्रतिशत आबादी का खास ध्यान रखा है। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने के साथ-साथ सस्ती दवाओं, हर जिले में डायलेसिस सेवा जैसी सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। लगभग 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला कर सरकार ने उनके घरों में उपस्थिति सुनिश्चित की है।

ऐसे समय में जबकि भारत में मेडिकल बीमा का फीसदी बहुत कम है, सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक लाख रुपए का स्वास्थ्य योजना लाने का महत्वाकांक्षी फैसला लिया है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में एक लाख रुपए के अलावा 30 हजार रुपए का अतिरिक्त बीमा होगा। प्रधानमंत्री जन ओषधि योजना के तहत अगले वित्त वर्ष में तीन हजार स्टोर खोले जाएंगे जहाँ सस्ते दामों पर दवाइयां मिलेंगी। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग सवा दो लाख किडनी के नए रोगियों की संख्या जुड़ जाती है जिन्हें डायलेसिस की जरूरत होती है। सरकार ने इसके लिए पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल डायलेसिस सर्विस प्रोग्राम हर जिला स्वास्थ्य सेंटर पर डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध कराएगा। जाहिर तौर पर यह उन गरीबों के लिए खास उपयोगी होगा जो इस पर आने वाले सालाना लगभग तीन लाख रुपए का बोझ उठाने में असमर्थ है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायाकल्प की कोई कारगर छवि पेश करने के साथ यह भी आवश्यक था कि सरकार बुनियादी ढांचे पर विशेष बल दे। बुनियादी ढांचे की सवा दो लाख करोड़ रुपए में से वित्त मंत्री जी ने सड़कों के लिए 97000 करोड़ का आवंटन किया है। जबकि बाकी राशि रेलवे के अलावा छोटे हवाई अड्डे, बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के लिए रखी गई है।

इस बजट के माध्यम से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इससे न सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इतना ही नहीं बजट में उद्यमिता और नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। काले धन का प्रसार रोकने और गरीब तबके के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में किया गया प्रयास स्वागत योग्य है।

वित्त मंत्री को राज्यों की आकांक्षाओं का सम्मान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर बल देने के लिए मैं बधाई देता हूँ।

सरकार से जनता को ढेर सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं एवं उम्मीद है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम, ऊर्जावान एवं कुशल नेतृत्व एवं आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से एक सशक्त, सक्षम, विकसित एवं स्वर्णिम भारत का निर्माण कर पायेंगे।

[*]श्री संजय धोत्रे (अकोला): मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी व माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आम बजट के माध्यम से एक नई सोच के साथ देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए कदम उठाए हैं।

मेरी पारिवारिक पृष्ठ-भूमि कृषि व गाँव से जुड़ी है और मैं किसानों की वास्तविक समस्याओं से सीधे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिस प्रकार किसानों और उनकी समस्याओं के प्रति सरकार ने सकारात्मक, संतुलित और दीर्घगामी सोच रखकर बजट में उनके लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं।

मैं यहाँ पर कृषि विषय पर ही चर्चा करना अपनी प्राथमिकता समझता हूँ। इसीलिए किसानों की उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिन पर कार्रवाई अपेक्षित है।

माननीय प्रधानमंत्री की सोच - 'More crop per drop' किसानों को समर्पित इस बजट में झलकती है, जो आधुनिकतम खेती की उच्च तकनीक को प्रोत्साहित करती है। मैं यहाँ पर किसानों की उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अब तक छूट गए हैं। बैंक जहाँ एक ओर किसानों को फसल कर्ज देते हैं, उसकी ब्याज दर अपेक्षाकृत काफी कम है, लेकिन खेती के काम आने वाले उपकरणों- ट्रैक्टर, ग्रीस हाउस शेड, पंपिंग-सेट, इत्यादि की खरीद पर बैंक कर्ज तो देते हैं, परंतु इन पर 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर लगायी जाती है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर आर्थिक संकट के कारण किसान यदि इस बाद वाले कर्ज को समय पर नहीं चुका पाता है, तो उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है। उस पर 2 फीसदी की पेनल्टी लगा दी जाती है। इस प्रकार वह चाह कर भी, इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता है। अतः मेरा मानना है कि किसान को आवश्यक कृषि उपकरण खरीदने के लिए दिए जाने वाले बैंक कर्ज पर ब्याज दर को कम करके 7 से 8 फीसदी तक लाया जाए।

मैं सरकार की इस बात के लिए भी सराहना करना चाहता हूँ कि उसने कम प्रीमियम पर ज्यादा कम्पन्सेशन दिए जाने को आधार बनाकर किसान फसल बीमा योजना बनायी है। देश में पहली बार किसान को प्राकृतिक क्षतिपूर्ति दिए जाने की योजना में फसल की बुआई से लेकर,

---

[*] Speech was laid on the Table

तैयार फसल को बाजार में बेचे जाने तक की अवधि को इस नई बीमा योजना में शामिल किया है। यदि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा।

यहाँ पर मैं उन छिद्रों (loop holes) की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रायः देखा जाता है कि किसान को उसकी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो चुकी उसकी फसल की क्षतिपूर्ति के रेवेन्यू सर्किल को एक इकाई माना जाता है। जिसमें 8 से 10 गाँव होते हैं। यदि इन गाँवों में किसी एक या दो गाँवों में ओला-वृष्टि या अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल चौपट हो गयी और बाकी आसपास के गाँव, इस प्राकृतिक विपदा से अछूते रह जाएं तो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गाँव के किसान मुआवजा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अतः गणना की इस इकाई के स्थान पर 500 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को एक इकाई माना जाए, तो यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

जिस प्रकार सरकार देश में सूक्ष्म, मध्यम और लघु व्यवसायिकों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से आसान शर्तों व कम ब्याज दर पर शत-प्रतिशत पूँजी उपलब्ध करवा रही है, मेरा मानना है कि यदि उसी प्रकार ऐसे समान अवसर व योजनाएं किसानों के हितों के लिए भी लागू हो जाएं, तो उनकी आर्थिक दशा सुधारने में यह मददगार हो सकता है।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, आपने मुझे वर्ष 2016-2017 के बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को धन्यवाद देते हुए अच्छे अधिकारियों को भी जिन्होंने इस बजट को बनाने में सहयोग दिया है, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। महोदय, बजट के बारे में मैं जेटली जी के मन में एक बात लाना चाहता हूं कि बजट के डिस्कशन के बारे में हम लोगों को नया मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अगर सत्ता पार्टी ने यह बजट बनाया है तो विपक्ष के लोगों को देखना चाहिए कि इससे अच्छा बजट कैसे हो सकता है, इस बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि देश के जवान बच्चे जो पढ़े-लिखे भी हैं वे यह पूछते हैं कि अगर यह बजट सही नहीं है तो विपक्ष का बजट क्या है। पैसा कहां से ज्यादा आ सकता था, खर्चा कहां से कम हो सकता था, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार की मांग लोगों के बीच में है, इसलिए मैं यह बात आपके समक्ष रखना चाहता था। 18 करोड़ लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है तो 12.50 लाख करोड़ रुपयों का रेवेन्यु जमा होने वाला है। साढ़े पांच करोड़ का फिसकल डेफिसिट घाटे का बजट है तो आने वाले दिनों में बजट में ज्यादा पैसा आना चाहिए इसलिए हमें क्या करना चाहिए तो मुझे लगता है कि रीयल इस्टेट के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। रीयल इस्टेट का बिल पास हुआ है इसलिए मैं नायडू जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं मुम्बई की बात कहना चाहता हूं और आप भी मेरा समर्थन करेंगे। आज मुम्बई में रीयल इस्टेट का काम पूरा का पूरा बंद पड़ा जैसा है क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क का दस किलोमीटर रेडीयस का कायदा आ गया है। पर्यावरण का कायदा पहले से ही है। जावड़ेकर जी ने बहुत रिलेक्सेशन दिया है लेकिन अभी भी बहुत से मसले हैं। एयरपोर्ट आथोरिटी की वजह से बहुत से काम बंद पड़े हैं और खास करके डिफेंस के बारे में मैं कहूं तो साढ़े तीन साल कांग्रेस के समय से काम बंद पड़ा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी सरकार आने के बाद भी डिफेंस का यह मसला समाप्त नहीं हुआ है। जेटली जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो कहा था कि इस काम को तुरंत किया जाएगा लेकिन उनकी मिनिस्टरी बदल गई और पर्रिकर जी आ गए। पर्रिकर जी ने बहुत प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि यह सत्र समाप्त होने के पहले किस तरह से इसे विदड्रा करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। लेकिन अगर यह नहीं होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगला सत्र शुरू होने के पहले मुम्बई शहर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि एनफ इज़ एनफ। लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन डिफेन्स में रहने वाले लोग परेशान हैं, वे भी आत्महत्या करने के मूड में आ गये क्योंकि उनकी इस प्रकार की परिस्थिति बन गयी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि हम हाऊसिंग सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दें तो बड़े पैमाने पर सरकार की तिज़ोरी में रिवेन्यू आ सकता है। इसलिए इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

चार लाख करोड़ रुपये का एनपीए हुआ है। एनपीए के बारे में जो विलफुल डिफाल्टर हैं, उनके ऊपर ऐक्शन होना चाहिए। लेकिन जो नॉन-विलफुल डिफाल्टर हैं, जिनका व्यवसाय सरकार की पॉलिसी की वजह से नहीं शुरू हो पाया है, अधिकारियों के मनमानी की वजह से जो एनपीए हुआ है, ऐसे लोगों के बारे में भी एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए। इसके साथ ही देश के लोगों को ऐक्शन टेकन रिपोर्ट भी देना पड़ेगा ताकि जो चार लाख करोड़ रुपये के एनपीए में जो दोषी अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।

ज्वेलर्स लोगों का भी एक मसला है। सारे लोगों की भावनाओं का समर्थन करते हुए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि वित्त मंत्री उसका खुलासा करेंगे क्योंकि ज्वेलर्स लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भय निर्माण हुआ है कि एक्साइज के ऑफिसर्स उनको परेशान करेंगे और यह बात सही भी है। वे कहते हैं कि यदि एक टका के बदले दो टका सरकार को टैक्स देना पड़ेगा तो हम देना चाहते हैं। 4 तारीख का जो सर्कुलर निकला है, उसमें बहुत सारा खुलासा हुआ है, थोड़ा और खुलासा वित्त मंत्री जी करें, मैं इस बात की मांग करता हूँ। यह उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है।

किसानों के बारे में बहुत सारी सुविधाएँ दी गयी हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र के किसानों की ओर से वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

जो दिव्यांग हैं, जो अपंग हैं, दृष्टिहीन हैं, उनकी एक समस्या बहुत दिनों से प्रलंबित है। थावर चंद गहलोत जी और वीरेन्द्र सिंह जी के बीच यह मसला फंसा हुआ है। थावर चंद गहलोत जी चाहते हैं कि जो दृष्टिहीन लोग हैं, उनको कुछ न कुछ मंथली कंपेनशेसन दें, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार श्री वीरेन्द्र सिंह, रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर साहब के पास है। यदि वित्त मंत्री जी इसका खुलासा कर दें तो जो दृष्टिहीन हैं, अपंग हैं, उनको बड़े पैमाने पर मदद कर सकते हैं। चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने सारे सेक्टर के लोगों को छुआ है, यही एक सेक्टर रह गया है। इसलिए बहुत जल्दी ही हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, hon. Chairperson, Sir. The hon. Finance Minister presented the General Budget for the financial year 2016-17. Being a farmer and a Member representing my constituency in Kerala, I would like to start by saying that this Budget has been a disappointing Budget for Kerala.

Rubber is the backbone of Kerala's economy. Rubber prices have dropped from Rs.240 per kilogram to Rs.80 per kilogram. The Government of India is the sole beneficiary of all taxes coming from the rubber sector. We have corporate tax, income tax, excise duty and above all, the Rubber Board is collecting cess from rubber farmers. In the last financial year itself, a sum of Rs.15,000 crore has been collected as tax from the rubber sector. Moreover about Rs. 100 crore is being collected as cess from the rubber farmers every year. Due to fall in rubber prices, the rubber industries have amassed exorbitant profit in this sector. In their balance-sheet itself they have shown Rs 50,000 crore as profit. The Government got the benefit and the industrialists got the benefit but the only victims of the present condition are the rubber farmers.

Sir, in this regard, we, all the MPs from Kerala, had a meeting with hon. Prime Minister and the hon. Finance Minster and so many meetings with the hon. Commerce Minister. We begged them and we requested them to support the rubber farmers. The hon. Commerce Minister assured us so many times to do the needful. But what happened? In the Budget, they closed their eyes to the rubber farmers. What did the rubber farmers get in return? It is a total negligence!

Sir, we never asked the Government for any amnesty. We asked for only a rational amount of Rs. 1,000 crore for procuring rubber for higher prices… (*Interruptions*)

Sir, we are raising a grave issue, which is badly affecting our State of Kerala. Our request is for getting a small amount of just Rs. 1,000 crore for procuring rubber for higher prices. It is only six per cent of the tax collected from the Government from this sector.

Now, the Government is talking about providing insurance to rubber farmers. Ever since they have come to power, they have been saying about this insurance but there is no budgetary provision for it in this Budget. The rubber farmers have contributed a huge amount to the Government revenue but what did the Government do for them, in return? I am very sorry to say that they were not even given the value of beggars till date. They have not even given a singe penny for the rubber farmers of Kerala.

Sir, another sector, which is hugely affecting Kerala is the NRI population. Thousands of NRI Keralites have returned from Gulf region due to recession caused by fall in prices of crude oil. I am personally very much worried about them. My Constituency consists of the largest number of NRIs in the country. NRIs' contribution turns out to be billions of dollars every year. But it is very sad that the Government has mentioned absolutely nothing in this Budget for their rehabilitation. The first beneficiary due to fall in prices of crude oil in the Gulf countries is India and the sufferers are the ones, who lost their jobs in the Gulf countries due to recession cause by fall in crude prices.

Simultaneously, because crude is the main ingredient for synthetic rubber, the downfall of crude is supposed to trigger a production of synthetic rubber. Sir, is the Government not liable for this pathetic condition of these rubber farmers and the NRIs?

Sir, we beg before the Government and the hon. Finance Minister to please do something for the rubber farmers as the rubber is the backbone of our economy. Thousands of farmers are badly affected. We would also request the Government to take steps to rehabilitate these NRIs who have lost their jobs.

With these words, I conclude. Thank you.

[*] SHRI OM BIRLA (KOTA) **:** The citizens of this country, the media analysts and industry experts have all lauded the efforts of the budget calling it a pro-farmer and pro-agriculture budget. At the back of consecutive years of drought, there was a dire need for attention towards the rural sector. This budget is not only going to help rural India recover, but also lays down platform for a robust future.

There were three important announcements for rural India of which I feel the most important one was the new version of crop insurance scheme-Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana with a budgetary allocation of Rs.5501.15 crore for 2016-17. The Premium payment which was as high as 15% has now reduced to 2% for Kharif crops and 1.5% for Rabi crops. The scheme has been well-thought and practical. While we cannot control natural disasters, we can certainly focus on reducing the impact on the farmers.

While crop insurance takes care of damages, what use is the farmland if it doesn't have adequate irrigation facilities? Improved Irrigation facilities and agriculture growth go hand in hand. Apart from the focus on Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, I welcome the decision to bring all 89 projects under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), with an assurance to raise Rs.86,500 crore through budgetary and extra-budgetary resources. Today, we have more than half of our 142 million hectares of sown area depending on rainwater. This is one of the reasons for the high impact of droughts on agricultural productivity in turn having disastrous effect on the lives of farmers. With commitment and adequate funding. I am sure the government will ensure better irrigation facilities for the farmers.

I wish to recall a thought mentioned in the speech given by the hon. Prime Minister about comparing PMGSY vs. MNREGS. The previous government has gone overboard in claiming the benefits of spending excessively just to ensure that the extremely poor stay afloat above the poverty line. In the process, ghost jobs, manipulation in beneficiaries, poor outcome of assets have plagued the MNREGS

[*] Speech was laid on the Table.

scheme. In contrast, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has been a catalyst in road connectivity ensuring a much better quality of asset creation. As the hon. Prime Minister said, there needs to be a thorough comparison between the performances of the two most important rural development schemes in India. While my intention is not to demean the MNREGS scheme but emphasize on the possibility of empowering it with better resources, aims and objectives. The government has been accused of diluting the UPA schemes. It is important to point out that these schemes were passed on in diluted form thanks to the poor implementation process. In fact, what they called as their flagship scheme-MNREGS has got Rs.38,500 crore from this government. More than competing with allocation of money, the government has focused on improving the quality of assets created. Similarly, Rs.27,000 crore for PMGSY will transform lives of rural India. It is necessary to mention the efficiency with which the government has focused on rural electrification as well. The 'Give it Up' call to finance LPG in rural areas, Jan Dhan Yojana and the insurance schemes have continued to fuel change in the country.

And finally, the promised 'Aadhar Bill' in the budget was brought to the House and while we pass this budget in Lok Sabha, Aadhar has already received legislative backing. This Act will transform the way subsidies function and will reduce the unwanted leakages.

With all the focus on rural India, it is apt to point out that those who once complained about 'suit boot ki sarkar' are today found naked without any credibility to back their mud-slinging fest. If only they had spent some time co-operating on the landmark GST Bill, this budget would have been etched in history with agricultural reforms and one of the most anticipated tax reform for the people. The country suffered through scams during their regime and today, the deliberate delay in passage of Bills is stuttering India's journey to the top.

The Finance Minister started his budget highlighting the slowdown in global economy to 3.1% in 2015. Despite all the volatility in the global market

and its influence in India, we have been marked as a bright spot with growth rate of 7.6%. Moreover, the hon. Finance Minister has continued to remain disciplined on his promise of Fiscal Deficit, sending out a positive signal to the Indian market.

The decision to recapitalize Public Sector Banks will be key in bailing out the banks from the crisis of increasing Non Performing Assets. However, in the process of bringing in banking reforms, the budget hasn't curtailed on expenditure of other important social schemes.

Apart from rural India, the focus on developing infrastructure with an estimate of Rs.2,18,000 crore (roadways and railways) is game-changer for the sector. At the end of the day, the budget is a roadmap of where the government wants to spend and highlights its priorities. The analysis and discourse that happens is around the numbers and doesn't take into account the positivity and trust that has already developed between the citizens. Couple of years back, this country was crippled with an inefficient decision-making body at the top mixed with corruption and various levels of governance -a dangerous mix for the nation. Two full budgets since then, corruption and inefficiencies seems distant. This government has needs to be applauded for achieving the twin responsibilities of reversing the damage as well as developing efficient governance system. As we move on, the government has already introduced and passed several key legislations. The Real Estate (Regulation and Development) Bill that we are going to pass today will ensure that the buyer gets an equal power in the process of purchase.

Budget in itself is just a document, it's the actions of the government throughout the year what gives colour to the vision of the budget. Ease of doing business, Startup scheme, Swachh Bharat, Digital India and several other schemes have received financial support in the budget and also adequate legislative backing. With two full budgets and focus on real issues, the government has restored credibility which went for a long walk in the previous regime.

I wish to highlight a few important points pertaining to my constituency as per the geographical view. Rajasthan is the largest state in this country but due to the natural disturbances, several drinking water sources are extinguishing. The underground water level in the state is also in a dangerous state, 243 zones of Rajasthan are under Dark Zone and several other districts are facing the problem of high fluoride level in drinking water. Hence, I request the central government to allocate special package for the drinking water in Rajasthan.

Our Prime Minister has dedicated this budget to the farmers; he has focused on providing better coverage of irrigation facilities to maximum farmers so that it can help in increasing the agricultural output and betterment of the farmers. I wish to highlight that Vradh Parwan Sinchai Pariyojna in which thousands of acres of land in Kota, Baran and Jhalawad districts will be irrigated and the State Government has already allotted a sum of Rs.700 crore for this scheme. This scheme is of Rs.5,000 crore (expected) but the success of this scheme is not possible without the help to the Central Government so that maximum area of agricultural land will be irrigated in the said districts.

It is requested that funds should also be allocated for the re-establishment of Alniya, Sawan Badho, Dolya, Choma, Khata Kheda under the ERM and RRR scheme of Kota-Bundi districts and Bhim lath, Abhay pura's minor irrigation projects of Bundi district by the Central Government.

Chambal Pariyojna's right and left canal and residual water of other canals will be lifted and also Kota and Bundi districts' residual water should be lifted for irrigating the land of the farmers and special budget needs to be allocated for the same by the Central Government. Further special budget may be allocated for redevelopment of the right and left canal of Chambal so that the area of the irrigated land should be increased.

It is requested that Chakkan (Indragarh) Laghu Sinchi Pariyojna of Bundi District will be converted into mid-size irrigation projects so that thousand hectares of land should be irrigated.

For amalgamation of rivers in Rajasthan, four proposals have already been submitted by the state to the Central Government. I urge the government to provide funds for promoting the said proposals.

Chambal river flowing form Kota city is getting polluted day by day as 22 sewer lines of the city are being disposed of in this river. Central Government has included Chambal in the NAMAMI GANGE project for Ganga cleanliness. Hence, I request that in order to keep Chambal river clean, special package should be provided by the Central Government.

This government has rightly focused on improving manufacturing and revive job growth. Instrumentation Limited (IL) in Kota is in desperate need for revival and can also be an important aspect for revival of jobs. In furtherance to the discussion with the heavy industries as well as having raised the issue in the august house, I wish to propose the following steps for the revival of Instrumentation limited.

- IL can be restructured/revived and will generate its own funds once bridge loan is sanctioned for clearing pending liabilities. To provide one-time bridge loan/non-plan budgetary support of Rs.350 crore for meeting salary and statutory liabilities, BIFR (Board of Industrial and Finance Reconstruction) in its hearing in June 2013 recommended interim financial assistance of Rs.215 crore for the revival.
- Immediately provide salary support of Rs.73.41 crore for the period April 1, 2014 to March, 2015 pending with the government to mitigate the hardships of the employees. To provide orders on nomination basis from Railways, Defence, telecom and cost plus margin basis.
- To allow the company to sell its land owned by the company either through DIPAM or Asset sale Committee to generate additional funds worth Rs.100 and to appoint a consultant who will look into

Make in India, Digital India approach of the company, suggest further guidelines and directions for its restructuring.

Keeping in mind the development of Kota region, I would urge the hon. Finance Minister to kindly consider the demand for the revival of Instrumentation limited.

Second, Kota has been an important educational hub for several decades now. While many students come to this city for their preparations for IIT, the city itself does not have an Indian Institute of Technology. I urge the hon. Finance Minister as well as the Human Resource Development Minister to consider setting up an IIT and an Indian Institute of Management in Kota for the benefits of thousands of students.

In his speech, the hon. Finance Minister has proposed the development/revival of about 160 airstrips with co-ordination with the state governments at the cost of Rs.50-100 crore each. I urge upon the hon. Civil Aviation as well as the Finance Minister to consider the Kota airstrip among the ones for development. This will go a long way in providing better air connectivity to Kota where there is adequate demand for the same.

Rajasthan is also known for its traditional jewellary and the Central Government has imposed an excise duty of 1% of the Gold items which has been objected by all the jewellers, Jewellers' associations and trade associations. I hereby request that excise duty on gold items be withdrawn in order to consider the demand of the Jewellers and their associations.

***श्री पी.पी.चौधरी (पाली):** सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ।

मैं बजट में दिए गए आंकड़ों की और बौछार नहीं करना चाहता, मेरे योग्य साथियों द्वारा बड़े विस्तार से उस पर चर्चा हो चुकी है। देश एक ऐसी विकट स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ दुनिया में मंदी का दौर है और भारत कठिनाइयों के बावजूद विकास के रास्ते पर दृढ़ता से चल रहा है। बजट पढ़ने के बाद स्पष्ट धारणा बनेगी कि ये एक और विकासपरक और निरंतरता का बजट है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, दलित उत्थान, अल्पसंख्यक कल्याण की मदों में ऐतिहासिक वृद्धि कर सरकार ने अपने दृष्टिकोण को अत्यंत स्पष्ट कर दिया है कि उपेक्षित वर्ग को हर प्रकार से समान अवसर उपलब्ध करवाते हुए देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मैं इस शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने बजट के द्वारा आधारभूत ढांचे में सुधार करने पर पूरा जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के बिना कोई विकास नहीं हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता क्योंकि वहां अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के अनुसार 9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए 12 प्रतिशत अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि होना अनिवार्य है।

बजट का मुख्य जोर वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, उत्पादन के साथ उत्पादकता बढ़ाकर, दीर्घकालीन रणनीति अपनाकर इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करना है।

कृषि पर देश की जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग निर्भर रहते हैं और यू.पी.ए. सरकार द्वारा इन 70 प्रतिशत लोगों को इग्नोर किया गया, जिसके कारण कृषि का जी.डी.पी. में योगदान 60 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत रह गया। 1998-2000 तक एन.डी.ए. के शासन काल में यह हिस्सा 26 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2012-13 में 13 प्रतिशत ही रह गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा कृषि को नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन एन.डी.ए. ने पुनः कृषि को बहुत अधिक महत्व देते हुए बजट पेश किया है। हमारी सरकार को जानकारी है कि बजट वर्तमान की बजाए भविष्य का होना चाहिए और इन्डस्ट्रियल व एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ के माध्यम से आज के इस वातावरण में 7 से 8 प्रतिशत तक जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट प्राप्त की जा सकती है.

---

* Speech was laid on the Table

किसानों को लेकर हमारे वित्त मंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष पूरे देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार द्वारा कुछ माह पहले किसानों को 30 प्रतिशत फसल खराब होने पर भी मुआवजा दिलाए जाने के मापदण्ड से सभी किसानों में खुशी की लहर दौड़ उठी। लगभग 6 माह पूर्व प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुई क्षति के एवज में राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए 11,886 करोड़ रू. की धनराशि की मांग भारत सरकार से की गई थी, जिसके एवज में 1378 करोड़ रू. धनराशि राजस्थान सरकार को वर्ष 2015 में आवंटित की गई थी, जो कि प्रभावित काश्तकारों को भारत सरकार के एसडीएफआर नोर्म्स के अनुसार वितरित की जा चुकी है।

अभी हाल ही में गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सूखे प्रभावित क्षेत्रों को आपदा प्रबन्धन मद में धनराशि आवंटित की गई, जिसमें राजस्थान राज्य को 1193.41 करोड़ की धनराशि जारी की गई। राजस्थान सरकार शेष राशि का आवंटन अभी भी बाकी है। यही नहीं इसके अतिरिक्त पिछले सप्ताह से लगातार मौसम की मार झेल रहे राजस्थान के किसानों की फसल चौपट हो गई है, पश्चिमी राजस्थान में तो हुई ओलावृष्टि के कारण पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो गई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द नकुसान का आकलन करने हेतु केन्द्रीय टीम भेजी जाए तथा राजस्थान सरकार को पिछली बकाया धनराशि के साथ वर्तमान में हुए नुकसान की धनराशि आवंटित करने की कृपा करें, ताकि किसानों को आपदा प्रबन्धन मद से पूरी सहायता मिल सके।

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। एन.डी.ए. सरकार ने जब-जब सत्ता की कमान संभाली तब-तब राजमार्गों के विकास के कार्य में तेजी आई है। हम सभी जनते हैं कि राजमार्ग देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले एन.डी.ए. सरकार द्वारा 11 कि.मी. प्रतिदिन के हिसाब से राजमार्ग निर्माण का कार्य किया जाता था, जो वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ाकर 23.4 कि.मी. प्रतिदिन किया गया है। यू.पी.ए. के कार्यकाल के दौरान तो राजमार्ग निर्माण की गति केवल मात्र 5.2 कि.मी. प्रतिदिन ही रह गई थी। माननीय नितिन गडकरी के नेतृत्व में ही राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य प्रतिदिन 30 कि.मी. का प्राप्त हो सकेगा।

मैं सरकार और माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का ध्यान पुराने राजमर्गों की मरम्मत की और आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में राजस्थान को राजमार्गों की मरम्मत हेतु आवश्यकता से लगभग आधी धनराशि जारी की जाती रही है। वर्ष 2011-12, 2013-14 तथा 2014-15 के बजट में तो कुल मिलाकर 41.68 करोड़ ही जारी किए गए, जो कि अनुमानित लागत से एक चौथाई से भी कम था। राजमार्गों की खराब स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में 50 करोड़ रू. की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्भरित किए जाने के आधार पर जारी की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजमार्गों की मरम्मत हेतु 22.34 करोड़ तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों हेतु 4.08 करोड़ की राशि ही जारी की गई है।

इसके साथ-साथ राजमार्गों की लंबाई तथा उन पर वाहनों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी के कारण मरम्मत हेतु धनराशि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। राजस्थान सरकार के माध्यम से प्रतिवर्ष 75 करोड़ की धनराशि राजमार्गों की मरम्मत हेतु आवंटित किए जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है।

अतः मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमर्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान राज्य में राजमार्गों की मरम्मत हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति जारी करते हुए बजट स्वीकृत करने की कृपा करें।

सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राईजेज की सभी कम्पनियों को सी.एस.आर. कमेटी बनाना आवश्यक है, जिसका कार्य कम्पनी के लाभ के कुछ हिस्से को सामाजिक सुधार में खर्च सुनिश्चित करना है। ऐसा पाया गया है कि कुछ कम्पनियों द्वारा सी.एस.आर. के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि कुछ नवरत्न जैसी बड़ी कम्पनियां भी सी.एस.आर. के तहत बजट को अत्याधिक कम मात्रा में आवंटित कर रही है। यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ कम्पनियां बजट तो आवंटित कर रही है परन्तु पूर्ण मात्रा में खर्च नहीं कर रही हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि महारत्न, मणिरत्न और नवरत्न जैसी पूरे देश में व्यापार करने वाली कम्पनियों के द्वारा सी.एस.आर. के माध्यम से कराए जाने वाला कार्य एक सीमित क्षेत्र के लिए नहीं होना चाहिए। अनेकों प्रस्तावों को कम्पनियां यह कह कर लौटा देती हैं, कि वह स्थान उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है। ऐसी स्थिति में देश के वे जिले जहां एक भी

पी.एस.यू. नहीं है, उनकी पहचान केवल पिछले जिलों के रूप में ही रह जाती है। वर्तमान में सी.एस.आर. निर्देश में भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर प्राथमिकता से ध्यान देने का प्रावधान नहीं है।

अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोक उद्यम विभाग द्वारा सी.एस.आर. के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जाए तथा ऐसे भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए सी.एस.आर. का खर्च किया जाना सुनिश्चित करें, जहां कोई भी पी.एस.यू. नहीं होने के कारण रोजगार की समस्या के साथ-साथ अन्य विकास के कार्य भी रुके हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों की सूची में राजस्थान का पाली लोक सभा क्षेत्र भी एक है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है व अधिकतम आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ग्रामीण क्षेत्र के विकास तथा उत्थान हेतु ग्रामीण बैंकों की महत्ती भूमिका रही है। विगत 40 वर्षों से ग्रामीण बैंक सफलतापूर्वक कार्य करते हुए ग्रामीण विकास में सहभागी रहे हैं तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण बैंक किसी भी क्षेत्र में अन्य सार्वजनिक बैंकों से कम नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत पूंजी अंशदान केन्द्र सरकार का 50 प्रतिशत, राज्य सरकार 15 प्रतिशत तथा प्रायोजक बैंक का 35 प्रतिशत है। समय के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति आज सुदृढ़ हुई है। 196 ग्रामीण बैंकों की संख्या निरंतर किए जा रहे सम्मेलनों के पश्चात अब 56 रह गई है।

उपरोक्तानुसार ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राप्त की गई सफलता व सुदृढ़ता के मद्देनजर व ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं स्टार्टअप प्रोग्राम के सफल क्रियान्वयन हेतु आपसे यह सविनय अनुरोध करते हैं कि ग्रामीण बैंक से संबंधित समस्याओं व मुद्दों को उचित मंच पर रखा जाए, जो निम्नानुसार हैः-

सांसद कोण (एमपीएलएडी) की राशि को हमेशा सार्वजनिक बैंकों में ही रखे जाने का प्रावधान है, जिससे ग्रामीण बैंक इस कोष से हमेशा वंचित रहते हैं।

ग्रामीण विकास के लिए जो राशि आवंटित की जाती है वह करोड़ों में होती है तथा इस राशि का वितरण सीधे संबंधित राज्यों के ग्रामीण बैंकों को प्रेषित किया जाना चाहिए।

यदि उपरोक्त बिन्दुओं पर मंथन किया जाए तो निश्चय ही जमा अभिवृद्धि से ग्रामीण बैंकों का मनोबल ऊंचा रहेगा। कोषों के उपलब्ध होने से ग्रामीण व कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अधिक ऋण वितरण संभव हो सकेगा। इससे न केवल ग्रामीण बैंक अधिक सुदृढ़ बनेंगे बल्कि अधिक उत्साह से

कृषि व ग्रामीण विकास में भागीदार बनेंगे। अतः मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

देश में जनसंख्या के साथ-साथ अपराधों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। अपराधों की वृद्धि के साथ-साथ अपराध के तरीकों और इसमें काम में लिए जाने वाले आधुनिक हथियारों और तरीकों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। आए दिन समचार पत्रों के माध्यम से यह देखने को मिलता है कि अपराधी तत्व पुलिस से कहीं ज्यादा होशियार तथा तेज होते जा रहे हैं। पुलिस का उन्हें पकड़ना और मुठभेड़ में मार गिराना अत्यंत मुश्किल होता जा रहा है। मुम्बई में ताज होटल पर हुए हमले के दौरान स्थानीय पुलिस के आधुनिकीकरण पर अनकों सवाल खड़े हो गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पुलिस आधुनिकीकरण हेतु बजट सहायता प्रदान की जाती रही है। राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए जारी की गई नॉन-प्लान मद की राशि नाकाफी बताई गई है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है। राजस्थान प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 स्क्वायर कि.मी. है। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान प्रमुख राज्य है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ भी है। पाकिस्तान से भारत से लगी सीमा की लम्बाई 2043.63 कि.मी. है, इसका 1056.63 कि.मी. 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। सीमा से सटे जिलों में कई बार हाई अलर्ट की संभावना भी बनी रहती है। राजस्थान प्रदेश की पुलिस को और अधिक आधुनिक किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत और अधिक धनराशि जारी करने तथा नॉन प्लान मद में केन्द्रीय अंशदान को बढ़ाने की कृपा करें। केन्द्रीय बजट 2015-16 में सरकार द्वारा दो लाख या इससे अधिक की ज्वैलरी की खरीद पर पेनकार्ड या फार्म-60 अनिवार्य किया गया है, जो कि नोटिफिकेशन द्वारा 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ। इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पैन कार्ड अनिवार्य किए हुए 2 माह का समय बीत चुका है, यदि इससे कुछ लाभ सरकार को नहीं हुआ है, तो इस बारे में अध्ययन करवाकर इसकी अनिवार्यता समाप्त करने पर विचार किया जाए क्योंकि पैन कार्ड की अनिवार्यता किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 60 करोड़ लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में लगभग 25 करोड़ लोगों के पास ही पैन कार्ड है। कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त है इस करमुक्त राशि से यदि कोई कृषक अपने परिवार के लिए जेवर या गहने आदि खरीदता है तो उसे पेनकार्ड उपलब्ध कराना होगा। मांगलिक अवसरों पर जेवर आदि देने-लेने का रिवाज है। महिलाएं बच्चों के शादी/विवाह आदि को ध्यान में रखकर छोटी-छोटी बचत करती हैं ताकि अभी से गहने/जेवरों की व्यवस्था कर सकें, जिसका उपयोग भविष्य में कर सकें।

इसके अतिरिक्त स्वर्ण आभूषणों के व्यापार पर थोपे गए विभिन्न कर से पूरे हिन्दुस्तान भर के व्यापारी, कारीगर एवं सभी जुड़े हुए व्यक्ति जिसमें उपभोक्ता भी आते हैं, सभी हतोत्साहित हैं, वे ऐसा महसूस कर रहे हैं, जैसा इंस्पेक्टरराज उन पर थोपा जा रहा है। व्यापारी वर्ग कर के साथ-साथ कई विभागों द्वारा अलग-अलग नियमों से भी पीड़ित है।

आभूषणों पर 1 प्रतिशत (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट) और 12.5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) उत्पाद शुल्क लगने से सभी स्वर्णकारो, व्यापारियों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। सर्राफा एसोसिएशन का विरोध देखते हुए निवेदन है कि हमें संकट में नहीं डाला जाए और लगाए गए एक्साइज को तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए। इसके विरोध में सर्राफा एसोसिएशन द्वारा पिछले कई दिनों से प्रतिष्ठान बंद रखने का एलान किया है यह विरोध देशव्यापी हो गया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि पैन कार्ड की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए तथा आभूषणों पर 1 प्रतिशत (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट) और 12.5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) उत्पाद शुल्क को तुरंत हटाने के निर्देश प्रदान किए जाए। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष पूरे देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं में किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, ऐसी स्थिति में देखने में आया है कि वे किसान और कास्तकार अपना पेट पालन आसानी से कर पाते हैं जिनके पास पशु है। पशुपालन खेती के अलावा अतिरिक्त आय का प्रमुख साधन है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पशुपालकों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। भारत सरकार की नेशनल लाईव स्टॉक मिशन सब मिशन फोडर एण्ड फीड डवलपमेंट योजनान्तर्गत तीन परियोजनाओं में केन्द्र के अंश के रूप में धनराशि का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है।

1. फोडर प्रोडक्शन फ्रॉम नान फोरेस्ट लैण्ड - 112.45 लाख
2. फोडर सीड्स प्रोक्योरमेंट एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन्स - 721.50 लाख
3. हस्तचलित, पावर चलित चॉफ कटल वितरण - 1112.93 लाख

उक्त तीनों परियोजना में केन्द्र अंश के रूप में 1214.26 लाख रू. की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जानी प्रस्तावित है।

अतः मेरा कृषि एवं पशुपालन मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र अंश की राशि जारी करे की कृपा करें, ताकि राजस्थान प्रदेश के पशुपालकों को सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान की जा कके।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बजट विकासपरक है, जहां पर धनराशि की आवश्यकता थी, वहां पर धनराशि देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। किसान, ग्रामीण एवं शहरी दलित एवं गरीब अल्पसंख्यक तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अधिक से अधिक धनराशि देने के लिए अतिरिक्त कर लगाना अनिवार्य था, लेकिन उसे भी इतने सुन्दर ढंग से लगाया गया है, जिससे कोई भी वर्ग विशेष रूप से आहत नहीं है। मैं इस शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

***श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) :** मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2016-17 ''सबका बजट'' है, गरीबों के विकास, युवाओं को शिक्षा व रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, किसानों के जीवन में खुशहाली,रज्यों की समृद्धि और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस साल के बजट का मैं मेरे क्षेत्र के लोगों की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ।

मैं, अपने कार्यक्षेत्र दिंडोरी सहित उत्तरी महाराष्ट्र की जमीनी तौर की समस्याओं से बहुत करीब से परिचित हूँ। मेरा क्षेत्र का किसान-बहनदेश में अंगूर, अनार, प्याज और सब्जी का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इस क्षेत्र हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन देखते हुए, मेरे क्षेत्र दिंडोरी में 'कृषि अनुसंधान केंद्र' और 'बागबानी युनिवर्सिटी' के अंतर्गत महाविद्यालय की जरूरत है, इस संदर्भ में मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से पत्र-व्यवहार भी किया है। मेरे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए।

इस आम बजट में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया है। इस परियोजना के अंतर्गत मेरे क्षेत्र की पश्चिम वाहिनियां, नार-पार नदियों पर डैम बनाने से पूरे उत्तर महाराष्ट्र का सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का हल करने के लिए केंद्र की सहायता की जरूरत है। इसलिए नार-पार योजना के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही देश की सभी वाटर बॉडीज को रीस्टोर किया जाए, ताकि खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सके।

मेरा कार्यक्षेत्र दिंडोरी आदिवासी बहुल होने के कारण यहां पर आदिवासी मेडिकल कॉलेज और उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए आदिवासी अभियांत्रिकी कॉलेज की सख्त जरूरत है। इन दोनों आदिवासी महाविद्यालयों के कारण महाराष्ट्र के आदिवासी विद्यार्थियों की प्रगति होगी।

मेरा जिला नासिक की भूमि, जो प्रभु रामचंद्र के चरणों से पावन हुई है तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर-ज्योतिर्लिंग नासिक में है, साथ ही दिंडोरी में 'वणी' जो सप्तश्रृंगीदेवी का गढ़ है जैसे कि इस बजट में संस्कृति, योग और पर्यटन के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इन सबको 'राष्ट्रीय तीर्थयात्रा स्थल' तथा आध्यात्मिक आवर्धन अभियान में जोड़ दिया जाए तथा पर्यटन सर्किट में भी समावेश करने की जरूरत है।

---

* Speech was laid on the Table

वाराणसी की तरह मेरे क्षेत्र दिंडोरी में येवला तहसील में पैठनी साड़ी का हथकरघा उत्पादन होता है। पैठनी साड़ी का उद्योग और उसके कारीगर आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है उनके लिए केंद्र से बड़ी उम्मीद है।

अंत में मैं चाहूंगा कि 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज 16 वर्ष की आयु में स्वराज्य स्थापना की शपथ ले सके क्योंकि उनके पास दृढ़ इच्छाशक्ति थी और देश निर्माण की सोच थी। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य निर्मिती में बुनियादी ढांचा किसान की समृद्धि और 'राज्य की सेना' को अहम महत्व दिया और साथ ही कमियों को दूर करना और स्वराज्य के शक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर ध्यान दिया था, आज फिर से 21वीं सदी के प्रतियोगी युग में देश को 'फॉरवर्ड' ले जाने के किसी फॉरेन ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड शिक्षित व्यक्ति नहीं बल्कि शिवाजी महाराज की 'आर्थिक स्वराज्य नीति' तथा मोदी सरकार का 'हार्डवर्क' जरूरी है और मैं यह भी विनती करता हूँ कि सरकार ने 'मेक इन इंडिया' के साथ साथ 'थिंक इन इंडिया' की भी शुरूआत करनी चाहिए।

हमारी सरकार का यह 'आम बजट' देश को तरक्की की राह पर लाने और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलकर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण के सपने को साकार करने वाला बजट है। इसी के साथ मैं आम बजट का समर्थ करता हूं।

[*]**श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर):** मैं 2016-17 के आम बजट का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे वित्त मंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा है। आज आलम यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधारों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब वाहवाही हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

आज विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है और तो और चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सभी देशों से ज्यादा रहती थी आज वह भी भारत से पिछड़ गया है। गत वर्ष 2015-16 में हमने अर्थव्यवस्था की चाल को 7.6 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। वह भी जब देश में मानसून की स्तिति बहुत खराब रही। हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। हमारी कृषि का उत्पादन मानसून पर आधारित है। अच्छी बारिश होती है तो अच्छा कृषि उत्पादन होता है और कम बारिश में कम कृषि उत्पादन होता है और हमारी अर्तव्यवस्था कृषि पर निर्धारित है। इन सबके बावजूद अर्थव्यवस्था की रफ्तार को ढीली न होने देना, यह अक अच्छे अर्थशास्त्री की योग्यता का प्रमाण है, जो हमारे वित्त मंत्री जेटली जी हैं।

अभी तक मुख्य विरोधी दल हम पर सूट-बूट की सरकार कहकर हमारा मजाक उड़ाया करते थे। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने गांव की ओर मुख करके विरोधी दल के नेताओं का मुंह बन्द कर दिया है। अबकी बार वित्त मंत्री जी का ध्यान कृषि विकास, सिंचाई और गांव के आधारभूत ढांचे के निर्माण की ओर अधिक रहा है। साथ ही साथ, गरीब जनता जो गरीबी रेखा के नीचे रह रही है उनको राहत प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया गया है। यह बजट असल में आम जनता का बजट है, न कि पूंजीवादी बजट है।

बीते वर्ष विषम परिस्थितियों के बाबजूद राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य जी.डी.पी. 3.9 प्रतिशत रखा था, हमारे कुशल वित्त मंत्री जी ने इसको पार नहीं होने दिया। इस वर्ष वित्त वर्ष (2016-17) यह राजकोषीय घाटा घटाकर जी.डी.पी. का 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य रख दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं हमारे वित्त मंत्री जी 3.5

[*] Speech was laid on the Table

प्रतिशत के लक्ष्य से ज्यादा राजकोषीय घाटा नहीं होने देंगे। यह केवल संभव है कि एक योग्य अनुभवी और कर्मठ व्यक्ति के द्वारा जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं।

आम बजट में सकारात्मक पहलुओं की भरमार है और इसने राजकोषीय पथ पर सरकार की विश्वसनीयता में इजाफा किया है जो ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सड़कों में निवेश में वृद्धि, गरीबों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, जिले स्तर पर डायलिसिस की व्यवस्था करना, नए कर्मियों के लिए कम्पनियों को प्रोविडेंट फंड में अनुदान देना, हाईवे, रेल, पोर्ट एवं एयरपोर्ट में निवेश बढ़ाना इत्यादि।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बुनियादी विकास पर जोर देते हुए सड़क निर्माण के लिए बजट में 82,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और पूंजीगत खर्च का भारी भरकम आवंटन को जी.डी.पी. के फीसदी के स्तर पर रखा है। बजट में ग्रामीण आय सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं का फंड बढ़ाया है साथ ही साथ, सिंचाई और सड़क संपर्क में निवेश बढ़ाने की बात कही गई है। ये दोनों कदम क्रमशः अल्पावधि और मध्यम अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होंगे। इन निवेश योजनाओं के तहत जो निर्माण कार्य होगा, उसका शीघ्र प्रभाव देखने को मिलेगा।

हमारी सरकार ने वादा किया है कि एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों का दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत विद्युतीकरण हो जाएगा। साथ ही गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात भी कही गई है। सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि भूमि रिकार्ड के डिजिटल आधुनिकरण का काम एक केन्द्रीय योजना के जरिये किया जाएगा। इन बातों से साफ प्रतीत होता है कि हमारी सरकार ने अब कृषि पर नई सोच के साथ ठोस कार्य आधारित योजना पर काम करने का मन बना लिया है।

इस बजट में कोई भी लोकलुभावन बातें नहीं हैं, बल्कि कुछ कर दिखाने का वायदा है। कृषि के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही है। कुछ शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर का बनाने का भी हमारी सरकार का वायदा है।

हमारी सरकार की सूझ-बूझ की वजह से अब गांव की सड़कें हिचकोले नहीं लेंगी, बल्कि इनसे मुक्त होगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का क्रियान्वयन जिस तरह से किया जा रहा है वैसा पहले नहीं हुआ। 27 हजार करोड़ इस योजना के तहत खर्च करना और साथ ही 65,000 नई बस्तियों को सड़कों से जोड़ना गांव के लिए एक सुनहरा उपहार है। 2019 तक करीब सवा दो लाख

किलोमीटर तक सड़क निर्माण का लक्ष्य भी एक सराहनीय कदम है और यह सरकार की इस क्षेत्र के प्रति कटिबद्धता की ओर इशारा करता है।

हमारी सरकार के कुछ और कदम ऐसे हैं जिनकी सराहना करते हुए मैं थकता नहीं हूं। जैसे कि खुले में शौच मुक्त होने वाले गांव को इनाम देने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के लिए प्राथमिक आधार पर आवंटन करना उर्वरक सब्सिडी को सीधे किसान तक पहुचाने के लिए डी.बी.टी. नेटवर्क का इस्तेमाल इत्यादि करना।

हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के माध्यम से इस बात को साबित किया है कि गांवों की समृद्धि के बिना बहुत आगे तक चलना मुश्किल है। दूसरे शब्दों में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि देश के विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। मई 2019 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य एक बड़ा साहसिक कदम है। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता को शुरू करने की योजना, सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाया जाना , एक तिहाई आबादी को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान किया जाना भी सशक्त बजट की विशेषता है।

अंत में मैं यही कहूंगा कि इस बजट में वह सभी बातें कही गई हैं जो इस देश को और देशवासियों को सशक्त बनाती है। वित्त मंत्री जी की सोच बिलकुल नई है और यही सोच देश के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले हर भारतीय को उम्मीद की रोशनी प्रदान करती है। राजस्थान को पानी के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। जयपुर के रामगढ़ बांध एवं फालख बांध के पुनर्भरण को विशेष पैकेज दिया जाए।

मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट के विषय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मैं वर्ष 2016-17 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने इतना प्रभावशाली बजट पेश किया। बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग और हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, मुख्यतः अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं एवं समाज के अन्य वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरूआत करूंगी और सदन का बहुत कम समय लूंगी।

"सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती,
नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती,
जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर,
उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती।"

मैं बजट के दो मुख्य बिन्दुओं पर इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ सुझाव देना चाहती हूं। पहला, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य झुकाव समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान को लेकर है। अभी हाल ही में केन्द्र की कैबिनेट ने अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं को उद्यमिताओं में बढ़ावा देने के लिए स्टेंड अप इंडिया स्कीम को मंजूदी दी है और वर्ष 2016-17 के बजट में इस योजना को लागू करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आशा है कि इस योजना से कम से कम सवा दो लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे।

महोदय, वास्तव में यह एक अच्छी दिशा में उठाया गया कदम है। देश में लगभग 21 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति-जनजाति और पचास प्रतिशत महिलाएं हैं और उनको पैरों पर खड़ा करने की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए देश की लगभग एक चौथाई आबादी अनुसूचित जाति-जनजाति और पचास प्रतिशत की आबादी वाली महिलाओं को देखते हुए उनके उत्थान के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की जो राशि निर्धारित की गयी है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि स्टेंडअप इंडिया स्कीम के लिए कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए जाएं ताकि इस योजना को सफल बनाया जा के।

महोदय, मेरा दूसरा बिंदू है कि बजट में आभूषण निर्दिष्ट कर क्रेडिट के बगैर एक प्रतिशत या निर्दिष्ट कर क्रेडिट के लिए साढ़े बारह प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। महिला होने के नाते मैं इस बात को भली-भांति जानती हूं कि आभूषणों का भारतीय समाज में कितना महत्व है? इनका

सामाजिक महत्व भी है। मैंने महसूस किया है कि सरकार के इस प्रस्ताव से न केवल इस देश की महिलाओं में बल्कि सर्राफा व्यापारी भी व्यथित हैं। मैं कुछ दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र गयी थी। वहां हजारों की संख्या में सर्राफा व्यापारियों ने मुझ से मिलकर इस प्रस्तावित कर को हटाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए निवेदन किया था। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि सर्राफा भाइयों की पीड़ा को देखते हुए प्रस्तावित आभूषण पर कर का वापस लिया जाए।अंत में मैं विपक्ष में बैठे हुए अपने सम्मानित सदस्यों से यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत सारी व्यथा इस बजट के माध्यम से रखी हैं।

मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता,
हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता।
जिस इंसान के अच्छे होते हैं करम,
उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2016-17 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने इस बजट को कृषि बजट के रूप में दिखाने का काम किया है। मै सरकार से यह आग्रह भी करूंगा कि कृषि क्षेत्र में जिस तरह से लगभग 5 हजार 7 सौ करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। लेकिन पिछले तीन दिनों से मौसम की खराबी के कारण हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत में अधिकतर किसानों की फसलें फिर से बर्बाद हो गयी हैं। केवल कृषि बीमा की बात करके हम किसान को समृद्ध नहीं बना सकते हैं। सरकार को स्पेशलाइज्ड तरीके से कृषि में बढ़ोतरी के उपाय करने चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने अगले साल की सरकार की क्या विचारधारा है, उसे बजट के माध्यम से बताने का काम किया है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि तीन महीने बाद ओलम्पिक गेम्स होने वाले हैं।

सरकार ने एशियाड और कॉमनवैल्थ के लिए दो सौ करोड़ रुपये का पैकेज अपने पहले वित्त वर्ष में लाने का काम किया था, मगर इस बार पूरे सवा घंट के भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी खेल और हमारे खिलाड़ियों को कहीं न कहीं देश की विचारधारा से जोड़ना भूल गये। महोदय, आज हम ब्रिक्स नेशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर आज हमारे डैवलपिंग नेशंस के अंदर कोई कम्पिटीटर्स हैं तो ब्रिक्स देश हैं। वे भी अपने देश का पांच से छः प्रतिशत जीडीपी एजूकेशन में डालने का काम करते हैं। परंतु हमारा देश सबसे युवा देश है, हमारे देश की करीब 80 करोड़ की आबादी 35 साल से नीचे है और हमारे देश का लगभग तीन परसैन्ट जीडीपी सरकार एजूकेशन और हैल्थ सैक्टर में डालती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार विचार करके कम से कम पांच से छः परसैन्ट हमारे देश का जीडीपी एजूकेशन और हैल्थ सैक्टर में डालने का काम करे। जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपये हमारी सरकार रूरल एरिया के डैवलपमैन्ट के लिए देती है और उसके बाद वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि लगभग 80 लाख रुपये प्रत्येक गांव को सरकार देने का काम करेगी। अगर मैं सीधे-सीधे हिसाब-किताब करूं तो लगभग साढ़े चार लाख गांव हमारे देश में हैं और 80 लाख रुपये के हिसाब से हम हिसाब लगायें तो लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपये हमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए देना पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार ने क्या प्रोविजंस किये हैं, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम पैसा पहुंचाने का काम करें।

महोदय, सरकार पानी की बात कर रही थी। आज नाबार्ड को लगभग बीस हजार करोड रुपये सरकार ने दिये हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि नाबार्ड को आदेश जारी किये जाएं, जिससे नाबार्ड और

पैसा इस सीड फंड के तहत जोड़ पाये, जिसके तहत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारी नहरों को जोड़ने का जो सपना था, उसे हम जल्द से जल्द पूरा कर पायें। जिस तरह से हमने नेशनल हाईवेज बनाने का काम किया है, उसी तरह से सरकार को नेशनल वाटरवेज बनाने का काम भी करना पड़ेगा और आज जिस तरीके से पंजाब सरकार ने हमारा पानी छीनने का प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा एसवाईएल का मामला पैंडिंग पड़ा है तो उन्होंने विधान सभा में एक रिजोल्यूशन पास करके हमारा पानी छीनने का काम किया है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि तुरंत प्रभाव से मजबूत कदम उठाकर उस रिजोल्यूशन को कैंसिल किया जाए या हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अधिकार का पानी भी उन तक पहुंचाने का काम किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[*] SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR) **:** I express my sincere thanks to the Finance Minister, Shri Arun Jaitley for this budget and to our Prime Minister Shri Narendra Modi for his vision. For the first time ever, there has been such a holistic budget, which catered to the needs of people from all sectors. Right from farmers to agriculture, to growth, to investment, the Government has taken active interest in people from all sections of the society. Also, infrastructure boost along with education and youth have been prioritized.

Since the present Government took over, there has been an economic transformation. An increase in GDP growth has made India one of the world's fastest growing economies. Inflation, fiscal deficit and current account deficit have decreased and the country has recorded the highest ever foreign exchange reserves in 2015. While focusing on the growth agenda the Government is also adhering to the fiscal deficit target.

One of the many takeaways from the budget in the farm sector is that a plan has been announced to double the income of farmers in the next 5 years and a committed allocation of nearly Rs.36,000 crore has been budgeted for the sector while raising the agri-credit target to Rs.9 lakh crore for the next fiscal.

The budget has extensively focused on the agricultural sector with the announcement of launching the ambitious 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (crop insurance scheme) which will ensure lowest ever premium rates be given for farmers to end the farm distress. Besides, the Government also intends to achieve convergence of investments in irrigation at the field level through the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana.

Moving from the farmers of India to where they dwell, the Government is prioritizing electricity and roads agenda in rural India. The Government intends to connect all villages by roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana by 2019, while all of them will be electrified by 2018. The Government has a clear roadmap to alleviate poverty and assure growth in India in a time-bound manner.

---

[*] Speech was laid on the Table.

The Government has made record allocations for MNREGA to strengthen rural jobs programme and efforts will be made to assure the economically weak a house of their own under the 'Housing for All' scheme.

As much as the Government is focusing on rural India, on agriculture and farmers, the Government is equally committed to developing infrastructure and to worth mention, 85 percent of stalled road projects are back on track.

The Government is allowing 100 per cent FDI in food processing and FDI rules are likely to be eased in exchanges, insurance and asset reconstruction. Also, Shri Jaitley has proposed a divestment target of 565 billion rupees, including 205 billion as strategic sales, compared with 695 billion rupees in the previous year.

The Government has also announced a slew of initiatives in the Budget for start-ups, including 100% tax exemption for 3 years and allocation of Rs.500 crore for SC/ST and women entrepreneurs, aimed at facilitating growth for these new businesses.

The budget is aimed at taking forward economic reforms. The country's development is not only dependant on the services and sectors, but also on the people. Hence, the budget is people-centric.

Keeping this in mind, a new initiative to provide cooking gas to women of BPL families has been announced. The scheme will have a two tier benefit. This will free the 5 crore women in rural areas from the curse of smoke while cooking and will also generate employment for the youth in rural areas as they join the supply chain.

The Government has also launched 'Nai Manzil', a scheme that will benefit the minority youths who do not have a formal education with a view to enabling them to seek better employment in the organized sector and thus to equip them for better lives.

The Government is giving big push for small trades and offering tax exemptions for small business units. However, this was just not a Budget priority; the Government has been backing MSME all along. I would like to take this

opportunity to specifically mention the support that was provided to the MSME sector in Jamnagar, which is my constituency. After registering a decade long of nominal growth, the Jamnagar based brass parts industry has witnessed a turn around on the back of increased exports recently. This was made possible with the timely help and intervention of our very own Prime Minister, Shri. Narendra Modi and the Finance Minister, Shri Arun Jaitley. The Government of India had reduced the earlier levied 4% SAD on import of Brass scraps to 2%. The Government has reduced SAD on imports of brass scrap even at the cost of huge revenue outgo to benefit the Jamnagar's Brass Industries.

The benefits of duty reduction would go directly towards the efforts of revenue generation through manufacturing activities to the working class people engaged in the sector. There are 4,000 brass-making units in Jamnagar, over 80 per cent of them in the small -scale category. The industry employs over 200,000 people, directly and indirectly.

The Government has also revised and rationalized export duty on bauxite down to 5% which will immensely benefit Bauxite mine owners from Jamnagar and Devbhoomi Dwarka, Gujarat. Small miners are providing employment to about 50,000 people in backward areas of Jamnagar, this will help them retain business and also generate more employment courtesy improved business and exports.

On behalf of the people of Jamnagar, I take this opportunity to wholeheartedly acknowledge the efforts of the present Government in reviving Jamnagar brass manufacturing sector and also help legalize mining export industry to an extent.

The recent announcement of IT/ITeS policy and waiver to stamp duty on share broking transactions in Gujarat by the Government of Gujarat, along with the Union Budget announcement for IFSC will further boost the development of India's first IFSC in Gujarat.

With a view to aspire to first generation entrepreneurs and existing small businesses too, the Government is doing commendable task of granting loans to young people through the MUDRA scheme. This is one of the great steps taken by the hon. Finance Minister to meet the financial needs of the micro-finance institutions and these institutions will greatly benefitted through this step. To mention, my state of Gujarat is also benefitting largely through the MUDRA loans. The Government has disbursed around Rs.3,386 crore to the State of Gujarat for MUDRA loans.

Complimenting schemes like MUDRA; the Government has more to offer like through Start up India and Stand up India. This will provide a favourable ecosystem for start-ups, the budget has provided plans in the taxes. Skills training will also be focused to for the economically weak.

The youth of the country is moving ahead. In order to provide him employment opportunities we are going to come out with two new initiatives, 'formalizing the informal' and 'employing the unemployed.'

Our country should be protected, our citizens should feel safe and our forces should be equipped with modern defence equipment and expenditure prioritized for 'One Rank One Pension' post retirement. This budget has made provisions for boosting defence manufacturing and providing the armed forces with modern and potent equipment.

It's the people who make our nation and this Budget is aimed at improving everyone's life in some form or the other and bring about a qualitative change within a specified time frame.

* SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA) : People voted for BJP Government in 2014 General elections believing that Shri Narendra Modiji's would fulfill the promise of 'Achche Din". But I am sorry to say that very same people are feeling disgusted and cheated because of the way this NDA Government is functioning. People are realizing that the promises made during General elections were only false promises and nothing is visible on the ground. There is growing discontent in the rural India as there is no significant change taking place since the new Government came to power.

Today, the greatest concern of the people is about the falling rupee. This was one of the major promises made by the NDA Government before coming to power. They had said that they would bring the price of dollar to Rs.40 when they would come to power. Now, going by the trend, it is quite certain that it would hit a century mark. In fact, the common people of this country are not able to understand this. But when he sees in the TV that the cost of dollar has touched around Rs.67 or Rs.68 then he becomes concerned about it. I am sorry to say that this Government has not addressed this issue at all in the last three Budgets.

I would now come to the issue of the One Rank One Pension. The NDA Government had said that as soon as they would come to power, they would immediately implement this OROP scheme. But it has not happened for the last two years. Now this Government has linked it up with the recommendations of the Seventh Pay Commission. I would only say that if it is a question of the honour of our military, if it is about the honour of our countrymen, then we should go an extra mile to sort this issue out. I would urge upon the Government to implement this OROP scheme immediately.

Now, I come to the issue of Non-Performing Assets (NPAs). NPA is a matter of major concern for the financial sector and the health of our nation. To solve this issue, I would suggest that the Government can think of a settlement

---

* Speech was laid on the Table.

mechanism with the borrowers. The Government can bring forward a new policy on NPAs which could decide the criteria for treating a bad loan as NPA. It is also necessary that the repayment period of loan should also be extended and interest rates are renegotiated to enable the genuine borrowers to repay the loan to avoid falling it in the category of NPA.

The General Budget presented by the hon. Finance Minister Shri Arun Jaitely has not mentioned any significant steps to solve the problems in agriculture, infrastructure, employment and other problems. As far as agrarian crisis is concerned, there are multiple problems in this sector due to natural calamities like drought, flood, untimely rain, hailstorm, landslide, increasing cost of farm inputs, wild animals menace, unscientific fixation of minimum support price, etc. As a result, agriculture becomes economically unviable and farmers are running away from this traditional sector. It is a matter of great concern that the country's food requirement is gradually going up due to increase in population. Yet there are several thousands of people who find it difficult to have two square meals of a day. Under these circumstances, it is the need of the hour to evolve a comprehensive mechanism to make the agriculture sector more viable and attractive for our farmers.

With regard to drinking water, I would say that it is a matter of great concern that a large number of people of the country are consuming contaminated water. As per the available data, about 1600 people die every day from water borne diseases. People both in urban and rural areas are not getting safe water for drinking. A recent report of Union Ministry of Health and Family Welfare stated that the fluoride content in the water has gone beyond permissible level in nearly 14,132 habitations in 19 states of the country. Thousands of people in various states including my state Karnataka are suffering from diseases such as skeletal fluorosis. Every other day, there are reports of individuals or students in hostel and so on becoming terribly sick after consuming contaminated water. For example, a water-borne disease like Jaundice is affecting a large number of

people, but it is neglected by the authorities to control and save the health of common people with proper preventive measures. Hence, I would urge the Union Government to take effective measures to provide safe and adequate drinking water to people of the country.

India's public spending on healthcare is just 1.3% of the GDP. With 75% of the population outside the health insurance ambit, the Government needs to put the spotlight on health insurance. As per the latest records of the World Health Organizaton, patients in India pay for 58% of the total healthcare expenditure. So, I would like to request the Government to create better healthcare infrastructure in all the Government hospitals in the country.

Now, I come to the aspect of education. During XII Five Year Plan, it was expected that Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Rashitriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) will lift our school education and higher education from the current stagnancy and will help our schools, universities and colleges to attain respectable standards. The Budget proposals does not talk about RTE, RMSA and RUSA.

I would like to point out that the banks are discouraging people to avail education loan for higher studies. Due to this, talented but poor students are facing difficulties to pursue higher education. I would like to say that the proposed higher education financing agency would be an economic spring for the Indian education sector. Setting up a dedicated agency would give the thrust that is needed today. Here, I would like to say that we hardly have any university in top 500 universities of the world. We have a serious dearth of original research and focus on such area is forthcoming. Development of world-class teaching institutions is a dire need for the rapidly developing India.

The Union Government has earmarked Rs.38000 crore for MGNREGA. I would like to point out that as per the reports there are significant number of job seekers who have not got the mandatory 100 days of work. I would like to suggest to the Government that apart from allocating funds to MGNREGA, there is also

need to ensure that 100 days of mandatory work is made available to uplift the poor from the clutches of poverty.

In the end, I would only say that people have given this Government a historic mandate. This has happened because this Government had promised to the people about bringing stability, accountability, clarity in policy, predictability in policy and an efficient delivery mechanism. But, what do we see after two years and three Budgets? We only see about publicity, hyper-nationality and so on. They are not in touch with the reality. It is high time this Government understood this and take corrective steps. The Government cannot take people for granted. People have started showing signs of resentments. It is getting clear day by day when we see the results of the Assembly elections or by-elections. This Government talks only in words that they are a people-friendly Government. But, they should show it in deeds also.

SHRI NEIPHIU RIO (NAGALAND): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me time to participate in this Budget discussion for the year 2016-17.

I applaud the hon. Finance Minister for the impressive growth and for the welfare oriented Budget for the year 2016-17 presented in this august House. It is encouraging to note that the GDP growth is expected to be about 7.6 per cent and inflation to be contained at 5.4 per cent in the current financial year. Another positive indicator is that macro economic stability, which will be maintained with fiscal prudence, is evident from the fiscal deficit target of 3.5 per cent in 2016-17 from the current 3.9 per cent, in this global economic recession period.

Sir, I welcome the hike of 15 per cent Plan expenditure in the Budget, and also, the devolution of fund from 32 per cent to 42 per cent to the States and Union Territories is appreciated. The Government efforts to mob up a total receipt of Rs.19.65 lakh crore, that is, an increase of six per cent compared to the previous year, and a slew of taxation measures announced to promote growth with equity are laudable.

18.00 hours

Sir, I hope, increase in Plan expenditure will cover the development deficit areas for the exclusive growth in the country.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I have six more Members to speak on the General Budget. If the House agrees, the time for discussion may be extended by one hour including the Minister's reply.

MANY HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

Hon. Member, Shri Neiphiu Rio may continue his speech.

SHRI NEIPHIU RIO : Sir, I would like to highly appreciate the 9-Point Transformation Agenda initiated by the Government to make India one of the largest economies in the world, maybe after USA and China. These initiatives are: Agriculture and Farmers Welfare; Rural Sector – Infrastructure and Employment;

Social Sector including Healthcare; Education, Skills and Job Creation; Infrastructure and Investment; Financial Sector Reforms; Governance and Ease of Doing Business; Fiscal Discipline, Prudent Management and Tax Reforms.

Sir, while appreciating the Budget, I want to draw your attention on the progress of the country. I wish to impress upon the Union Government the necessity of according special attention to the North East region in infrastructure development and promote entrepreneurs to ensure success of Start Up India programme.

Sir, I would like to say that the Budget for NEC and DoNER has been declining and at present it is stagnant. During the 10th Five Year Plan the percentage of shortfall in the Budget was 28.24 per cent; in the 11th Plan, the shortfall was 56.07 per cent and in 12th Plan also, it is 53.80 per cent. So, the shortfall in NEC and DoNER Budget is a matter of concern. I hope the Ministry of Finance will relook at it.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI NEIPHIU RIO : The NEC Budget Estimates for 2016-17 is Rs.795 crore whereas the requirement is Rs.2000 crore. It is a matter of serious concern. The Northeast is a backward region and I speak on behalf of them. Why is it backward? The simple reason of it is that the CD Ratio in North East region is only 40 per cent whereas the national average of the same is 70 per cent. That is why we are not availing the bank opportunities. Banks are not coming forward to help the entrepreneurs. So, this being a serious issue, I hope the Finance Minister will look into it and deal with the banks. I also request the hon. Finance Minister to extend the branches of Bharatiya Mahila Bank in the North East region. Thank you.

* ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA) **:** At the outset, I would like to congratulate the Finance Minister for presenting a very good budget, taking along all sections of the society, at a time when the global economy is in serious crisis. Despite several unfavourable conditions, efforts of the Finance Minister to convert the difficulties and challenges in to opportunities deserve highest commendation.

First, I come to the agriculture sector where the allocation for farmers welfare has been increased from Rs.15,809 crore to Rs.35,984 crore, setting up a long term irrigation fund with corpus of Rs.20,000 crore. A major programme for sustainable management of ground water resources has been prepared at an estimated cost of RS.6,000 crore and provision of Rs.412 crore has been made for 'Parmparagat Krishi Vikas Yojana' which will bring 5 lakh acres under organic farming over a three year period. Rs.500 crore under National Food Security Mission has been assigned for enhancement of pulses production. A provision of Rs.5500 crore has been made for effective implementation of Crop Insurance Scheme, namely, Prime Minister Fasal Bima Yojana.

Secondly, I would like to mention about the steps taken for the upliftment of the poor people of the society, their health care and housing. In this category, the government will launch a new health protection scheme which will provide health cover up to Rs.One lakh per family. For senior citizens of age 60 years and above belonging to this category, an additional top-up to Rs.30,000 will be provided. 3000 stores under Prime Minister Jan Aushadhi Yojana will be opened during 2016-17 for supply of generic drugs. The Government propose to start a 'National Dialysis Services Programme' to provide dialysis services in all district hospitals and empowering women by giving connection in their names. There is a plan to cover 1.5 crore BPL households in 2016-17 and total 5 crore households across three years. An amount of Rs.2000 crore has been earmarked for the purpose. Further, under Pradhan Mantri Awas Yojana, the Government proposes

---

* Speech was laid on the Table.

to give 100% deduction for profits to an undertaking from a housing project for flats up to 30sqare meters in four metro cities and 60 square meters in other cities, approved during June, 2016 to March, 2019 and is completed with three years of the approval.

Thirdly, for the development of the rural areas, a sum of Rs.2.87 lakh crore will be given as Grant in Aid to Gram Panchayats and Municipalities as per the recommendations of the 14th Finance Commission. This is a quantum jump of 228% compared to the previous five year period. The funds now allocated, translate to an average assistance of over Rs.80 lakh per Gram Panchyat and over Rs. 21 crore per Urban Local Body. A sum of Rs.38,500 crore has been allocated for MGNREGS in 2016-17. Rs.8,500 crore has been provided for village electrification under Deendayal Upadhayaya Gram Jyoti Yojana and Integrated Power Development Schemes. All villages will be electrified by 1st May, 2018. In order to develop governance capabilities of Panchayati Raj Institutions to deliver on the Sustainable Development Goals, Rs.655 crore has been set apart in 2016-17. Rs.9000 crore has been provided for Swachh Bharat Mission-India's biggest drive to improve sanitation and cleanliness, especially in rural areas.

My fourth point will cover public spending on infrastructure which has been massively increased to Rs.2.21 lakh crore, which is 22.5% over the previous year. Aiming to complete construction of 2.23 lakh kms of roads by 2019 instead of 2021, with central allocation for PMGSY increased to Rs.19,000 crore, about twice of that in 2012-13. Together with the capital expenditure of the Railways, the total outlay on road and railways will be Rs.2,18,000 crore in 2016-17. For development of new Greenfield ports, provision of Rs.800 crore has been made.

My next point will cover education and skill development. 62 new Navodaya Vidyalayas will be opened in the remaining uncovered districts over the next two years. The Government also proposes to set up a High Education Financial Agency (HEFA) with an initial capital base of Rs.1000 crore. Rs.1700

crore has been earmarked for setting up of 1500 Multi Skill Training Institutes across the country.

In so far as my home state Goa is concerned, I compliment the Finance Minister for exempting the mining industry from 10% export duty. As mining is an important aspect of the Gaon economy and employs a significant section of the state population. I am sure this exemption will contribute to the economic development of the state.

To conclude, the Budget 2016-17 represents a balance between the commitment of the Prime Minister to the citizens of the country and the commitment of the Finance Minister to financial market, investors and global credit rating agencies. I am sure, all efforts being made by the Government in this direction will be crowned with success.

***श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर)**- मैं प्रधानमंत्री के विजन को साकार रूप देने वाले हमारे बहुआयामी व्यक्तित्व क्षमता और योग्यता के धनी वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट के पक्ष में अपना समर्थन करता हूं। हमारा यह समर्थन शाब्दिक अभिव्यक्ति से अधिक राष्ट्रीय सोच और अनुभूति का प्रकटीकरण है। याद करें दो वर्ष पहले का माहौल जब पूरे देश में एक अजब किस्म की हताशा और टूटन का माहौल था। सच्चाई का स्तर प्रतिशत कुछ भी हो लेकिन पूरे देश में चौतरफा हर जुबान पर केवल और केवल भ्रष्टाचार, लूट-खसोट और घोटालों की चर्चा थी।

पूरे देश में ऐसा माहौल था कि मानों अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। मैं स्पष्ट कर दूं कि पूर्ववर्ती सरकारों की लूट-खसोट से हुयी आर्थिक क्षति तो देश को चोट पहुंचा ही रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी क्षति राष्ट्रीय सोच और मानसिकता में पैदा हुई यह नकारात्मकता थी कि यह देश भ्रष्टाचार के दलदल में धंस कर पतन के उस गर्त में डूब जाएगा जहां से उबरना नामुमकिन नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। यह मानसिकता इसलिए और ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि यह देश नौजवानों का है। यह दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जिसकी 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से नीचे की है। यह नौजवान तबका न केवल ऊर्जा, कौशल और योग्यता से लवरेज है बल्कि इसके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे जीवन्त जाग्रत युवा शक्ति को हताशा और नकारात्मकता के माहौल में धकेल देने से बड़ा अपराध क्या हो सकता है। निराशा के माहौल में भारत को बदलने का संकल्प लेकर हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभाली। जादुई छड़ी तो किसी के पास नहीं लेकिन देश के माहौल में आये बदलाव की अनुभूति गांव की गली से लेकर संसद के गलियारों तक हर किसी को हो रही है। ये जाना समझा तथ्य है कि भारत गांव का देश है और इसके विकास का कारवां खेत खलिहान और पगडंडियों से होकर आगे बढ़ना है। मुझे आज यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा को मूर्त रूप देते हुए वित्त मंत्री जी बजट का फोकस ट्रांसफार्म इंडिया के इसी एजेंडे की ओर रखा है। कृषि और किसान कल्याण की तमाम परियोजनाओं के अलावा पहली बार किसानों को आय सुरक्षा देने

* Speech was laid on the Table

की अवधारणा पर काम शुरू हुआ है। इसके लिए 35984 करोड़ रूपए का विशाल बजट आवंटन सन् 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए रखा है।

यह केवल हवा-हवाई संकल्पना नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वाथ्य कार्ड स्कीम, परम्परागत कृषि विकास योजना और जैविक मूल श्रृंखला विकास की परियोजनाएं खड़ी की जा रही है जो जमीं पर उतरने के बाद गांव की तस्वीर बदलने वाली साबित होंगी।

इस श्रृंखला में अतिशय क्रांतिकारी प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता जिसने आपदाओं से टूटे किसानों को न केवल जीने का हौसला दिया है, बल्कि अपने कल्याण के नए उपक्रम कर सकने का जोखिम उठाने की क्षमता भी दी है।

इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और दूध उत्पादन के साथ-साथ शहद उत्पादन के महत्वाकांक्षी प्रयास पर्याप्त वित्त पोषण के साथ शुरू किए गए है। कृषि और ग्रामीण विकास में विभाजन की कोई रेखा खींच पाना बहुत कठिन है इसीलिए बजट का पूरा फोकस कृषि के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की ओर रखा गया है जहां ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को 2.78 लाख करोड़ की राशि देकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। वहीं सूखा और ग्रामीण आपदा वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए मनरेगा जैसी रोजगार परक योजनाओं के आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है।

वोटों के लालच में देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठे लोगों द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों पर इस अथवा उस संप्रदाय का हक गिनाये जाने के विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की अंत्योदय संकल्पना को ही केंद्र में रखकर यहां नारा दिया है कि ''देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक यहां के सबसे गरीब निवासी का है।'' उनकी इसी सोच ने 'सबका साथ सबका विकास' की अवधारणा को व्यापक समर्थन और विस्तार दिलाया है। गांव को विकसित किये बिना और वहां रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन के साधन जुटाए बिना शहरों की ओर पलायन को रोका नहीं जा सकता। इसी समेकित दृष्टि के साथ गांव के विद्युतीकरण वहां की साफ-साफाई, डिजिटल साक्षरता का विस्तार समेत कई योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया है। आजादी के 70 साल बाद तक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की बातें तो बहुत हुई, किन्तु पहली बार बीमा और पेंशन की सर्वस्पर्शी योजनाएं लागू कर देश को सच्चे अर्थों में सुरक्षित और

संरक्षित होने का भरोसा दिलाया है। खान-पान की अशुद्धता और परिवर्तित जीवन शैली ने मानवता को बीमारियों के ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जिनका इलाज तो दूर जांच करवाना भी आम आदमी के बूते के बाहर है। ऐसे लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कैंसर और गुर्दे की बीमारियों की चिकित्सा के विशेष उपाय प्रस्तावित किये गए हैं। गरीबी हटाओ के दशकों पुराने वादों का खोखलापन अब सबके सामने उजागर हो चुका है। पूर्ववर्ती सरकारों के कुशासन और भ्रष्टाचार ने गरीबी के बजाय गरीबों को ही मिटाने की स्थितियां पैदा कर दी थी। ऐसे में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीं पर उतारते हुए कौशल विकास, रोजगार सृजन और अवसंरचना विकास के जो उपाय किये हैं उससे आशा और उत्साह का नया वातावरण दृष्टिगोचर होने लगा है। स्थितियां आज भी कम गंभीर नहीं हैं पूरी दुनिया गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना आधार मजबूत बनाए रखा है। इस सरकार की नीतियों की बदौलत पूरे विश्व में भारत को लेकर अपार विश्वास और आशा कायम है। शायद इसी लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्यस्था के बीच भारत को एक देदीप्यमान प्रकाश स्तम्भ नाम दिया है।

प्रधानमंत्री की दृष्टि में विकास की गतिविधियों के विकेंद्रीयकरण और उसे समावेशी बनाने का बड़ा महत्व है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कभी पूर्व के मैनचेस्टर कहलाने वाले कानपुर की आर्थिक, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा और संबल लिए जाने की आवश्यकता है, ताकि गंगा के किनारे बसा यह पौराणिक शहर अपनी गरिमा और समृद्धि को कायम रख सके। पर्यटन, राजस्व के साथ-साथ रोजगार का भी बड़ा जरिया है और कानपुर के बगल में स्थित बिठूर जिसे पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मावर्त के रूप में जाना जाता है, के महत्व को कैसे नकारा जा सकता है। केंद्र अपने पर्यटन मानचित्र पर बिठूर को रखकर विकास की परियोजनाएं बनाए तो क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। हमारे संसदीय क्षेत्र का लगभग सम्पूर्ण हिस्सा ग्रामीण और कृषि प्रधान है जहां सिंचाई की परिस्थितियां अत्यंत विषम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इस क्षेत्र के किसानों के मन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। खास तौर से यमुना पट्टी के दूरदराज गांवों में बसे किसानों को बहुतेरी उम्मीदें हैं। याजनाएं बनाते समय उनका ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। देखने, सुनने में आता है कि औद्योगिक विकास की राह में एक प्रमुख रोड़ा जमीन की अनुपलब्धता है। कानपुर देहात की यमुना पट्टी में तमाम ऐसी भूमि पड़ी है

जिसके समतलीकरण के बाद औद्योगिक इकाइयां लगाए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित देखने का जो सपना संजोया है, जेटली जी का यह बजट उस दिशा में तीव्र और क्रांतिकारी परिणाम लाने वाला साबित होगा और ट्रांसफार्म इंडिया का उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा इसी भरोसे के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

* SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) : The highest ever allocation for MGNREGA, rural roads and agriculture, new road projects under the extremely-aided project category and the Prime Minister's rural road scheme will really contribute to the development of the country significantly. I hope my state Karnataka would also get better deal in all these schemes taken up by the NDA government led by Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi.

I would also mention that increasing allocation for road sector would help revival of the stalled national highway project, which will help the state to complete several incomplete road projects. The state has several national highway proposals pending before the Union Surface Transport Department. Hence, I request the Union Government to take steps to clear all those road projects to ensure balanced development across the state.

I welcome the steps to introduce new projects like a dialysis unit in every district hospital, and Rs.1 lakh health insurance for senior citizens from BPL families could come as a big relief for villagers all across the country.

As per the UN Human Development Index, 2015 India is lagging behind. But Union Budget presented by the Finance Minister does not show adequate commitment and financial allocation towards it to remove this malady. The United Nations Human Development Report, 2015 has ranked India at 130th position among 188 nations listed in the UN Human Development Index. Among BRICS countries, India is left behind by Russia, Brazil, China and South Africa.

The Budget has announced that 62 more Navodaya Vidyalayas will be opened in the next two years. There are thousands of government schools functioning without proper school building, there is no quality education due to poor infrastructure, lack of teaching faculty in those schools. But there are no indications how millions of government schools will be improved to provide quality school education. Right to Education (RTE) was launched in 2009 with lot

* Speech was laid on the Table.

of noble expectations, but the RTE scheme is losing its steam due to half-hearted implementation and lackluster execution.

During XIIth Five Year Plan, it was expected that Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) will lift our school education and higher education from the current stagnancy and will help our schools, universities and colleges to attain respectable standards.

Another important point I would like to make is - we hardly have any university in top 500 universities of the world. We have a serious dearth of original research and focus on such area is forthcoming. Development of world-class teaching institutions is a dire need for the rapidly developing India. In that direction, it is good step from the Government for enabling a regulatory architecture to provide to 10 public and 10 private institutions to emerge as world-class teaching institution. I hope it would help the Higher Education sector which has been sluggish for past few years and it will get a much-needed stimulus to grow further.

As it is proposed in the Economic Survey, I would also like to suggest that a free market for agriculture with direct transfer of cash should be put in place to replace subsidies for fertilizers, food and the minimum support price be paid to farmers to ensure transparency and to plug leakage. Such a free market will end all controls on domestic movement and import of food, etc.

As we are all aware that the country's rural sector is reeling under two consecutive droughts. The severe drought has lead to widespread distress in many states including Karnataka. The State government of Karnataka has declared drought in 27 out of 30 districts as it received 35 percent deficient rainfall. The Centre has approved Rs.1540 crores. Hence, I request the Union government to direct the state government to utilize the money for drought relief activities at the earliest.

SHRI T. RADHAKRISHNAN (VIRUDHUNAGAR): Hon. Chairman, Sir, *Vanakkam*. I express my gratitude and sincere thanks to our beloved leader Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma for giving me an opportunity to participate in the Discussion on the General Budget 2016-17.

Our hon. Chief Minister, *Puratchi Thalaivi Amma* has welcomed the emphasis made in this budget on agriculture and rural income. I would like to request the Union Government to allocate the funds for Tamil Nadu as requested by our hon. Chief Minister, *Puratchi Thalaivi Amma* for providing financial support to lakhs of farmers in Tamil Nadu who have been affected due to the damages and devastations caused by floods.

The hon. Chief Minister, *Puratchi Thalaivi Amma* has asked the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi to release Rs 25,912.45 crore for relief and restoration works in those parts of the State which were devastated during extremely heavy flood in the first week of December 2015. The Union Government has so far provided Rs.1940 crore only. This is absolutely inadequate considering the heavy damages caused by the floods to the properties and belongings of the people in Tamil Nadu.

Sir, agriculture and agro-based industries are the backbone of our country. Farmers and agro-based allied workers constitute about 60 per cent of our total population. Braving the most hostile and difficult problems, the farmers continue to toil hard to fulfill our farm needs. Their service and sacrifices have to be appreciated appropriately in order to keep them engaged continuously in agriculture. Farmers need to be encouraged as much as possible by way of introduction of comprehensive crop insurance schemes, issuance of kisan credit cards to all the farmers in the country and providing them with adequate financial support as well as ensuring to them adequate supply of seeds, fertilizers, insecticides and pesticides, farm equipments etc. Also, farmers should be encouraged by providing them good and reasonable Minimum Support Price for

their produce.

In the times of drought or natural calamities like floods, their crops get damaged completely and at such times, the agriculture loans provided to them need to be waived completely. Also, farmers should be given proper compensation for the loss of their crops and it should be done on a war-footing mode. Otherwise, the cash starved farmers may not be in a position to continue practising agriculture after the damage of their crops due to flood or loss of revenue due to severe drought conditions.

The Government should focus more on the overall development of agriculture and farming industry to provide a ray of hope to the Indian farmers. Farmers should be provided all the necessary financial, logistic and trade support to do trade on their own and get maximum benefit. The gap between the producer and the end-user, - the farmers and consumers - has to be narrowed. The middleman menace has to be curbed completely so that farmers get decent income for their produce and the consumers should also be made to pay less.

Therefore, I urge upon the Union Government to provide all necessary support to farmers, on the lines our Amma has done, for them to come out of the clutches of drought conditions and flood situations and make their life brighter and wealthier forever.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Puratchi Thalaivi* Amma had sought the assistance of the Union Government for implementation of a proposal to divert the flood waters of Cauvery to drought prone areas by linking the rivers Cauvery, Vaigai and Gundar at a cost of Rs. 5,166 crore. This project proposal should be approved quickly.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member Shri Asaduddin Owaisi, you may start now.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I stand to oppose the Budget over here. At the outset, I would like to reiterate that the one per cent Central Excise Duty, which has been imposed on jewellery, should be taken back immediately. If it is not done, it will lead to destruction of the 2,000-year old industry.

Sir, I would like to quote what has been said by the hon. Finance Minister when he spoke in the Haryana Investment Summit. He said:

> "We must bear in mind that social challenges emerge and one of the principal reasons they emerge is on account of inequalities between communities."

If I put this statement in front of me and see what he has done for the most backward community, it is not good. I say this on the basis of the empirical data which is available. The hon. Finance Minister has stated that social challenges emerge because of inequalities. But when you have seen his Budget, he is perpetuating social inequalities. How is it that by decreasing the Budget of Pre-Matric Scholarship of minorities of Rs. 109 crore by Rs. 30 crore?

The empirical data tells us that the MHRD in 2014 had commissioned a survey of 640 districts wherein it found that out-of- school children of Muslims are 25 per cent and SCs and STs are 49 per cent. The Kundu Committee says that current attendance of Muslims as compared to other social / religious communities is the lowest in the age group of 6 years and 14 years and also in the age group of 15 years and 19 years. The children who have never attended -- within the age group of 6 years and 14 years -- are again from the Muslim community.

How is it that the Finance Minister has decreased the Budget of Pre-Matric and Post-Matric? He has decreased the Budget of Scheme to Provide Quality Education to Madrassas and Minorities to the tune of Rs. 256 crore. This Budget was there to construct schools for minorities and to modernise the Madrassas so

that the Madrassas can get good teachers and you have decreased Rs. 256 crore. He has not only done that, but he has finished the scheme of improvement of State Wakf Boards. Last year, it was Rs. 7 crore, and not a single pie is there. May I request, through you, to the Government that you allow the MPLAD Funds to be used for the development of Wakf Board so that we can develop the Wakf properties and generate income?

Let me also point out about priority sector lending. An RTI Application has come today in a national newspaper, which has clearly told that 15 per cent is earmarked for minorities, but only two per cent Muslims are getting their share in priority sector lending. What is the Government doing? Can the hon. Finance Minister -- when he replies and he is a very eloquent speaker -- please enlighten us as to whether he has taken a single meeting of priority sector lending wherein to ensure that the share of Muslims, within the 15 per cent, increase in priority sector lending?

This is the last year of the Twelfth Five-Year Plan. Only 60 per cent of what has been allocated for the Maulana Azad National Fellowship has been given. I do not blame this Government, and the Congress also has to take the blame equally. There is 62 per cent allocation for NMDFC; 79.6 per cent for MsDP; and this year, the hon. Finance Minister has decreased Rs. 126 crore for the Multi-sectoral Development Plan. How do you realise that development should come up in 60 districts and 110 blocks?

You talk about *sabka saath sabka vikaas*. Why has the Finance Minister decreased the Budget of AMU as compared to BHU? Nearly, Rs. 120 crore less you have given to AMU as compared to BHU.

Lastly, an RTI Application has come out about the AYUSH Ministry. Is this the Government policy to say that Muslims will never be given an employment opportunity in AYUSH? An RTI Application has come out and it is so shameful. Is this the policy of the Government? If that is wrong, then let the

Government take action against that officer. An RTI Application with stamp is there.

I conclude by congratulating the Finance Minister for presenting a socialist Budget, which is against their ideology. Thank you, Sir.

[*] DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I thank the Hon'ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley for announcing fresh proposals to shore up the Agriculture sector, which has suffered enormously due to the vagaries of weather and flawed policies in the last two years and seeking to please the common man through concessions to bottom level tax-payers.

BJP led NDA Government had given election manifesto to implement Dr. Swaminathan Committee Report for M.S.P. But unfortunately the manifesto has not yet been implemented, though Finance Minister submitted the Budget for the third time. The Farmers are the backbone of our society. They are suffering a lot due to absence of good marketing facilities.Krishak Bazar should be located in nooks and corners of our country. Steps should be taken for implementation of Dr. Swaminathan committee for M.S.P. at the earliest.

The big pro-farmer measure in the Budget is the Krishi Kalyan Surcharge that will be levied on all taxable services to improve agriculture and overall economy. The Krishi Kalyan cess would cover all services, proceeds of which will be used for financing incentives for improvement of agriculture and welfare of farmers. The cess will come into effect from 1st January.

At the same time, there is reduction of duties in project imports for cold rooms, for cold chains, refrigerated containers and a number of other items. It is a welcome step for hike in excise duties from 10 to 15% for cigarettes, tobacco products and luxury cars, while solar lamps and footwears will cost less.The unexpected amnesty scheme for the Black Money amounts to an admission that the Government is not able to unearth Black Money in India on a significant scale, despite the huge powers it has assumed under the Income Tax Act, 1961.

Noted Lawyer Palkiwala observed "Amnesty Scheme results in transfer of resources from the honest rich to the dishonest rich"

It is not clear why Section 80C of the IT Act has been amended to place a cap of Rs. 1.5 lakh on the tax exempted amount contributed by an employer to an

[*] Speech was laid on the Table.

employees' Provident Fund. More importantly, why 60% of all pensions and P.F. withdrawals of Salaried sections be taxed?

In spite of expenditure on Public Health at a mere 1.2% of GDP, there has no mention of increase in public health spending in the Union Budget. However, Finance Minsiter outlined certain reforms in regard to new health projections and health cover schemes.

Rs. 1 lakh per family coverage shall not be enough to take care of cardiac emergency and poly trauma though.

Creation of dialysis centres in the hospitals will keep in tackling in rising chronic cases of rural families, but it has to be ensured that the facilities are well maintained and functional always. The start of drugs stores is concerned , it should be ensured that the generic medicines are tested and of the best quality.

Regarding Budgetary allocation in education, there is a mismatch when it comes to allocation. Overall the hike of Rs 48,68 crore over the revised estimate of Rs 67,586 crore. A big programme like SSA has a meager hike in the mid-day meal scheme allocation.

Already, SSA and MDM are floundering on quality issues and safety, despite devolution of funds have failed to prioritise education.

Similarly, RMSA and RVSA, both parts of the 12th Five Year plan, found no mention in the Budget.

Lastly, I would like to urge upon the Union Government to provide Special Category Status to my State, Odisha as demanded by our Hon'ble Chief Minister, Odisha Shri Naveen Patnaik.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2016-2017 के आम बजट पर धन्यवाद भाषण करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, माननीय वित्तमंत्री अरुण जेटली साहब को धन्यवाद देना चाहती हूं और जयंत सिन्हा साहब को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने पहली बार एक शानदार बजट बनाया है। इस बजट को ग्रास रूट पर किसानों ने सराहा है, आम आदमी ने सराहा है, महिलाओं का जहां सम्मान किया गया है, पढ़े-लिखे नौजवान की जहां फिक्र की गयी है।

सभापति महोदय, हमें विरासत में जो हालात मिले थे, उसे सारा देश जानता है। लड़खड़ाती हुयी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का यह भगीरथी प्रयास जेटली साहब ने किया है। यह तीसरा आम बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें उनकी विद्वता और दृढ़ संकल्प स्पष्ट झलकता दिखायी दे रहा है। माननीय सभापति महोदय लगता है कि वह कह रहे हैं -

"आसमां की ज़िद है, वह बिजलियां गिरायेगा यहीं
हमने भी ठाना है कि हम आशियां बनायेंगे वहीं।"

ऐसा लगता है कि जैसे देश के समस्त वातावरण में...(व्यवधान) आपके पेट में दर्द हो रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, पर आम जनता इस बात को कहती है कि पहली बार हिन्दुस्तान की संसद में वह बजट प्रस्तुत हुआ है, जिसको खेती से लेकर व्यापार तक और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है, उसको पूरा हिन्दुस्तान सैल्यूट करता है। जेटली जी द्वारा पेश बजट में किसान की बेहतरी के प्रयास किए गए हैं। इस बजट में गांव की दिशा और दशा सुधारने के कारगर कदम उठाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि बजट के प्रावधानों से देश की आर्थिक विकास की दर और बढ़ेगी। दरअसल 2016-2017 का बजट नौ अलग-अलग मुद्दों को लेकर बनाया गया है। कृषि और किसानों का कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का सामाजिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, विनिवेश, वित्तीय सुधार, शासन और कारोबार में सुगमता, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार पर आधारित यह बजट अपने आप में एक शानदार बजट है। बजट में 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। अभी तक सिंचाई के अभाव में किसान को काफी आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते थे। अब सिंचाई की व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर किसान का जीवन खुशहाल बनेगा। जब गांव में खुशहाली आएगी तो देश स्वत: ही विकास की डगर पर आगे बढ़ेगा।...(व्यवधान)

मुझे बोलना बहुत कुछ था लेकिन पुन: आपका आभार व्यक्त करते हुए एक बात अपने विपक्ष के दोस्तों को कहना चाहती हूं --

कभी-कभी दीया तेल के अभाव में भी बुझ जाता है।
हमेशा दोष हवाओं का नहीं होता।

धन्यवाद।

[*]**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी की सरकार ने अपने दो साल की अवधि पूर्ण नहीं की है परन्तु जिस प्रकार से देश के विकास एवं बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं ।

इस साल के जनरल बजट के लिए मैं हमारी सरकार प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । यह बजट गरीबों, किसानों और गांव का बजट है । मुझे स्मरण होता है कि भारत के इतिहास में इस प्रकार गांव की इकोनोमी, कृषि तथा गरीबों की बात करने वाला शायद ऐसा बजट पहले कभी आया नहीं है । इस सरकार की चुनौतियों को ध्यान में लिया जाए तो बढ़ती हुई वैश्विक मंदी के जोखिम, 7वें वेतन मंच की सिफारिशें तथा एक रैंक एक पेंशन के कारण काफी अतिरिक्त राजकोषीय बोझ को होते हुए भी सरकार गरीबों और गांव के लिए बेहतरीन बजट पेश किया है । इस बजट में कृषि तथा किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रू. का आवंटन किया है ।

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" को मिशन मोड़ में लागू किया जाना और सिंचाई के अधीन 28.5 लाख हैक्टेयर जमीन को लाया जाए । आईबीपी के तहत् 89 सिंचाई योजनाओं जो अपूर्ण रही है उसे त्वरित कार्यान्वयन किया जाएगा ।

- नाबार्ड में लगभग 20,000 करोड़ की प्रारंभिक विधि से एक दीर्घकालीन सिंचाई नीधि सृजित की जाएगी ।
- "सोएल हेल्थ कार्ड" स्कीम की बजट से 14 करोड़ क्षेत्रों को शामिल किया जाए ।
- फर्टिलाइजर के नए 2000 खुदरा केन्द्रों के जिरये उर्वरक मुहैया किया जाएगा और नीम कोटेड यूरिया के जरिए यूरिया किसानों के पास पहुंचे उसको निश्चित किया जाएगा ।
- औरगेनिक फार्मिग के जरिए उर्वरकों के अतिशय इस्तेमाल की वजह से बेजान हुए खेलों को फिर से नव पल्लवित किए जाएंगे ।"परंपरागत कृषि विकास योजना" की वजह से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा ।
- "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत आवंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रूपये किया जाएगा और 2019 तक शेष 65000 गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5500 करोड़ रू. का आवंटन होगा ।
- अगले पांच सालों में किसानों की आवक दुगुनी की जाएगी ।

[*] Speech was laid on the Table.

श्वेत क्रांति के जरिये चार डोरीयां परियोजनाएं की वजह से कुछ उत्पादन बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 850करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है । महोदय, ग्रामीण विकास के लिए 87,700 करोड़ रू. का आवंटन किया जाएगा जिसकी वजह से हर गांव को 80 लाख रू. विकास के लिए मुहैया किया जाएगा । हर नगरपालिका को करीबन 21 करोड़ आवंटित किया जाएगा । मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ का अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है । 1 मई, 2018 तक शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा ।

किसान को अपनी खेत पैदाइश के सही दाम के लिए ई-प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 तक बाबा साहेब अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर उपलब्ध् किया जाएगा । महोदय, इस बजट में स्वास्थ्य में अन्य प्रावधान किए गए हैं । स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए बजट में 1,51,881 करोड़ रूपये का भारी आवंटन किया गया है । नई स्वास्थ्य रक्षा स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को एक लाख रू. तक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी । वरिष्ठ नागरिकों को इसके अलावा 30000 रू. तक अतिरिक्त टोप-अप पेकैज मिलेगा ।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत "राष्ट्रीय डायलसिस सेवा कार्यक्रम" हर जिला हास्पिटल में किया जाएगा । वर्ष 2016-17 में "जन औषधि योजना" के तहत अतिरिक्त 3000 स्टोर खोले जाएगें जिसमें दवाईयां 40% कम दाम पर उपलब्ध होंगी ।

- अनुसूचित जाति और जनजाति उद्योग संघों की भागीदारी से हब बनाया जाएगा तथा प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम दो परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए "स्टेन्ड अप इंडिया स्कीम" से कम से कम 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ मिलेगा ।

- देश में हर बी.पी.एल.परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा जिसके लिए 2000 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है ।

इस बजट में कौशल विकास के तहत रोजगार सृजन का ध्येय रखा गया है । राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में तेजी आयी है तथा ईन्फ्रास्टक्चर, ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है । हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण होगा । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

* SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR) **:** India has a serious problem. Indian farmers are continuing to take their own lives as monsoon failed in certain parts of India for the second straight year in a row. Parts of Maharashtra, A.P., Telangana and Odisha have been severely affected on account of poor monsoon and this has led to a continuing spate in farmer suicides.

While monsoon failure tops the list, lack of state investment in water conservation and management has only added to the problem. Adding to this has been lack of soil health management and monitoring, improper seed selection and timely distribution, lack of adequate crop insurance, and timely disbursal of insurance relief, which have all contributed to the overall distress faced by farmers. Maharashtra can lay claim to many records that point to positive achievement, but it also has the dubious distinction of witnessing 3,228 farmers committing suicide in 2015, the highest since 2001.

As per Union Agriculture Minister, Maharashtra Government has responded by identifying 1,841 cases of the 3,228 farmers committing suicide, as being eligible for ex-gratia payments, 903 cases were classified as ineligible and 484 cases were still under enquiry process. The Minister stated that Rs.1 lakh had been paid as immediate relief to 1,818 families of farmers that committed suicide.

Each year, larger sums are allocated to the farming sector but farmer suicides have continued to increase. The obvious conclusion is that benefits are not reaching the section of farmers that need maximum support.

Therefore, unless the government takes up the focus on small and marginal farmers and ensure that maximum benefits are allocated to them, mere budgetary provisioning will not work. In Maharashtra, most of the funds that were allocated for building catch dams have either turned into white elephants or the benefits have been cornered by certain large farmers with strong political affiliations.

The present crisis in Maharashtra could well have been avoided if proper fund allocation, management and monitoring would have been followed in the past

* Speech was laid on the Table.

15 years. If Arun Jaitley, along with the Union Agriculture Minister, fails to break this vicious cycle, farmer suicides will continue unabated. Can a country that gave the call 'Jai Jawan -Jai Kisan' really afford that.

SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Since I am going to speak in Telugu, I would request the hon. Minister of Finance and the hon. Minister of State for Finance to listen to the translation.

[*]Sir, today people of this country are happy about this New Budget. I am happy to note that concerns of farmers and people living in rural areas were taken care of in this budget. Though this Budget is good, there are some issues and demands which were neglected and I would like to bring to your notice those issues. Hon'ble Speaker, I would like to know from the Government why the long pending demand to confer Special Status to Andhra Pradesh has been ignored. Madam, at the time of bifurcation of Andhra Pradesh, the party in power promised Special Status to Andhra Pradesh for 5 years, whereas the party in opposition demanded that status for 10 years. Though the state was not bifurcated in scientific manner, I was happy that there will be some relief for Andhra Pradesh. This is third Budget of this Government and I am disappointed that provisions of bifurcation act could not be fulfilled by this Government. Whenever Central Ministers visited Andhra Pradesh they said that there is a need for political resolution.

18.18 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

In spite of having narrow majority, UPA Government bifurcated Andhra Pradesh in an unscientific manner with the help of political resolution. Today even after having absolute majority, why NDA Government is hesitating to confer Special Status to the State of Andhra Pradesh.

Madam, I just started my speech. Hon’ble Prime Minister announced Rs. 1 lakh crores Special package to Bihar. We have no objection as Bihar is a backward state. Similarly Rs. 60,000 crores Special Package was announced for J&K. As a special consideration, we welcome that move as well. Hon’ble Prime Minister brought holy soil from Parliament and Ganga water for the proposed Capital City

[*] English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

of Andhra Pradesh. People of Andhra Pradesh eagerly waited for favourable announcement from the Prime Minister. 5 Crores people of Andhra Pradesh were glued to their Television sets for the most awaited announcement. But nothing was announced.

Therefore, I request the Central Government to protect Andhra Pradesh by conferring Special Status and help our State in its rebuilding. One more minute madam. I am happy about the Government's concern for rural areas. There is an assurance to improve income in rural areas, which is a commendable resolution. There are regions like Anantpur, which are frequently affected by drought. Shri Arun Jaitley visited this place during inauguration of Customs and Excise Academy and assured that he will consider problems of drinking water and drought in Anantpur. I demand Finance Minister to consider these problems and do justice to our region.

* SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR) : I thank the hon. Finance Minister for presenting the budget this year and applaud the NDA government's delayed yet much appreciated acknowledgement of the importance of Aadhaar card and MGNREGA schemes introduced by UPA.

Even though the NDA government has claimed that this year's budget is pro-farmer and promised doubling of farmer's annual income by 2022, the budget acutely falls short of a plan for the same. Keeping in mind the drought situation, allocation towards MGNREGA could have been enhanced thereby creating job opportunities to support livelihood. This is when there has been a decline in the number of households under MGNREGA, person-days of employment generated and average days of employment. The total number of families that asked for employment last year was 1,95,13,989 while only 86,75,141 jobs were made available. By December last year, 95% of the budget allocated for 2015-16 was already spent, which meant an additional fund of Rs.6300 crore was still required to run MGNREGA till March this year. Only Rs.2000 crore was assigned. There was not a word in the budget about minimum support price for farmers. There has been 26 per cent increase in farmers' suicide since NDA took power.

The allocation made towards the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has seen a constant decline under the NDA Government. If you compare the figures released by the government, under the UPA government the budgetary allocation increased every year, Rs.25,338 crore in 2012-13, Rs.27,049 crore in 2013-14, Rs.28,198 crore in 2014-15. This trend was reversed when the NDA government took power with an allocation of Rs.21,828 crore in 2015-16. Now they claim to be increasing allocation for farmers, but in fact the allocation of Rs.25,700 this year is much lower than that under the UPA. The budget has set aside a negligible amount of Rs.1,377 crore for Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP). My State Karnataka won't get more than Rs.100-150 crore out of this fund when there is dire need for it. The budget has slapped a 9.36 per

* Speech was laid on the Table.

cent duty on import of raw cashew, which has affected a lot of cashew processors in different states including Karnataka. Raw cashew nut imports had been so far exempted from import duty on grounds that the cashew industry was providing employment to about 7 lakh women and is the second largest industry in the country providing employment to rural women, after tea industry. Sericulture farmers across the nation, particularly in my state, Karnataka, which happens to be India's leading raw silk producing State, are disappointed over the Union Budget's failure to increase the customs duty on import of raw silk. The customs duty on imported silk, which used to be around 30 per cent a couple of years ago to ensure that the price of indigenously produced silk remained competitive in the market, had been brought down to 10 per cent, affecting a larger number of sericulture farmers. At reduced import duty, the superior quality Chinese silk is available at low rates, which pushes indigenously produced silk's price further down.

Funding for Integrated Child Development Service Programme has been reduced from Rs.16,361 crore in 2014-15 to Rs.13,888 crore in 2016-17. The figure of Rs.71,139 crore allocated towards education constitutes only 3.7 per cent of the GDP, a fall of one percent from last year. The Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA), both part of the 12th Five Year Plan, found no mention in the budget. Over the last two years, there has been a net effect of 7% reduction since there was a 10 per cent cut last year in planned outlay from Rs.43,517.9 crore in 2014-15 budget estimates to Rs.39,038.5 crore in 2015-16 in the primary education sector. This is when the Economic Survey has pointed out that there is decline in percentage of enrolment in government schools in rural areas, from 72.9 per cent in 2007 to 63.1 per cent in 2014. NITI Ayog had recommended Skill Development for students in Madrasas which does not find mention in the National Education Mission announced.

The provision of Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan has been violated in the NDA-II budget. As per the provision, out of the total budget of

Rs.19.78 lakh crore, there should be 16.8 per cent for Scheduled Castes and 8.8 per cent for Scheduled Tribes, as per their total population, allocated under SCSP and TSP. But only Rs.38,833 crore for SCSP and Rs.24,005 crore for TSP have been allocated. A total amount of Rs.75,764 crore has been denied by violating the provision.

There is lack of clarity on the government's promise of ensuring accessible and affordable healthcare by opening 3000 stores under PM Jan Aushadi Yojana since only last month the Central Board of Excise and Customs issued a notice withdrawing customs exemptions on 76 life-saving drugs, including those used in the treatment of diabetes, cancer, HIV etc. The government also intended to withdraw customs concessions meaning a tax of up to 22% on the imports of healthcare products.

Required amount to tackle the problem of Non-Performing Assets (NPAs) in public banks is Rs.4 lakh crore, but the government has allocated only Rs.25,000 crore. The Budget has also made a meager provision for strategic petroleum reserves for maintaining reserved oil stocks. This year's budgetary allocation of Rs.3 crore is insufficient compared to last year's allocation of Rs.1200 crore. Lower oil prices and the government's announcement on building reserves needed a greater budgetary allocation. There has been a severe slump in exports in the last 15 years but exports were largely ignored in the budget. The government has been constantly adding on to the indirect taxes that consumers have to pay. Last year, the service tax was increased from 12.36% to 14.5% which included a 0.5% cess towards Swachh Bharat. This year a 0.5% of Krishi Kalyan cess has been added, taking it to 15%. This means increase in prices for mobile phone bills, insurance, restaurant bills, air travel, etc. Airfares are likely to go up as the Centre announced an increase in the excise duty on aviation fuel, up from eight percent.

The Budget this year seems inadequate and has missed out on addressing a lot of issues that are currently troubling the country. The NDA government really

needs to start focusing more on delivering on their promises to the farmers instead of merely changing the names of schemes and Ministries. They have been elected to power for action and not rhetoric. The UPA government has provided them with an effective tool in the form of MGNREGA that they should implement diligently and without hesitation. They need to follow the policy of farmer and consumer first.

***डॉ मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर)** : मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में किसानों और गरीबों का ध्यान रखा। साथ ही हमारे राजस्थान का भी ध्यान रखा है। चाहे नवोदय विद्यालय हो, पीएम ग्राम सड़क योजना हो, किसानों के लिए ई-पोर्टल योजना हो या पंचायत को विशेष राशि दिये जाने का प्रावधान हो, अस्पताल में डायलिसिस सुविधा हो, जन औषधि स्कीम हो सभी का फायदा देश को मिलेगा और राजस्थान को भी मिलेगा। मैं माननीय वित्तमंत्री एवं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि राजस्थान, करौली, धौलपुर में पीने एवं सिंचाई के पानी हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए।

देखा जाए तो इस बजट में हरेक राज्य का ख्याल रखा गया है और बजट से सिद्ध हो गया है कि सरकार ने सूझ-बूझ वाला बजट दिया है। ग्रामीण विकास की बात करें तो सरकारें गांवों को 87 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा रकम दी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर में चम्बल लिफ्ट परियोजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटन किया जाए जिससे लोगों को सिंचाई एवं पीने का पानी मिल सके।

मैं कुछ विशेष बातों पर जोर देना चाहता हूं कि इसी सरकार ने पहली बार किसान कल्याण को अलग से प्राथमिकता दी है और इस बार 35 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा का आबंटन किया है। मनरेगा के तहत जैविक खाद के लिए 10 लाख कंपोस्ट के गड्ढे, इससे मनरेगा योजना और मिट्टी का स्वास्थ्य दोनों का ध्यान अपने आप आ जाता है। वहीं जैविक खेती को प्राथमिकता देने से जनता का स्वास्थ्य का ध्यान भी अपने आप आ जाता है।

सरकार दलितों के लिए न सिर्फ उत्थान की योजना बना रही है, बल्कि उसे अमली जामा पहना कर उनकी उन्नति की ओर तेजी से अग्रसर है। दलित चैंबर आफ कामर्स के सहयोग से एस सी, एसटी और महिलाओं के लिए स्टार्ट अप के लिए 500 करोड़ रूपए का फंड दिया। प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए हब भी बनाया है। इस योजना से दलितों की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार होगा। सटार्टअप इंडिया के तहत सभी बैंकों के लोन देने का दायरा बढ़ जाएगा और इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आसान लोन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं हर बैंक ब्रांच को कम से कम दो सूक्ष्म उद्यमों को लोन देना अनिवार्य होगा। इसके

* Speech was laid on the Table

साथ ही भारत सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक से इसके तहत 10,000 करोड़ रूपए तक के कोष की व्यवस्था करने की बात कही है। इस कोष के माध्यम से दलित और महिला उद्यमियों की मदद की जाएगी।

आज हर किसी की आवश्यकता घर खरीदने की है। सरकार ने 50 लाख के मकान पर 35 लाख का लोन लिया हो तो ब्याज में 50 हजार रूपए की छूट दी। नई नौकरी वालों को सरकार 3 साल अपनी तरफ से ईफीएफ भरेगी, रही बात ईपीएफ निकालने पर टैक्स की बात तो वित्त मंत्रालय ने उस पर अपना रूख साफ कर दिया है। छोटे करदाताओं के लिए 87 क के तहत छूट 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार कर दी गई है। किराये के मकान में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दी गई है। नौकरियों के लिहाज से ये बजट जबर्दस्त संभावनाएं लाया है, कौशल विकास के लिए सरकार ने 1804 करोड़ रूपए दिए हैं। मॉडल करियर केंद्र खुलेंगे। स्टार्ट अप को तीन साल की छूट देने से एक अनुमान है कि 10 हजार रूपए का रोजगार मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग में जब 100 परसेंट एफडीआई आएगा तो करीब 1.5 लाख रोजगार मिलेंगे, डेयरी सेक्टर की 850 करोड़ रूपए की चार परियोजनाओं पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई पशुधन हाट और राष्ट्रीय देशी नस्ल जेनोमिक केंद्र से करीब 30 हजार नए रोजगार की संभावनाओं का अनुमान है। 2000 मॉडल रिटेल आउटलेट्स फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए खुलेंगे, मिट्टी परीक्षण योजना से कई रोजगार आएंगे। इसी तरह सातों दिन दुकान खुलने से कोई फायदा नहीं हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग को सेवा कर से छूट देने से भी नौकरियां बढ़ेंगी।

अब कालाधन की बात करें तो सरकार ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत 45 प्रतिशत पेनल्टी वाली योजना लाई है। इससे काले धन पर लगाम लग सकेगी। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि अब उनको घर खरीदने के लिए अंडर द टेबल मनी नहीं देना पड रहा इसलिए घर के दाम में भी कमी आई है। तीन साल पहले जो घर 18 लाख का मिल रहा था उसके आज 15 लाख रूपए दाम लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो जैनुईन बायर है उसके अकाउंट के तो तीन लाख रूपए तो बच गए। यानि तीन लाख रूपए अपने आप अकाउंट में आ गए। एक सबसे बड़ी योजना पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। 3 हजार स्टोर्स जन औषधि के खुलेंगे। इससे सस्ती दवाइयों की जरूरत पूरी हो सकेगी और गरीबों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो भी इस योजना से जुड़ेगा सरकार को दिल से दुआएं देगा।

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में बहुत प्रचार किया गया, इसकी बहुत पब्लिसिटी भी हुई। इस बजट में हैरानी यह हुई कि जो स्वर्णकार हैं जो सोने के व्यापारी हैं उन पर एक परसेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, पूरे देश में वह प्रदर्शन कर रहे हैं। सोने के गहने 100 परसेंट इंडिया में ही बनते हैं, मेक इन इंडिया को इससे धक्का लगा है और जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जब माननीय नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस ने उस समय टैक्स लगाया था तो उन्होंने ट्वीट किया था It is a cruelty and the Government should roll back this tax. अब मुख्यमंत्री होते हुए वह कदम जालिमनामा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद वही कदम ठीक कैसे हो जाता है। मैं इस बात का जवाब आपके माध्यम से चाहता हूं।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न खाने देंगे न खाएंगे। पिछले दिनों हम अखबारों में देख रहे हैं कि नौ हजार करोड़ रुपये लेकर हमारे उद्योपगति जो राज्य सभा के मेंबर है, देश से भाग रहे हैं। इससे पहले भी ललित मोदी गेट हुआ था। हर चीज पर सेस लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत योजना पर सेस लगा दिया गया। यह आलसी सरकार की निशानी है जब आपको प्राथमिकता नहीं पता है कहां पैसा खर्च करना है। आदर्श गांव के तहत हमें बोल दिया गया कि एक गांव गोद लो। हर बात के लिए एमपीलैड से काम करने के लिए कहते हैं। पांच करोड़ रुपये एक गांव के लिए और हर बात के लिए एमपीलैड है, 25 करोड़ रुपये एमपीलैड में कर दो तो हम कुछ न कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिफेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हमारे देश के फौजियों के पास बुलेटप्रुफ जैकेट की कमी है, इसके लिए कुछ नहीं है। जब पठानकोट में हमला हुआ तो फौज ने पैरामिलिट्री भेजने के ऐवज में छह करोड़ पैंतीस लाख पंजाब सरकार से मांगे। क्या पंजाब को देश का हिस्सा नहीं माना जाता। पंजाब भी देश का हिस्सा है और कुर्बानियों के लिए मशहूर है। ऐसे कदमों को वापस लिया जाए।

***श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर)** : सरकार के काम काज पर टीका टिप्पणी और छिद्रान्वेषण जीवन विपक्ष की सहज परंपरा है। इस परंपरा का मूल आधार है जनहित। लेकिन देखा यह जा रहा है कि विपक्ष सरकार के काम काज पर नहीं व्यक्ति विशेष को केंद्र में रख अपने तरकश के तीर जाया कर रहा है। विपक्ष जनहित से विमुख स्वहित और अपनी कुंठा के मचान से ऐसे मुद्दे चर्चा में ला रहा है जो संसद को मूल विषय से भटका रहे हैं। बजट की उपलब्धियों उसकी खूबी और खामियों पर चर्चा न कर मीडिया में आ रहे अधकचरे बयानों, वीडियो और सोशल मीडिया के स्वच्छंद कार्य व्यापार पर अपना कौशल दिखा रहा है। बहस से मुंह चुराना, अपनी सुनाना, बेतुके सवाल उठाना, जवाब न सुनना, बहिष्कार के बहाने तलाशना विपक्ष का यही चाल चरित्र दिख रहा है। देश और समाज से इनका कोई सरोकार नहीं बचा है। जीवन मूल्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है, जनहित के कोई मुद्दे इनके पास नहीं है, शुभ्रता-सुचिता इनका विषय नहीं, भारत - भारतीयता और सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें तो इनकी सेक्यूलर आत्मा कराह उठती है, ये अभिव्यक्ति के नाम पर स्वच्छंद और मूल्यहीन आजादी के पैरोकार हैं। सरकार का हर संभव प्रतिरोध ही इनका जन्म सिद्ध अधिकार है।

सरकार के बजट और रेल बजट में इन्हें कुछ भी रुचिकर नहीं लगा। बजट 2016 में काफी कुछ ऐसा जिनका लाभ तो हमें जल्द ही देखने को मिलेगा इसी साल के अंदर। कृषि और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, मनरेगा मूलाधार हैं। अगले छह साल में ग्रामीण क्षेत्रों की आय दुगनी करने और 2018 तक हरेक गांव का बिजलीकरण करने की योजना है। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रूपए अब तक की सबसे बड़ी राशि है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रूपए। ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन केंद्रित है यह बजट। सरकार ने सबसे बडा निवेश इसी क्षेत्र में किया है। उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था में जान आएगी।

इस साल के रेल बजट पर भी गौर करें तो बजट में रेलवे व सड़क परिवहन पर कुल 2.18 लाख करोड़ रूपए के निवेश की घोषणा की गई है। सड़कों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 97 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान है। 10 हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की योजना है।

---

* Speech was laid on the Table

इसके समांतर करीब 50 हजार किलोमीटर स्टेट हाइवे का विस्तार भी होगा। यह कार्यक्रम भविष्य की व्यापारिक गतिविधियों के लिए रास्ता बनाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के जरिये भी खोलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सरकार डिजिटल साक्षरता के लिए भी धन लगाने की योजना है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि अगल तीन साल में करीब छह करोड़ अतिरिक्त परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके।

बजट में इंश्योरेंस, पेंशन और शेयर बाजार में विदेशी निवेश को और ज्यादा उदार बनाया गया है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में सौ फीसदी एफडीआई की घोषणा शहर और गांव दोनों को लाभ देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को इसके सहारे एक नया बाजार मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में देश में एफडीआई में 40 फीसदी की बढ़त हुई है। इसी तरह बाजारों को सातों दिन खोलने की पहल की गई है। इसके लिए राज्य सरकारों का सहयोग अपेक्षित होगा। राज्य सरकारें इसे ठीक ढंग से लागू करें तो रोजगार बढ़ेंगे और कारोबार भी बढ़ेगा।

सरकार की अगले तीन वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने की योजना है। इसके लिए 15000 बहु कौशल प्रशिक्षण स्स्थान खोले जाएंगे। अगले दो वर्ष में 62 नवोदय विद्यालय खोलने की योजना भी है। सस्ती दवाओं की 3000 दुकानें खुलेंगी। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब दोनों के लिए राहत की योजना है। इसी तरह गरीबों के रसोई गैस के लिए 2,000 करोड़ की राशि आबंटित की गई है जो शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के गरीबों के जीवन को बेहतर बनाएगी। आयकर स्लैब में बेशक कोई बदलाव नहीं किया गया है, पर छोटे करदाताओं को कुछ राहत मिली है। पांच लाख तक की सालाना आय वालों की 3 हजार रूपए की अतिरिक्त छूट मिल गई है। इसके साथ ही आयकर में छूट के लिए मकान भत्ते को 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दिया गया है। सस्ते आवास को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 50 लाख तक की कीमत वाले मकान खरीदने पर 50 हजार की छूट मिलेगी। दूसरी ओर एक करोड़ की आय वाले लोगों पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है।

सरकार अपने तमाम प्रयासों से जन जीवन सहज सरल बनाने का प्रयास कर रही है, पर अकेले सरकार ही सर्व समर्थ है, ऐसी बात नहीं। सरकार सभी दलों, राज्य सरकारों, और जन-जन से सहयोग की आकांक्षी है। स्वस्थ आलोचना का स्वागत है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब

बेशक अपने दलों से चुनकर आए हों पर हमें जिस जनता ने चुना है उसने हमें यहां जन कल्याण के लिए बेहतर व्यवस्था का सृजन करने की जिम्मेदारी के साथ भेजा है। दलों की राजनीति करने के लिए नहीं। दलों की राजनीति के और भी मंच हैं। आखिर हम सब को यहां तक का टिकट जनता की अदालत से जारी होता है।

*DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): The Finance Budget for the year 2016-17 presented to the August House by the Hon'ble Finance Minister is during a time when the global economy is facing a serious crisis. Global growth has slowed down from 3.4% in 2014 to 3.1% in 2015. Financial markets have been battered and global trade has contracted.

The Government in the financial sector needs to focus on key areas, those are (1) fiscal consolidation (2) Job creation (3) Increasing saving of the Government (4) inflation control (5) improving the investor climate for a favourable growth in economy. Here at this juncture, I would like to appreciate the initiate taken to give unliftment to the agriculture and the rural sector. Several schemes which were announced by the Hon'ble Finance Minister were perhaps the replica of the policies and schemes initiated by our Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma.

The launch of National Rural Digital Literacy Mission is a recognition of the pioneering role that our Hon'ble Chief Minister had played in implementing the free laptop scheme for school and college students which was a mammoth effort taken to bridge the digital divide which the Government of India has recognized now. The Pradhan Mantri Jan Aushadi Yojana, under which 300 new medical stores are to opened for selling generic medicines at low cost is perhaps the replica of the Amma Marunthagam Scheme launced by our leader Puratchi Thalaivai Amma to provide low cost affordable medicine to the poor. The launch of a new health protection scheme to provide insurance cover for poor families who require hospitalization is a welcome. This scheme is very similar to the Chief Minister's Comprehensive health insurance scheme launched by our Hon'ble Chief Minister. Our leader had requested that the health scheme of the Government of India should act in convergence with the Tamil Nadu health Insurance Scheme, which will enable smoother roll out of the Central Scheme in Tamil Nadu and reduce overlap and administrative burden.

---

* Speech was laid on the Table.

In a Federal system of Governance, the State Governments are depended on the funds due to the States from the Central Government. The delay in release of funds from Central Government for the expenditure incurred by the States leads to backlogs in the developmental pathway and poses a threat to the financial stability of the States. I would like to point in the Budget discussion, a number of schemes for which the Central Government share of funds is yet to be released and year after year the arrears have piled up. The Central Government needs to take cognizance of this matter and act immediately to dispense the funds immediately for the key infrastructural projects of the State.

There is huge pending amount to be released to the Government of Tamil Nadu under the grants for flood protection works, command area development and water management programme, performance grant under the 13th Finance Commission. With regards to Education, Central assistance from Ministry of Human Resource Development which are pending under the SSA programme, Right to Education compensation, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. Several major grants in Aid due from Government of India are 13th Finance Commission grants for Roadside Bridges Maintenance, slum improvement, coastal protection, renewable energy, grants for post matric scholarship for SC students, statistical strengthening project, comprehensive handloom development programme, revamped Central Road Fund, family welfare programme Modernisation of police force, Central support for desalination plants. With a huge list of projects for which the State Government has incurred expenditure and the Central Government mindset of not releasing the funds at appropriate and scheduled time period has caused a substantial financial burden on the Tamil Nadu State. The Central Government should take effective steps to release the funds within the stipulated period to the States for faster growth of our economy.

I would also like to bring it to the notice of the House a number of projects for which the Government of Tamil Nadu has been repeatedly asking the Central Government for its investment, which the Central support for desalination plants

namely 150 MCD SWRO desalination plant at Nemmoli (!) 400 MCD SWRO desalination plant at Perur near Chennai (3) Desalination plants at Ramanthapuram and tuticorin. Other major projects include Extension of corridor I of Chennai Metro Rail project upto Thiruvattriyr and Wimconagar, Chennai Metro Rail Project – Implementation of phase –III corridors. Massive investment from Central Government in Tamil Nadu's urban infrastructure to meet the housing requirement of the urban slums.

I would like to mention here that even in the Presidents speech it was mentioned about the unprecedented foods that submerged Chennai in December, 2014 which brought untold sufferings and economic loss. Even after using the words like unprecedented and untold sufferings and loss in the Presidential address, there is not a single word or a sign of action to be taken by the Government of India in the Budget speech by the Finance Minister for releasing matching financial compensation much expected from the Centre. The Centre has released less than Rs. 2000 crores when the Government of Tamil Nadu is asking for Rs. 25,000 crores. That great natural disaster was taken note of even in the Climate Submit held in Paris at that point of time, but the Centre has not taken note of the tragedy and its foremost responsibility of releasing the fund that it should have released to allay the untold suffering by the recent floods. The Central Government should immediately release the requested amount to the Tamil Nadu Government

The Government of India has announced a Blue revolution with the Central outlay of Rs. 3000 crores. It is to be mentioned here that our leader Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu has repeatedly asked the Union Government through memorandum and several letters addressed to the Hon'ble Prime Minister with regard to a comprehensive special package for diversification of fisheries involving a grant of Rs 1520 crores from the Centre under various schemes such as (1) Diversification of bottom travelers into deep seat tuna long lines. (2) Assistance for Mid-Sea fish procession park (3) Reimbursement of Central Excise

Duty on high speed for mechanized boats (4) Motorisation of traditional crafts (5) creation of infrastructural facilities for deep sea fishing (6) dredging of fishing harbours and bar moaths. Thereby the entire comprehensive special package of Rs 1520 crores and a grant of Rs 10 crores per annum for maintainance dredging is sought from the Centre which is pending.

It is necessary that agriculture needs to be utmost importance in our Country where the length and breadth of our country is covered with agricultural land. The long awaited inter-linking of Rivers of India should be commenced at once for effective irrigation of our agricultural lands. It is necessary to mention here the long pending request by the Government of Tamil Nadu for Central assistance with regard to Inter-linking of rivers within the State and for modernization of Cauvery scheme which is pending with the Government of India.

It is to be mentioned here that the Finance Ministry has cut funds for several Ministries such as Ministry of Minority Affairs, Ministry of Women and Child Development, and further for fertilizer subsidies, Nirbhaya fund, National afforestation programme. Certain sectors which are of utmost importance should be compromised by the Centre and hence the centre should rectify the mistakes and allocate additional funds under the various Ministries which has suffered from budgetary cut.

Thank you.

[*]**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):**देश की आजादी के बाद सर्वाधिक बजट 19 लाख 78 हजार 60 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.8% अधिक धनराशि की व्यवस्था की गयी है । इस बार श्री मोदी की सरकार ने बजट को किसानोन्मुखी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के लिए सर्वाधिक धनराशि की व्यवस्था की गयी है । एक तरफ दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही है इसके बावजूद भारत ने जीडीपी में काफी वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया है । भाजपा एवं एनडीए की सरकार का गठन हुआ था उस समय भारत के विकास दर 5% से नीचे थी और आज इस सरकार को अभी दो वर्ष भी पूरे नहीं हुये फिर भी 7.6% विकास दर का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त किया है । सरकार के गठन के समय मंहगाई (सीपीआई) औसत तीन वर्षो में 9.4% की ऊचाई तक पहुंच गयी थी लेकिन आज संतोष की बात है कि मंहगाई दर घटकर सीपीआई 5.4% से नीचे आ चुकी है जिससे देश के सभी वर्गो को मंहगाई से राहत दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है जबकि विगत तीन वषों में औसत वर्षा के सापेक्ष 13% बारिश कम हुयी जिसके कारण किसानों के समक्ष सूखे के कारण गंभीर संकट पैदा हो गया । इसके बावजूद किसानों की हालत सुधारने के लिए देश के 28.5 लाख हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने का फैसला किया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं मानते हैं कि इस बार का बजट सरकार के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के समक्ष मोदी सरकार की परीक्षा है ।

इसलिए हमारी सरकार ने सोच विचार करके लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बजट तैयार किया। आम जनमानस की आर्थिक हालत बेहतर हो इसका उपाय किया गया । परिणामस्वरूप कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बजट में काफी वृद्धि की गयी है । सरकार का संकल्प है कि किसानों की आमदनी दो गुना 2022 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसलिए प्रधानमंत्री ने किसान फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे किसानों की मेहनत के उत्पाद को दैवी आपदा से प्रभवित होने पर किसानों की क्षति की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना का परिव्यय निर्धारित किया गया है । फसल के नुकसान होने पर किसानों के खाते में सीधे धन जायेगा । गांवों के पलायन को रोकने के लिए गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है । एक तरफ गांव के विकास की प्राथमिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ का परिव्यय निर्धारित ककिया है । मनरेगा के अन्तर्गत पिछले वर्ष की तुलना में परिव्यय में वृद्धि केवल स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9,000 करोड़ की धनराशि निर्धारित किया गया है । हमारी सरकार ने केवल विकास के लिए वोट नहीं लिया है बल्कि विकास को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए अलग मदों में परिव्यय निर्धारित

[*] Speech was laid on the Table.

किया गया है । देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के लिए 87, 765 करोड़ रूपये का परिव्यय निर्धारित किया है जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके । देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक गांव एवं घर में विद्युतीकरण पूरा करने के लिए वर्ष 2018 तक का लक्ष्य रखा गया है ।

देश के किसानों की सिंचाई के लिए नाबार्ड से "सिंचाई फंड" के लिए 20,000 करोड़ की व्यवस्था की है । किसानों को पहली बार ओरगेनिंक फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 412 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है । देश की ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है । राज्यों का सहयोग मिलाकर 27,000 करोड़ का परिव्यय होगा । किसानों को फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए 9 लाख करोड़ का फसल ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रधानमंत्री का निश्चय है कि देश के प्रत्येक गांव को धुंआ रहित शत प्रातशत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । अप्रैल, 2016 से तेल मंत्रालय ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए एक उज्जवला नाम की स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जायेगा । प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश की महिलायें जो एक वक्त में खाना बनाने में 400 सिगरेट के धुंए के बराबर धुंआ इनहेल करती हैं ।

इस बार रेलवे एवं सड़कों के विकास के लिए 2 लाख 18000 करोड़ रूपयों का परिव्यय निर्धारित किया गया है । पहली बार 1500 मल्टी टास्क स्कील ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है जससे ग्रामीण युवा पढ़ने के लिए तथा स्वास्थ्य अधिकाय स्थापित करने का कार्य किया है । भाजपा की सरकार ने फिसकल डिफासेट पिछले वर्ष की तुलना 3.9% से नियंत्रित करके 3.5% तक पहुंचाने का कार्य किया । पहली बार बजट का सर्वाधिक ध्यान कृषि एवं किसानों के लिए केन्द्रित करके भारत के किसानों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार ने इस वर्ष बजट में 35,984 करोड़ की व्यवस्था की है । 14वे वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने 2.87 लाख करोड़ ग्राम पंचायत एपं नगर पालिकाओं को परिव्यय देने का निश्चय किया गया है । पहली बार देश के किसानों के लिए ई-प्लेटफार्म के माध्यम से कृषि मार्किट मुहैया कराने का निर्णय लिया है । अभी 1 अप्रैल, 2015 को 18,542 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है । भविष्य में प्रत्येक घर की महिलाओं का नाम देश में 1.5 करोड़ परिवारों को अगले एक वर्ष में कनेक्शन दिया जायेगा जिसके लिए भारत सरकार ने 2000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है । भारत में शिक्षा का अधिकार लागू किये जाने के बाद इस बार के बजट में 62 नये नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे जो जिले बाकी रह जायेंगे वहां अगले दो वर्षो में खोल दिएं जायेंगे । इसी तरह दस-दस शिक्षण संस्थाओं को विश्व स्तरीय बनाने का निर्णय लिया गया है । हीफा के अन्तर्गत 1000 करोड़ रू. के फंड का गठन किया गया है । देश के दो करोड़ लोगों को टैक्स रीलीफ दिया गया है । सेक्शन 87ए के अन्तर्गत 2000 से

3000 रूपये का रीलीफ दिया गया है । पहली बार केन्द्र सरकार ने हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लागू किया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को 1 लाख रूपये की सहायता स्वास्थ्य के लिए दिये जायेंगे ।

इसी के साथ वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2016-17 के लिए बजट का समर्थन करता हूं । यह बजट देश के लिए कल्याणकारी होगा ।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Madam Speaker, I thank you for allowing me to participate in the General Budget. I rise to support the Budget. The Prime Minister has indeed staked his own standing on the Budget by calling it his personal test. So far, I think, he has done rather well.

The world is going through some very difficult times. Under the circumstances, because of the NPAs, there has been a huge problem in trying to balance this particular Budget. Therefore, under the circumstances, I think, the Budget has come through as both pro-poor and progressive.

But, what is affecting the States and especially the small States like Sikkim is that in the new financial architecture, we are in a transition period. I want to bring it to the notice of the hon. Finance Minister because the hon. Chief Minister Shri Pawan Chamling has already brought it to his notice that during this transition, we have gone into a deep deficit. To come out of that deficit in this new architecture, is the greatest challenge for all the North-Eastern States.

Since the Commerce Minister is here, I would also like to bring to her notice that the North-Eastern Industrial and Investment Promotion Policy 2007 which has been kept on hold. Because of this, there has been a growing deficit in the way in which industrialisation takes place in the North-East. Since the Prime Minister has already said that North-East will be given a fillip in this direction and in the area of organic value chain development in the North-East, I think it is time for a re-look at this particular policy. I would be very very grateful and I would like to place it on record that this particular policy needs to be re-looked and rejuvenated.

With these words, Madam, I would thank you again for giving me this time.

HON. SPEAKER: Thank you very much for concluding in time.

*__कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर)__: मैं आम बजट 2016-17 के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत किसान हितैशी, गरीब समर्थक एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास वाले बजट का सर्मथन करता हूं। मैं मात्र तीन महत्वपूर्ण विषय माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

देश के कोने-कोने में कृषि करने वाले किसानों एवं मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार करने का भारत सरकार का सराहनीय कदम प्रशंसनीय है । मैं बुन्देलखण्ड के पूरे क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 2016-17 में ही पूर्ण रूप से सिंचित करने हेतु बजट उपलब्ध कराये जाने का निवेदन करता हूं । पिछले 10 वर्षों से लगातार सूखा पड़ने वाले बुन्देलखण्ड में शीघ्रातिशीघ्र, देश में सबसे पहले सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना ही होगा अन्यथा बुन्देलखण्ड के किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं शर्मसार करती रहेंगी और अकारण भारत सरकार पर छींटे पड़ते रहेंगे ।

कितनी भी कठिनाई क्यों न हो हमारे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, हिन्दवारी, महोबा जो पिछड़े, परेशान गरीव व लाचार बुन्देलखण्ड क्षेत्र का भाग है । हमको हमारे क्षेत्र में निम्नलिखित प्रावधान भारत सरकार के 2016-17 के बजट पर हर हालत में चाहिए जो निम्न हैं -

सबसे पहले देश में सर्वाधिक सूखे व अकाल की मार झेल रहे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण सिंचाई के प्रबंध बांधों, नहरों, तालाबों, पाइपलाइनों, ट्यूबवैल एवं सोलर पम्पों के माध्यम से 2016-17 के बजट से ही पूरा धन आवंटित करके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की सार्थकता को सिद्ध किया जाये । सर्वाधिक पानी बुन्देलखण्ड को सर्वप्रथम पानी पिलाया जावे, क्योंकि बुन्देलखण्ड में खेत तो सूखे हैं ही नागरिकों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है । मवेशी प्यास से मरने को मजबूर है । बुन्देलखण्ड के किसान कर्ज में डूबे हैं । बीमारी का इलाज करवाने में भी मजबूर हैं । मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र बुन्देलखण्ड का एकमात्र संसदीय क्षेत्र है जहां एक भी, कोई भी मेडिकल कालेज नहीं है । अतः हमीरपुर, महोबा हिन्दवारी में कहीं भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस) खोला जाये, एम्स की नितान्त आवश्यकता है । अतः मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये अंधेरे में दीया (रोशनी) जलाने वाली अपनी सरकार के दावे का स्मरण करते हुए एम्स की अविलम्ब स्थापना करने की व्यवस्था इसी बजट में करने का कार्य करे । बुन्देलखण्ड का अन्नदाता किसान सदैव भारत सरकार का आभारी रहेगा। बुन्देलखण्ड में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे एक महत्वपूर्ण सुझाव देना है कि भारत सरकार बुन्देलखण्ड में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने के लिए समूचे बुन्देलखण्ड में प्रत्येक जिले में 10 वर्षो के लिए टैक्स रहित औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए इस बजट में

---

* Speech was laid on the Table.

स्पेशल बजट का प्रावधान करें। शीघ्रातिशीघ्र उद्योग लग सके एवं बुन्देलखण्ड से हो रहा पलायन रोका जा सके ।

अनेकों माननीय सदस्य आम बजट में अपना विषय रखना चाहते हैं। समय कम है । माननीय वित्त मंत्री को बजट पर अपना वक्तव्य देना है । शेष मांगों को पत्र के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री एवं जला संसाधन व स्वास्थ्य मंत्री को उपलब्ध करा चुका हूं ।

अंत में, माननीय रेल मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आजादी के बाद से आज तक सर्वाधिक बजट रेलवे ने देकर 411 कि.मी. डबल लाइन एवं महोबा से चरवारी राठ उरई-भिण्ड नई रेलवे लाईन देकर मेरे संसदीय क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों की बहुत पुरानी मांग को पूरा किया है । मैं हमीरपुर-महोबा हिन्दवारी क्षेत्र के नागरिकों की तरफ से भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए आम बजट 2016-17 का प्रबल समर्थन करते हुए अपना विषय पूर्ण करता हूं ।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Madam, I rise to support the Budget 2016-17. During the last two consecutive years there was a shortfall in monsoon by 13 per cent. Despite these very unfavourable conditions, a robust growth is achieved. The growth of economy has accelerated to 7.6 per cent in the year 2015-16 and I congratulate the Government for the collective efforts taken for achieving this position. Today India is recognized as world's fastest growing economy.

A very good decision taken in the Budget is the changing the structure of schemes which was recommended by the Subgroup of Chief Ministers on the rationalisation of Centrally-sponsored schemes. The Committee has recommended a set of core Centrally-sponsored schemes and optional Centrally-sponsored schemes to give States more flexibility in selection of the priority areas.

The existing funding pattern of the schemes is defined as core of the core and a total of six schemes have been retained by a ratio of 90:10. Eighteen schemes have been defined as the core schemes. The core of core scheme is mainly focusing on the needy, the most vulnerable and most neglected groups. It includes the MNREGA, National Social Assistance Programme, umbrella scheme for development of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward and Minorities.

The agenda of the Budget is to transform India and this transformation will be built on nine pillars which include agriculture and farmers' welfare, rural sector, social sector, educational skills and job creation. India is an agriculture based country with more than 60 per cent of its population being farmers. Keeping this in mind, Government has stated its goal to reorient its intervention in the farm and non-farm sectors to double the income of farmers by 2022.

The total allocation of agriculture, farmers' welfare and animal husbandry is estimated to be Rs.44,485 crore as compared to Rs.20,909 crore in the last Budget which is almost the double. Previously the crop insurance schemes implemented in the country were including only selective crops and because of

this many farmers could not avail the benefit of the insurance. Not just this but also the crops which were included in the insurance schemes were given the benefit only till the time they were in the farm and not harvested.

I come from the State of Maharashtra where in the last two years we have faced lots of weather problems causing hailstorms, unseasonal rains and drought like situations. And the farmers of Maharashtra have suffered very badly because of the previous insurance policies for the farmers. Now this new scheme which has been implemented by the Central Government which is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is inclusive of all the crops and it is also including those crops which are post harvested and still kept in the farm. Even those will now be included in this insurance scheme. So, it is in a true sense giving justice to the farmers who have suffered this kind of destruction of the crops.

Also, a big push for irrigation is the Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana which will now be implemented in mission mode and 28.5 lakh hectares will be brought under irrigation under this scheme. This will not only assist in increasing the crop production but it will also help in job creation and also will increase the agriculture allied businesses. I would like to state the example of Gujarat where the backwater of the Ukai dam has been lifted and provided in the form of lift irrigation to the farmers which has really benefited those farmers.

My constituency also has a similar kind of situation. I request the hon. Minister to implement this scheme in my constituency also.

HON. SPEAKER: Please conclude now. You have put it very nicely.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: In a big push in the rural road sector, Rs. 19,000 crore has been allocated for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The goal of the programme has been revised to connect the remaining 65,000 eligible habitations through 2.23 lakh kilometres by an advanced deadline of 2019. When we are talking of eligible habitations, it means villages which have more than 250 habitations. I come from a tribal and hilly area where we also have small villages which have a population of less than 250 people living in one area or small

hamlets. It is very essential to connect all these hamlets through road connectivity and it is only after the road connectivity is reached to these areas that these areas will develop in a true sense and will not be deprived of basic amenities which are required. So, I request the Government to relax the norms for such hilly and tribal areas which have a population of less than 250 and small villages where people live in very larger areas in small *paadas*. This is one request I have for the hon. Minister.

Five crore BPL families will be given LPG connections which is again a very good step. Many of the women who work on the *chulhas* will now be protected from the respiratory diseases that they get because of the use of *chulhas*. Since I am a doctor, I must mention this as well that the *Rashtriya Swasthya Suraksha Yojana* which will provide a health cover of upto Rs one lakh per family is also a very good step. These days, we have many patients coming with chronic renal failure and kidney diseases and we don't have enough of dialysis facilities available in the Government hospitals. So, establishment of National Dialysis Service Programme in all the district hospitals is also a very good step taken by the Government. Opening of 62 new Navodaya Vidyalayas is again a very welcome step. About skill development, I would specifically like to mention that Rs 600 crore has been allotted for human resource for health and medical education and this will provide with large number of medical and paramedical staff and will also help in improving the healthcare.

With these words, I strongly support the Budget.

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमने खास तौर से कृषि बजट के बारे में प्री बजट डिसकशन में जो सुझाव दिए थे, उन्होंने उनमें से कई सुझाव स्वीकार किए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में लगभग तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। यह देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा क्योंकि किसान कर्ज की वजह से ही आत्महत्या करते हैं। आपने कर्ज का दायरा तो बढ़ाया लेकिन किसान किस तरह से कर्ज वापिस करेगा इसके बारे में जो प्रावधान करना चाहिए था वह ठीक तरह से नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर अगले पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है तो या तो उनका लागत मूल्य कम करना पड़ेगा या समर्थन मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। हम समर्थन मूल्य ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर लागत मूल्य कम करना है तो उन्हें बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज, सड़क, बिजली, वेयर हाउस और सिंचाई परियोजनाओं पर भी ध्यान देना होगा। प्री हार्वेस्टिंग लॉसिस और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसिस बढ़ रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो बुनियादी प्रावधान होने चाहिए वे नहीं हो पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप एग्रीकल्चर सैक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई ला रहे हैं। नाबार्ड के प्रोत्साहन से प्रोड्यूसर कंपनियां किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैंकिसानों के बेटे उसमें काम कर रहे हैं और कोआपरेटिव सैक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर एफडीआई और कोआपरेटिव सैक्टर या प्रोड्यूसिंग कंपनीज के साथ मिल-जुलकर काम किया जाए तो इस देश का नौजवान जो किसान के घर में पैदा हुआ है, उसे भी कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास दिमाग है। वे हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको जो अवसर मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए सौ प्रतिशत एफडीआई की बजाए हमारे नौजवान किसानों को अवसर दे दीजिए, यह मेरा सुझाव है।...(व्यवधान)

मैं वित्त मंत्री जी से एक और मांग करना चाहता हूं कि इस देश के कई गिने-चुने उद्योगपतियों ने 1,14000 करोड़ रुपये का कर्जा डुबाया है और हमारे किसानों का कर्जा कितना है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण या लागत मूल्य कम मिलने के कारण वे कर्जा वापस नहीं कर पाए हैं। किसान कभी देश छोड़कर नहीं भागता है। वह आत्महत्या करता है लेकिन कभी भागता नहीं है। इसलिए अगर सरकार किसानों की मदद करना चाहती है तो सरकार एक बार और उसका कर्जा माफ कर दे। इस देश का किसान आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, बैंकों को 25000 करोड़ रुपये इस देश के वित्त मंत्री जी दे रहे हैं तो इस देश का किसान ऋणमाफी के लिए हकदार क्यों नहीं है? यह सवाल मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जरूर पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूॅं कि हमारे गांव में भैंस की कीमत एक लाख रूपये है और आपने गॉंव के गरीब मज़दूर को एक लाख रूपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की है। यह बात ठीक नहीं है, कृपया यह बीमा राशि पांच लाख रूपये तक बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आपने किसानों की बात रख दी है। अब आपकी बात पूरी हो गयी है। बैठिए।

***श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) :** हमारे देश के बजट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव, गरीब एवं किसान को समर्पित एक बजट संसद में पेश किया गया है। सबसे पहले मैं सरकार के इस किसानों और गरीबों को समर्पित प्रयास के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी श्री अरूण जेटली को बधाई देता हूं और देश के सभी गरीबों और किसानों की ओर से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। इस बजट से कृषि और सिंचाई के बजट में भारी वृद्धि हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। इसलिए इस बार का बजट देश के गांव, गरीब और किसान के विकास की तस्वीर को बदलने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए पेश बजट ने यह साबित कर दिया है कि हमारी मोदी सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। जिस तरह से देश के कुछ भागों में विशेषकर महाराष्ट्र में कई सालों से लगातार सूखा पड़ा है। उसे देखते हुए बजट का कृषि और गांव पर फोकस होना समय की मांग था और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी था। इस बजट से न केवल ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि अगले पांच साल में किसानों की आमदानी को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। देश में पहली बार मोदी सरकार ने देश के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाया है। निश्चय ही इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार, जो गांव, गरीब, किसान के लिए समर्पित है। ने जो कहा वह कर दिखाया है। इसके लिए मैं देश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली जी का अभिनन्दन करता हूं। गांव, किसान और कृषि विकास की दृष्टि से इस बार के बजट आवंटन में रिकार्ड बढ़ोत्तरी की गई है। बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। किसानों की आय को आगामी 5 वर्षों में दोगुना करना हमारा लक्ष्य है, प्रति इकाई उपज बढ़ाना, किसानों के लिए उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना, पशुधन-डेयरी एवं मात्सियकी के अलावा कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को बढ़ावा देना हमारी प्रतिबद्धता है। मेरा मानना है कि किसानों के हित में सरकार की निम्नलिखित योजनाएं किसानों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होंगी।

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अधीन 28.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा जिसके लिए इस 2016-17 के लिए 5717 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस वर्ष नाबार्ड के माध्यम से लगभग 20000 करोड़ का सिंचाई फंड सृजित करने का फैसला किया गया है तथा वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना (एआईबीपी) के 89 सिंचाई परियोजनाओं, जो काफी समय से अपूर्ण रही

* Speech was laid on the Table.

हैं, का त्वरित कार्यान्वयन किया जायेगा। इसमें 80.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी। साथ ही मनरेगा के तहत वर्षापोषित क्षेत्रों में 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं की व्यवस्था होगी।

कृषि उन्नति योजना की निम्नलिखित मुख्य बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत सरकार किसानों के खेतों की मिट्टी की उर्वरकता पर विशेष ध्यान दे रही है तथा इस स्कीम के तहत चालू वर्ष में कुल 362 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, यह 155 प्रतिशत की वृद्धि है। मंत्रालय मार्च 2017 तक देश के सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वाथ्य कार्ड वितरण करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्थ हो जाएगा। साथ ही उर्वरक कम्पनियों के 2 हजार मॉडल खुदरा केन्द्रों को अगले 3 वर्ष में मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रंखला के तहत जैविक कृषि स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण किया जाएगा। जैविक खेती के विकास के लिए पारंपरिक कृषि विकास योजना पिछले साल से लागू की गई है जिसके परिणामस्वरूप जैविक कृषि में 19 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है तथा यह योजना आगे भी चालू रहेगी। समेकित कृषि विपणन स्कीम के द्वारा ग्रामीण भण्डारण को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने आबंटन बढ़ाकर चालू वर्ष में 788 करोड़ रूपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के द्वारा सरकार राज्य सरकारों को उनकी कृषि विस्तार मशीनरी के सुदृढ़ीकरण करने में सहायता कर रही है तथा इस साल इस योजना के तहत 635 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है जो कृषि सूचना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में सहायक होगा। यही नहीं, बजट में घोषित सरकार निम्नलिखित प्रयास भी सराहनीय हैं जिससे किसानों की वर्तमान स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम) के माध्यम से मंडी सुधार के संबंध में सरकार कृषि क्षेत्र में विपणन को अत्यंत महत्वपूर्ण समझती है और इसलिए सरकार राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना के लिए वचनबद्ध है। सरकार दिनांक 14 अप्रैल 2016 को स्कीम की शुरूआत करेगी तथा सितम्बर 2016 तक 200 मंडियों तथा मार्च 2017 तक कुल 400 मंडियों को कवर किया जाएगा, मार्च 2018 तक देश में 585 एपीएमसी को कवर करने का लक्ष्य है। इससे किसानों को अपना उत्पाद मंडियों में लाभकारी मूल्यों पर बेचने में काफी हद तक मदद मिलेगी। ऋण प्रवाह को बढ़ाकर 9 लाख करोड़ किया गया है जो 2015-16 में 8.50 लाख करोड़ था व किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए, ब्याज सहायता हेतु बजट अनुमान 2016-17 में 15,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आबंटन 5,500 करोड़ रूपये किया गया है जो पिछले बजट में 3185 करोड़ रूपया था। इस प्रकार इस मद में लगभग 73 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बजट में 5400 करोड़

का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी कार्यक्रम हेतु पहली बार बजट में 75 करोड़ केन्द्रांश का प्रावधान किया गया है इससे मेड पर पेड अभियान को गति मिलेगी। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन के लिए 1600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अलग से चार नई परियोजनाओं- 'पशुधन संजीवनी' 'नकुल स्वास्थ्य पत्र' ई-पशुधन हाट और राष्ट्रीय देशी नस्ल जेनोमिक केन्द्र बनाई गई हैं जिनके लिए 850 करोड़ रूपये दए गए हैं। सरकार ने गांव एवं किसान हित की निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजनाओं को और सुदृढ़ किया है ताकि देश के ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों के बराबर विकसित किया जाए तथा गांवों से रोजगार हेतु युवकों का शहरों को पलायन रोका जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है जिसके तहत वर्ष 2019 तक शेष 65,000 पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।

सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदा से ग्रस्त प्रत्येक ब्लॉक जो दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के तहत विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम किए जाएंगे जिसके तहत सघन रूप से स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा जिन्हें विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दी जाएगी। साथ ही मनरेगा के तहत कलस्टर सुविधा टीमों का भी गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध को सुनिश्चित करेगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी। गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी (रूरबन) मिशन की शुरुआत की गई है जिसके तहत 300 ग्रामीण शहरी कलस्टरों का विकास किया जाएगा जिसमें किसानों के लिए आधारभूत संरचना जैसे कृषि प्रसंस्करण, कृषि बाजार को सुलभ कराना, गोदाम एवं वेयरहाउसों का निर्माण सम्मिलित है। 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण का भी प्रावधान किया गया है।

यह महत्वपूर्ण है कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों का इस बजट में पूरा पूरा ध्यान रखा है। सरकार की निम्नलिखित योजनाएं आगे आने वाले वर्षों में समाज मे खुशहाली बहाल करने में काफी हद तक कामयाब होगी। अस्पताल व्यय से बचाव के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत नई स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम प्रत्येक परिवार को एक लाख रूपये तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। इसके तहत वरिष्ठ नागिरकों को 30,000 रूपये तक अतिरिक्त टॉप-अप पैकेज का प्रावधान होगा। बीपीएल परिवारों के लिए रसोई गैस कनेक्शन सुविधा के लिए इस बजट में 2000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इससे 2016-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2016-17 मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दे दी है तथा इस प्रयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए

उद्यमिता को युवाओं के दरवाजे पर लाना चाहते हैं। सरकार ने देश में 15,000 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं, की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इन कार्यक्रमों के लिए 17000 करोड़ रूपये की राशि अलग रखी जा रही है। वर्ष 2016-17 में सड़कों और रेलवे संबंधी कुल खर्च 2,18,000 करोड़ रूपये होगा।

प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए 3,000 स्टोर खोले जाएंगे। अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा कौशल विकास के लिए 'उस्ताद' स्कीम का कारगर कार्यान्वयन किया गया है। शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने के की योजना है। डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के इस वर्ष में उद्योग संघों के साथ भागीदारी करके सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। छोटे कामगारों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 1 लाख 80 हजार करोड़ रूपये के ऋण देने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष के बजट में इस योजना में 1 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था।

यहां मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जलगाँव के एक ज्वलंत विषय की ओर नागर विमानन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। भारत सरकार ने 2012 में लगभग 100 करोड़ रूपयों की लागत से जलगाँव एयरपोर्ट का नवीकरण किया तथा वहां सभी अल्ट्रामार्डन सुविधा उपलब्ध करवाई। भारत सरकार इस समय इस एयरपोर्ट के रखरखाव तथा वेतन आदि पर हर महीने 12 करोड़ रूपया खर्च कर रही है तथा यह सब व्यर्थ हो रहा है क्योंकि अब तक यहां से न तो घरेलू उड़ाने चालू की गई हैं और न ही कार्गो सेवाएं।

जलगाँव औरंगाबाद की अपेक्षा विश्व धरोहर अजंता अलोरा गुफाओं के बहुत पास है तथा इस एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें चालू होने से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अत्यधिक सुविधा हो जाएगी। दूसरे जलगांव में केले, प्लासटिक की वस्तुओं व सोने के जेवरातों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा यह दाल मिलों का हब है। इस कारण यहां से एयरकार्गो के माध्यम से निर्यात की अनंत संभावनाएं हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग की समस्या के कारण इसके निकटवर्ती जलगांव को पार्किंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इन सबके होने तथा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद यहां से घरेलू उड़ानें तथा कार्गो सेवाएं आरंभ नहीं की जा रही हैं। हालांकि कतिपय निजी एयरलाइंस यहां से घरेलू उड़ाने चालू करने के लिए तैयार हैं परन्तु एयरपोर्ट उन्हें नाइट लैंडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है।

मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकार जलगांव एयरपोर्ट पर हो रहे भारी खर्च के मद्देनजर तथा यहां के निवासियों की लम्बे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए जलगांव एयरपोर्ट से इंदौर, पुणे होते हुए दिल्ली और मुंबई के लिए घरेलू उड़ानें और कार्गो सेवाएं शीघातिशीघ्र चालू करवाई जाएं तथा निजी एयरलाइंस को नाईट लैंडिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए

कार्यवाही की जाए ताकि सरकार के खर्च की अनावश्यक बर्बादी रोकी जा सके तथा उससे आम जनता लाभ उठा सके।

मैं अपने जलगांव संसदीय क्षेत्र की निम्नलिखित कतिपय अन्य समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा तथा अनुरोध करूंगा कि इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इनके समाधान हेतु यथोचित एवं शीघ्र कार्यवाही की जाए तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। केन्द्रीय जल आयोग के पास महाराष्ट्र के जलगांव जिले की तीन सिंचाई परियोजनाएं 1) पाडळसरे - तहसील अमळनेर 2) वरखेड लेंढे - तहसील अमळनेर 3) नार - पार योजना काफी समय से लंबित हैं। इन पर शीघ्र अनुमोदन दिए जाने तथा उनके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि जारी करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के धुलेगांव और चालीसगांव के बीच पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 211 का हिस्सा बुरी तरह जर्जर हो गया है तथा आम जनता को परेशानी हो रही है। इसलिए इस हिस्से की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत किए जाने तथा उसे चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार महाराष्ट्र के जलगांव शहर में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 6 का हिस्सा बुरी तरह जर्जर हो गया है तथा आम जनता को परेशानी हो रही है। इसलिए इस हिस्से की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत किए जाने तथा उसे चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है। आम जनता की आकांक्षाओं के मद्देनजर महाराष्ट्र के जलगांव जले में 100 बिस्तरों वाला एक नेचुरोपैथी अस्पताल स्थापित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के लगभग 50 वर्ष पुराने गिरणा बांध और सिंचाई प्रणाली के जमदा और दहीगांव जल संचय क्षेत्रों में जमा भारी मात्रा में गाद को निकालने, जलसंचय की क्षमता बढ़ाने और तटबंधों के निर्माण हेतु केन्द्रीय जल आयोग के पास गिरणा नदी पर सात रब्बर डॉम का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है जिस पर शीघ्र अनुमोदन दिए जाने तथा उसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि निर्गत किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी को चेनलों के माध्यम से बोरी, अंजानि, तितूर और तापी और मन्याड नदियों से जोड़ने हेतु केन्द्रीय जल आयोग के पास एक रीवर लिंकिंग परियोजना प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है जिस पर शीघ्र अनुमोदन दिए जाने तथा उसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि निर्गत किए जाने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। देश में जलगांव जिला प्लास्टिक उत्पादनों में काफी अग्रसर है। इसलिए मेरी मांग है कि आने वाले समय मे सरकार देश में 3 प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा करने वाली है और इस विषय में, मैं सरकार से जलगांव के प्लास्टिक उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के बारे में मांग करते आया हूं। इसी तहत मैंने जलगांव में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मांग

की थी अब मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन तीन प्लास्टिक पार्क में से एक पार्क मेरे जलगांव शहर में दिया जाये।

मेरे संसदीय क्षेत्र चालीसगांव तहसील में एक एनटीसी मिल है। बहुत सालों से बंद पड़ी हुई है। हमारी सरकारी की ओर से काफी पैसा वेतन में खर्च हो रहा है। जब हमारी कौशल विकास योजना के तहत हम रोजगार उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य रखा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार की बंद पड़ी निजी मिलों मे से एक चालीसगांव एनटीसी मिल है उसे तुरंत चालू करने का प्रावधान करें। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में केला, आम और संतरा प्रजाति के फलों का काफी बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। इनके प्रसंस्करण हेतु लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में खादी और ग्रामोद्योग संस्थान का एक स्थानीय कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में लगभग 200 कताई मिलें हैं। इन मिलों को सभी आवश्यक सुविधाओं की एक स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक कताई मिल क्लस्टर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार द्वारा पेश किए गए इस संतुलित बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं तथा उन्हें बधाई देता हूं। मैं बजट में दिए गए सभी प्रस्तावों का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश के सबसे विद्वान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी जो ईमानदार थे, उन्होंने 1991 में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को रास्ते पर लाने का प्रयास किया और उसके बाद जब वह प्रधान मंत्री बने तो इस देश के 80 प्रतिशत आम लोगों के लिए फूड बिल भी उसी प्रधान मंत्री को लाना पड़ा। यह दुर्भाग्य है कि एक अर्थशास्त्री वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्र को रास्ते पर लाने का प्रयास किया और दूसरी तरफ जब वह प्रधान मंत्री बनते हैं तो 80 प्रतिशत आम लोगों के लिए फूड बिल लाते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं बोलूं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं इसको ले कर दूं क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, मैं राजनीति, जुमले, आंकड़े और मुहावरे के बीच राजनीति में फंसना नहीं चाहता। मैं प्रो. अमृत्य् सेन और प्रो. बात्रा के अर्थव्यवस्था संबंधी विचार ले करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : नहीं अब नहीं। या तो बोलना होता है या ले करना होता है। दोनों बातें नहीं हो सकतीं।

…(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं ले करना चाहता हूं। मैं नहीं बोलूंगा। मैं ले करना चाहता हूं। मैंने अपनी बात रखी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। आपकी बात हो गयी। अब आप बैठिए। I am sorry.. यही बात आप उठते ही बोलते तो बात अलग थी। अब आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे ले करवा दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज शांत रहें। मैंने आपको पप्पू नाम से तो नहीं पुकारा। इसलिए आप राजेश जैसा व्यवहार करें। इसलिए प्लीज बैठ जाइए।

[*]**श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर):** माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2016-17 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह अत्यंत सराहनीय, देश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला तथा गांव, गरीब और खेती किसानी को नई संजीवनी देने वाला है जिसके लिए मैं मा0 वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। ऐसे समय जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है यह बजट आम लीक से हटकर एक नई दिशा और नई रोशनी देने वाला है। प्रस्तुत बजट से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्र की मौजूदा सरकार सभी को कुछ न कुछ देकर संतुष्ट करने और आंकड़ो के जरिये गुलाबी तस्वीर पेश करने के बजाय देश के बुनियादी बदलाव के लिये कमर कस ली है। इससे यह तस्वीर भी सामने आती है कि सरकार ने उन समस्याओं का समाधान करने का मन बना लिया है जो देश की अर्थ व्यवस्था को पर्याप्त मजबूती देने में बाधक बनी हुयी थी। बजट के माध्यम से मा0 वित्त मंत्री नये भारत की स्पष्ट सोच के साथ सामने आये हैं इस सोच की केन्द्र में नौ स्तंभ हैं और मुख्य आधार है गांव, गरीब, किसान और नौजवान से नौ स्तंभ किसान, गांव, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, वित्तीय सुधार, सुशासन, खजाना प्रबंधन और कर सुधार के रूप में हैं। ग्लोबल मंदी की काली छाया से मुक्ति के लिये वित्त मंत्री ने गांव और किसानों पर सर्वाधिक ध्यान दिया है और भरोसा भी जताया है। इसके साथ ही युवाओं की भी सुध ली गयी है और शिक्षा, सेहत के साथ पर्यावरण की भी चिंता की गयी है।

मौजूदा बजट पूरी तरह से गांव, किसान पर कुर्बान है। वित्त मंत्री ने यदि किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है तो उसे मजबूती देने के लिये ठोस कदम भी उठाये हैं। कृषि क्षेत्र का आवंटन 25000 से बढ़ा कर 44000 करोड़ किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के लिये आवंटन 82000 से बढ़ा कर 88000 करोड़ किया गया है। देश में छिपे काले धन को बाहर निकालने की सरकार जो योजना लाई है उससे भी किसानों के हित जुड़े हैं। सामने आने वाले काले धन का 7.5 फीसद कृषि क्षेत्र को मिलेगा सेवा कर से भी 0.5 प्रतिशत सेस कृषि को मिलेगा। मा0 प्रधानमंत्री ने हर किसान के एक बच्चे को नौकरी दिलाने का वादा किया था। खाद्य प्रसंस्करण में 100 फीसद एफ.डी.आई. उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सिंचाई के लिये 20000 करोड़ रू0 की भी घोषणा की गयी है। इसी तरह गांव में संपर्क मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी है।

बजट में सामाजिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, दलितों को आगे लाने के लिये आरक्षण के सियासी दांव से यह सरकार आगे बड़ी है। 250000 दलित उद्यमियों की फौज खड़ा करने के लिये सरकार बड़े कदम उठा रही है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के

---

[*] Speech was laid on the Table.

लिये सरकार इकाई लगाने तक में मदद करेगी तथा उनके उत्पाद को खरीदेगी इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को 30000 हजार से बड़ा कर 100000 रू0 कर दिया गया है। बुजुर्गों का इलाज होने पर 30000 हजार रू0 अलग से मिलेंगे। कई नवोदय विद्यालयों के खोले जाने की भी घोषणा की गई है। लघ उद्योगों को राहत देने के लिये उनकी अनुमानित टैक्स की रकम 10000000 के स्थान पर 20000000 रू0 तक मुक्त कर दी गयी है। आर्थिक सुधारों के लिये उठाये गये कई छोटे छोटे कदम देश की विकास दर को दहाई अंग तक पहुंचाने का आधार बन सकते हैं। राजकोषीय संतुलन का ढांचा तैयार किया गया है। नेहरू युग की योजनागत और गैर योजनागत खर्च आवंटन की निशानी को भी वर्ष 2017 से अलविदा कहने की घोषणा कर दी गयी है। अब बजट में केवल राजस्व और पूंजी खाते की श्रेणियां ही रहेंगी। पंचवर्षीय योजना माडल को देश तिलांजली देने जा रहा है। कुल मिलाकर यह बजट प्रधानमंत्री जी की इस कथन को चरितार्थ करता है कि यह गांव गरीब और किसान का बजट है।

मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Respected Madam Speaker, I beg to draw your kind attention to the salient features pertaining to the Budget presented by Shri Arun Jaitley.

I am not only a son of a farmer but also a son of a freedom fighter. I want to place on record that when India under the able leadership of Mahatma Gandhi got Independence, not only on religion, Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and all others fought together to get freedom. Gandhiji wanted tolerance in this country. The whole world appreciated his leadership and his ideology. India wants that tolerance in this country.

Madam, there are more than 70 per cent farmers in this country. They are the backbone of this country. We have to appreciate the *Fasal Bima Yojana.* It is a good programme given to this country. So many such good programmes are required and I would like to suggest only one which is the mechanism to find out the production, consumption, export and import. There should be a mechanism at the State level as also at the district level. A corpus fund should be formed to protect the farmers.

Second important programme is linking of rivers. We are facing drought in 150 districts. You should find out a mechanism to implement this programme. I would like to place on record that it was started by Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Ji and Atal Bihari Vajpayee Ji also fought for this programme. You may take all the States into confidence and you will see that this is the only way to solve the entire problems of this country.

The former Prime Minister Deve Gowda Ji also raised the issue concerning silk farmers. I would like to place on record that 5 crore population of our country living in Assam, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka also people living in the Northern States are suffering. There are three categories; silk growers, reelers and weavers and you have to protect them by increasing the duty. That is the only way to protect the silk farmers.

Members on all sides have expressed concern over the jewellers' issue. When UPA Government was in power, Arun Jaitley Ji himself argued the case to increase the excise duty. You can double the indirect customs duty but excise duty is directly affecting the jewellers. All the Jewellers from two districts, around 100 people, came and met me last Sunday in my constituency. They said that Arun Jaitley Ji had pleaded their case when UPA Government was in power. UPA Government was kind enough to withdraw it. Now, you should take it up.

Finally, I would like to place on record that according to SC/ST population in the State, which is 24 per cent, the Karnataka Government has allocated Rs,16,000 crore for their welfare. At the State level as also at the Central level there are more than 30 per cent SC/ST population. In the same way, there are 70 per cent farmers in the country and according to their population you should give budgetary support to them. It will send a good message.

If you see the history, Madam, during Chandragupta's time Chanakya recorded a golden age. In Modern India Manmohan Singh Ji set a record. Now, you have to go to that level and give a good Budget for the welfare of the country.

Thank you, Madam.

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 के भारत सरकार के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में अपनी बात रख रहा हूं। एन.डी.ए. सरकार का तीसरा बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। 8 प्रतिशत के आस-पास की आर्थिक विकास दर बनाए रखते हुए, कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र पर पुरजोर ध्यान देने वाला बजट है। भारत देश की आत्मा गांवों में, कृषि आधारित कामों में बसती है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने - (a) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, (b) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, (c) बीस हजार करोड़ के नाबार्ड के सिंचाई फंड के माध्यम से तथा (d) 6 हजार करोड़ के ग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों को मजबूत करने की योजना बनाई है। अध्यक्ष जी, किसान खुशहाल एवं मजबूत होगा तो देश की 70 प्रतिशत आबादी खुशहाल एवं मजबूत होगी। कुल 35,984 करोड़ की व्यवस्था कृषि एवं किसानों के लिए है, जो सराहनीय है। मनरेगा में बड़े बजट का प्रावधान एवं पांच लाख तालाब एवं कुएं खोदने की योजना जल-संसाधन एवं सिंचाई के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ की व्यवस्था एवं किसान-लोन के लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था, सरकार की गांवों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति एवं पिछड़ों के प्रति कटिबद्धता दोहराता है।

पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में है। ऐसे समय में विकसित देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। भविष्य का समय भारत का है। ऐसे में वित्त मंत्री जी ने रेवेन्यु डेफिसिट एवं फिसकल डेफिसिट दोनों को कंट्रोल मे रखा है। भारत की रेटिंग दुनिया में बेहतर होती जा रही है। एल.पी.जी. में अमीर लोगों के द्वारा सब्सिडी छोड़ने की मुहिम प्रधानमंत्री जी के देश से आग्रह पर शुरू हुई थी। आज ये मुहिम अत्यधिक सफल हुई है। बी.पी.एल. परिवार को एल.पी.जी. से जोड़ने के लिए वित्त मंत्री ने 2000 करोड़ का प्रावधान रखा है, जो अति सराहनीय है। 38,500 करोड़ मनरेगा को आबंटित है। सरकार ने सभी गांवों में अप्रैल, 2018 तक बिजली पहुंचा देने का बीड़ा उठाया है। गांवों के विकास का काम, मूलभूत सुविधाओं का काम इस बजट का हाईलाइट है। सरकार शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास दोनों के लिए कृतसंकल्प है, यह साबित हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्किल डेवलपमेंट पर शुरू से जोर रहा है। इस काम के लिए 1804 करोड़ का बजट इस मंत्रालय को ऊर्जा देगा एवं इससे देशव्यापी कार्य तेजी से बढ़ेगा। देश की 65 प्रतिशत आबादी नौजवान है। इसे रोजगार चाहिए। वित्त मंत्री जी ने कई उपाय इस बजट में किए हैं। मेक-इन-इंडिया की मुहिम इस कार्य में सहायक साबित होगी। अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी

---

* Speech was laid on the Table.

को इस ऐतिहासिक बजट के लिए धन्यवाद देता हूं। 72,000 करोड़ के सातवें वेतन आयोग के अतिरिक्त बोझ के बावजूद उन्होंने हर क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा है।

मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि बजट में तमाम उपलब्धियों के बावजूद कृषि सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में सिंचाई के इक्युपमेंट एवं खेती के लिए ट्रेक्टर इत्यादि हेतु सस्ते लोन की व्यवस्था हो, सस्ती खाद्य की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो। रोजगार के और अधिक अवसर हो जिससे गरीब जनता रोजगार हेतु पलायन न करे।

झारखंड में कृषि हेतु सिंचाई की अत्यधिक कठिनाई है। यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सिंचाई की बेहतर व्यवस्था कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य उत्पादन किया जा सकता है। मेरा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है यहां लोगों को अस्पताल की सुविधा प्राप्त होना अत्यधिक आवश्यक है। अस्पताल व्यय से बचाव हेतु नई स्वास्थ्य बीमा स्कीम झारखंड में चलायी जाएं। शिक्षा हेतु 62 नए नवोदय विद्यालय आरंभ किए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह को लाया जाए। ग्रामीण विकास हेतु 87700 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं जो बहुत ही सराहनीय कदम है। इन तमाम स्कीमों, योजनाओं में झारखंड क्षेत्र जो अति पिछड़ा है, की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

[*]श्री जुगल किशोर (जम्मू): मैं बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि यह बजट गांव, गरीब और किसान का बजट है। जहां तक मुझे ज्ञात है कि देश में पहली बार ऐसा बजट वित्त मंत्री जी द्वारा लाया गया है। मा0 नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतत्व में इस बजट की सभी क्षेत्रों में प्रशंसा हुई है विशेषकर गांव और गरीबों में इस बजट को लेकर बहुत उत्साह है। क्योंक इस बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वो हर प्रावधान रखा हुआ है जिससे गांव और गरीब का उत्थान होगा। गरीबों के लिए जो योजनाएं इस बजट में दी गई हैं उससे गरीबों का अवश्य भला होगा।

देश में पहली बार गरीबों के खाते बिना किसी पैसे के बैंकों में खुले। वो बैंक जो गरीबों को सीढ़ियां तक नहीं चढ़ने देते थे, उन्होंने, उनके घरों में जाकर बैंकों ने खाते खोलने का काम किया।

जन धन योजना का देशभर में स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना उसका भी भरपूर लाभ गरीबों को मिल रहा है।

देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गरीब की लड़की की शादी पर 5 ग्राम सोना और 25 हजार रूपया दिया जाये। देश भर में गरीब इसका लाभ ले रहे हैं। सुकन्या योजना की बात करें चाहे किसी अन्य की, लेकिन माँ-बहनों-बेटियों के लिए जितनी योजनाएं नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने उनको अर्पित की है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माँ-बहनों का मान-सम्मान अपने आप में एक मिसाल है।

माँ-बहनों के अलावा युवाओं के लिए भी इस सरकार ने कई कदम उठाये हैं। जिन नौजवानों के पास कुछ कौशल है और वे अपना काम आरंभ करना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है तो इसके लिए मोदी सरकार ने मुद्रा बैंक की स्थापना की है। लोन आसानी से उपलब्ध हो ऐसा प्रावधान किया है। जिन नौजवानों के पास कोई कौशल नहीं है उनको कौशलयुक्त बनाने के लिए कौशल विकास योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य आरंभ किया है।

गरीब आदमी ज्यादातर बीमारी से परेशान होते हैं, उनके लिए भी इस सरकार ने तीन हजार से ज्यादा सस्ती दवा की दुकाने खोलने का निर्णय लिया है एवं किडनी की बीमारी से निजात पाने के लिए कदम उठाये हैं।

यह देश के पहला बजट होगा जिसमें किसानो के उत्थान के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि। अब सूखे खेतों में भी हरियाली आयेगी और किसान खुशहाल होगा। फसल का नुकसान होने पर बीमा योजना से अब उसके नुकसान की भरपाई होगी और उसको आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण

[*] Speech was laid on the Table.

सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय आरंभ की गई थी, रूक सी गई थी। इस बजट में मा0 वित्त मंत्री जी ने फिर से उसमें जान डाल दी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तेजी से आगे बढ़े और ग्रामों को इसका फायदा मिलना आरंभ भी हो गया। पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों, इसका भरपूर प्रयास इस सरकार में हुआ। बांग्लादेश सीमा विवाद को हल करके एक मिसाल पैदा की। पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया। आज दुनिया में भारत का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के लिए भी इस सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाये हैं। जम्मू कश्मीर की सड़कों, पुलों, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशनों का काफी ध्यान इस बजट में रखा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ जम्मू लोकसभा क्षेत्र, जिससे मैं आता हूं, इस बजट में वहां की गरीब जनता को मिला है। जिसमें गरीबों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करना और कौशल विकास के लिए कदम उठाना। सी.आर.एफ. के द्वारा कुछ सड़कों और पुलों के काम के लिए धन उपलब्ध करना। जम्मू से पूंछ तक नेशनल हाईवे के लिए 5 हजार करोड़ से भी ज्यादा धन उपलब्ध कराना अपने आप में एक मिसाल है। देश के आजाद होने के 60 वर्षों बाद भी जहां बिजली नहीं थी उसके लिए दीन दयाल उपाध्याय विद्युत योजना के तहत उन गांवों में बिजली पहुंचाना, एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने यह बजट जो गांव, किसान और गरीब के हित में लाया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

***प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन)**: , मैं आपने ट्रांसफार्म इंडिया के संकल्प से सिंचित इस आम बजट का समर्थन करता हूं। अपने भाषण का प्रारंभ में माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण की अंतिम पंक्तियों से करना चाहता हूं, बजट सदन को समर्पित करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था "हमारी इच्छा है कि प्रत्येक भारतीय खासकर किसानों, गरीबों और कमजोर वर्ग को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा दी जाए हमारा स्वप्न है अधिक समृद्ध भारत को देखने का और सपना है भारत को विकसित देखने का।" भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि गरीबों, दलितों, अनु. जाति और जनजाति के लिए केवल राजनैतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है जब तक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना न हो तब तक राजनैतिक लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं है। भाजपा सरकार ने डॉ. बाबा साहेब के सपनों को हकीकत बनाने का ईमानदार प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है। बजट और अर्थव्यवस्था का साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी यह कह सकता है कि यह बजट किसानों, गरीबों, अनु. जाति, जनजाति और युवाओं पर केन्द्रित है।

किसान दुनिया में सबसे ज्यादा दुःखी और परेशान हैं। वो परेशान है बाढ़ से, वो परेशान है सूखे मौसम की अनिश्चितता से, साहूकार से, गंदे ग्रामीण परिवेश से, वो दुःखी हैं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में, सड़कों के अभाव में, आजादी के 68 साल बाद भी हमारे गांवों के स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन मोदी सरकार ने यह बजट गांवों की किसानों की सूरत बदलने के लिए समर्पित किया है। 87700 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कृषि समृद्धि की कल्पना सिंचाई की सुविधा के बगैर नहीं की जा सकती लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें देश की नदियों की विशाल सम्पदा के बावजूद खेत तक पानी पहुंचाने में असफल रही है। हमारे पास पानी बहुत है पर पानी का व्यवस्थापन वाटर मैनेजमेंट नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गयी। 28.5 लाख हेक्टेयर जोत की सिंचाई 5 लाख कुओं और तालाबों से की जाएगी। लम्बे समय से लम्बित पड़ी 89 सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने के लिए 17000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है, 20000 करोड़ रुपए से दीर्घावधि सिंचाई निधि बनाई गयी है, 19000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हेतु दिए गए हैं, 38500 करोड़ रुपए मनरेगा में दिए गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कहां हैं वो जो सरकार को सूट-बूट की सरकार कहते थे। एक चाय बेचने वाले ने सूट पहन लिया तो लाखों-करोड़ों के भ्रष्टाचार पर भारी हो गए? एक शेर मुझे याद आता है -

---

* Speech was laid on the Table.

हम आहे भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।।

हमारे किसानों ने हमें खाद्य की सुरक्षा दी लेकिन देश उन्हें आय की सुरक्षा न दे सका, किसान आत्महत्या को विवश हैं। सरकार ने 5500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु आवंटित करके कृषिकारणों से आत्महत्या के रास्ते बंद कर दिए हैं। मात्र 2% और 1.5% की प्रीमियम पर किसानों को बोवनी से लेकर बिक्री तक की सुरक्षा इस योजना में दी गयी है।

हम जानते हैं कि हमारे देश में खेतों का आकार छोटा है और ज्यादातर सीमांत किसान हैं। सिंचाई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शायद उनके जीवनस्तर में सुधार न ला सके, इसलिए वित्त मंत्री जी ने मनरेगा में 38500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 19000 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिए है। इन सबसे बढ़कर देश के 100% गांवों में 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांवों में रोजगार बढ़ेगा, बिजली की उपलब्धतता से गांवों में छोटे कुटीर और लघु उद्योग पनप सकेंगे। 80 लाख रुपए प्रति पंचायत को आधारभूत विकास के लिए और किसानों को 9 लाख करोड़ के कृषि ऋण बाटने का लक्ष्य वास्तव में गांवों और किसानों के लिए अच्छे दिन की गारंटी है।

मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं और मैं उन लोगों से जो डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र लगाकर अपनी राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आवरण बना रहे है वो जो झूठ बेच रहे हैं जैसे छिपकली जीव जंतु खाकर महात्मा गांधी के चित्र के पीछे छिप जाती है, अपने पापों को छुपा लेते हैं वैसे ही जिन्होंने बाबा साहेब को कभी स्वीकार नहीं किया कभी माना नहीं उन कम्यूनिस्टों और कांग्रेसियों को निराशा होगी। इस बजट में 38833 करोड़ रुपए अनु. जाति के लिए विभिन्न योजनाओं में दिए गए है, मुझे याद है पिछली यूपीए सरकार ने अनु. जाति के कम्पोनेंट प्लान की राशि विभिन्न मदो में खर्च की थी। भाजपा सरकार ने स्टेंड-अप स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। निर्देश दिया है कि प्रति बैंक कम से कम 2 अनु. जाति, जनजाति वर्ग के व्यक्ति को उद्योग लगाने हेतु ऋण देगी, इससे देश में एक वर्ष में 2.5 लाख उद्यमी तैयार होंगे। उद्योग संघों की भागीदारी से राष्ट्रीय अनु. जाति, जनजाति हब की स्थापना की जाएगी। ये बात शायद मेरे विपक्षी मित्रों को रास न आए। क्योंकि हमेशा से कांग्रेस और कम्यूनिस्टों की रूचि अनु. जाति, जनजाति वर्ग को गरीब और पिछड़ा रखने में रही है। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं केवल उन्हें गरीब रखने की मानसिकता से लाई गई थी, ताकि वे गरीब बने रहे और उनके पिछड़ेपन को गरीबों को हथियार बनाकर कभी उन्हें नक्सली बनाया जाए, कभी कन्हैया जैसे गरीब वर्ग से आए विद्यार्थी का ब्रेनवाश करके राष्ट्रविरोधी बना दिया जाए। भाजपा सरकार अनु. जाति, जनजाति वर्ग के जीवन में बदलाव लाना चाहती है, उन्हें जॉबसीकर नहीं जॉब प्रोवाईडर बनाना चाहती है, आर्थिक बराबरी पर

खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस और कम्यूनिस्ट युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं ताकि उनमें राहुल वेमुला निकले। लेकिन सरकार उनमें उद्यमी देखना चाहती है, साहसी देखना चाहती है, युवा शक्ति को चारा, अपनी गंदी राजनीति का साधन बनाने वाली पार्टियों को बजट से निराशा है, निराशा होनी भी चाहिए क्योंकि मोदी सरकार 1500 नए ट्रेनिंग स्कूल खोलने जा रही है। उन्हें स्किल्ड बनाना चाहती है। पहले गरीब के पास विकास की संभावना कम थी, न प्रशिक्षण था न पैसा था न कोई ऋण सुविधा थी। माननीय वित्त मंत्री जी इन आवश्यकताओं को समझा और मुद्रा योजना में 1.80000 करोड़ रुपए के ऋण देने का लक्ष्य रखा है। मुझे उम्मीद थी कि देश में बेरोजगारी पर चिंता प्रकट करने वाले दल और नेता इसका स्वागत करेंगे, स्टार्ट-अप, स्टेंड-अप और मुद्रा योजना की प्रशंसा करेंगे लेकिन यह नहीं सुनाई दिया। वे परेशान हैं कि यदि युवाओं को रोजगार मिला तो अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा।

गरीब वर्ग में गुर्दे की बीमारी किडनी फेल होने की बीमारी बहुत होने लगी है और जिस गरीब की किडनी बिगड़ जाए तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। वो रोज मृत्यु की और बढ़ता है और परिवार उसे अपनी और खिंचता है। जब किडनी खराब हो तो आदमी एकदम नहीं मरता क्रमशः शनैः-शनैः मरता है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, एक बार डायलैसिस का शुल्क 1000 रुपए होता है और यह हर सप्ताह में करवाना होता है। इस प्रकार परिवार को 5000 रुपए अलग से जिन्दा रहने की कीमत चुकानी होती है। भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख 20 हजार मरीज नए जुड़ते हैं लेकिन केवल 4950 डायलिसिस सेंटर हैं। सरकार ने "राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम" की शुरूआत करके सिद्ध किया है कि सरकार मानवीय है।

हम विकसित देशों में देखते हैं कि हर व्यक्ति का मेडिकल इंश्योरेंस होता है लेकिन भारत के सदंर्भ में यह कल्पना ही थी कि हर व्यक्ति का और खासकर गरीब व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा हो, सरकार ने नई "स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम" लाकर करोड़ों परिवारों को राहत देने का काम किया है जिसमें प्रति परिवार 1 लाख तक का बीमा है जिसमें 70-75 तक की सारी बीमारियां कवर होगी। वृद्धों के लिए 30 हजार अलग से बीमा राशि बढ़ाकर आम आदमी की तकलीफ को कम किया है।

अटल जी की सरकार के पूर्व गैस कनेक्शन के लिए एक दो साल और कभी-कभी तो इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता था जिसे 6 महीने में मिल जाए वो खुद को भाग्यवान समझता था। अटल जी ने एलपीजी गैस की लाइन और प्रतीक्षा खत्म की अब जो चाहे कनैक्शन ले सकता है। लेकिन पिछली यूपीए सरकार ने उसे आगे नहीं बढ़ाया और अभी भी 1.5 करोड़ परिवार उससे वंचित है। गरीबी का नारा देने वाली पार्टियों से इस दिशा में कुछ नहीं किया लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का जिन्होंने 1.50 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनैक्शन रियायती दर पर उपलब्ध करवाने के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया।

जो अपना हाथ गरीबों के साथ होने का झूठा दावा करते आए हैं, गढ़ते आए हैं उनसे गरीबों का मोह भंग हो गया है। मोदी सरकार के इस जन-कल्याणकारी बजट ने उनकी आंखें खोल दी है उन्हें लगने लगा है कि अब तक जिसे हम हाथ समझकर पकड़े हुए थे वो दस्ताना था। उन्होंने दस्ताना छोड़ दिया है। हमारा किसान जी-तोड़ मेहनत करके अनाज उगाता है लेकिन असली उपज का 10% तक भाग बेकार चला जाता है, सब्जी और फल तो 25% तक बेकार हो जाता है लेकिन उनकी प्रोसेसिंग को लेकर कोई पुख्ता योजना पूर्व की सरकार ने नहीं बनाई। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण में 100% एफडीआई की अनुमति दी है, इससे देश में भंडारण और खाद्य प्रोसेसिंग प्रणालियों की सुविधाओं में सुधार आएगा। उत्पादों का बेहतर लाभ किसानों को मिलेगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, निर्यात बढ़ेगा। हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा और सम्पन्न भी होगा।

*SHRI P.R.SUNDARAM (NAMAKKAL) : Hon. Madam Speaker, Vanakkam. I thank Hon Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma for allowing me to take part in the discussion on General Budget for the year 2016-17, on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK). Hoarding black money is a challenge to nation's development. Hon. Prime Minister before coming to power, said that black money stashed abroad would be brought back to India. There was no concrete action by the Union Government in this regard. On the contrary, the Union Government has now announced about voluntary disclosure of black money and paying tax for them. Time has also been extended by the Government for availing such benefit. This will only help the hoarders of black money. Labourers and employees save in Employees Provident Fund (EPF) and Insurance Schemes as it would help them at the time of their financial need. But tax on EPF and Insurance policies, as announced in the Budget, is a matter of worry. I welcome the announcement by the Union Government to withdraw imposition of tax on EPF. No change has been effected in raising the income tax exemption limit. This is also a matter of concern. These issues clearly reflect the fact that the Union Government has no concern towards the welfare of poor and middle class people.

In comparison to last year, additional funds of 10% have been allocated to Defence this year. This is just 1.74 % of the Gross Domestic Product (GDP). Even our neighbouring country China has allocated more funds to its Defence sector. This is a threat to India. At least 3% of GDP should be allocated to Defence forces of our country. Even though Government of India spearheads the programme called "Make in India", 60% of defence equipment are imported from foreign countries. We have to domestically produce our defence equipment. Then only we can add weightage to the term, 'Make in India' in the true sense.

Due to the untiring efforts of Hon. Amma the Notification of Cauvery River Water Tribunal was published in the Union Gazette. As demanded by the

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

Hon. Chief Minister *Puratchithalaivi* Amma, in a letter addressed to Hon. Prime Minister, the Cauvery River Water Management Authority should soon be set up.

Hon. Madam Speaker, Under the Saansad Adarsh Gram Yojana (Member of Parliament Model Village Scheme), a village is being adopted by every Hon. Member of Parliament. No funds are being allocated by the Union Government under this Scheme. How is it justifiable to ask the Hon. Member of Parliament to adopt a village under this Scheme without allocation of any fund?

Under MPLAD Scheme, Rs. 5 Crore is allocated every year to each parliamentary constituency. This amount should be increased as Rs.10 Crore per year.

Hon. Madam Speaker, Import duties on life saving drugs should be abolished. I urge that drugs for treatment of cancer should be included in the list of essential drugs. Due to the unseen and unprecedented heavy rains that devastated Tamil Nadu particularly Chennai and 7 districts were worst affected. To restore normalcy and to undertake rehabilitation work, Hon. Amma demanded Rs. 5000 Crore in the first phase and Rs. 25912.45 Crore subsequently. But only a meager amount of Rs.1900 Crore has been so far provided by Tamil Nadu. I, therefore, urge that the funds, as demanded by Hon. Amma, should be released immediately to Tamil Nadu.

The Fishermen of coastal districts of Tamil Nadu, while engaging in fishing in traditional sea waters, are time and again arrested by the neighbouring country. After the efforts of Hon. Amma, they were released in the past. This is becoming a continuous affair. The Union Government should act upon to stop this menace of fishermen being arrested by neighbouring country. As demanded by Hon. Amma, Katchaththeevu – an islet should also be taken back which was earlier ceded to Sri Lanka.

Hon. Madam Speaker, the Union Government has allocated Rs.72394 crore for education. During last 5 years, Hon. *Puratchithalaivi* Amma has allocated Rs. 85,000 Crore for education in Tamil Nadu. That is why Tamil Nadu

has been progressing too much in the field of education and continues to remain a *Numero Uno* State in the country in the field of education. Taking cue from Tamil Nadu, the Union Government should allocate more funds to the field of education. As regards power generation during previous minority DMK Government, Tamil Nadu faced acute power shortage. Now Hon. Amma has made Tamil Nadu self-sufficient in power generation. Power grid aimed at distribution of power to Tamil Nadu should be strengthened by the Union Government.

During the years 2011 to 2014 the then Finance Minister Shri P. Chidambaram of the UPA Government announced in the Budget that Rs.1000 Crore will be allocated for setting up of a desalination plant in Tamil Nadu. But not even a single paisa was allocated. The then Finance Minister had not allocated any money because of his political vendetta and his helplessness to digest Hon. Amma getting name and fame. Due to this, he did not even contest in his own Sivaganga parliamentary constituency but sought candidature for his son and thereafter the latter also could not secure his deposit in 2014 elections.

Another party, which was a partner of congress Party and involved in 2G Scam, had a damaging defeat. Hon. Amma has been implementing this desalination project for the welfare of the people of Tamil Nadu.

"Unworthy friendship will do more harm." As the saying goes, the DMK, which went away from the Congress led coalition during the 2014 Lok Sabha elections, has once again joined hands with the Congress party. During 2014 Lok Sabha elections, this coalition could not secure a single parliamentary seat in Tamil Nadu. This time also they will not be able to win any Assembly seat. Rs.1,76,000 Crore 2G Spectrum Scam, Rs.1,86,000 Crore mining scam and several scandals has brought defame to the DMK-Congress combine and that coalition will be defeated by the people of Tamil Nadu in the forthcoming Assembly Elections. The people of Tamil Nadu will teach them a lesson.

DMK leader, while expressing his wish to join hands with another party, said that there would be a fruitful result. But to his discomfort all ended in vain.

Another leader who glorified himself as king and kingmaker should know that he is only kingfisher. Their chapter is a closed one. Tamil Nadu will see a new beginning under the rule of Hon. *Puratchithalaivi* Amma once again. Thank you.

* DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR) : This year's Union Budget is a great disappointment for the Nation. The allocation to various Ministries has been minimal against the backdrop of huge promises made by the Prime Minister, Union Ministers amounting to tens of thousands of crores. This Budget is a testimony to all this.

It is no secret that the Finance Minister had to present this budget under the two silver lines; the falling oil price and the comfortable foreign exchange reserves at USA $351 billion. Further, the recent implementation of the 14th Finance Commission recommendation that has raised the share of states in the divisible pool of central taxes from 32% to 42% has to some extent squeezed the revenue and resource intervention base of the central government. This Budget has absolutely failed to exploit this advantageous situation.

We know that budget is neither the only economic policy paper nor the last word in economic policy making.

The next issue is: from where the money will come? The Finance Minister has stuck to his fiscal consolidation promise of maintaining fiscal deficit at 3.5% of the GDP. In the absence of the corporate growth, he heavily depends on indirect taxes.

In the absence of any visible benefits to the neo middle class, this class may hold back its income from spending. This makes the expected indirect tax realizations uncertain. The Government has to live with this uncertainty.

I come from the state of Manipur. My state Manipur was an independent kingdom till we lost our independence to the British in 1891. After this, Manipur remained as a princely state.

With the lapse of British suzerainty following the adoption of the Indian Independence Act, 1947, Manipur regained its sovereign independence. During this transition period the Manipur State Constitution Act, 1947 was passed. In early 1948, the first election was held in Manipur on the basis of adult franchise.

---

* Speech was laid on the Table.

Our Maharaja was called to Shillong and made to sign the Manipur Merger Agreement in 1949. On adoption of the Constitution of India on 26 January 1950, Manipur became a part C state and then a Chief Commissioner State, then the Territorial Council in 1957; then the Territorial Legislative Assembly in 1963; and Union Territory under the Union Territories Act, 1963. Manipur became a full-fledged State on 21 January 1972 by the North-Eastern (Reorganization) Act, 1971.

What is the position of the present Manipur in the country vis-a-vis the Constitution of India. We the people in Manipur feel that had Manipur been merged into the Union of India as a full-fledged state at the time of its merger in 1949, most of the problems the state is now facing might not have occurred.

In 1963, when the Naga Hills of Assam was granted Nagaland state, the two erstwhile princely states of Manipur and Tripura could have been granted statehood. Unfortunately, it did not happen. These demand-driven actions of the Government of India do more harm than good.

We know that till Manipur attained statehood, the people did have little say whatsoever. But in 1972, when Manipur attained full-fledged statehood, all that Manipur had before its merger into the Union of India could have been restored to Manipur by the Union Government.

These include, among others, the protection of territorial integrity of the state (including International boundary), the regulatory system of entry into and exit from Manipur by outsiders (abolished in 1950), the tribal status for all the indigenous people of the state, the redeeming of Rs.500 tax/tribute for Kabaw valley by the Burmese Government under Treaty of Yandaboo. Unfortunately, these things did not happen. Even the merger agreement had not been implemented at all and has been completely forgotten. Because of this, Manipur is now facing a huge demographic challenge.

The state of Manipur had been facing a serious insurgent movement from around the beginning of 60s, which in my opinion, requires a political solution.

Instead, Government of India promulgated Armed Forces (Special) Powers Act, 1958 (AFSPA).

This AFSPA is really draconian and a black law. Many Committees, Commissions, Conferences including most recent Justice Verma Committee and UN agencies recommended repeal of the Act. I have been always urging the Government of India for the immediate repeal of AFSPA, but of no avail till date.

In order to safeguard the territorial integrity of Manipur, I have moved a Constitutional Amendment Bill twice to insert an extra Article 371CC : that 'Article 3 of the Constitution of India shall not apply in respect of the state of Manipur. Till now, this Bill does not get the space for consideration.

At the moment, there are three Bills passed by the Manipur Assembly and waiting for the assent from the President of India. These are good Bills and will help protecting the indigenous people of Manipur for all time to come. I hope, very soon the President of India will give his assent.

We are all for a peaceful settlement of vexed Naga issues. Unfortunately in 2001, because of the three words 'beyond territorial limits in the Indo-NSCN(IM) cease fire agreement, there was a huge upsurge in the state of Manipur killing 18 innocent people and burning down the State Assembly building and many other government offices in 2002. That was during NDA regime.

Last year again, on August 3, a framework agreement was signed between Government of India and NSCN(IM). What are there in the framework, it appears nobody knows. Manipur, Assam and Arunachal Pradesh Governments are demanding the details of the framework agreement. Because NSCN (IM) does speak among others including their demand for some sort of integration of Naga people of the neighbouring states by expanding their territory and also of shared sovereignty with the Government of India.

Considering all these aspects, I do urge upon the Union Government to take all possible steps within the framework of our Constitution for a political solution of the age-old problem of insurgency in the state of Manipur and also a generous

special economic package for all round development of this erstwhile princely state of Manipur.

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):** माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह बजट गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को समर्पित है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमारी विकास दर 7.6 प्रतिशत रही है। नई फसल बीमा योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। कृषि और किसान कल्याण के लिए इस बार बजट को दुगुना कर दिया गया है। पिछली बार यह 22,958 करोड़ था जिसे बढ़ाकर इस बार 44,485 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार से कृषि एवं सिंचाई के बजट को 25,988 करोड़ से बढ़ाकर 54,212 करोड़ किया गया है। किसानों की आमदनी 5 वर्ष में दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गरीब परिवारों को 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। 60 साल के ऊपर के लोगों को 30 हजार का अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है जिससे उनको 1 लाख 30 हज़ार रुपए स्वास्थ्य का बीमा मिलेगा। गुर्दे के मरीजों की संख्या को देखते हुए हर जिले में एक डायलेसिस केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सराहनीय है। 5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनैक्शन देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे उन गरीब महिलाओं को लाभ होगा। जो धुएं से अपनी आंखों एवं फेफड़े को खराब करती थीं। आधार कार्ड से सब्सिडी सीधे उनके खातों में भेजने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे आम जनजीवन को बहुत ही लाभ होगा। सरकार ने 3 हजार जन औषधि केन्द्र खोलने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उससे गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। 300 कलस्टर बनाकर ग्रामों के समूहों को विकसित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है उससे गांवों को विकसित करने में सुविधा मिलेगी। ग्राम पंचायतों के बजट को 228 प्रतिशत बढ़ाकर 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे हर ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपया कम से कम मिलेगा। साथ ही प्रत्येक टाउन एरिया एवं नगरपालिका परिषदों को को भी 11 करोड़ से लेकर 21 करोड़ तक मिलेंगे। जिससे वहां के विकास में मदद मिलेगी। वर्ष 2016-17 में 10 हजार कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हर रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर बनाने की विशेष योजना शुरू की गई है जो सराहनीय है और एक क्रांतिकारी कदम है। छोटे घर खरीदने वालों को 50 हजार रुपए तक की कर कटौती छूट प्रदान की गई है। इससे आम लोगों का घर खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा। किराएदारों को राहत देते हुए उनको आयकर कटौती में छूट की सीमा 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कर दी गई है जो कि एक सराहनीय प्रयास है।

---

* Speech was laid on the Table.

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जन भावनाओं को देखते हुए सर्राफा व्यवसाय पर जो अतिरिक्त कर लगाया गया है उसे वापस लेकर सर्राफा व्यवसायियों को विश्वास में लेकर उक्त कर की पूर्ति किसी दूसरे रुप में करने हेतु बजट में प्रावधान करने की कृपा करें। आयकर की छूट की सीमा जो पिछले वर्ष भी नहीं बढ़ाई गयी थी उसे ढ़ाई लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने हेतु अपने जवाब में ऐसी घोषणा करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। सांसद क्षेत्र विकास निधि जो कई वर्ष पूर्व बढ़ाई गई थी उसमें रॉ मेटेरियल की मंहगाई की दर के अनुसार उसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अतः इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर उसे बढ़ाने हेतु इसी बजट में प्रावधान करने की कृपा की जाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए विशेष अनुदान की इस बजट में व्यवस्था की जाए ऐसा मैं अनुरोध करता हूं।

मैं बुन्देलखंड क्षेत्र से आता हूं जहां पिछले 10 वर्ष से सूखा की वजह से विषम हालात है। किसान आत्महत्या कर रहा है। अतः बुन्देलखंड के प्रत्येक जिले को विशेषकर उत्तर प्रदेश के आठों जिलों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में लेकर इसी वर्ष से काम शुरू करने का अनुरोध करता हूं। बुन्देलखंड क्षेत्र में सभी जिले के किसानों के कर्जे एवं ब्याज को माफ कर इस अनुदान को सीधे उनके खातों में जमा कराने हेतु इसी बजट में प्रावधान करने की प्रार्थना करता हूं। बुन्देलखंड क्षेत्र में गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बांदा या महोबा में एक एम्स की स्थापना हेतु विशेषतौर से निवेदन करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बांदा जिले में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। इसी सत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु निवेदन करता हूं। मेरे क्षेत्र में कैंसर मरीज बहुतायत में हैं। आस-पास कई सौ कि.मी. में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अस्तु चित्रकूटधाम में एक कैंसर अस्पताल खोलने हेतु मैं अनुरोध करता हूं।

इसी के साथ माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाए गए बजट का समर्थन करते हुए एक ऐतिहासिक बजट लाने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

* PROF. RICHARD HAY (NOMINATED) **:** First of all, I compliment the hon. Finance Minister and the Government of India for presenting a pro-people budget which is for all purpose a pro-poor budget. I compliment the Government for keeping in control the fiscal deficit, which is the result of prudent fiscal planning and control.

The budget unequivocally supports the MGNREGA, Crop Insurance, and a host of such people friendly schemes to help the marginalised to be freed from the shackles of poverty which they have been undergoing for several decades.

Doubling farmers income is by itself a formidable task which the Government is committed to and this Budget shows the way for doubling the farmers income by 2022. The basic needs of the rural poor are taken care of by this Government which understand the pangs of the pain suffered by the poor all these years.

I urge upon the Finance Minister to provide more financial support to enable marketing of the farm products, value addition, augmenting the farmers income, constituting a Food Regulatory Authority by the Union Government to support the prices of all farm produce so as to ensure fair price for the farmers as well as fair price to the consumers which are most welcome and for which we look forward to.

Allocation of more budgetary provisions for the education sector is most welcome as this is the key method by which a nation can progress by providing educational opportunities, especially for the underprivileged. A concerted action is called for helping the weak and poor to be provided with educational facilities on a war footing from primary to higher education. The GER has to increase and catch up with other developed countries. More funds are to be used for research and innovative practices in the universities which would help industry and the society to progress at a greater speed. Simultaneously, this Government is laying emphasis on skill development which would ensure jobs to the youth who have

* Speech was laid on the Table.

registered their faith in a Government which fulfills the aspirations of its citizenry, especially the youth. The linguistic minority, Anglo-Indian seeks financial support for their socio-economic development.

Also the hon. Finance Minister has laid so much importance to the development of infrastructure by allocating huge outlays for infrastructure, including roads, rail, inland water way, ports, etc. The construction industry too will also develop by leaps and bounds due to fiscal policies and budgetary support. Providing homes for millions of people is yet another laudable achievement. The low cost housing scheme would fulfill the dreams of millions of homeless.

The Aadhar cards are going to help millions to obtain their legitimate claims and would make them enjoy the fruits of their hard earned labour.

The budgetary support for completing rural electrification is another admirable feat that would bring the joy of light to millions of homes throughout the country. The gas connections in the homes of millions of poor in our country will bring lot of relief to the poor - a result of the love and affection showered by the hon. Prime Minister to the common man by sending out a call to the fellow citizens to give up subsidy so as to help the needy.

The hon. Finance Minister has given an opportunity to the tax defaulters to pay up their tax which would necessarily help the poor as the Government would be able to bring out more welfare measures to save the poor from poverty. We hope the tax defaulters will show concern for the poor brethren and sisters and pay their tax as a true citizen of the nation.

The Mudra Bank, the Start Up and Stand Up, the several insurance schemes, etc. are bringing out positive results that needs the budgetary support and the support of every citizen who can also reap the benefits of such a pro-people budget. The ripple effect of such people-centric budget is the acceptance by the people who has immense faith in this Government economic policies.

The nation needs the backing of both PSU's and private sector to revitalize her economy to build a modern India where progress is achieved through equity,

justice and integrity. I once again pay my compliments to our hon. Visionary Finance Minister and the leader of the nation, the Prime Minister for bringing out a growth-oriented welfare budget that fulfills the dreams of her citizenry. Resurgence of India is a fact and reality.

*श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2016-17 का समर्थन करता हूं। अर्थव्यवस्था में एक नयी क्रांति की शुरूआत है। वर्तमान माहौल में गरीब, किसान, गांव, मध्यम वर्ग व इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण व उद्योग तथा व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक संतुलित बजट है। विपक्षी दल (पूर्वाग्रह व राजनैतिक कारणों से) विरोध कर रहे हैं परन्तु उनको भी पता है कि कृषि, किसान, गांव, गरीब, स्वास्थ्य, सस्ती दवाओं, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार की चिंता के साथ गांव व शहर के जीवनस्तर में अंतर को भी समाप्त करने के साथ अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने के प्रस्ताव किए गए हैं, जिनके परिणाम शीघ्र ही दिखायी देंगे। बजट दर्शाता है कि यह सरकार देश के सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार व सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के सामान्य नागरिकों से लेकर उद्योग जगत, किसानों व युवाओं की अपेक्षायें पूरा करने वाला यह बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा मुश्किल राजकोषीय चुनौतियों के दौर में अर्थशास्त्र व प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस देश के 70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने 36000 करोड़ रुपए देकर व पांच वर्षों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रशंसनीय प्रस्ताव किया है।

सरकार ने कृषि ऋण बढ़ाकर नौ लाख करोड़ करने के साथ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, डेरी, फूड प्रोसेसिंग जैसे सहयोगी कृषि व्यापारों सहित स्किल डेवलेपमेंट व 300 ग्रामीण कलस्टर (100 इस वर्ष) का विकास करके गांवों में आवासीय सुविधाएं बढ़ाने के प्रस्ताव करके गांव व किसानों को सुविधाएं देने के प्रस्ताव किए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 30 प्रतिशत योगदान है, वहीं कुल निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का योगदान है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराने के अलावा उत्पादित अनेक वस्तुओं की खपत भी कृषि क्षेत्र में होती है। सरकार ने जमीन के स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु मार्च, 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया है। देश में जैविक खेती पर भी जोर दिया गया है। सरकार निश्चित ही किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। देश ने दाल की कमी दूर करने व महाराष्ट्र तथा बुंदेलखंड के सूखे से निपटने की रणनीति भी बनायी है। सरकार 28.5 लाख हैक्टेयर जमीन 23 प्रोजेक्ट्स के, 2017 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत करने व दीर्घकालिक सिंचाई कोष बनाने का भी प्रस्ताव किया है।

---

* Speech was laid on the Table.

सरकार ने कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर जोर देने के साथ मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर किसानों को फसल का पूरा दाम दिलाने का भी प्रस्ताव किया है।

इस बेहतरीन बजट में प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक लाख रुपए स्वास्थ्य कवर, एयरपोर्टों के विकास, कनेक्टिविटी बढ़ाने, कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक परिवहन सुविधाएं बढ़ाने, रोजगार के अवसर प्रदान करने, आम लोगों के जीवन स्तर में बेहतर परिवर्तन लाने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर जोर दिया है। देश को बेहतर सुरक्षा व सुविधापूर्ण रेल और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भी यह बजट स्वागत योग्य है। निश्चित ही देश सम्पूर्ण विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि देश के स्थायी विकास के लिए 2016-17 का बजट एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*__श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) :__ माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए देश के किसानों, ग्रामीण भारत की तरक्की वाला एक ऐतिहासिक, शानदार बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं । साथ ही बजट का समर्थन करता हूं । इस बजट से देश के करोड़ो नौजवानों, छात्रों को बहुत आशाएं हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनकी इच्छाओं के अनुरूप तैयार यह बजट, जिससे केन्द्र में किसानों की खुशहाली, गांव-गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं, युवा को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार आदि अनेक ऐसी जनोपयोगी योजनाएं इस बजट में हैं जिनके कार्यान्वयन से निश्चित रूप से देश की प्रगति होगी, देशवासी खुशहाल होंगे और देश का विकास होगा । इस बेहतरीन बजट से केन्द्र में, गांव, गरीब और किसानों के लाभ, उनकी सुविधा से जुड़े विषयों के समावेश से विपक्ष की बोलती बंद है । विरोध करने को उन्हें मुद्दे नहीं मिल रहे हैं । इस बजट की सराहना करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे प्रदेश बिहार में किसानों की स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है ।

जहां विगत चालीस वर्षो से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना, जो बिहार-झारखंड के सवा लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई करने वाली अंतर्राज्जीय सिंचाई परियोजना, जिसका नाम उत्तर कोयला सिंचाई योजना है । इसके बांध, कटकु(मंडल) डैम में लोहे के फाटक के अभाव में योजना अधूरी हैं और लाखों हेक्टेयर भूमि असिंचित है ।

बिहार में पिछले कई वर्षो से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा धान की सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों की स्थिति और खराब होती जा रही है । कहना चाहूंगा कि यदि कोई राज्य सरकार अपने सूबे के करोड़ों किसानों की चिंता ना करे तो क्या केन्द्र सरकार भी उनको उनके हाल पर छोड़ देगा ? मैं समझता हूं किसानों की हितैशी मोदी सरकार निश्चित रूप से इस गंभीर विषय पर विचार करेगी और किसानों की माली हालत में सुधार के लिए अपने स्तर से कोई न कोई रास्ता निकालेगी जिससे सरकारी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीद हो साथ ही बढ़े हुए लागत खर्च को देखते हुए कम से कम 500 रू. प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी मिलना चाहिए ।

अंत में इस अच्छे बजट को पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को धन्यवाद देता हूं और साथ-साथ इस बजट का समर्थन करता हूं ।

---

* Speech was laid on the Table.

[*]श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट): मैं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा 2016-17 के लिए प्रस्तुत बजट के समर्थन हेतु खड़ा हूं। इस बजट को देखकर देश की जनता को लगने लगा है कि अब अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोक सभा चुनाव के दौरान जनता से अपील की थी, सबका साथ सबका विकास यह नारा अब सार्थक होते दिखाई दे रहा है। इस बजट में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों के कल्याण सहित सामाजिक क्षेत्र और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष 2015-16 में अर्थव्यवस्था की 7.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 9.4 प्रतिशत थी, वर्तमान में 5.4 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि 13 प्रतिशत मानसून की वर्षा की कमी तथा वैश्विक निर्यातों में 4.4 प्रतिशत कमी के बावजूद थी। राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रखा गया है। इस बजट में पहली बार पिछली सरकारों की तुलना में सर्वाधिक राशि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई है। चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। करीब 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। सन् 2016-17 के बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में दोगुनी है। सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ की लम्बी अवधि का फंड तैयार किया गया है तथा किसानों की आय अगले पांच वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रकृति के प्रतिकूल प्रभावों से किसानों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 5,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक 1.5 करोड़ बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं के लिए रसोई गैस देने का प्रावधान 2016-17 के बजट में किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च 22.5 फीसदी बढ़ाकर 2.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे 2019 तक 2.23 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जा सकेंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 2012-13 के मुकाबले खर्च दोगुना बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए किया गया है। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत ग्रामों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 8,500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र ग्रामीण विकास हेतु 87,765 करोड़ की राशि रखी गयी है। प्रधानमंत्री जनऔषधि योजनान्तर्गत 3,000 स्टोर खोलने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान

---

[*] Speech was laid on the Table.

किया गया है। अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के उद्यमियों हेतु स्टेंड-अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। जिससे 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा उस्ताद स्कीम का कारगर क्रियान्वयन करने का प्रावधान किया गया है। 72 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास हेतु 1700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजमार्गों के निर्माण हेतु 5,500 करोड़ की राशि रखी गयी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु 1,80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिससे युवा बेरोजारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के विकास के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के विकास के लिए 2,87,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 लाख एवं स्थानीय निकायों को 21 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। इस बजट में मध्यम वर्ग के हितों का भी ध्यान रखा गया है। होम लोन के लिए 50,000 तक के अतिरिक्त ब्याज पर छूट तथा दालों की कीमतों में स्थिरता के लिए प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आयकर की धारा 87ए के तहत छूट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई है। मकान किराए संबंधी आयकर की धारा 87ए के तहत छूट की सीमा 24,000 से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 60,000 की गई है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी स्थापित की गई है। इस प्रकार 2016-17 के बजट में सभी वर्गों के कल्याण हेतु उपाय किए हैं। आज तक जितने बजट आजादी के बाद प्रस्तुत किए हैं उसमें यह सबसे अच्छा बजट है। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो वैभवशाली हो, अखंड हो, विकसित हो, सुन्दर हो, स्वच्छ हो। निश्चित हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना साकार होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री जेटली जी को धन्यवाद देता हूं तथा इस बजट का समर्थन करता हूं।

* DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR) **:** On behalf of our AIADMK party, I strongly oppose the Union Government's proposal to bring about a lesser interest on the hard-earned and prudently saved provident fund savings of the salaried class. This would cause great hardship especially to senior citizens. This would also discourage the habit of savings affecting our economy in a big way.

Even before moving an amendment in the Finance Bill, the Prime Minister who was all in praise for this year's Union Budget has reportedly promised and the Finance Minister has also announced about partly rolling back the stringent tax proposal on withdrawal from the PF savings.

The Centre's insistence to invest 40% of PF in bonds and imposition of income tax on the remaining 60% of PF has been felt as harsh a measure. This amounts to double taxation and hence deplored. The balancing act of budget becomes an imbalanced one due to this tinkering. In its eagerness to please the corporate sector as a fore-thought and to woo the rural population as an after-thought, the Union Government is losing sight of the middle class. Therefore, our leader hon. Amma urged upon the Centre to have a relook. As per the proxym, 'better late than never' the Centre has considered the plea of our leader hon. Puratchi Thalaivi made on behalf of the salaried class. It must not be a half hearted move.

The statement of the hon. Finance Minister with regard to paragraph 138 and 139 of his budget speech is not fully convincing. So, I still urge upon the Centre to drop your proposal entirely.

The people of Tamil Nadu especially those who live in the capital city of Chennai and the coastal districts were seriously affected by the deluge-like rain-floods that inundated and submerged many places. Hon. President of India described it to be a huge loss and an unprecedented havoc. But still, when the hon. Chief Minister of Tamil Nadu asked for a minimum of Rs.25,000 crore to offset the heavy loss, only Rs.2150 crore was announced by the Centre.

* Speech was laid on the Table.

There again the second installment came very late, much delayed after the assessment of damages by the Central team. When the Centre is in a delaying mood, hopefully not a denial mood, we are still waiting for a package for rebuilding the lives, livelihood and the vastly affected infrastructure. When we are yet to be come out of the shock and pain, it is like adding insult to the injury, irresponsible statements are made by some Union Ministers like Mr. Prakash Javedakar.

Our Chief Minister of Tamil Nadu hon. Amma extended whatever possible assistance to begin the relief measures immediately. Union Finance Minister is still expected to extend assistance further. But in the meantime, the Union Environment Minister who is neither directly connected with the Union Budget nor associated with the allocation of funds, made derisive comments about the measures of our Government of Tamil Nadu. He made a tall claim that whatever that was extended by the Tamil Nadu Government to the flood affected people came only from the Centre. He lost sight of the fact that the Government of Tamil Nadu was fully geared up to address the grievances of the people even at the time of managing a difficult financial situation. When generous help came from various states and even individuals, what was announced by the Centre did not meet our expectation.

Where does the Centre get its revenue to apportion funds to various states? All the money that Centre gets is coming only from the people living in various States. The Central revenue is at the cost of the needs and the interests of the State Governments. Though the Centre is not having its own dominion, it gets a lot of money through income tax and customs duties apart from the non-shareable excise duties and cess under various heads. The shares the states get are far from satisfying. Federal spirit is very much lacking. Should we call Federalism is in peril?

As it is, the Centre has washed off its hands from many social welfare schemes and rural development programmes. The Centre must treat disasters of

high-magnitude like the recent rain-floods in Tamil Nadu as national calamity with suitable compensation. At this juncture, the comment made by Shri Javadekar is too much. Instead of rushing with a helping hand, such Union Ministers must not rush to Tamil Nadu and rush away making sweeping comments.

I wish such irresponsible Ministers learn niceties from diplomatic and cultured Ministers like Minister of Parliamentary Affairs, Shri Venkaiah Naidu. He even went to the extent of helping the people of Chennai city at the time of natural calamity that affected us in last December.

[*] DR. A. SAMPATH (ATTINGAL) : I would like to express my strong reservations on the tendency of the Government of India to by-pass the supremacy of the Parliament. The role of the various departmentally related Standing Committees are being reduced to near organs to look into the Demands for Grants, whose recommendations are not at all seriously considered by the executive.

The Finance Minister is trying to generate a set of numbers for projected revenues that are unlikely to be met. Then they find it as an excuse for reducing certain expenditure below the allocated amounts. The end result is that every succeeding year, the Parliamentary discussions on General Budget as well as discussions on the Demands for Grants for various Ministries become a futile exercise. The centralized and secretive manner for the eventual spending below the budgeted amount is not at all a healthy practice for a developing nation like India.

Despite the Global decline in commodity crisis and the Chinese downturn, government is heavily counting on the external sector for growth. Is it possible? The Budget has kept the capital expenditure same as that in the previous Budget. How has the GOI kept the revenue deficit at 3.5%. It is counting on two things, a favourable growth in the economy, and low oil prices. Neither of this likely to continue then what would Government do, it will cut down on the now increased NREGA, because by that time the elections in Bengal, Kerala and UP would be over.

Why is the Government reluctant to raise the tax GDP ratios, our country has one of the lowest compared to different OECD countries. We are making subsidy as if it a big issue. Compared to the subsidy transfers done by the US farm bill and European common agricultural policy, our transfers to farmers is far less. Does the Budget address the decline in the price of agricultural commodities which is affecting Kerala badly.

---

[*] Speech was laid on the Table.

Preoccupied with further reduction of the fiscal deficit, the Finance Minister has proposed to reduce the Central Government expenditure to GDP ratio further. Notwithstanding claims of increases on certain heads of expenditure, there is a parallel slashing on other heads. In agriculture the main increase which the budget shows are by way of transfer to banks and insurance companies that has no real benefit to the farmers. Despite tall claims of a big push in infrastructure, capital expenditure in 2015-16 was lower than budgeted and is proposed to be kept at almost the same level in 2016-17 - implying a reduction in real terms and as a share of GDP from 1.8% to 1.6%. Both food and fertilizer subsidies have been cut by Rs.5000 crores and Rs.2000 crores respectively. The expenditure on Tribal Sub Plan, which is supposed to be 8.6% of the total plan expenditure, is only 4.4% - a shortfall of Rs.24000 crores. Allocations for Minority Welfare have fallen in real terms. The allocation for the ICDS has been slashed by Rs.1500 crores despite the direction of the Supreme Court for its universalisation, which would have required an additional Rs.10,000 crores. Similarly, in the case of the SC sub-plan, the expenditure is pegged at 7% of the total when it should be 16.6.% - ashortfall of Rs.52,470 crores. The Finance Minister also proposes that, for the first time, 60 per cent of all pension and provident fund withdrawals will be taxed! Therefore, if the workers and salaried middle class withdraw their own savings, they will have to bear the burden of this proposed tax.

The lofty claim of highest ever allocation for MNREGA is patently false because it was higher in the year 2010-11. Maintaining 2010-11 levels in real terms would have required an expenditure of over Rs.65,000 crore in 2016-17. What is even more shocking is a concealment of the fact that in 2015-16, despite it being a drought year and the promise of doubling the number of days of work from 100 to 200, the actual level of expenditure was so low to generate only an average of 38 days of work.

The budget is, therefore, distorted without any vision. It is once again a blatant attack on the poor and the oppressed. This is a budget to appease the rich accentuating the problems of unemployment and rising inequality.

If we implement Aadhar Card, will each and every Indian be able to receive the "promised sum" of Rs.15/- lakh in their respective bank accounts? Many of the Budget proposals are detrimental to the economic growth of states like Kerala. Justice is not shown to the five million Indians working abroad and the millions of poor farmers, many of them in the path of committing suicide.

*__श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर):__ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली जी को बधाई देना चाहती हूँ और इस जनरल बजट का समर्थन करती हूँ कि विश्व जो प्रतिकूल परिस्थितयों का सामना कर रहा है भारत ऐसे समय भी अपनी जीडीपी को ऊँचा ले जाने में सफल हो रहा है वह इस आम बजट से हुई जीडीपी दर की वृद्धि से दिखता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत देश को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जैसी नई-नई योजना के माध्यम से देश को और ज्यादा ऊँचाई पर ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

यह आम बजट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्रीजी व माननीय वत्त मंत्री ने खास आम जनता तथा किसानों के कल्याण व उन्नति को केंद्र बनाते हुए भारी निधि उपलब्ध कराते हुए किसानों के आय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया है जो किसान हम सब भारत वासियों के लिए खाद्य सुरक्षा देता है। किसानों का और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु किसानों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को जैसे जल संसाधनों का इटतम प्रयोग, इरीगेशन के नए संसाधन जुटाना (देश में विभिन्न कारण से धीमी गति से या रुके हुए इरीगेशन के 89 प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द एआयबीपी के माध्यम से पूरा करने के लिए विशेष निधि का आवंटन), इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 20,000करोड़ की लंबी अवधि की व्यवस्था, और जमीन की उपजाऊ क्षमता कायम रखने तथा बढ़ाने हेतु संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के लिए आने वाले तीन वर्ष के भीतर 2000 मॉडल खाद बिक्री केंद्र का निर्माण करना और इस केंद्र में जमीन (मृदा) तथा बीज टेस्टिंग मशीन/लैब व्यवस्था होगी। मनरेगा योजना के अंतर्गत 5 लाख फार्म पॉन्ड्स व रिचार्ज वेल तथा 90 लाख कंपोस्ट पिट्स जिसमें आर्गेनिक खाद डेवेलप करने की योजना है जिससे किसान अपने ही खेतों में इस व्यवस्था का निर्माण कर सकें। अध्यक्ष महोदया, किसान भाइयों को अपनी कृषि उपज जैसे अनाज, फल एवं वेजटेबल्स को पूरी व उचित कीमत मिलने हेतु ई-मार्केट जो कि ब्लॉक के दायरे में काम करने वाली एपीएमसी (कृषि उत्पादन बाजार समिति) से संलग्न किया जायेगा जिससे किसान को यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिलेगा। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान को अल्प राशि प्रीमियम के साथ उपलब्ध होगी इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान के लिए ज्यादा भरपाई राशि मिलने की व्यवस्था भी की गई है। नुकसान क्लेम करने में अधिक सरलता, फसल बीमा नियमों में भी राहत जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदा में ज्यादा से ज्यादा फायदा कम समय के अंदर मिले। इससे कृषि और किसानों के लिए की गयी योजनाओं के साथ किसानों की आय आने वाले पांच साल में दोगुनी होने के

* Speech was laid on the Table.

अनुमान से सरकार ने यह कदम उठाएं हैं और यहाँ न रुकते हुए इन सब योजनाओं की पूर्ति के लिए भारी मात्रा में राशि उपलब्ध कराई है। किसानों द्वारा उगाये हुए फल व सब्जी जो मार्केट जल्दी न पहुँचने के कारण खराब हो जाती है। अगर खाद्य संस्करण से वैल्यू एडिशन करने से न ही केवल यह लंबे समय तक अच्छे रहेंगे बल्कि किसानों को उसका लाभ भी होगा। इसलिए ऐसे उद्योगों को बनाने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की स्वीकृति की जायेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए उठाये हुयी योजनाओं का, जब विश्व आर्थिक दृटि से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, ऐसे विपरीत माहौल में माननीय वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलतापूर्वक इन सब योजनाओं का मेलजोल बनाया, उसका मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ।

हमारे ग्रामीण क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19000 करोड़ की आज तक की सबसे अधिक राशि का आवंटन जिसमें राज्य की राशि मिलाकर 27000 हो जाएगी से अब तक के देश भर में बाकी 65000 बस्तियों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान 2021 के बजाय 2019 तक पूरा करने की व्यवस्था है। किसानों एवं ग्रामीणों के लिए और दुग्ध विकास के लिए पशुधन को बढ़ावा देने तथा उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए चार नई दुग्ध उद्योग योजना पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, पशुधन हाट और राट्रीय जीनोमिक केंद्र जो भारत की अपनी ब्रीडर को बढ़ाने हेतु प्रजनन केंद्र होगा। आम आदमी की रोजाना जरूरत के लिए हर गाम पंचायत व हर नगरपालिका क्षेत्र विकसित करने के लिए निधि का आवंटन बढ़ाकर अब 80 लाख व 21 करोड़ प्रति साल का प्रावधान जो पिछले पांच साल से बढ़ कर आज तक किये जाने वाले आवंटन से सबसे अधिक है। हर बीपीएल कार्ड धारक को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु 2016-17 वर्ष में 1.5 करोड़ बीपीएल परिवार के महिला के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन दिए जायेंगे जिसमें आनेवाले तीन साल तक 5 करोड़ बीपीएल परिवार तक पहुँचाने का प्रावधान है। ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षरता बनाने तथा आनेवाले 3 वर्षों के भीतर 6 करोड़ और परिवारों को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था प्रस्तावित करना सामान्य जनता के लिए किफायती कीमतों पर औाधियां मिलने के लिए नये 3000 जन औषधि स्टोर्स इस साल में खोलने की योजना किडनी के बढ़ते हुए मरीजों को डायलिसिस के साइकिल को आनेवाले खर्चे जिनकी संख्या कम होने खर्चे को एवं लंबी दूरी का सफर को देखते हुए "राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम " जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हर जिले में डायलिसिस केंद्र को प्रस्तावित करने के उपाय सराहनीय है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला के बीच उद्यमिता बढ़ाने हेतु "स्टैंड अप इंडिया स्कीम " की घोषणा, इस स्कीम में हर श्रेणी के एक उद्यमी को एवं हर बैंक ब्रांच से कम से कम दो प्रोजेक्ट्स कराने के लिए प्रस्तावित करने से रोजगार उपलब्ध होने, इस क्षेत्र के उद्यमी को बढ़ावा व नई ऊर्जा देने के उपाय, अल्पसंख्यक के कल्याण

हेतु कौशल विकास कार्यक्रम उस्ताद स्कीम का कार्यान्वयन, प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा व सर्वसुलभ (यूनिवर्सलायजेशन) करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को ज्यादा फंडिंग की व्यवस्था तथा नये 62 नवोदय विद्यालय का प्रस्ताव। उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षण व अनुसंधान क्षेत्र में विश्व व्यापी बनाने हेतु 10 सरकारी व 10 प्राइवेट संस्थानों को इस क्षेत्र में अधिक संरचना मुहैया करना जिसके चलते आम परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण लेने में सुविधा मिल सके, विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट्स जैसे स्कूल लिव्हिंग, डिग्री सर्टिफिकेट्स मार्क्स शीट तथा आकादमिक अवार्ड देना उल्लेखनीय हैं। अब डिजिटल डिपाजिटरी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें दस्तावेज सुरक्षित तो रहेंगे ही व गुम एवं खराब (डैमेज) होने से बच जाएंगे और इन्हें अपने साथ लेने की जरूरत नहीं होगी। स्मॉल व मीडियम उद्योग सेक्टर में ज्यादा कर्मचारी रिकॉर्ड पर लेने पर उन सब का फैमिली पेंशन रजिस्ट्रेशन इएफपीओ में करने हेतु ऐसे सबका फैमिली पेंशन हिस्सा पहले तीन साल तक सरकार अदा करेंगी जिससे नये रोजगार निर्माण के होंगे। रोजगार सृजन हेतु इस वर्ष 100 नये मॉडल करियर सेंटस खालने व राज्य एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जोड़ने का प्रावधान है।

रोड व राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 70000 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसके अंतर्गत पुराने 70 प्रोजेक्ट्स का कार्य 75 प्रतिशत पूरा करने के लिए इस बजट में प्रस्तावित है। हालाँकि में माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 6 का फोर लेन का कार्य शुरू करने का आदेश भी पारित किया। जलगांव शहर में तीन जगह पर रेलवे ऊपरी पुल का भी काम करने के लिए अधिकारियों को सूचित किया। मैं यह काम बिना रुकावट से जल्द पूरा हो और इसके लिए आवश्यक निधि सरकार आवंटित करे, यह निवेदन करती हूँ। नए प्रस्तावित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के तहत देशभर में बहु विकास कौशल केंद्र मेरे हर ब्लॉक में हो जिसके चलते हमारे यहाँ के किसान अपने बच्चों को खती के जुड़े हुए व्यवसायों के बारे में ट्रेनिंग देने से यह हमारे केले की फसल लेने वाले किसान जो भारत में करीब करीब 34 प्रतिशत सप्लाई करता है वह और अधिक सशक्त बनेगा। और आखिर इस वर्ष 2016-17 का जनरल बजट जो किसान, ग्रामीण जनता, पिछले वर्ग व अल्पसंख्यक तथा महिला की सुविधा, स्वास्थ्य, फसल एवं फसल बीमा, शिक्षा, उच्च शिक्षण व्यवस्था, रोजगार सृजन, इन पर केंद्रित रखते हुए और दुनिया भर में विपरीत परिस्थिति होते हुए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत तथा सशक्त बनाते हुए भारत को एक नई उन्नति की दिशा में ले जानेवाला है जिससे भारत विश्व में एक बार फिर अपना स्थान बनाने के लिए तैयार है यह दिखाता हुआ बजट देने के लिए मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी व माननीय वित्त मंत्री जी को फिर से धन्यवाद दे कर जनरल बजट का समर्थन करती हूँ।

[*]SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER):The General Budget is pro-farmer and focuses to strengthen the Rural Development of the Country. It is a very welcome Budget for Rural India. In this context, I would like that Budget provided for PMKSY should be increased so that Agriculture growth can take place properly at the rate of 4% which is very much required for the overall development.

Thanks.

[*] Speech was laid on the Table.

***श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा):** मैं आपका ह्रदय से आभारी हूं कि आपने सामान्य बजट 2016-17 पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। इस बजट द्वारा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार समृद्ध, श्रेष्ठ, गौरवमयी, भारत के निर्माण की प्रक्रिया में देश के प्रत्येक वर्ग के नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ी है, बल्कि हर देशवासी के मन में नए उत्साह नई स्फूर्ति का संचार हुआ है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्री अरूण जेटली व वित्त राज्य मंत्री श्री जयन्त सिन्हा जी को हार्दिक बधाई देता हूं।

मेरा पूरा विश्वास है कि सुशासन गरीबी उन्मूलन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, रोजगार सृजन और कृषि क्षेत्र में उन्नत नया अध्याय लिखने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'सबका साथ सबका विकास' का जो आवाहन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस बजट से भारत के चहुमुखी विकास को चार चांद लगेंगे। बजट में ग्रामीण भारत की चिन्ताओं और समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है, ऐसा इतिहास में पहली बार है जब किसी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र व किसानों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया और एक तय सीमा समय अवधि में किसानों की आय को न सिर्फ बढ़ाने बल्कि उसे दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वर्तमान बजट ग्रामीण भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और यह सही भी है क्योंकि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के लिए यह जरूरी है कि हम शहरी भारत व ग्रामीण भारत के बीच की दूरियों को निरन्तर कम करें। इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, गांवों में रोजगार का एक बड़ा जरिया बनकर उभरे मनरेगा कार्यक्रम के लिए भी सरकार ने अच्छा-खासा धन उपलब्ध कराया है और इस योजना को ग्रामीण ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा सिंचाई योजना पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है लगातार गिर रहे भूमिगत जल के स्तर को देखते हुए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ असिंचित खेतों को पानी मिल सकेगा बल्कि जल का बेहतर प्रबंधन भी किया जा सकेगा जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे।

वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट में तमाम छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रख गया है जो दीर्घकालिक दृष्टि से बेहद अहम है। ऐसी एक योजना सभी घरों में एलपीजी उपलब्ध कराने की है इससे

---

* Speech was laid on the Table.

पर्यावरण को तो फायदा होगा ही साथ ही गरीब महिलाओं को ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करने से होने वाले तमाम रोगों से भी निजात मिलेगी। इसी तरह देश के 18,500 गांवों में एक मई 2018 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो स्वागत योग्य है।

इसी तरह रोजगार सृजन की गति को तेज करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पर बल दिया गया है जो एक सही कदम है इस समय सरकार की प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है और इस कारण बजट पर युवाओं का बहुत ध्यान रखा गया है। इस दिशा में केन्द्र सरकार ने निजी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नव उद्यमियों को तमाम वित्तीय सुविधाएं के साथ कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है उम्मीद है कि सरकार इस पहल से देश में रोजगार सृजन में तेजी आएगी और युवाओं की अपेक्षाएं पूरी होगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैण्ड अप इंडिया योजना बनाई गया है।

सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से देश भर में 1550 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान कर इस योजना से 2.5 लाख उद्यमियों का लाभ मिलेगा। इसके लिए जहां अनुसूचित वर्ग के कल्याण के तहत 388833 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सरकार ने प्रस्तावित बजट में गत वर्ष 6580 करोड़ रुपए की तुलना में इस साल 7350 करोड़ रुपए दिए हैं इसमें अनुसूचित जाति स्कॉलरशिप के लिए 2791 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए 1200 करोड़ रुपए वन बंधुओं के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस बजटीय आवंटन से यह तबका किसी के यहां नौकरी करने के बजाए खुद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल हो सकेगा। यह एक बहुत उपयोगी कोशिश इस बजट में नजर आ रही है।

जिंदगी की बदलती चाल ढाल को देखते हुए आज हमें लगभग सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में कुछ बदलाव की गुंजाइश दिख रही है जो समस्त दिशाओं की ओर अनुकूलता का ही परिणाम है यही कारण है कि हम आज शहर सहित तमाम क्षेत्रों में डीजिटलाइजेशन का भी पड़ाव आता है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई महत्व पूर्ण कदम भी बढ़ाए गए है आज हम ई-बैंकिंग ई-टिकटिंग, ई कामर्स जैसी तमाम डीजिटल सेवा का लाभ ले रहे हैं। जहां अब गांव-गांव में इंटरनेट की पहुंच को आसान बनाने के लिए आप्टिकल फाइवर केबल बिछाई जा रही है जो कहीं न कहीं मौजूदा सरकार की डीजिटल सोच और उस ओर बढ़ाए गए आवश्यक कदमों के परिणाम हैं। इस क्रान्तिकारी बजट में ई-हास्पिटल भी एक क्रान्तिकारी कदम है। जिससे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के परिणाम तथा प्रभाव की गति तेज करने के लिए भारत में स्वास्थ्य संचार प्रयासों को मजबूत करने के लिए डायलिसिस के एक देश व्यापी

योजना शुरू की गई है। आज देश में किडनी संबंधी विकारों के बढ़ने से ऐसे लोगों की तादाद बढने लगी हैं जिनके लिए डायलिसिस कराना एक मजबूरी बन जाता है। इस बजट में सरकार ने देश के हर परिवार को एक लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देने का फैसला किया है परिवार में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो यह राशि 1.30 लाख रुपए होगी। वित्त मंत्री जी के इस कदम से बहुत जरूरतमंदो को अपना इलाज कराने में मदद मिलेगी, इस मद में सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा है। जिससे देश में गरीबों के लिए सस्ती जैनरिक दवाइयां मुहैया कराने के लिए 2016-17 में तीन हजार जन औषधी केन्द्र खेलने व संक्रामक असंक्रामक रोगों, एड्स, टीवी, अंधता निवारण परिवार नियोजन और अन्य मदों के लिए भी पैसे का इंतजाम इस बजट में किया गया है। हेल्थ बजट गत वर्षों से कहीं बेहतर है, मुझे खुशी है कि सरकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से मरीजों का ख्याल रखा गया है। इस बजट में डायरेक्ट रूप से डायलिसिस फ्री कर दिया गया है। राष्ट्रीय डायलिसिस का फायदा देश भर के 2.5 लाख लोगों को होगा।

वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में हाइवे और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करके देश की इकोनॉमी की रफ्तार देने की कोशिश की है, रोड ट्रान्सपोर्ट सेक्टर के लिए मंत्री जी ने खुले दिल से खजाने के दरवाजे खोले हैं1 दरअसल रोड हाइवे बढ़ाने से कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ही रोजगार के मौके पैदा होंगे और साथ ही साथ इकोनॉमी पर इसका पोजिटिव असर पड़ेगा। सरकार ने बंद पड़े हवाई अड्डे को दोबारा चालू करने के लिए भी अर्थ का प्रावधान किया है। रोड ट्रान्पोर्ट सेक्टर में अटके पड़े 70 में से 65 फीसदी प्रोजेक्ट ट्रैक पर लौट आए हैं। इस बजट में सड़क परिवहन मंत्रालय को 45 हजार 500 करोड़ रुपए मिले हैं इसका मुख्य कारण हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी की कर्त्तव्यनिष्ठ कार्यशैली का जीता जागता उदाहरण है। इसके लिए मैं गडकरी जी को भी धन्यवाद देता हूं।

2016 के बजट में प्रधानमंत्री जी का आर्थिक दृष्टिकोण अब और ज्यादा स्पष्ट होने लगा है। दरअसल यह भारत की तस्वीर बदलने के लिए युवा भारत को सशक्त करने वाला बजट है। यह बजट इस मान्यता को आगे बढ़ाता है कि युवा और उद्यमी अर्थव्यवस्था और देश की तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं इससे निवेश और नौकरियों के लिए केवल कुछ बड़े कारपोरेट समूहों पर निर्भरता के परम्परागत आर्थिक मॉडल का विकल्प भी तैयार होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले 3 साल में एक करोड़ से अधिक युवाओं की कार्यकशुलता में सुधार के मद में निवेश पर मुख्य जोर है। इसके जरिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों की पूंजी तक पहुंच के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर की जा सके। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत 76 लाख युवा पहले से ही प्रशिक्षित हो चुके हैं और इस बजट प्रस्तावों के अनुसार 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थानों

की स्थापना से इस तादाद में और वृद्धि होगी। जो कम्पनियां बेरोजगारों को 25000 रुपए तक के वेतन पर काम देगी उन्हें टैक्स में छूट देने के निर्णय से भी देश में रोजगार के सृजन बढ़ने में मदद मिलेगी। यह बजट गांव गरीब किसानों और नौजवानों के लिए है इससे उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। खास बात यह है कि इस बार बजट में 0.5 फीसदी कृषि कल्याण शेष और सरकार के खजाने में जमा होने वाले काला धन पर 7.5 प्रतिशत शेष के प्रावधान से कृषि योजनाओं को अधिक गति मिलेगी। आजादी के बाद पहली बार आम बजट में 36 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई के लिए 5717 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जिससे पूरे देश में 5 लाख तालाब व कुओं का निर्माण किया जाएगा। मिट्टी की सुधारने के लिए 362 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया करा दिए जाने का प्रावधान है तथा जैविक खेती के लिए बजट में 297 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 19 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सफल बनाने के लिए उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मद में 1700 करोड़ रुपए दिए गए हैं, दलहन उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन कर इस बजट से सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया को सफल बनाया गया है।

इस वर्ष के बजट में किसानों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह बजट ग्रामीण भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और सही भी है क्योंकि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। गांव की सड़कें अब हिचकोले नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का क्रियान्वयन जिस तरह से अब हो रहा है वैसा पहले नहीं था। 27 हजार करोड़ इस योजना के तहत खर्च किया जाना है व साथ ही 65 हजार नई बस्तियों को सड़क से जोड़ना गांवों के लिए एक सुनहरा उपहार है। बजट में किसानों, गरीबों और वंचित लोगों का ध्यान रखा गया है। मैं प्रधानमंत्री जी और अपने दोनों वित्त मंत्री को उनकी दूरदर्शिता के लिए बधाई देता हूं। इस बजट में सामाजिक क्षेत्र कौशल विकास व रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। यह बजट आम जनता की अपेक्षाएं पूरी करेगा।

जय जवान जय किसान जय विज्ञान

आओ मिलकर बनाएं मेरा भारत महान।

*श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर)**: मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा पेश दूरगामी प्रभावशाली 2016-17 आम बजट के लिए उन्हें बधाई देता हूं साथ ही वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी को भी बधाई देता हूं।

मेरा मानना है कि "जलबिन्दुनिपोतन क्रमशः पूर्यते घटः। स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च।।" जिस प्रकार पानी की एक-एक बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार समय के साथ ज्ञान में भी वृद्धि होती है और आज मैं बड़े हर्ष से यह कहना चाहता हूं कि बीते वर्ष के साथ हमारे वित्त मंत्री जी ने जो पूर्व सरकार द्वारा विफल नीतियों का अध्ययन करते हुए विकासशील नीति के तहत इस आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण के लिए 35984 करोड़ रुपयों का आवंटन, 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" को मिशन मोड़ में लागू करने, मनरेगा के तहत वर्षापोषित क्षेत्रों में 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं तथा जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्टगड्डों का निर्माण, जैविक खेती को बढ़ावा, थोक बाजारों के लिए सांझे ई-बाजार की व्यवस्था, वर्ष 2019 तक शेष 65,000 पात्र बस्तियों का सड़कों से जुड़ाव, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5,500 करोड़ का आवंटन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन के तहत 300 ग्रामीण शहरी कलस्टर का विकास, 1 मई 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण, साथ ही इसमें स्वास्थ्य देखभाल सहित सामाजिक क्षेत्र को भी प्राथमिकता देते हुए- बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान, नई स्वास्थ्य रक्षा स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं वरिष्ठ नागरिकों को 30000 रुपए तक अतिरिक्त टॉप-अप पैकेज, 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री जी की जन-औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर का प्रावधान, पीपीपी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम, उद्योग धंधों की भागीदारी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब की स्थापना, शिक्षा के क्षेत्र में 62 नए नवोदय विद्यालय, 10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं को विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थाओं में विकसित करने, साथ ही कौशल विकास के लिए 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उद्योग और अकादमी की भागीदारी से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना, साथ ही 2016-17 में लगभग 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी, सड़क परिवहन क्षेत्र को खोलने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन, राज्य सरकारों की भागीदारी से उपर्युक्त और कम प्रयुक्त विमान पतनों के पुनरूत्थान हेतु कार्रवाई योजना, गहरे पानी, अत्यंत गहरे पानी और उच्च दाब उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उचित विपणन स्वतंत्रता, बीमा और

---

* Speech was laid on the Table.

पेंशन आदि पुनर्निर्माण कंपनी, स्टॉक एक्सजेंज के क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार वित्तीय क्षेत्र में सुधार, छोटे करदाताओं को राहत, रोजगार और विकास को बढ़ावा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा, पेंशन प्राप्त समाज की ओर बढ़ाने, सस्ते आवास निर्माण को बढ़ाने, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने, कराधान में निधित्ता पैदा करने, करों का सरलीकरण और यौक्तिकरण करने, जवाबदेही निहित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का प्रावधान रखा गया है। मैं इस बजट की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट काफी सकारात्मक एवं संतुलित बजट है। इसमें विकास और वित्तीय समझदारी का संतुलन है। सबसे बड़ी बात कि वित्त मंत्री वित्तीय घाटे के संदर्भ में अपने वायदे पर दृढ़ रहे। पिछले बजट में वित्तीय घाटा 3.9 प्रतिशत था और यह वायदा था कि अगले बजट में यह घाटा 3.5 फीसदी ही रहेगा। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों के धन आवंटन में कोई कटौती भी नहीं की है। उन्होंने आधारभूत संरचनाओं और कृषि पर होने वाले निवेश को काफी बढ़ावा दिया है। पिछले दो साल मानसून काफी कमजोर रहा इसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तनाव इस हद तक बढ़ा कि कई जगह किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हुए हैं। खराब उपज के चलते ग्रामीण बाजारों में मांग काफी घटी है। इसका बुरा असर उन उद्योगों पर भी पड़ा है जो ग्रामीण क्षेत्र की मांग को पूरा करते हैं। मसलन ट्रैक्टर और दुपहिया वाहनों का बाजार। वित्त मंत्री ग्रामीण बाजार की इस हालत को बड़े स्तर पर बदलना चाहते हैं इसलिए उन्होंने घोषणा की है कि अगले पांच साल में किसानों की आय को दुगुना कर दिया जाएगा। खासकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर होने वाले खर्च को विशेष महत्व दिया गया है। फसल बीमा जैसी योजनाओं की घोषणा तो सरकार पहले ही कर चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के प्रावधान को काफी बढ़ाया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है।

बजट में दूसरी प्राथमिकता शिक्षा और कौशल विकास को दी गई है। शिक्षा के अधिकार ने शिक्षा को सब लोगों तक जरूर पहुंचाया लेकिन इसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। इसकी गुणवत्ता पर सरकार द्वारा बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। कौशल विकास के लिए दस विश्वस्तरीय संस्थान विकसित करने का प्रावधान भी है जिसके तहत एक करोड़ लोगों को नए कौशल से लैस किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है। बजट में शिक्षा के साथ ही पूरे सामाजिक क्षेत्र को भी उतनी ही प्राथमिकता मिली है खास कर जन स्वास्थ्य सेवाओं को, जिसके प्रावधान को काफी बढ़ाया गया है।

केन्द्रीय बजट में सड़क, नागरिक उड्डयन और बंदरगाहों के विकास के लिए काफी प्रावधान किया गया है। भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कई लम्बित सड़क परियोजनाओं को फिर से शुरू कराया है। देश में 160 ऐसी हवाई पट्टियां हैं जहां से नियमित उड़ान नहीं होती। वित्त मंत्री जी ने इन्हें वायु यातायात के क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करने की बात कही है।

पिछले कुछ समय से बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति काफी चिन्ताजनक बनी हुई है। इसके लिए 25000 करोड़ रुपए का एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन फंड बनाया गया है। साथ ही बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए इन्द्रधनुष योजना भी है। इसके अलावा बैंकों के डूबे कर्जों को वसूलने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की भी घोषणा की गई है। रसोई गैस को आधार से जोड़कर सीधे उपभोक्ताओं के खाते में पैसा पहुंचाने की योजना काफी कामयाब रही है, अब इसे उर्वरक तक बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बजट का एक महत्वपूर्ण पक्ष कारोबार को आसान बनाने की कोशिशें हैं। इसके तहत एक डिस्प्यूट रिड्रेसेल सेल बनाया गया है जो एक सीमित समय में वाद का निपटारा करेगा। सरकार ने काले धन को सामने लोने के लिए बजट में कई प्रावधानों की घोषणा की है। यह काफी कुछ 1997 में बनाई गई आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना यानि वीडीआईएस की तरह ही है।

सच कहा जाए तो यह गाँव, गरीब और किसानों की दशा और दिशा सुधारने का बजट है। इस बजट से गांव की तस्वीरें बदलने के साथ-साथ् सुशासन की नई बयार भी बहेंगी। आयकर छूट में सीमा भले नहीं बढ़ी हो लेकिन 5 लाख रुपए तक आमदनी वाले लोगों को 3000 तक कर में छूट देकर राहत देने का प्रयास जरूर किया गया है। ईपीएफ और पेंशन योजना में सर्विस टैक्स में छूट देना भी आम लोगों के लिए ठीक कदम माना जा सकता है।

मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए इसे 2016-17 के बजट में प्रमुखता दी जाए। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर, जो मेरा संसदीय क्षेत्र "लघु (मिनी) काशी " के रूप में सुप्रसिद्ध है, प्राचीन संस्कृति एवं प्रमुख आध्यात्मिक केन्द्र रहा है। वहां भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केन्द्र" तथा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित "काशी हिन्दू विश्वविद्यालय " की शाखा के रूप् में स्थापित किया जाए। साथ ही बक्सर स्थित पुराना सदर अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत एक "केन्द्रीय अस्पताल-सह-ट्रॉमा सेन्टर" जो अत्याधुनिक संयंत्रों के साथ सुसज्जित हो, को स्थापित किया जाए, जिससे दुर्घटनाग्रस्त एवं हजारों गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों की प्राणरक्षा संभव हो पाएगी। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि एवं भगवान श्रीराम की प्रशिक्षण भूमि, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ताड़िका का वध किया था। इसे तीर्थाटन सर्किट के रूप् में अयोध्या से "लघु (मिनी) काशी " के रूप में सुविख्यादित बक्सर होते हुए माँ

जानकी की जन्मभूमि सीतामढी-जनकपुर धाम तक "रामायण सकिर्ट " के रूप में घोषित कर विकसित किया जाए। जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा यहां शुभागमन पर अपने भाषण में बक्सर को मिनी काशी के रूप में सम्बोधित करते हुए काशी के साथ-साथ बक्सर का भी विकास करने पर जोर दिया था। साथ ही बक्सर में "राम दरबार " सहित विश्वामित्र की भव्य ऊंची कद की मूर्ति, अहिरौली, बक्सर में माता अहिल्या (जो शापित होकर शिला बन गई थी, पुनः वहां भगवान राम के चरणों की धूली के स्पर्श मात्र से उनका उद्धार हुआ एवं वो अवतरित हुई) की शिला सहित भव्य मूर्ति स्थापित की जाए। साथ ही यह बामन भगवान की भी अवतरित भूमि है। इसके अतरिक्त भगवान राम द्वारा इस क्षेत्र में प्रारम्भ की गई "पंचकोशी यात्रा " के सभी स्थानों को तीथ्र केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे प्रतिवर्ष आने वाले लाखों यात्री इससे लाभान्वित होंगे।

बक्सर स्थित रामरेखा गंगा तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित प्राचीन रामेश्वरनाथ मंदिर एवं ब्रह्मपुर में ब्रहमेश्वरनाथ मंदिर तथा गौरीशंकर मंदिर को आध्यात्मिक एवं तीर्थाटन केन्द्र के रूप में विकसित करते हुए इसे (बक्सर को) "रेल आस्था सर्किट " से जोड़कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रतिस्थापित किया जाए। बक्सर जिला अंतर्गत नया भोजपुर स्थित राजा भोज के नवरत्न किले का भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण एवं इसकी खुदाई कर, इस धरोहर का संरक्षण किया जाए, जिससे लाखों पर्यटकों के लिए यह दर्शनीय केन्द्र बन सके। हमारा संसदीय क्षेत्र बक्सर सहित शाहाबाद "धान का कटोरा " कहलाने वाले क्षेत्र में एफसीआई द्वारा सभी जिलों में कम से कम दो-दो बड़ा केन्द्रीय अन्न भंडारण का निर्माण कर उक्त क्षेत्र में कृषि आधारित नए उद्योग क्षेत्र स्थापित किए जाए। साथ ही बक्सर में कृषि विभाग द्वारा "चावल शोध उपकेन्द्र " की भी स्थापना की जाए। राज्य के पुराने सभी बंद पड़े उद्योग धंधों यथा भागलपुर, सीवान एवं पंडौल कॉपरेटिव स्पीनिंग मिलों, बहादुरपुर स्पन सिल्क मिल, सबौर (भागलपुर) का डी.पी.आर. तैयार कर यथाशीघ्र चालू करने हेतु विशेष सहायता राशि प्रदान की जाए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भागलपुर, पूर्णियां, कोसी प्रमंडल सहित बक्सर, रोहतास, कैमूर,भोजपुर के नहरी क्षेत्रों के किनारे खाली जमीन पर मलबरी/तसर शहतूत का पौधा व्यापक पैमाने पर लगाया जाए, जिससे बेरोजगारी भी दूर होगी एवं किसानों को उसका अधिकाधिक लाभ मिल पाएगा।

सुल्तानगंज (अजगैवीनाथ धाम, भागलपुर) से बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर, झारखंड) बांसुकीनाथ धाम (झारखंड), मधुसूदन-मन्दार (बांका, बिहार) होते हुए बाबा बृद्धेश्वरनाथ धाम (भागलपुर) तक विश्वप्रसिद्ध श्रावणी कांवरिया मेला को "कांवरिया सर्किट " के रूप में घोषित कर विकसित किया जाए। प्राचीन विश्वविख्यात अंग जनपद, कहलगांव (भागलपुर) स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों यहां केन्द्रीय

विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। रेशमी शहर भागलपुर में केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बैंगलोर की इकाई अत्याधुनिक संयंत्रों के साथ स्थापित किया जाए, जिससे यहां के सिल्क निर्यातकों को सिल्क वस्त्र प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने का अवसर प्रदान हो सके। साथ ही भागलपुर के रेशम संस्थान में "राष्ट्रीय बुनकर कौशल विकास संस्थान " की भी स्थापना की जाए। बिहार के कोसी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का "डिजास्टर मैनेजमेंट संस्थान " स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त भागलपुर में "कतरनी धान " की खेती को प्रोत्साहित करते हुए "कतरनी चूड़ा " का देश-विदेश में व्यापार को बढ़ावा देने भागलपुर के जरदालू आम, मुजफ्फरपुर की लीची, नौगछिया एवं हाजीपुर में केले की खेती को प्रोत्साहित करते हुए बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग के साथ-साथ "फ्रूटपार्क " की स्थापना की जाए। चम्पानगर, भागलपुर में प्राचीन बिहुला-बाला पर आधारित "मजूषा कला पेंटिंग " को (मुधबनी पेंटिंग के तर्ज पर) भागलपुर स्टेशन सहित वहां से खुलने वाली सभी गाड़ियों में पेंटिंग प्रदर्शित की जाए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इस कला को सम्मान एवं प्रसिद्धि मिल सके।

बुद्ध-जैन सर्किट के रूप में सारनाथ काशी से लघु काशी के रूप में विख्यादित बक्सर, बोध गया नालन्दा होते हुए मंदार पर्वत जैन शिखर, जैन तीर्थांकर वासुपूज्य महाराज की जन्म एवं अवसान भूमि चम्पापुरी, भागलपुर, विक्रमशिला (कहलगांव) केसरिया, चम्पारण आदि जगहों से होते हुए पार्श्वनाथ पर्वत (गिरिडीह, झारखण्ड) तक बुद्ध-जैन सर्किट घोषित कर तीर्थाटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाय। मक्का एवं मखाना की खेती को प्रोत्साहित करते हुए कोसी, दरभंगा, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर आदि क्षेत्र में इसे बढ़ावा देने हेतु कृषि आधारित उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स बिहार में खोलने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विगत वर्ष के बजट में घोषित की गयी है। इसके लिए बिहार में मेरे स्वास्थ्यमंत्रित्वकाल में तत्कालीन केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव भागलपुर स्थित जवाहर मेडिकल कालेज की खाली पड़ी जमीन पर (जो बिहार के पूर्वी क्षेत्र का अंतिम छोर झारखण्ड, पश्चिम बंगाल से सटी हुई है तथा वर्षों से उपेक्षित अति पिछड़ा क्षेत्र रहा है) खोलना सर्वश्रेष्ठ होगा।

विपक्ष के हमारे साथी द्वारा इस बजट का विरोध एवं सरकार का उपहास करने पर मुझे कहना है कि

"मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि
मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है।"

हमारी अपील है कि विपक्ष के लोग सरकार के इस बजट का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा "सबका साथ सबका विकास " को अमलीजामा पहनाने का सार्थक सहयोग करें,

जिससे आजाद भारत का सपना साकार हो सके, जो भारत के स्वतंत्रता-सेनानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

देश को आजादी के नए अफसानों की जरूरत है,
गांधी, सुभाष, भगत, आजाद, मंगल पांडेय, खुदीराम बोस जैसे
दीवानों की जरूरत है, भारत को फिर देशभक्त परवानों की जरूरत है।"
जय भारत-जय हिन्द
"वन्दे मातरम"

HON. SPEAKER : Yes, Mr. Minister.

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष जी, सदन के बहुत सारे सदस्यों ने बजट की चर्चा में भाग लिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं एक प्रारंभिक टिप्पणी करना चाहूंगा। मैंने बजट की बहुत चर्चाएँ देखी हैं, लेकिन पिछले तीन दिनों में जितने सांसद बोले, लगभग सब लोग बहुत ही तैयारी के साथ बोले। इस बहस का एक और महत्त्व भी था कि इस पर जितनी महिला सदस्य बोलीं, उनका स्तर बहुत ही अच्छा था। It was exceptionally good.

बहस का आरंभ मेरे मित्र शशि थरूर ने किया था। स्वाभाविक है कि वह हमेशा अच्छा बोलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें 40-45 वर्षों से जानता हूँ, जब से हम लोग विद्यार्थी थे। उन्होंने सरकार की आलोचना भी की, बजट की आलोचना भी की, लेकिन उस आलोचना में अर्थ-शास्त्र कम था और कविता ज्यादा थी। अर्थ-शास्त्र की दृष्टि से जो तर्क था कि टैक्स लगाना अपने आप में गलत है, इसे सरकार को कम कर देना चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपये के बजट में यदि 20 हजार करोड़ रुपये के करीब टैक्स लगता है, तो यह एक फीसदी भी नहीं होता। जो अर्थ-शास्त्र थरूर साहब का था कि टैक्स मत लगाइए, खर्चे को बढ़ा दीजिए, पर वित्तीय घाटे को मेनटेन करके रखिए। So there should be no tax increase but expenditure must increase. Now this *Shashinomics* is something which I found myself unable to understand how without levying tax, you can spend more.

जिस परिस्थिति में यह बजट दिया गया है, उसकी तरफ हम लोग एक बार देख लें। शायद इतनी गंभीर आर्थिक परिस्थिति पूरे विश्व की पिछले कई वर्षों में नहीं दिखी। यह चिन्ता की परिस्थिति है, चुनौती की परिस्थिति है और लगभग यह एक संकट की दिशा में जा रही है। विश्व की अर्थ-व्यवस्थाएँ एक-दूसरे के साथ इतनी जुड़ गयी हैं कि विश्व के किसी कोने में कुछ होता है, तो स्वाभाविक है कि उसका असर पूरी दुनिया में जाएगा। अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि चाइना की अर्थ-व्यवस्था में मंदी आयी है। चाइना वह देश है, जो लगभग 30 वर्षों तक 9 और 10 फीसदी की औसत के साथ बढ़ा है। It was unprecedented to grow for 30 years at an average of nine per cent plus. Fifty per cent of global growth came only from China. उसके बाद अचानक चाइना का ग्रोथ-रेट कम हो जाए, तो स्वाभाविक है कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। Global currencies are impacted. Global trade is impacted. In fact, global trade has shrunk. I mentioned in my Budget Speech that when the UPA was in power global trade was increasing by seven per cent a year. Today, it is shrinking by

four per cent. यह टिप्पणी करना बड़ा सरल है कि एक्सपोर्ट कम हो गये हैं। स्वाभाविक है, यह कम होंगे। Export will come down because trade is shrinking and it is shrinking because of two reasons. जो लोग हमसे खरीददारी करते थे, उनकी जेब में पैसा कम है। दूसरा कारण यह है कि जब तेल की कीमत कम हो गयी, कमोडिटीज़ की कीमत कम हो गयी, अगर एक्सपोर्ट की मात्रा उतनी ही रही, लेकिन कीमत कम हो गयी, तो स्वाभाविक है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। Shrinkage can be in volumes and it can also be in value. Eighteen per cent of India's export is refined oil. Crude oil gets treated and then it is sent out and it goes back. जब आयल की कीमत कम होगी तो उसका इम्पोर्ट पर भी असर पड़ता है, एक्सपोर्ट पर असर पड़ता है, इसलिए हम केवल उस आंकड़े को न देखें, बल्कि उस परिस्थिति को देखें। जो दुनिया के विकसित देश थे, यूरोप बहुत धीमी प्रगति कर रहा है, एक या डेढ़ फीसदी से ज्यादा नहीं है। अमेरिका में ग्रोथ होती है, लेकिन एक तिमाही में होती है, दूसरी तिमाही में रुक जाती है, अभी पैची है। जिनके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा थी, जिनको ब्रिक्स देश कहते हैं, उनमें ब्राजील की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। वहां की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। रशिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था थोड़ा बढ़ी है, लेकिन कमजोर है, चाइना नीचे आ रहा है। इस परिस्थिति में हम अगर देखें जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसका भी असर पड़ता है। सउदी अरेबिया और ईरान के बीच क्या स्थिति बनती है, तेल की पैदावार को लेकर क्या नीति अन्य तेल उत्पादक देशों में बनती है, उसका असर होगा।

आने वाले साल में, जिस साल में हम जा रहे हैं, जिस प्रकार की चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हो रही है, उसका परिणाम क्या होगा और वह बहस एवं नीति को किस दिशा में ले जाएगा, वह भी अपने आप में विश्व की आर्थिक परिस्थिति के ऊपर असर डालने वाला है। इस परिस्थिति में आईएमएफ, जो पूरे यह देखता है कि पूरे विश्व में हर देश की और विश्व की आर्थिक परिस्थिति कैसे बढ़ रही है, वह हर तिमाही बाद विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे नीचे आती जा रही है, global growth is declining and they repeatedly come out with figures. इस परिस्थिति में हम कहां हैं? Where do we stand? The challenge really is, how do we build firewalls around ourselves that we are least impacted by the global situation? China impacts us only partly. We are not a part of China's production chain or their distribution chain. But then China does impact us because the volatility that it creates impacts our markets and it impacts our currency. Oil fortunately is an advantage for us. The oil prices coming

down actually have amounted to transfer of wealth from producing countries to the consuming countries. Therefore, oil is an advantage for India. We are net buyers and it is therefore helping us. But then globally the export markets have shrunk. Job market all over the world is shrinking. Under these circumstances we did about 7.2, 7.3 per cent growth last year and this year it is expected that it will be about 7.5 to 7.6 per cent. That was the figure which was indicated by the experts. Despite this our basic economic parameters, our macro data seems to be reasonably good. Current Account Deficit would be below 1.5 per cent.

Some comments were made on inflation. I have the data and I need not go into the details. We inherited an economy near double digit inflation. When we came into power 22 months ago it was double digit inflation. Over that time it has gradually been under control, never crossed 6 per cent. In fact, for the 15th month or 16th month in a row the Wholesale Price Index is in the negative. Even today the data which has come out shows that the Wholesale Price Index is in the negative and the Consumer Price Index has come down again today. Foreign Exchange reserves are fortunately good. It is now accepted that last year and in this year and hopefully next year India has, in this atmosphere of global slow down, the distinction of being the fastest growing major economy in the world. But then we have our own areas of worry. हमारा जो सात-साढ़े सात फीसदी का विकास हो रहा है, यह किस ताकत पर हो रहा है? इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इंजन कौन से हैं? निजी क्षेत्र का जो निवेश होता है, वह आज भी कमजोर है और कमजोर इसलिए है, मैं इस बारे में कोई राजनैतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने अपने आपको काफी ओवर स्ट्रेच कर लिया था। उनको बैंकों से खूब पैसा मिला था। आज उनमें से कई उसको लौटा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे एक मूल कारण यह भी है कि जिन सेक्टर्स में काम करने के लिए उन्होंने पैसा लिया था, उन सेक्टर्स में ग्लोबल स्लो डाउन का या डोमेस्टिक स्लो डाउन का प्रभाव है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि दो वर्ष लगातार बारिश 13 फीसदी तक कम हुई है। कृषि पैदावार की चिंता नहीं है, क्योंकि यह आज भी सरप्लस है। लेकिन गांव में जो खरीदारी करने की क्षमता है, वह कमजोर हो जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व बाजार में जो सामान भेजना है, क्योंकि विश्व की

अर्थव्यवस्था में मंदी है तो उसमें भी कमी आयी है। इस परिस्थिति में पिछले वर्ष हम लोगों ने यह तय किया था कि जो सरकारी खर्च है जिसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं public expenditure will be the key driver of India's economic growth. पिछले साल इनफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था ने कुछ तेजी पकड़ी। दूसरा, देश में विदेशी निवेश खूब आया, उसकी मात्रा बढ़ी तो एफडीआई आने से अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से लाभ हुआ है। निवेश नहीं होगा तो आर्थिक गतिविधि नहीं होगी और रोजगार नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में डिमांड बढ़ी है, इसलिए वे चीजें जिनका शहरी क्षेत्रों में ज्यादा प्रयोग होता है, उनकी बिक्री और व्यवसाय बढ़ा है। इसके साथ ही साथ इनकी बढ़ोतरी से एक अच्छे स्तर की अर्थव्यस्था हम लोग बढ़ा पाए हैं।

लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि इस देश की जो क्षमता है, आज इस मंदी की दौर में बाकी दुनिया की तरफ हम देखें if we compare ourselves to the rest of the world, we are doing well. If we compare ourselves with our own standards, we can probably do better and in a more helpful environment. When I say helpful environment, I mean both globally a helpful environment and domestically, at least, absence of an obstructive environment. Therefore, what was the philosophy behind the Budget? Obviously, the philosophy was जिन क्षेत्रों में इस मंदी के दौर में कमजोरी दिखाई दे रही है, वहां अधिक से अधिक सरकारी संसाधन डाले जाएं। इसलिए इस बजट के बारे में कोई कहे कि ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से है, किसान की दृष्टि से है, it is a realistic budget. पहला कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि में एक अपने आप में कमजोरी थी, क्योंकि दो वर्ष तक सही से बारिश नहीं हुई। गांव की खरीदारी करने की क्षमता कम हुई। इसलिए अधिक से अधिक साधन गांव के अंदर डालने की आज आर्थिक आवश्यकता भी है। कोई अर्थशास्त्री आपको यह नहीं कह सकता कि वहां कम पैसा डालिए। This was economic logic, this was social logic and this is also the political logic. तीनों तर्क यही कहते हैं कि वहां डालिए। अब ग्रामीण सड़के हैं, पहले आठ-नौ हजार करोड़ रुपये खर्च होता था, यह तर्क देना कि राज्यों को हिस्सा देना पड़ रहा है, राज्यों को जो साधन जाता है, वह भी इस देश के लिए ही जाता है, राज्य के लिए ही जाता है और केन्द्र की बजाय राज्य की सरकारें लोगों के ज्यादा नजदीक होती हैं। इसलिए कई योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें केवल केन्द्र देता है। मैं आपको आज आंकड़े दूंगा कि हमने राज्यों की आर्थिक परिस्थिति कैसे खड़ी की है और जो कमजोर राज्य हैं, उनके लिए हम आगे क्या करने वाले हैं? जहां तक राज्यों की परिस्थिति की बात है, ग्रामीण सड़कों के लिए 60 फीसदी केन्द्र देता है और

यह मुख्यमंत्रियों ने तय किया है। उनकी कमेटी की रिकमण्डेशन थी कि 40 फीसदी अब राज्य देंगे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के बाद राज्यों के पास भी साधन अधिक हो गए हैं।

<u>19.00 hours</u>

हम लोगों का जो आठ हजार, नौ हजार करोड़ रुपया साल का जाता था, हमारा हिस्सा लगभग 18 हजार करोड़ हो गया और राज्य का नौ हजार करोड़ हो गया और अब इस वर्ष 27 हजार करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों में जायेगा। यानी कि पहले की तुलना में तीन गुणा ज्यादा जायेगा। हर गांव में बिजली पहुंचे, परंतु यह जो चुनौती है कि 2018 तक पहुंचे, कल श्री पीयूष गोयल ने मुझे बताया कि 18 हजार में से लगभग छः, साढ़े छः हजार गांव हम कवर कर चुके हैं और इसलिए जो टारगेट डेट है, हम उससे आगे तेज गति में चल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : हमने हाउस शायद सात बजे तक बढ़ाया था, इसलिए जब तक बजट का काम पूरा नहीं होता है, आप सबकी सहमति से तब तक के लिए हाउस का समय एक्सटेंड कर लेते हैं।

श्री अरुण जेटली : सिंचाई के संबंध में यह स्वाभाविक है कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं और उद्योग के लिए लगाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उद्योग लगेगा, उद्योग मुनाफे में आएगा, उसमें रोजगार मिलेगा तो पांच-सात या आठ साल उसका प्रभाव आने में लग जाते हैं। जो सिंचाई में पैसा खर्च होता है, उसका परिणाम आपको अगले साल नजर आ जाता है। इसलिए गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का जो पुराना अनुभव आया है कि जहां-जहां सिंचाई में साधन लगे हैं, उसका वहां की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। हम केवल आंकड़ा देखें तो बजट में तीन-चार अलग-अलग हैड्स में एक्सपेंडीचर है। सिंचाई स्टेट लिस्ट में हैं, जिम्मेवारी राज्यों की है और राज्य इस पर जो खर्चेंगे, वह अलग है। केन्द्र ने चार-पांच हैड्स में सिंचाई के लिए अलग-अलग साधन दिये, एक्सट्रा बजटरी रिसोर्सेज लगाये और उसके साथ-साथ नाबार्ड भी उसमें योगदान देगा और विशेष रूप से एक Irrigation Fund is going to be created. Whatever commitments are required by some special States – the Polavaram project, for instance – we are going to make sure that special funds are created so that those areas can get water and the funds go from this expanded resources as far as the irrigation is concerned. … (*Interruptions*) You will get the particulars. Once the Rs. 20,000 crore Fund is created several States will be benefited. I have just given this example because that issue is part of the Centre's commitment. So, I just referred to it. But it applies to all the States.

इसके अलावा इंटरेस्ट-सबवेंशन छः-सात हजार करोड़ रुपये मिलता था। इस बार हमने 15 हजार करोड़ रुपये दिया है। मुझे परसों एक विशेष बैठक में किसी ने एक सुझाव दिया कि जो कानून हमने पास किया है, हम लोग जो ब्याज की भी सहायता करते हैं, वह भी डायरेक्ट किसान के खाते में भेजो, इस तरह के सुझाव अब आने शुरू हो गये हैं। इस बार जो इंटरेस्ट-सबवेंशन किसान का होगा, वह सबसे अधिक होगा। मनरेगा का मैंने उदाहरण दिया, सदस्यों ने कहा कि इस बार साढ़े 38 करोड़ रुपये अगर हम खर्च करते हैं तो किसी वर्ष में खर्च हुआ मनरेगा का सबसे अधिक खर्चा होगा।

महोदया, प्रधान मंत्री जी के बयान को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, उन्होंने ठीक बयान दिया। अगर 65 वर्ष बाद भी हमें कानून चाहिए कि किसान की जेब में एक रोजगार डालना है, क्योंकि उसके पास साधन नहीं हैं तो यह हमारी विफलता की निशानी है, यह कहने में क्या गलत है। इसलिए वह विफलता की निशानी होते हुए अगर एक योजना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में उसके माध्यम से हम अधिक साधन पहुंचायेंगे - चाहे सड़क के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, स्वच्छ भारत के माध्यम से, बीमा योजना के माध्यम से, रुरल हाउसिंग के माध्यम से, हर पंचायत को जो साधन जाने वाले हैं, उसके माध्यम से तो एक-एक हैड में हम लोगों की जो योजना बनी है कि अधिक से अधिक साधन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो सबसे कमजोर सैक्टर है, आज वह है और इसलिए उस सैक्टर के अंदर ताकत देने की आवश्यकता है।

आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग स्थिति देखें। हाइवेज एक प्रकार से रूकावट पर आ गए थे, स्टैन्ड स्टिल थे। वाजपेयी जी ने शुरू किए थे, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता था और एक प्रकार से धीरे-धीरे आते-आते दो-तीन-चार किलोमीटर प्रतिदिन की स्थिति पर आ गए। पहले 17 टेन्डर, जो गड़करी जी के मंत्रालय ने निकाले, एक व्यक्ति ने उस टेन्डर का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से संचालन हो रहा था, हर टेन्डर को लेकर, हर कान्ट्रेक्ट को लेकर कान्ट्रेक्टर से झगड़ा है। सारे ठेकेदार जो बनाते हैं, वे एक प्रकार से बैंक करप्ट हो गए। हमारे आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो मित्र यहाँ हैं, वे जानते होंगे कि बहुत सारे लोग बनाने वाले उनके राज्यों से आते थे। यह परिस्थिति हो गई कि कोई बैंक उनको छूने को तैयार नहीं था। यह परिस्थिति हाइवेज की हो गई और इसकी वजह से हाइवेज पैरालाइज हो गए। हमने पिछले साल के बजट में अधिक साधन दिए। इस साल 55 हजार करोड़ रूपए एक, 15 हजार करोड़ रूपए एक, 70 हजार करोड़ रूपए, 27 हजार करोड़ रूपए ग्रामीण सड़क और जब 97 हजार करोड़ रूपए हाइवेज और सड़कों में जाएंगे सरकारी साधनों से तो फिर निजी क्षेत्र भी अपनी रकम लगाता है, क्योंकि यह क्षेत्र घूमने वाला है और हाइवे सेक्टर जो था, वह अपने आपमें दोबारा इस देश का रिवाइव हुआ है। ग्रामीण सड़कों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। एयरपोर्ट्स हैं, हर राज्य में ऐसी एयर स्ट्रिप्स हैं, छोटे शहरों में भी हैं, दूसरे महायुद्ध में

अंग्रेजों ने 160 एयर स्ट्रिप ऐसी बनाई थीं, जो अन्यूज्ड हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के 25 एयरपोर्ट ऐसे हैं, जहाँ एक जहाज नहीं उड़ता। इस बार हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकारों से बात करकर, कोई आरम्भ तो करे, दस-पाँच नए एयरपोर्ट्स में हर साल पैसा लगाएं, एक मॉडल बनाया है, जिसमें 50 से 100 करोड़ रूपए तक वहाँ एक छोटा एयरपोर्ट बनाने के लिए, जहाँ एक-दो फ्लाइट रोज की आ सकें और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब साधन हैं, श्री अशोक गजपति राजू साहब का मंत्रालय इसमें योजना बना रहा है कि उन एयरपोर्ट्स को, एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से कम से कम दस को इस बार ये डेवलप करेंगे। सी पोर्ट्स क्लॉक्ड हैं, उसमें निजी क्षेत्र कुछ सरकारी साधन के माध्यम से अब कोरपोरेटाइज्ड पोर्ट्स आएंगे। इसका हम लोग प्रयास करें।

पावर सेक्टर की यह स्थिति थी कि आज अगर हम बैंक एनपीएज देखते हैं, बहुत से सदस्यों ने उसका जिक्र किया है। बैंक्स की क्या क्षमता है? Banks are supposed to support growth. बैंक पैसा देगा तो उससे उद्योग खड़ा होगा, बैंक पैसा देगा तो किसान खेती कर पाएगा, बैंक पैसा देगा तो उसमें कोई व्यक्ति मुद्रा योजना से खड़ा कर पाएगा। अगर बैंक की ऋण देने की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो बैंक की क्षमता उस विकास को समर्थन करने में, सपोर्ट करने में अपने आपमें समाप्त हो जाएगी। आज बैंक्स की यह स्थिति थी, यह कोई एनपीएज अब नहीं आए, पिछली बार 31 दिसम्बर को संख्या क्यों बढ़ी? एक अखबार ने अभियान चलाया कि बैंक्स ने लोन राइट ऑफ कर दिए हैं। एक रूपया किसी ने राइट ऑफ नहीं किया। एनपीए का अर्थ है कि जब तक अकाउन्ट फंक्शनल है तो बैंक को यह उम्मीद रहती है कि यह व्यक्ति पैसा वापस करेगा। एनपीए जब होता है तो उसको लगता है कि नॉन परफार्मिंग अकाउन्ट है, यह न ब्याज वापस कर पा रहा है, न मूल वापस कर पा रहा है और इसलिए उसका जो कॉलम है, जो श्रेणी है, उसको एनपीए में डाल देते हैं तो the categorisation is changed. इसमें किसी की ऋण माफी नहीं होती है। किसी समाचार पत्र ने इस रीक्लासिफिकेशन, जिसे बैंक की भाषा में प्रोविजनिंग कहते हैं, इस प्रोविजनिंग को ऋण माफी मान लिया। किसी ने पीआईएल डाल दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ऋण माफी कैसे हुई? कोई एक रूपया भी ऋण माफी नहीं हुई है। It is only a re-provisioning from one category you go to another category. अब बैंक की असली परिस्थिति को हम छिपाकर रखें। You indefinitely cannot clean up the room by sweeping the dust below the carpet. कारपेट के नीचे गन्दगी डाल दें तो उसका यह मतलब नहीं कि कमरा साफ हो गया है तो आपको स्पष्ट बताना चाहिए कि ताकत क्या है?

इन एनपीएज के पीछे दो कारण हैं। एक कारण यह हो सकता है कि गलत व्यक्ति को बैंक ने ऋण दे दिया और वह व्यक्ति वापस नहीं कर पाया, उसकी नीयत में खोट था, वह तो फ्रॉड केस है। दूसरा कारण यह रहता है कि बिजनेस फेल्योर है, इकॉनामिक फेल्योर है उस सेक्टर का और मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि हमारे देश की क्या परिस्थिति थी। मैं चाहूंगा कि अन्य दलों, विशेष रूप से कांग्रेस के लोग भी, मैं इसमें राजनीतिक दृष्टि से इसकी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वास्तविक स्थिति समझें। हमारे देश में सबसे अधिक एनपीए हुआ है स्टील में, स्टील में क्यों हुआ? हमारी जो क्षमता स्टील बनाने की है, देश में जितनी स्टील चाहिए, उतनी हमारी क्षमता है। चाइना के पास सरप्लस कैपेसिटी है। चाइना ने जिस कीमत पर स्टील बनता था, उससे आधी-अधूरी कीमत पर, जब वहां मंदी आई, तो अपने उद्योग को जीवित रखने के लिए दुनिया के बाकी देशों में सस्ते दामों पर स्टील बेचना शुरू कर दिया। They flooded the global market with their steel. यह कुछ समय से चल रहा था। इसका असर यह हुआ कि हमारी स्टील बनाने वाली कंपनियां स्टील बनाती थी, उनका स्टील कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि चाइना से सस्ता मिलता था। यह केवल हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ, पूरे यूरोप के साथ हुआ और अमेरिका के साथ हुआ। इसलिए स्टील की कंपनियां, मैं चाहूंगा कि लोग इकॉनामिक सर्वे को पढ़े, एक बहुत अच्छा चैप्टर है उनका इस पर, उन्होंने कहा कि it is a twin balance-sheet problem. ट्विन बैलेंस शीट की दोहरी समस्या यह है कि स्टील मिल्स की अपनी बैलेंस शीट खराब हुई और वह बैंक्स को पैसा नहीं दे पाए और बैंक्स की बैलेंस शीट खराब हो गई। अब इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें किसी ने फ्रॉड किया हो। यह एक इंटरनेशनल इकॉनामिक फैक्टर था, जिसकी वजह से यह हुआ। अब सरकार क्या चुप बैठी रही? इस पर कार्रवाई पिछले तीन-चार साल से होनी चाहिए थी, जब यह स्थिति बिगड़ रही थी। हमने स्टील की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। इसके अलावा इस तरह का स्टील का अटैक हो जाए, उसको रोकने के लिए और ड्यूटीज बढ़ाईं। हम बढ़ाते गए, चीन दाम कम करता गया और यह खेल चलता रहा। फिर हमने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय कर दिया कि इस इंपोर्ट प्राइस के नीचे बाहर से स्टील नहीं आएगा। अब ये तीनों कदम उठाने के बाद आज हमारे मिलों की स्थिति में पिछले कुछ महीनों में सुधार आया है, अगले दो-तीन तिमाहियों में स्टील दोबारा से खड़ा हो सकता है और उसकी एक उम्मीद है।

चीनी मिलें, गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं हो रही थी। दुनिया में चीनी का दाम गिर गया। ब्राजील की चीनी तो 18 रूपए प्रति किलो मिल रही थी। सबसे अधिक पैदावार वे लोग करते हैं। इसलिए हमारे यहां जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो स्टेट एडवाइज प्राइस होता है, वह अधिक था शुगरकेन का, उससे मिलें घाटे

में चली गईं, मिलों ने पैसा देना बंद कर दिया। सरकार ने दो-तीन योजनाएं बनाईं, बैंकों से पैसा दिया ताकि स्पष्ट रूप से सीधा किसान के पास जाए और 21 हजार करोड़ रूपए जो किसानों को देना था, आज वह घटाते-घटाते 18 सौ करोड़ पर आ गया है। अब दुनिया के बाजार में चीनी का दाम थोड़ा सा बढ़ा है, इसके बढ़ने से चीनी मिलों को भी राहत मिली है और इस परिस्थिति में भी इस क्षेत्र में भी सुधार आया है।

तीसरा, हाइवेज का क्षेत्र था। हाइवेज का मैंने जिक्र किया कि एकदम ठप्प पड़े थे, अब दोबारा पिछले साल भर से हाइवेज रिवाइव हुए हैं। इसलिए हाइवे बनाने वाली कंपनियों की बैलेंस शीट सुधरेगी तो उसका बैंक की बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा। इन तीन क्षेत्रों में सुधार आया है।

चौथा, जो सबसे गभीर था, वह था बिजली। कोल माइंस दे दी गईं, बिजली के हमने कांट्रैक्ट्स किए। बीच में कोल माइंस का झगड़ा हुआ, उसका स्पष्ट हल ढूंढा। हमने बिजली की पैदावार बढ़ा दी। पैदावार बढ़ाने के बाद पूरे राज्यों तक बिजली पहुंचा दी, ग्रिड भी बन गए। लेकिन कुछ राज्यों ने यह सोचा और यह हम सबके लिए यह सबक है, कुछ राज्यों ने यह सोचा कि राजनीति यह कहती है कि बिजली कीमत से सस्ते दाम पर मिले। अगर एक दाम पर बिजली मिलती थी, खरीदते थे या उसकी पैदावार की कीमत थी, तो उससे सस्ते दाम पर देनी शुरू कर दी। अब यह घाटा कौन उठाएगा? इस घाटे को उठाने का, बिजली के कानून में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा है कि सरकार अपने बजट में से दे। राज्य सरकारों के पास बजट से धन देने की क्षमता नहीं थी। इसलिए राज्य सरकारों ने बैंको कहा कि उधार देना शुरू कर दो, बिजली कंपनियों ने बैंकों से उधार लेना शुरू कर दिया और यह लगा कि बिजली सस्ती देंगे तो चुनाव जीत जायेंगे। राजस्थान से जो सांसद चुन कर आयें हैं, वे जानते हैं कि वर्ष 2008 में जब सरकार बदली तो बिजली कंपनी का घाटा 15,000 करोड़ रुपये थे, बिजली कंपनी को वह देना था। जब वर्ष 2013 में राजस्थान की सरकार गयी तो वह 70,000 करोड़ रुपये हो चुके थे। उस 70,000 करोड़ रुपये का यह असर हुआ। ऐसे कई राज्य थे, जो बैंक से पैसा लेकर सस्ती बिजली देते थे और बैंक का पैसा कौन लौटायेगा, इसका कोई उत्तर नहीं। इस परिस्थिति में केन्द्र ने कुछ कदम नहीं उठाये। बिजली कंपनियों के जो स्टेट डिसकॉम्स हैं, उनके घाटे बैंकों के ऊपर रिफ्लैक्ट होने शुरू हो गये।

अब राजस्थान मे यह स्पष्ट हो गया कि इतिहास में सबसे अधिक घाटा भी बिजली कंपनी का कर दिया और इतिहास में सबसे कम सीटें भी आयी तो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था। अब नयी सरकार आयी तो उसने कहा कि मैं इसका क्या हल ढूंढू। अभी पावर मिनस्ट्री ने जो 'उदय स्कीम' निकाली है कि सारे के सारे राज्य सरकारें इस घाटे को अपने बजट में लें, तीन चौथाई घाटे को, फिर बैंक्स को बॉन्ड्स दें, बैंक्स उन कारपोरेट बॉन्ड्स को बेचेंगी, ब्याज की वजह से जो बिजली की दर बढ़ती है, उससे वह कम होगी। फिर, फीडर के संबंध में जो इनिशिएटिव्स हैं, उनकी सुविधा दी। आज 15-16 राज्यों ने जो

एमओयू है, उसको साइन कर दिया है। धीरे-धीरे लोगों को भी अभ्यास हो कि जो सुविधा आप लेते हैं, उस सुविधा के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर किसी कमजोर वर्ग को सरकार मदद करना चाहती है तो सरकार अपने बजट में से वह दे। बैंक्स से उधार ले कर पैसा दे दे और बैंक्स का पैसा वापस न करे, यह परिस्थिति चल नहीं सकती है।

मैडम, इसी प्रकार की समस्या टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स और कई ऐसे जो स्टॉल्ड प्रोजैक्ट्स हम कहते हैं, उनको हल कैसे करेंगे। इस देश में एक वास्तविक समस्या है और खड़गे साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी पार्टी में इसकी चर्चा कीजिए। हम लोग राजनीति से ऊपर उठ कर बात करें। कभी आप भी सरकार में थे, यह समस्या आती थी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट में कोई समझौता या सेटलमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए प्रोजैक्ट विलंब हो गया और उसकी कीमत बढ़ गयी। आपने कहा कि दुनिया में कीमत बढ़ गयी है इसलिए हम पैसा ज्यादा देंगे। फिर, डर लगता है कि सीबीआई आ जायेगी, सीएजी भी आ जायेगी और पीआईएल भी दायर हो जायेगी तो इसलिए इस झगड़े को चलने दें। 15-16 लाख करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट्स ठप पड़े हैं, जब आप शासन से बाहर गये, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। हम लोगों ने आर्बिट्रेशन एक्ट बदला है और आपने उसका समर्थन किया है कि साल-छः महीने में फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन से डिसप्यूट को हल करो। हर हाई कोर्ट ने इसका हल ढूंढने के लिए एक कॉमर्शियल डिविजन बनाया है कि एक कॉमर्शियल डिविजन बने, वह उसका हल ढूंढे। उसके बाद मैंने बजट में प्रस्तावना की है कि रेजोल्यूशन ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कानून बने जिसमें एक स्टैचुअरी मेकैनिज्म हो, जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वे राज्य सरकारों के हैं या केन्द्र के हैं, वे ठप न पड़े रहें। वे रोजगार भी देंगे, अर्थव्यवस्था से राज्य को भी लाभ होगा, इसलिए उसका हल हम लोग ढूंढ़े। जहां प्राइस एसक्लेशन होता है, उसका भी एक स्टैचुअरी मेकैनिज्म का मैंने बजट में जिक्र किया है, ताकि हम लोग इन समस्याओं को हल करें और जो इसका हल करने जा रहा है, उसको शक की नजर से देखेंगे कि यह सरकार भ्रष्ट है, बेइमान है, यह राज्य सरकार की है, केन्द्र की है, या कोई अधिकारी है, इसलिए इसका हल ढूंढ रहे हैं। आज कोई कानूनी प्रोटैक्टशन नहीं है, वह उसको मिले। इसलिए अगर इस दिशा में हम लोग जाते हैं तो उसका अर्थव्यस्था को भी अपने-आप में लाभ होगा।

गरीबी की वजह से सामाजिक चिंता इस देश में स्वभाविक है। पहले वर्ष में हमारी प्राथमिकता फाइनैंशियल इंक्लूजन थी कि हर व्यक्ति को बैंक एकाउंट के साथ जोड़ दिया जाये। नए खाते खुलें। उन खातों को ऑपरेशनलाइज़ किया जाए। आज 70-75 प्रतिशत ऑपरेशनलाइज़्ड हैं। उसके बाद हमारी योजना थी कि जो समाज अनइंश्योर्ड है, अनपैंशन्ड है, उस पर हम पिछले साल 12 रुपये और 300 रुपये वाली आकर्षक योजना लाए। अटल पैंशन योजना लाए ताकि 60-65 साल की आयु के बाद लोगों के पास थोड़े

साधन हों। पूरी दुनिया में यह होता है कि जैसे ही अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं, बीमा और पैंशन आप जीवनभर कमाएं और रिटायर होने के बाद आपको सरकारी पैंशन की सुविधा मिल जाए। कभी न कभी समाज को उस दिशा में जाना पड़ेगा। हमने उस इरादे से कुछ घोषणा की थी। उसका कुछ लोगों को एतराज था तो हमने छोड़ दिया। लेकिन नैशनल पैंशन स्कीम में हमने जो रियायत दी है, वह इसी दिशा में है। जो लोग उसमें जाएंगे, उन्हें लाभ होगा। ये निजी लोग हैं, उसमें सरकारी लोग तो हैं, पब्लिक सैक्टर इम्प्लाइज हैं, प्राइवेट सिटिजन्स भी हैं। हम में से भी कोई चाहे, जिस आयु में हम कमाते हैं, हर महीने थोड़ा सा उसमें डाल दें, रिटायरमैंट के बाद मंथली पैंशन मिलती रहेगी। हमारे बाद बच्चों को मिलेगी और टैक्स रिबेट भी अपने आप मिलेगी। इस बार हम और आगे बढ़े। मैंने पहली योजना क्रॉप इंश्योरैंस का जिक्र किया। दूसरी सोशल सैक्टर स्कीम बनाई जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय बना रहा है कि 33 फीसदी लोग, इस देश की एक-तिहाई गरीब जनता को एक लाख रुपये परिवार हरेक के पास कार्ड होगा। वे किसी भी प्राइवेट या पब्लिक अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर वहां कोई सीनियर सिटीजन होगा, उसके लिए 30 हजार रुपये और मिलेंगे। 30 हजार रुपये कहां से आए। पिछले साल बजट के साथ जो कानून पास किया था कि जिन सरकारी योजनाओं, स्कीम्स में लोग पैसे जमा करवाते हैं और बीस-बीस, तीस-तीस साल से वापिस लेने नहीं आए, वह व्यर्थ पड़ा है। उसे टेक-ओवर करके उसके प्रिमियम के माध्यम से बीपीएल के सीनियर सिटिजन्स को 30 हजार रुपये एक्सट्रा मिलेंगे।

हमने 'आधार' कानून पारित किया। लगभग सभी दलों ने उसका समर्थन किया। पहले वर्ष में एलपीजी में डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर से 25 फीसदी का लाभ हुआ है। सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, गरीब आदमी को मिले और कोई नाजायज व्यक्ति उसका लाभ न उठा पाए, यह उसका उद्देश्य था। इसमें गिव इट अप और जो लाभ हुआ है, क्योंकि सब्सिडी टारगैट करनी है, इसलिए गैस कनैक्शन का लाभ गरीब आदमी को मिले। पांच करोड़ परिवारों को तीन वर्ष में, कुछ को इस साल और कुछ को अगले दो सालों में, पहला गैस कनैक्शन, स्टोव सारा सरकार देगी। उसके बाद उसे अभ्यास डालेंगे। उसके एकाउंट में भी पैसा जाएगा। यह पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है और सामाजिक दृष्टि से भी अपने आप में अच्छी योजना है। मैं चाहूंगा कि हमने आधार का जो कानून बनाया है, उसके तहत केवल केन्द्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी उसका भरपूर लाभ उठाएंगी जिसमें सब्सिडी का पैसा बचेगा ताकि उसे गरीब वर्ग के लिए और तीव्रता से डाल सकें।

मुद्रा योजना एक बहुत सफल योजना है। 50 हजार, 5 लाख, 10 लाख तक के छोटे ऋण लोगों को मिलते हैं। ये समाज के गरीब लोग हैं लेकिन ईमानदार हैं। इसमें रिकवरी रेट 99 फीसदी से भी ज्यादा

है। वह कोई पैसा नहीं मार रहा है। वह रात को बारह बजे से पहले आकर एटीएम मशीन में पैसे वापिस जमा करवा देते हैं ताकि उस दिन का ब्याज बच जाए।

मैं उनके कुछ कार्यक्रमों में गया जहां उन्हें टैक्स भरने थे। स्लम्स में महिलाओं से पूछा आप किसके लिए प्रयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं वहां ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी। आप किसलिए करेंगी। मैं बॉटिक चलाऊंगी। उनकी उम्मीद भी बढ़ रही है। इसमें अधिकतर व्यक्ति, 70 फीसदी से ज्यादा लोग जो इसका लाभ उठा रहे हैं, वे महिलाएं हैं जो घर के अंदर एक सैकिंड इनकम बनाने का प्रयास कर रही हैं। इसका अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों, एससी, एसटी को भरपूर लाभ मिलेगा। सरकार या निजी क्षेत्र हरेक को इस देश में रोजगार नहीं दे सकता। इसलिए लोग अपने पांवों पर खड़े हो जाएं, यह उसका प्रयास है। उसी दिशा में हमारा स्टार्ट अप या स्टैंड अप है उनके लिए साधनों की कमी नहीं होगी।

स्टैंड अप में योजना ही महिलाओं और एससी/एसटी के लिए है, हर बैंक का ब्रांच इन वर्गों से दो-दो व्यक्तियों को लेगी, एक-एक करोड़ रुपये तक ऋण देगी। एक एससी व एसटी और महिला वर्ग से इन्टरप्रिन्यूर को खड़ा करेगी। इस देश में डेढ़ लाख से ज्यादा ब्रांचेज हैं, एक साल में हम लोग ढ़ाई-तीन लाख इन्टरप्रिन्यूर को ऋण देकर व्यवसाय के लिए खड़े कर सकेंगे और यह अपने आप आगे बढ़ेगा। हमारा बजटरी अकाऊंटिंग डिफरेंट है। यह पहला बजट है जितना हमने कहा था उससे ज्यादा किया है। हमने लाख-डेढ़ लाख फिसिकल डेफिसिट को मेन्टेन करने के लिए काटा नहीं है। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में देश में जो कृषि पैदावार होती है उसमें कहीं से भी निवेश आए, बाहर से आए लेकिन इस देश की पैदावार प्रोसेस हो, व्यर्थ न जाए उसका किसान को लाभ होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हमने खोला है। 'आधार' अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना है। राज्यों को हमने कितना दिया। पिछले वर्ष 6,68,000 करोड़ रुपये राज्यों को दिए। गत वर्ष में 8.11 लाख करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अगले साल 9.11 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, यह तीनों वर्षों का हिस्टोरिक एक के बाद एक राज्यों का शेयर बढ़ता जा रहा है। मैं शिकायत की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। जब जीएसटी लागू होगा सेसेज अपने आप समाप्त हो जाएंगे।

एक चीज स्पष्ट याद रखिए केन्द्र को भी सर्वाइव करना है। I am sure Shri Shashi Tharoor will appreciate that India is the union of States. The Union has to survive. Therefore, it has to financially survive. Having given 42 per cent to the States through various Schemes to the States, obviously the Union needs some money. These are methods of keeping some resource with the Union so that you need for the Union funding itself plus others. You cannot have the Union which is penniless and which is then dependent on the States for its survival. आप टैक्सेशन के

संबंध में कल्पना कीजिए, इसके लिए हम लोगों की क्या नीति रही? डॉयरेक्ट टैक्स, पहले बजट में मैंने दो लाख की छूट को ढ़ाई लाख किया। 80 सी में जो छूट एक लाख रुपये मिलती थी उसे डेढ़ लाख किया। घर के लिए जो उधार लिया उसमें जो छूट मिलती थी उसे 50,000 रुपये बढ़ा दिया। पिछले साल मेडिकल के नाम पर बढ़ाया, ट्रांसपोर्ट के नाम पर बढ़ाया जिससे ये छूट बढ़ती जा रही है। इसका उद्देश्य यह था कि टैक्स पेयर बेस भी छोटा न हो। इसके साथ-साथ लोगों के हाथ में ऐसी आमदनी रहे जिसे वह खर्च कर सके, यह सब छोटे टैक्सपेयर के हित में थे। इस बार किरायेदार को हम लोगों ने 60,000 रुपये की छूट दे दी। हर छोटे टैक्स पेयर को 5000 रुपये की छूट दे दी। इसके अंदर दो करोड़ टैक्स पेयर आते हैं। दो ऐसे प्रावधान जिसकी चर्चा किसी ने नहीं की कि हमने टैक्स व्यवस्था को कितना सरल किया। जितने भी छोटे दुकानदार और व्यावसायिक इस देश में हैं, जिनकी टर्न ओवर दो करोड़ रुपये साल की है, दो करोड़ में अधिकतर दुकानदार, वर्कर्शाप ऑनर, सारे छोटे लोग आते हैं, उसे कोई किताब मेन्टेन नहीं करना है कोई बुक्स ऑफ अकाउन्ट नहीं चाहिए, हमने इसे प्रिजम्प्टिव इनकम मान लिया है। हम अंदाजे से मान रहे हैं कि जितनी उसकी टर्न ओवर है, उसका आठ परसेंट उसकी आमदनी होगी, उस आठ परसेंट की छूट 80 सी वगैरह वह ले ले और बकाया पर टैक्स दे दे, वह जो टैक्स भरेगा वह स्वीकार हो जाएगा। वह ऑनलाइन टैक्स भरेगा, ऑन लाइन आर्डर मिलेगा और ऑन लाइन रिफंड आएगा। उसे कोई किताब मेन्टेन नहीं करना है। कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। इसमें लाखों लाख लोग प्रिज्मटिव इनकम में आने वाले हैं और छोटे आदमी का सिरदर्द एकदम समाप्त हो जाएगा। जितने प्रोफेशनल हैं जैसे चाटर्ड अकाउन्टेंट, एडवोकेट, डॉक्टर के क्लीनिक में जाते हैं और बाहर पैसा देते हैं। उसमें लोगों को लगता है कि कितना टैक्स देते होंगे, कितना नहीं देते होंगे। हमने सारे प्रोफेशनल्ज को एज ए क्लास कह दिया कि आप अपनी जितनी भी इनकम डिसक्लोज करेंगे, उसमें से आपकी इनकम 50 फीसदी मानी जायेगी और 50 फीसदी आपका खर्चा माना जायेगा। आपको कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है। आप असेसमैंट भरिए और उसे स्वीकार कर लिया जायेगा। जो नौकरीपेशा हैं, सैलरीड हैं, उन्हें वैसे ही तकलीफ नहीं होती। हमारी अधिक से अधिक असेसमैंट ऑन लाइन होंगी। जो प्रश्न पूछे जायेंगे, वे ऑन लाइन होंगे और डिपार्टमैंट को एक प्रकार से फेस लैस बना दिया गया है। जितने आइटम्स में हमने छूट दी है, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि कुछ की ड्यूटी बढ़ायी, ताकि विदेशों से सामान आता है, तो उसकी तुलना में भारत में बढ़ जाये। यह सारा हमने उस दृष्टि से इसे रखा है।

हमने सबसे अधिक लाभ हाउसिंग सैक्टर को दिया। स्वाभाविक है कि इस सैक्टर के अंदर लाभ हो और धीरे-धीरे हमारे टैक्सेज, कारपोरेट टैक्सेज ग्लोबल लैवल पर आ जायें, ताकि निवेश आने पर हमें उसमें

भी आपने आप लाभ हो पाये। अब सदन में और सदन के बाहर टिप्पणी की गयी कि काले धन का क्या हुआ?

अध्यक्षा जी, मैं आपको इसका जिक्र कर दूं कि मैंने इस बजट में तीन सैटलमैंट स्कीम्स बनायी है। वैसे चार स्कीम्स हैं। पहली यह है कि किसी के पास कोई पैसा है, जो असेसमैंट से छूटा हुआ है, तो 30 परसेंट टैक्स और 15 परसेंट पैनल्टी, यानी 45 परसेंट देकर उसे सैटल कर सकता है। दूसरा यह है कि जिसकी अपील डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में पैंडिंग है, वह टैक्स प्लस इंटरस्ट देकर बिना पैनल्टी के टिल दी डेट ऑफ असेसमैंट, कुछ केटेगिरीज तक उसे सैटल कर सकता है। तीसरा, जिन पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू होता है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि भविष्य की तारीख में टैक्स लगेगा, तो वह केवल मूल अमाउंट देकर सैटल कर लें, तो टैक्सेशन को क्लीन अप किया जाये। अब यह कहा गया कि आपने 30 प्लस 15 परसेंट लगा दिया। I heard a phrase.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): 'Fair and Lovely'.

SHRI ARUN JAITLEY: I have no problem with this phrase. But this phrase is politically incorrect. It shows a racist mindset that what is not fair is not lovely… (*Interruptions*) World over, people frown on the use of such a phrase. In any case, I will pass it off as ignorance. But let me come to economics. I have, now, gone through every scheme, which came out when other Governments were in power.

You came out, let us say, with bearer bonds, which were called the black bonds – if you have cash, just deposit Rs. 10,000 of cash in a bond, you will get Rs. 12,000 back; no tax, no penalty. Very fair. Black money converted into white; no tax, no penalty. That is why I say, that such a phrase is politically incorrect; and it is also borne out of ignorance of your own history.

When the United Front was in power and Mr. Chidambaram was the Finance Minister, the last such scheme came out. It was called the VDIS scheme. That VDIS scheme was that if you have any asset, which you have not declared, you can, now, declare. But you can value it at the value of 1987. आपने वर्ष 1997 में योजना बनायी और कहा कि वर्ष 1987 की वैल्यूएशन दे दो। आप पर कोई इंटरस्ट नहीं लगेगा, कोई पैनल्टी नहीं लगेगी। आप आज की तारीख का टैक्स दे दो। आप लोग उस सरकार का समर्थन कर रहे थे।

खड़गे साहब, आप उसका असर देखिये। वह स्कीम, अगर मैं एक बात कहूं, कई लोगों का कहना है कि अनैतिक थी। इसलिए अनैतिक थी, it was immoral and improper अगर एक व्यक्ति ईमानदार टैक्स पेयर है और उसने दस लाख रुपया टैक्स 1987 में दिया। डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर ने 1997 में दस लाख रुपया दिया। ऑनेस्ट आदमी का 1987 का दस लाख रुपया 1997 तक 25 लाख हो चुका था और डिसऑनेस्ट दस लाख रुपए देकर चला गया, कोई पेनल्टी नहीं, कोई ब्याज नहीं। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी भी वही होने वाला है।

श्री अरुण जेटली : अभी नहीं हो रहा है। The 1997 scheme was commented upon as being discriminatory against an honest tax payer because there was no penalty and it was valued at a ten year old value and the effect of ten year old value was that most of the declarants were either housewives or minor children. So, what business people did was that in the name of their wives or children, they started saying मैंने 1987 में गोल्ड खरीदा था, कैश तो सिस्टम में नहीं आया या मैंने 1987 में बिजनेस, लैंड या प्रापर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था, 1987 की वैल्यु पर मैं आज टैक्स दे रहा हूं, नो पेनल्टी, नो इंटरस्ट। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया क्योंकि कुछ लोग मांगते थे after me the deluge सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि यह हमारी अंतिम स्कीम है, इसके बाद कभी भारत सरकार नहीं लाएगी। अरे भई, सरकार तो चली गई लेकिन भारत तो जीवित रहने वाला था। What was the need for any Government to bind all the future Governments? Now, the position is that this is not an amnesty or VDIS. If you have got any income today, which you have not declared, at today's market value you must declare and pay fifty per cent over and above the tax. So, 30 plus 15 is equal to 45 per cent. That is why, it is neither VDIS nor any form of amnesty or a concession.

There are several issues which Members have raised. Many Members across have raised the issue of one per cent on jewellery. Sir, let me just make it clear. मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर दूं, आपकी जिस दिन कृपा होगी और जीएसटी आएगा, तब हर वस्तु जीएसटी में आएगी तो स्वाभाविक है कि गोल्ड भी आएगा। यह उसकी तैयारी है। पहले भी सरकारें करती रही हैं और अब भी कर रही हैं। अब लगता है कि शायद जल्दी आएगा। उस परिस्थिति में यह किसी छोटे उद्योगी पर नहीं लग रहा है, जिसकी पिछले वर्ष 12 करोड़ रुपए की टर्न ओवर है और आने वाले वर्ष में हर साल छः करोड़ या उससे ज्यादा होगी। यह केवल प्रिसींपल ट्रेडर पर लगेगा, बनाने वाले पर नहीं लगेगा। यह स्पष्ट इंस्ट्रक्शन हैं।

तीसरी बात, माननीय सदस्य श्री गोपाल शेट्टी और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, इसकी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन भी दे दी गई है कि कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सैल्फ सर्टिफिकेशन है। राज्यों में जो जिस वैल्यु पर वैट देते हैं या सीए का जो सर्टिफिकेट होगा, केवल उसी के बेस पर होगा। सैल्फ सर्टिफिकेशन से होगा क्योंकि हर वस्तु जीएसटी के दायरे में आती है इसलिए यह उसकी तैयारी है। किसी

का ह्रासमेंट नहीं होगा, कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ सर्टिफिकेशन होगा, इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे दी है।

माननीय सदस्यों ने कुछ राज्यों के इश्यु उठाए हैं। स्वाभाविक है कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा की हुई है। हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर और उसके तीनों क्षेत्रों का अत्यधिक जल्दी से जल्दी विकास हो। हमने जितने इंस्टीट्युशन्स, जितने प्रोजेक्ट्स पिछले दो-तीन सालों में अलग-अलग क्षेत्रों में सैंक्शन किए हैं, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी लागू हों।उसमें जितनी कमिटमेंट्स दी गई हैं, We stand by them. जो बिहार के संबंध में की गई हैं, उसमें एक-एक को निभाया जाएगा। जो आन्ध्र प्रदेश के साथ माननीय सदस्यों का कहना सही है कि जब बंटवारा हुआ, हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में आया, इसलिए एक कानून आन्ध्र प्रदेश रीऑरगेनाइजेशन एक्ट में दिया गया है। पिछले वर्ष लगभग जितनी कमिटमेंट्स थी, उसके अलावा चार साढ़े चार हजार करोड़ हमने एक्सट्रा उसी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए दिया गया। उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। कैपिटल के लिए है। रेवेन्यू डैफिसिट जो फाइनेंस कमीशन ने दिया, वह हम पूरा दे रहे हैं। जो पहले वर्ष का जो फाइनेंस कमीशन के पहले का था, उसको लेकर चर्चा राज्यों से चल रही है। कुछ हमने पिछले साल दिया था, कुछ इस साल भी देंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसके अतिरिक्त जो उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, कैपिटल आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम उनकी योजनाओं में मदद कर रहे हैं और पोलावरम के संबंध में मैंने पहले कहा क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था कृषि उसके ऊपर निर्भर करती है। उसके लिए सरकारी साधनों से भी और नाबार्ड के माध्यम से भी जो फंड हमने बनाया है, इसी प्रकार की सहायता करने की दृष्टि से बनाया है। जितने भी उस कानून में हम लोगों की कमिटमेंट्स हैं, एक एक कमिटमेंट हम लोग पूरा करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी चर्चा हुई। एससीएसटी सब प्लान- एससी प्लान 12 प्रतिशत इस बार बढ़ाया है और एसटी 14.5 प्रतिशत बढ़ाया है। इसके बाद यह कहा गया कि स्किल्ड डवलपमेंट के लिए कम कर दिया। पिछले साल 1000 करोड़ रुपये था। इस बार 1700 करोड़ रुपये दे दिया। आपने कहा कि जो पहले प्रधान मंत्री आवास योजना जिसको कहते हैं, 54 प्रतिशत घटा दिया। एक गलती हो गई, 54 प्रतिशत बढ़ाया है। यू.पी.ए. के दौरान और पिछले वर्ष 10004 करोड़ रुपये था, इस बार उसको 15000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसलिए एक एक आइटम जो है, …(व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों की जो भावनाएं हैं, मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हैं और सरकार के साधन मुझे जब भी अनुमति देंगे, निश्चित रूप से हम इस पर

विचार करेंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बजट में राज्यों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आर्थिक सुधार के लिए और जिस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था आई है, उसको और तेजी से हम लोग बढ़ा पाएं, यह एक प्रयास किया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इन प्रस्तावों को वे स्वीकार करें और विशेष रूप से जितने हमारे सुधार के कदम आते हैं, मैं खड़गे जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि आपने इतने साल देश पर राज्य किया है, कम से कम दुनिया के सामने देश इस परिस्थिति में कमज़ोर न पड़े, उसमें सरकार आपके सहयोग और सहायता की अपेक्षा करती है। मुझे उम्मीद है कि वह सहायता और सहयोग आप देंगे। धन्यवाद।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Please do something for the rubber farmers. The farmers are struggling.… (*Interruptions*)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): You do justice for the rubber farmers.… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष जी, जेटली साहब ने बहुत लम्बी तकरीर दी है, जवाब दिये हैं, डेढ़ घंटे तक उनकी तकरीर हमने बड़ी शांति के साथ सुनी है लेकिन देश को यह बताने में वह भूल गये कि उनको जो फायदा क्रूड ऑयल, पेट्रोल से जो भी पैसे आए थे, 1,50000 करोड़ आए थे। आज के प्रश्न में ही आपके मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि जो पैसा हमें एक्साइज ड्यूटी के तहत आया है, वह आधे से ज्यादा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया है। उपभोक्ताओं के लिए इस पैसे का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी फायदा हुआ उसका एक चौथाई भी उपभोक्ता को ट्रांसफर नहीं किया और आप कह रहे हैं कि आपने सारी चीजें की हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दोबारा भाषण मत दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, प्रधानमंत्री जी के इकोनोमिक एडवाइजर का कहना है कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनमें से 30 परसेंट लोगों को यूपीए सरकार के बहुत सारे इन्क्लुसिव ग्रोथ प्रोग्राम्स के तहत ऊपर उठाया गया है। यह सरकार के लोगों का ही कहना है।

HON. SPEAKER: Do you have any clarification to seek?

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह बात प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर ने ही कही है। यूपीए सरकार के प्रोग्राम गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए गए थे। मोदी साहब ने जो कहा था उसका फिर आपने समर्थन किया है कि मनरेगा स्मारक है। आपने अप्रत्यक्ष रूप से फिर कहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महताब जी, आप बोलिए। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन पूछिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने फिर भाषण शुरू कर दिया है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जो बातें मंत्री जी ने कही हैं, वे सत्य से दूर हैं और ठीक नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस था, वर्ष 2008 में ग्लोबल क्राइसिस था लेकिन फिर भी भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत थी, यह सभी का कहना था लेकिन आप उसे नहीं मान रहे हैं।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record except what Shri Mahtab speaks.

… (*Interruptions*)…*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I have patiently heard what the hon. Finance Minister has said. Today morning while going through the newspaper, I also read the statement of the Finance Minister relating to NPAs. Along with that statement, the SEBI Chairman has come out with a statement that those defaulting corporate bodies, which have large amount of NPAs will not be allowed to participate in the share market. These two opinions are there before the public. I was anxiously waiting for the Finance Minister to spell out what steps are going to be taken against the derelict corporate bodies or persons who have actually bungled.

I had quoted the statement of the RBI Governor who has come out very openly that those who have bungled should be punished and penalized. But the Finance Minister in his statement has categorically mentioned that there are two types of NPAs. I would like the hon. Finance Minister to come out with a full White Paper against those corporate people, who have actually bungled.

* Not recorded.

My second point is regarding Polavaram Project. He has repeatedly mentioned it. I have said it very clearly that Odisha is not against the Polavaram Project. But there has been a tripartite agreement and the matter is before the Supreme Court. Yet, repeatedly the Government of India is saying that we are going to provide money for it and the Andhra Government is also proceeding with that. I want the Government to get it finalized before the Court and have a settlement and then provide the money. … (*Interruptions*) The matter is before the Supreme Court. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, it is not allowed. It is okay.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He will answer.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down.

Nothing will go on record. Only Minister's statement will go on record.

… (*Interruptions*)… *

HON. SPEAKER: Mr. Minister, you start. Only your version will go on record.

… (*Interruptions*)… *

श्री अरूण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खड़गे साहब ने दो-तीन विषय उठाये हैं। उनका एक विषय यह है कि तेल के दाम कम होने से जो पैसे बचते हैं, उन सारे पैसों का क्या हुआ? खड़गे साहब! आप पूरी अर्थ-व्यवस्था को देखिए। तेल के दाम कम होने से जो लाभ हुआ, वह लाभ का पैसा तीन हिस्सों में बंटता है। आपने दो हिस्सों का जिक्र किया है, लेकिन ये तीन हैं। जो पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियाँ हैं, वे दुनिया के बाज़ार से कच्चा तेल खरीदती हैं, तो उन फ्युचर परचेज में आरंभ में ऐसी कल्पना नहीं की गयी थी कि यह कितना घटेगा, उनका घाटा हुआ। किस प्रकार का घाटा हुआ? उन्होंने 80 डालर के हिसाब से तेल बुक किया और खरीदा और जब तक बेचना शुरू किया तो वह 60 डालर की कीमत तक आ गयी। एक स्थिति ऐसी थी कि इन कंपनियों का लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ। उसे इनकम बढ़ाने से या कोई और टैक्स लगाने से पूरा करना है क्या? स्वाभाविक है कि कोई भी कम्पनी जो दाम तय करती है, वह अपना घाटा उसमें से पूरा करेगी। उस घाटे को हटाया गया और वे लिस्टेड कम्पनीज हैं।

---

* Not recorded.

उनमें सरकार भी शेयर होल्डर है और प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा, हर 15 दिनों के बाद तेल कम्पनियाँ उसकी समीक्षा करती हैं। हर महीने की अंतिम डेट को और मध्य में हर 15 दिनों के बाद उसकी नयी कीमत की घोषणा करती हैं। बढ़ता है तो बढ़ी हुई कीमत का लाभ मिलता है और घटता है ...(व्यवधान) तो वह उपभोक्ता को जाता है। तो जो 80-82 रुपये तक था, वह 58-57 रुपये आया। कुछ राज्य सरकारों ने भी, जिसमें हर राजनीतिक दल की सरकार है क्योंकि राज्यों को एक नुकसान भी हुआ। मैं राज्यों की तरफ से यह कह रहा हूँ। लेकिन राज्य ऐड वेलोरम पर्सेंटेज़ के हिसाब से वैट लेते थे। जब दाम घटा तो उनका पर्सेंटेज कलेक्शन कम हो गया। कई राज्यों ने, जहाँ आपकी पार्टी की भी सरकारें हैं, उन्होंने अपना वैट बढ़ाया। तो उन्होंने भी इसका लाभ उठाया। कम से कम राज्य सरकारें भी उस पैसे का प्रयोग, किसी व्यक्ति के जेब में नहीं डालतीं, वे भी जनता के हित के लिए इसका प्रयोग करती हैं। जो केन्द्र सरकार के पास उसका एक छोटा-सा हिस्सा सेस या एक्साइज के रूप में आया, उन सारे पैसों को, जो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खर्चना था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चने से रोजगार भी बढ़ता है, अर्थ-व्यवस्था भी बढ़ती है और जीडीपी भी बढ़ती है। इसलिए जो आदमी स्कूटर, कार या ट्रक चलाने के लिए तेल खरीदता है, वह सड़क का भी प्रयोग करता है। इसलिए उसका यह योगदना सड़क के निर्माण में लगा। आप व्यापक अर्थ-व्यवस्था को देखिए।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What is the consumer getting?

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the consumer is also getting a road. … (*Interruptions*) I think, there is something wrong in my effort to explain because the simple explanation is that the consumer is entitled to pay less for petrol; he is also entitled to a good road. Therefore, the consumer gets a good road. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Why are you answering? Nothing is going on record. This is not fair.

… (*Interruptions*)…[*]

SHRI ARUN JAITLEY: I think, when we are in power, you allow us to run it our way.

---

[*] Not recorded.

Secondly, I do not think that the statement, which you are attributing to the Chief Economic Adviser, appears to be accurate, but I do not join issue on this. … (*Interruptions*)

Now again, your argument is that these are your schemes. Very well, you want to take the credit. That day during discussion on Aadhaar Bill, I said 'you want to keep the copyright. Please keep it.' But at least, then stand up and support the Budget because it is your scheme. The very fact that you say that you will still oppose it, it means that you have some doubts or you have changed your views or where you stand on issues, it depends on which side you sit on. … (*Interruptions*)

Shri Mahtab wanted to know about the SEBI Chief's statement. That statement is with regard to wilful defaulters. Now, wilful defaulter is a phrase under the RBI guidelines where a defaulter is declared as a wilful defaulter. Now, if you are a wilful defaulter, then you are barred from the rest of the financial system from either taking loans in any name, your name or any other company. Other companies that you are associated with are debarred. So, he has made a statement that they will debar him from financial dealings so that he cannot get money from the banks. So, he will start raising it from the market by misleading people. This is a facility, which is to be denied to a wilful defaulter.

What steps are the Government taking? Now, the first step is that the balance sheets must be clean. We must know where we stand. We cannot function under concealed balance sheets. This is a process, which is on. You take legal action where recoveries are to be made. Here, I must tell you that it is a big challenge to the legal system. I have got a briefing and if necessary and there is time, I can and the House also shares it that the most visible of defaulters who are managing to even escape out of the country, a question that we have to ask ourselves is this. Did the legal system also act as a hurdle in the recovery? How many cases, the banks, in the last three years have had to fight against such people? This is for every institution now to really look within.

Besides that, these tough measures like declaration of wilful defaulters, you have a very strong SDR mechanism with the banks whereby the banks can take over the share holding of the company, they can compel you to sell the asset, or they can bring a new promoter on it. So, the pressure is on some of these people who have not succeeded to induct in more liquid managements.

These days, you must be reading in the newspaper that some of the companies are being sold to persons who are in a position to induct money so that the banks itself could be returned.

As regards sectoral concerns, that I have just explained that for highway, steel, sugar, and power you have to address the cause of the illness as far as the sectors are concerned.

Lastly, my appeal to this House is that this country desperately needs the Bankruptcy and Insolvency Law. It is intended to deal with these situations. The earlier we are able to deal with it in this House, the better. I hope that the Joint Committee, which is working on it, will soon give its Report and in the second-half of the Budget Session we will pass it as that gives you the power, when the company is sinking, to take over the management or even transfer the management so that the incompetent and the failed can exit, the jobs can be saved and the more competent can come in and run the company. So, you need a mechanism of this kind. These are steps, which we have taken.

With these observations, Madam, I commend the Bill.

SHRI ANTO ANTONY: Mr. Minister, say something about the farmers. … (*Interruptions*) You have not said anything about them. … (*Interruptions*) The poor people are committing suicide. … (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, kindly allow me to ask a clarification. … (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY: Mr. Minister, do something about the farmers. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (General) for 2016-2017 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 30, 32, 34 to 56, 58 to 64, 66 to 68, 70, 71 and 73 to 98."

DEMANDS FOR GRANTS

The Motion was adopted.

HON. SPEAKER : The damands for Grants on Account (General) for 2016-17 are passed.

I shall now put the Supplementary Demands for Grants – Third Batch (General) for 2015-2016 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 6, 9, 10, 12 to 16, 18 to 20, 23 to 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 55 to 57, 59 to 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 80, 82 to 89, 91, 92, 94, 96, 99 to 101, 103 to 105, 107, 108 and 109."

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Supplementary Demands for Grants – Third Batch (General) for 2015-2016 are passed.

20.00 hours

HON. SPEAKER: Item No. 23, Shri Arun Jaitley.

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2016*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2016-17.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2016-17."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I introduce** the Bill.

HON. SPEAKER: Item No. 24, Shri Arun Jaitley.

SHRI ARUN JAITLEY : Madam, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2016-17, be taken into consideration."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 14.03.2016.
** Introduced with the recommendation of the President.